राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक: 1] पन्द्रहवीं विधान सभा के पहले सत्र का सातवां दिवस [संख्या: 5

सोमवार,

21 जनवरी 2019

(राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे
राजस्थान विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई)

(श्री सी. पी. जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष: श्री पुखराज।

भोपालगढ़ के चिकित्सालयों में रिक्त पद

1. **श्री पुखराज** (भोपालगढ़): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र भोपालगढ़ में कितने प्राथमिक, सामुदायिक व उप स्वास्थ्य केन्द्र किस-किस स्थान पर संचालित हैं तथा उनमें सृजित, कार्यरत व रिक्त पदों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त क्षेत्र में चिकित्सालयों में रिक्त पदों को भरने के लिए सरकार की क्या कार्य योजना है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार भोपालगढ़ में संचालित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में महिला चिकित्सक का पदस्थापन करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? कारण सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार जनहित में भोपालगढ़ उपखण्ड मुख्यालय पर उप जिला अस्पताल स्वीकृत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री (श्री रघु शर्मा): (1) भोपालगढ़ विधान सभा क्षेत्र में स्वीकृत प्राथमिक, सामुदायिक व उप स्वास्थ्य केन्द्रों के नाम का विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

विधान सभा क्षेत्र भोपालगढ़ में संचालित चिकित्सा संस्थानों में चिकित्सकों के स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों की सूची परिशिष्ट-ब एवं

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

अराजपत्रित संवर्ग के स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों की सूचना परिशिष्ट-स पर संलग्न है।

(2) पदोन्नति के रिक्त पदों को डीएसीपी के अन्तर्गत पदोन्नत चिकित्सकों से/पी.जी. पूर्ण चिकित्सक उपलब्ध होने पर यथासम्भव शीघ्र भरने के प्रयास किए जाएंगे। चिकित्सा अधिकारी के रिक्त पदों को शीघ्र भरने के प्रयास किए जाएंगे।

विभाग में नर्सिंग/पैरामेडिकल संवर्ग में रिक्त पदों को भरे जाने हेतु विज्ञप्ति जारी कर आवेदन प्राप्त किए जा चुके हैं तथा भर्ती की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। भर्ती की कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात् रिक्त पदों को प्राथमिकता के साथ भरे जाने का प्रयास किया जाएगा। विभाग में पदोन्नति वाले रिक्त पदों को विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक उपरांत रिक्त पदों को भरे जाने के प्रयास किए जाएंगे।

पदनाम	**रिक्त पदों की संख्या**	**जारी विज्ञप्ति की दिनांक**
नर्स श्रेणी - द्वितीय	6557	30.05.18
महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता	5602	18.06.18
फिजियोथेरेपिस्ट	30	29.03.18
प्रयोगशाला सहायक	1534	29.05.18
फार्मासिस्ट	1736	13.08.18
ईसीजी टैक्नीशियन	362	01.08.18
कुल	**15821**	

इस प्रकार कुल 15821 पदों के लिए भर्ती की प्रक्रिया जारी है।

(3) विधान सभा क्षेत्र भोपालगढ़, जोधपुर में स्त्री रोग विशेषज्ञ चिकित्सक का एक पद सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, भोपालगढ़ में स्वीकृत है जिस पर स्त्री रोग विशेषज्ञ चिकित्सक पदस्थापित है। वर्तमान में महिला चिकित्सक पदस्थापित नहीं है। पी.जी. पूर्ण/स्थानान्तरण से महिला चिकित्सक लगाने के यथासम्भव प्रयास किए जाएंगे।

(4) उपखण्ड भोपालगढ़ में 100 शय्याओंयुक्त सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र संचालित है।

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

चालू/आगामी वित्तीय वर्षों में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का नाम चिकित्सालय में परिवर्तित कर उप जिला चिकित्सालय की श्रेणी में सम्मिलित किए जाने का विचार किया जाएगा।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री पुखराज (भोपालगढ़): सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी ने जो जवाब दिया है, इसमें प्रश्न 2 के जवाब में बताया है कि विभिन्न पदों की विज्ञप्ति जारी की गई है। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि इनकी कब तक पोस्टिंग हो जाएगी और जो रिक्त पद हैं वह कब तक भरे जाएंगे? विज्ञप्ति का कोई तात्पर्य नहीं है। आप विज्ञप्ति की बात कर रहे हैं तो एक तरफ 2016 के जो चयनित आर.ए.एस. हैं वो सड़क पर बैठे हैं और पोस्टिंग का इंतजार कर रहे हैं जबकि आप विज्ञप्ति का जवाब दे रहे हैं। इसलिए इनकी तारीख बताएं कि कब तक पद भर दिए जाएंगे।

दूसरा, जो 4 नम्बर के प्रश्न के जवाब में बताया है कि उपखण्ड भोपालगढ़ में वर्तमान में 100 बैड का सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र संचालित है, यह बिलकुल गलत है। भोपालगढ़ विधान सभा क्षेत्र में आज की तारीख में 30 बैड का सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र संचालित है जिसमें 7 मेडिकल आफिसर नियुक्त हैं और 3 नर्सिंग स्टाफ है। अगर यह 100 बैड का हास्पिटल संचालित होता तो इसमें कम से कम 24 मेडिकल आफिसर होने चाहिए थे, 44 नर्सिंग स्टाफ होना चाहिए था। इन्होंने जो एक तरफ मेडिकल आफिसर की पूरी पोस्ट फिल-अप बताई है, वैकेंट नहीं है तो क्या 100 बैड का हास्पिटल संचालित है उसमें स्वीकृत पद 7 ही हैं क्या?

श्री अध्यक्ष: धन्यवाद। मंत्री महोदय।

श्री रघु शर्मा (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, विधान सभा क्षेत्र भोपालगढ़ में 4 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र हैं, 15 प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र हैं और 102 उप स्वास्थ्य केन्द्र हैं। विधान सभा क्षेत्र भोपालगढ़ में चिकित्सकों के कुल 47 पद स्वीकृत हैं जिनमें 42 पदों पर चिकित्सक कार्यरत हैं एवं 5 पद रिक्त हैं। 42 भरे हुए पदों में से एक चिकित्सक अन्यत्र कार्य व्यवस्था में लगा हुआ है तथा एक चिकित्सक 3 माह से ज्यादा समय से अनुपस्थित है। इस प्रकार व्यावहारिक रूप से 40 चिकित्सक कार्यरत हैं। रिक्त पदों को शीघ्र पदोन्नति और सीधी भर्ती से भरने की कार्यवाही की जा रही है। विधान सभा क्षेत्र भोपालगढ़ में अराजपत्रित

(श्री रघु शर्मा)

कर्मचारियों के कुल 405 पद स्वीकृत हैं जिनमें से 280 पद भरे हुए हैं एवं 125 पद रिक्त हैं। 280 भरे हुए पदों में 2 कर्मचारी अन्यत्र कार्य व्यवस्था में लगे हुए हैं, एक कर्मचारी अन्यत्र से वहां कार्य व्यवस्था के तहत विधान सभा क्षेत्र भोपालगढ़ में लगा हुआ है। इस प्रकार वास्तविक रूप से 279 कर्मचारी कार्यरत हैं। रिक्त पदों को शीघ्र ही पदोन्नति अथवा सीधी भर्ती के माध्यम से भरने की कार्यवाही की जा रही है।

जहां तक माननीय सदस्य ने सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, भोपालगढ़ में 100 शय्याओं की प्रशासनिक स्वीकृति के बारे में बात की है तो, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को यह बताना चाहता हूं कि 2013 में जब राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी तब हमारी सरकार ने इस आशय के आदेश जारी किए थे और उसकी प्रशासनिक स्वीकृति जारी की। मैं अफसोस के साथ कहना चाहता हूं कि विगत 5 वर्षों में पूर्ववर्ती सरकार ने एक कदम भी इसमें आगे नहीं बढ़ाया और न कोई वित्तीय स्वीकृति जारी की लेकिन मैं आपके माध्यम से, माननीय सदस्य को यह भरोसा दिलाना चाहता हूं कि हमारी सरकार उक्त लम्बित वित्तीय स्वीकृति को शीघ्र जारी करने पर सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाते हुए कार्यवाही करेगी।

श्री हनुमान बैनिवाल (खींवसर): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बहुत गम्भीर इश्यू है। चूंकि भोपालगढ़ के एम.एल.ए. साहब ने सवाल पूछा है, राजस्थान के अन्दर मेडिकल एण्ड हैल्थ डिपार्टमेंट में ज्यादातर पद खाली हैं जिनकी वजह से स्वाइन फ्लू जैसी भयावह बीमारी राजस्थान में पैर पसार चुकी है तथा जनवरी के अन्दर रिकार्ड तोड़ स्वाइन फ्लू से मौतें हुई हैं। न सी.एच.सी. पर कोई जांच का साधन है न पी.एच.सी. पर है, न जिला अस्पतालों में है। एस.एम.एस. मेडिकल कालेज और मेडिकल कालेज में जरूर स्वाइन फ्लू की जांच के साधन उपलब्ध हैं। गरीब आदमी जांच नहीं करवा पाता है, डाक्टर उसको देखते नहीं और बुखार समझकर वह लम्बा हो जाता है। (व्यवधान)

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): यह प्रश्न स्वाइन फ्लू का नहीं है। (व्यवधान)

श्री हनुमान बैनिवाल (खींवसर): रामलाल जी, बीच में क्यों कर रहे हो, बैठो न।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप सीनियर मैम्बर हैं।

श्री हनुमान बैनिवाल (खींवसर): मैं इसके अन्दर मंत्रीजी से यही जवाब चाहूंगा कि जितने जल्दी हो सके, भरें क्योंकि पूर्ववर्ती सरकार के टाइम में हम रोज देखते थे....

श्री अध्यक्ष: प्रश्न, माननीय सदस्य, प्रश्न पूछें।

श्री हनुमान बैनिवाल (खींवसर): एक मिनट। वो भूमिका बनाकर बोलूंगा न साहब थोड़ा-सा।

श्री अध्यक्ष: सीधा प्रश्न करें।

श्री हनुमान बैनिवाल (खींवसर): कर रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं यह चाहूंगा कि स्वाइन फ्लू की रोकथाम के पुख्ता इंतजाम किए जाएं, खाली पद भरे जाएं। अध्यक्ष महोदय, एक और है कि बार-बार डाक्टर्स हड़ताल पर चले जाते हैं। यह गरीब आदमी का मुद्दा है। बाद में समझौता हो जाता है।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी।

श्री हनुमान बैनिवाल (खींवसर): इन मंत्रीजी की जिद्द की वजह से 100 दिन हड़ताल चली है, अध्यक्ष महोदय। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, भोपालगढ़ के बारे में है प्लीज। भोपालगढ़ के बारे में प्रश्न पूछें बस।

श्री हनुमान बैनिवाल (खींवसर): अध्यक्ष महोदय, एक मिनट। भोपालगढ़ मेरा नजदीकी है। अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी की जिद्द की वजह से 100 दिन हड़ताल चली। आप नहीं, पुराने का कह रहा हूं, इनका कह रहा हूं, पूर्ववर्ती सरकार के अन्दर हुई। 100 से ज्यादा मौतें हुई।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्लीज।

श्री हनुमान बैनिवाल (खींवसर): अध्यक्ष महोदय, उन मौतों के लिए आखिर लाइबल कौन हैं? वो तो डाक्टर वापस हड़ताल से लौट आए।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी, बोलना चाहेंगे?

श्री हनुमान बैनिवाल (खींवसर): मंत्रीजी ने जवाब दे दिया। मंत्रीजी, रुको।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री हनुमान बैनिवाल (खींवसर): अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी पर इतने गम्भीर आरोप लगे, भ्रष्टाचार के आरोप उन पर लगे, पैट्रोल पम्प से पर्ची की बात चली और ए.सी.बी. ने. एंटी करप्शन ब्यूरो ने.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, अभी आप प्रश्न कर रहे हैं क्या? (व्यवधान) आप बैठें, यह मेरा काम है। (व्यवधान)

श्री हनुमान बैनिवाल (खींवसर): .... राजस्थान में मंत्री पुत्र के खिलाफ ए.सी.बी. ने जांच का परिवाद लिया। (व्यवधान) इसके बाद इनके स्टाफ के खिलाफ भी... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य मेरा काम मुझे करने दीजिए। मुझे गाइड मत करिए। मुझे पता है... (व्यवधान)

श्री हनुमान बैनिवाल (खींवसर): नर्सिंग कालेजों को लेकर भी भ्रष्टाचार के गम्भीर आरोप लगे, लेकिन इनकी दादागीरी ऐसी थी कि भ्रष्टाचार के भारी आरोप लगने के बाद भी मुख्य मंत्री इनको मदद करती थीं, प्रोटेक्ट करती थीं और भारी भ्रष्टाचार इन्होंने... (व्यवधान)

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़): पूर्ववर्ती सरकार को कोसने से स्वाइन फ्लू का इलाज है...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): इस तरह की बात होगी... (व्यवधान) अगर आसन अलाउ करेगा..

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप वरिष्ठ सदस्य हैं, मुझे क्या करना है मुझे मालूम है। आप बैठें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): अध्यक्ष महोदय, सदन नियमों से चलेगा।

श्री अध्यक्ष: मुझे मालूम है। मुझे मालूम है क्या करना है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): सदन नियमों से चलेगा, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष: Don’t guide me, Don’t guide me.

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): आसन भी नियमों से बंधा हुआ है।

श्री अध्यक्ष: Don’t guide me, आप बैठ जाइए प्लीज। मैं खड़ा हूं, इस समय आप बैठे हुए हैं। आप सीनियर लीडर हैं। मैं चेयर पर खड़ा हूं, आप बोल रहे हैं। आप दूसरे से एक्सपैक्ट करते हैं, वो तो नियम का पालन करें। आप नहीं करेंगे। मेहरबानी करके मुझे मालूम है, मुझे किस तरह सदन संचालित करना है। आप कृपया अपनी जो जिम्मेदारी है, उसका निर्वहन करें। माननीय मंत्रीजी। बैनिवाल जी नहीं, अब नहीं, अब हो गया। माननीय मंत्रीजी। माननीय बैनिवाल जी, नहीं, आप प्लीज। मैं मंत्रीजी को उत्तर के लिए मना कर दूंगा। उत्तर के लिए मना कर दूंगा मैं। माननीय मंत्रीजी।

श्री रघु शर्मा (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, भ्रष्टाचार को लेकर खींवसर से आने वाले माननीय विधायक ने यहां चिन्ता प्रकट की। मैं खुद भी इस मामले में बिलकुल चिंतित हूं, क्योंकि विभाग कभी बीमार नहीं होता। अध्यक्ष महोदय, विभाग में काम करने वाले की मानसिकता बीमार हो सकती है। मेरा यह मानना है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं। काली-काली कमाई, फ्रन्ट फुट पर बैटिंग होती रही और विभाग बैकफुट पर चला गया और हमारी पूर्ववर्ती सरकार देखती रही। मैंने इस विभाग का जिम्मा संभालने के बाद...(व्यवधान) एक मिनट यह क्या तरीका है, अध्यक्ष महोदय आपका संरक्षण चाहता हूं मैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): सवाल के जवाब में आप यह अलाउ कर रहे हैं?

श्री अध्यक्ष: आप मंत्री को भी डिक्टेट करेंगे।

श्री रघु शर्मा (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): जवाब दे रहा हूं मैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): भोपालगढ़ का सवाल है...

श्री अध्यक्ष: आप मंत्री को भी डिक्टेट करेंगे? आप, राजेन्द्र जी, ऐसा नहीं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): मैं तो बैठ जाऊंगा, अगर इस तरह बात चलेगी...

श्री अध्यक्ष: ऐसा नहीं होगा, आप बैठिए। आप बैठिए, आप बैठिए, आप सीनियर लीडर हैं, आप मंत्री रहे हुए हैं। आप मंत्री को भी डिक्टेट करेंगे? आप और हम सुन सकते हैं आराम से।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): आप स्वाइन फ्लू की बात करो...

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): आप भोपालगढ़ की बात करो।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप नियम का पालन करिए, दूसरे से आशा करने से पहले। माननीय मंत्रीजी, Be specific about the question, that’s all.

श्री रघु शर्मा (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह तो चोरी और सीना जोरी हो गई। मैं विभाग का...

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): आपकी सरकार है, जांच करवा लीजिए...

श्री रघु शर्मा (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): बात तो करो, बात करने में क्या दिक्कत है।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): भ्रष्टाचार किया है, इस प्रकार से आरोप नहीं लगाएंगे आप। क्या बात करते हो आप।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप वरिष्ठ सदस्य हैं सदन के। आप गलत परम्परा क्यों डाल रहे हैं।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): भोपालगढ़ के प्रश्न पर (व्यवधान) आपके संस्कार हैं, ताकत है तो जांच करवाइये।

श्री रघु शर्मा (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): बिलकुल करवाएंगे।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): क्या करवाएंगे, करवाइये।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप उत्तेजित नहीं हों, आप सीनियर लीडर हैं, please have patience. माननीय मंत्रीजी, be specific.

श्री हनुमान बैनिवाल (खींवसर): माननीय अध्यक्ष महोदय, जांच करवा लो, इनकी बात मान लो आप।

श्री अध्यक्ष: माननीय बैनिवाल जी..

श्री हनुमान बैनिवाल (खींवसर): नहीं, इनकी बात मान लो, अध्यक्ष महोदय। इनकी जांच करवा ही दो आप एक बार, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष: माननीय बैनिवाल जी। माननीय सदस्य, अगला प्रश्न पुकार रहा हूं। मैं अगला प्रश्न पुकार रहा हूं, नहीं सुन रहे हो उत्तर।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): जांच करवाइये, जांच करवाइये।

श्री रघु शर्मा (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह भ्रष्टाचार कोई हमारे लिए ही चिन्ता का विषय नहीं है। राजस्थान की साढ़े सात करोड़ जनता इस बीमारी से न केवल चिंतित है बल्कि परेशान है। मैंने विभाग का जिम्मा संभालने के बाद हमारे विभागीय अधिकारियों की मीटिंग में स्पष्ट निर्देश दिया है कि हमारी सरकार भ्रष्टाचार के मामले में जीरो टोलरेन्स की नीति पर काम करेगी। मैं आपके माध्यम से माननीय अध्यक्ष महोदय, सम्पूर्ण विवेक के साथ इस सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि मैं एवं हमारी सरकार किसी भ्रष्टाचारी को आशीष नहीं देंगे।

श्री अध्यक्ष: धन्यवाद। रामनिवास गावड़िया। आप प्लीज बैठिए सदस्य, सीनियर आदमी हैं आप।

परबतसर के पर्यटन स्थलों का विकास

2. **श्री रामनिवास गावड़िया** (परबतसर): क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र परबतसर में गत 5 वर्षों में पर्यटन विकास से संबंधित क्या-क्या कार्य कहां-कहां कराये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त विधान सभा क्षेत्र में ऐसे अनेक पर्यटक स्थल हैं जिनका विकास नहीं हुआ है? क्या सरकार उक्त पर्यटक स्थलों का विकास करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र के राना बाई का मंदिर व अन्य पर्यटन स्थलों का विकास करवाने का विचार रखती हैं? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

श्री अध्यक्ष: पर्यटन मंत्रीजी।

पर्यटन मंत्री (श्री विश्वेन्द्र सिंह): (1) विधान सभा क्षेत्र परबतसर में गत 5 वर्षों में पर्यटन विकास से संबंधित कार्य नहीं कराये गये हैं।

(2) विधान सभा क्षेत्र परबतसर में कुछ स्थल पर्यटन की दृष्टि से उपयोगी हैं। बजट उपलब्धता एवं प्राथमिकता चिन्हित कर प्रकरण में युक्तियुक्त निर्णय लिया जायेगा।

(3) जी नहीं। वर्तमान में ऐसा प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। बजट उपलब्धता एवं प्राथमिकता चिन्हित कर प्रकरण में युक्तियुक्त निर्णय लिया जाएगा।

श्री रामनिवास गावड़िया (परबतसर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न के भाग एक के उत्तर में यह बताया गया है कि गत पांच वर्षों में पर्यटन विकास से संबंधित कोई कार्य नहीं कराया गया। जो कहते हैं कि हमने भरपूर विकास कार्य करवाए, पूर्ववर्ती सरकार ने, इसका एक नमूना पेश किया है कि पर्यटन की दृष्टि से गत सरकार द्वारा मेरे क्षेत्र की घोर उपेक्षा की गई है जिसकी मैं सदन में निन्दा करता हूं। मैं आपके माध्यम से अध्यक्ष जी, माननीय पर्यटन मंत्रीजी को जो बहुत ही योग्य और अनुभवी हैं, उनसे पूछना चाहता हूं कि अब मेरे क्षेत्र में पर्यटन विकास की दृष्टि से आप क्या काम करवाएंगे?

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी को

(श्री रामनिवास गावड़िया)

अवगत कराना चाहूंगा कि विधान सभा क्षेत्र परबतसर में प्रदेश का सबसे बड़ा पशु मेला लगता है। जो पूरे राजस्थान में पशु मेले के नाम से पूरे देश में विश्वविख्यात है और ये जो 100 वर्ष पुराना पशु मेला है पर्यटन की दृष्टि से यह मेला एक महत्वपूर्ण मेला है और इस मेले को देखने हेतु हजारों पर्यटक आते हैं...

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्रश्न पूछें।

श्री रामनिवास गावड़िया (परबतसर): लेकिन उसका विकास नहीं हुआ है। कुचामन मंगलाणा के बीच हरियाजून पहाड़ी है, जो नागौर जिले की सबसे ऊंची चोटी है उसके ऊपर एक हजार वर्ष पुराना शिवजी का मंदिर है। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्रीजी से पूछना चाह रहा हूं कि वहां जो बावड़ियां हैं, झरने हैं, पूर्ववर्ती सरकार में जिनकी उपेक्षा की गई। आने वाले समय में जब हमारे माननीय मुख्य मंत्री अशोक गहलोत जी और माननीय सचिन पायलट साहब की जो सरकार है इसके द्वारा मेरे परबतसर क्षेत्र में शिवजी के मंदिर के लिए और जो वीर तेजा पशु मेला पूरे देश भर में प्रसिद्ध है उसके लिए आप क्या काम करवाएंगे?

श्री विश्वेन्द्र सिंह (पर्यटन मंत्री): आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को यह आश्वस्त करना चाहूंगा आपकी जो भी मांगें हैं, वाजिब हैं। आप अपने सुझाव रखें, स्वागत है आपका। मुझसे व्यक्तिगत मुलाकात कर लें और हम जांच करवाकर इसकी पूरी जो भी आगे की प्रक्रिया है बजट के लिए, सिफारिश कर दी जाएगी।

श्री अध्यक्ष: निर्मल कुमावत।

प्रदेश में नवीन जिलों का गठन

3. **श्री निर्मल कुमावत** (फुलेरा): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में नवीन जिलों के गठन एवं पुनर्गठन के प्रस्तावों पर विस्तृत परीक्षण कर नये जिले स्थापित किये जाने के संबंध में रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत किये जाने के लिए एक समिति का गठन किया गया है? यदि हां, तो कब व उक्त समिति के कौन-कौन सदस्य हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार को उक्त समिति द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गई

(श्री निर्मल कुमावत)

है? यदि हां, तो कब व नहीं, तो अब कब तक उक्त समिति रिपोर्ट प्रस्तुत कर देगी? रिपोर्ट की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार द्वारा उक्त समिति को अपनी रिपोर्ट शीघ्र प्रस्तुत करने हेतु पत्राचार किया गया है? यदि हां, तो कब-कब व नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या यह सही है कि जयपुर जिले के सांभरलेक को जिला बनाने की विभिन्न जन प्रतिनिधियों/संस्थाओं द्वारा मांग की जाती रही है? यदि हां, तो कब-कब व किस-किसके द्वारा ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या सरकार उक्त जिले के सांभर को जिला बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राजस्व मंत्री (श्री हरीश चौधरी): (1) जी हां। समिति का गठन आदेश दिनांक 20.01.2014 के द्वारा किया गया था समिति के सदस्यों के विवरण से संबंधित आदेश के प्रति परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) जी हां। उक्त समिति द्वारा रिपोर्ट वर्ष 2018 में राज्य सरकार को प्रस्तुत कर दी गई है। जो परीक्षणाधीन है।

(3) जी हां। पत्रों की प्रतियां परिशिष्ट "ब" पर संलग्न हैं।

(4) जी हां, विवरण मय सूची परिशिष्ट "स" पर संलग्न है।

(5) उच्च स्तरीय समिति द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट राज्य स्तर पर परीक्षणाधीन है। प्रशासनिक आवश्यकता एवं वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर यथोचित निर्णय लिया जायेगा।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से दो तीन स्पेसिफिक क्वेश्चन जानना चाहूंगा। जिस प्रकार आपने पूरा बताया कि 2014 की जो कमेटी गठित हुई। उसकी रिपोर्ट सरकार को मिल गई और उसका आप परीक्षण कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि कांग्रेस पार्टी बहुत संवेदनशील है और 2008 का भी घोषणा पत्र है। जिसे इस सदन में सरकार ने विजन डाक्यूमेंट के रूप में मान्यता दी थी और इस पर बहुत लम्बी डिबेट 2008 में भी हुई थी। 2013 का भी कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र है। दोनों में आपने स्पैस्फिक किया है कि हम छोटे और नये जिले सरकार गम्भीरता से उन पर विचार करेगी, नई तहसीलें भी बनाएगी और बहुत जल्दी उस पर कदम उठाएंगे।

(श्री निर्मल कुमावत)

मैं आपसे इतना जानना चाहूंगा कि जो रिपोर्ट समिति ने पेश की क्या सरकार उसको मानेगी या दुबारा कमेटी बनाएंगे या दुबारा परीक्षण करेंगे। अगर करेंगे तो कब तक करेंगे। नये जिले के गठन के लिए सांभर पात्र है या नहीं? आपकी रिपोर्ट में उसका भी आप जवाब दें और नहीं है, तो सांभर को जिला बनाना चाहते हैं या नहीं बनाना चाहते हैं? मैं इतना ही जानना चाहता हूं।

श्री हरीश चौधरी (राजस्व मंत्री): अध्यक्ष महोदय, आपकी मार्फत से मैं माननीय सदस्य को धन्यवाद देना चाहता हूं कि पूरी दुनिया जो कह रही है उसकी ताईद माननीय सदस्य कर रहे हैं कि कांग्रेस सरकार संवेदनशील है, उसके लिए तो आपको धन्यवाद। आपने जो प्रश्न किया है कि जो रिपोर्ट पिछली सरकार ने दी है उसके सन्दर्भ में मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि पिछली सरकार ने जो रिपोर्ट दी है अभी मंत्रालय में मुझे मिली है। आने वाले समय में उस पर विचार करके जो भी न्यायोचित निर्णय होगा, वह करेंगे। जहां तक सांभर का सवाल है, सांभर जिले को भी उसी श्रेणी में रखेंगे जैसे दूसरे जिले का प्रस्ताव आया हुआ है और जो भी न्यायोचित निर्णय होगा वह करेंगे। मैं आपको यह विश्वास दिलाना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: श्री मदन प्रजापत।

श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा): अध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा पूरक प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष: एक मिनट। बैठिये, एक मिनट।

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न भी इसी से संबंधित है। बालोतरा प्रायोरिटी में है और सालों से मांग है कि बालोतरा जिला बने। मेरा आपके माध्यम से मंत्रीजी से निवेदन है कि गत 2008 और 2013 के बीच में कमेटी बनी और भारतीय जनता पार्टी ने उसको जिला बनाने की बात को ठंडे बस्ते में डाल दिया। मैं आशा करता हूं कि जब भी जिले बने तो बालोतरा को पहली प्रायोरिटी में जिला बनायें और हमें विश्वास है कि कांग्रेस सरकार बालोतरा को जिला बनाएगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी से मैं मांग करता हूं।

श्री अध्यक्ष: श्री पब्बाराम जी।

श्री पब्बाराम (फलौदी): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं कि 1956 में राजस्थान का एकीकरण

(श्री पब्बाराम)

हुआ और अंत में केन्द्र प्रशासित जिला अजमेर राजस्थान में एकीकृत हुआ। उसके बाद में कितने जिले बने और कांग्रेस कार्यकाल में आपने कितने जिले बना दिये और भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में कितने जिले बन गये? जिले बनाने की और पिछली सरकार के बारे में आप बात करते हैं 7 जिले बनाये हैं और सातों के सातों भारतीय जनता पार्टी ने बनाये हैं।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्रश्न पूछें। श्री हमीर सिंह जी।

श्री पब्बाराम (फलौदी): इसलिए मुझे यह बताने का श्रम करें आप कि आपने कितने जिले बना दिये 1956 के बाद में? यह बता दीजिये आप।

श्री अध्यक्ष: श्री हमीर सिंह जी।

श्री हमीर सिंह भायल (सिवाना): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत आदरणीय मंत्रीजी को निवेदन करूंगा कि बाड़मेर की अगर पूरे राजस्थान में स्थिति देखें तो भू-भाग में किलोमीटर के दायरे में सबसे बड़ा है। बालोतरा जोधपुर डिवीजन में सबसे पहले सेशन कोर्ट होना और बालोतरा जिला बनना अति आवश्यक है। मंत्रीजी भी हमारे जिले से पधारते हैं। मंत्रीजी, राजस्व मंत्री हमेशा बाड़मेर जिले के रहे हैं। आदरणीय गंगाराम जी, आदरणीय हेमाराम जी, आदरणीय अमराराम जी...।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्रश्न पूछें।

श्री हमीर सिंह भायल (सिवाना): मेरा प्रश्न यही है कि बालोतरा को जिला बनाने के लिए जो पूर्व में समिति की रिपोर्ट में सिफारिश है और राजस्थान में सबसे ज्यादा अगर जिले की आवश्यकता है तो पूरे राजस्थान में भू-भाग को देखें तो बाड़मेर में बालोतरा की है।

श्री अध्यक्ष: श्री शंकर सिंह रावत।

श्री हमीर सिंह भायल (सिवाना): मैं आपके माध्यम से चाहूंगा कि मंत्रीजी आज ही घोषणा करें जिले की और हमारे जिले के ही मंत्री हैं। धन्यवाद।

श्री शंकर सिंह रावत (ब्यावर): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने जिले की मांग पर मुझे बोलने का मौका दिया इसलिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस के चुनाव घोषणा पत्र के पृष्ठ संख्या-36 के पैरा-14 में स्पष्ट लिखा है कि नये जिले बनाने के लिए हमारी सरकार निश्चित विचार करेगी तो मेरा निवेदन है कि आज प्रश्न काल का पहला ही दिन है और

(श्री शंकर सिंह रावत)

माननीय मुख्य मंत्रीजी विराज रहे हैं और सरकार की रिपोर्ट भी आ चुकी है और राजस्थान में पहले भी रिपोर्ट्स में ब्यावर जिले के लिए हमेशा मांग हुई है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्रश्न पूछें।

श्री शंकर सिंह रावत (ब्यावर): मेरा निवेदन है कि जो आपकी रिपोर्ट है, माननीय मंत्रीजी जवाब देंगे कि उस रिपोर्ट में ब्यावर का नाम है या नहीं है? और है तो क्या उसको जिला बनायेंगे?

श्री अध्यक्ष: मंत्रीजी।

श्री हरीश चौधरी (राजस्व मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मदन प्रजापत जी ने बालोतरा को जिला बनाने की बात और मांग रखी है। पब्बाराम जी ने इतिहास पूछा है। इतिहास तो मेरे हिसाब से पब्बाराम जी शिक्षक हैं तो अपने-आप ही उन्हें पता होगा कि कितने जिले कब बने हैं और ब्यावर से आने वाले माननीय सदस्य ने ब्यावर की मांग रखी। मैं तो आपके माध्यम से सदन को यह बताना चाहता हूं कि जो कांग्रेस ने घोषणा पत्र के मार्फत बात रखी कि नये जिले बनाने के लिए वह कार्यवाही करेगी। आने वाले समय में यह रिपोर्ट जो आयी है उसका अध्ययन करके जो विचारणीय है, इसके आधार पर राजस्थान के अन्दर नये जिले बनाने के लिए जल्दी से जल्दी जो भी न्यायोचित होगा वित्तीय स्तर पर और प्रशासनिक स्तर पर उस आधार पर निर्णय करेंगे।

श्री अध्यक्ष: श्री गुलाब चन्द जी कटारिया।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, मैं इसी प्रश्न में सप्लीमेंट्री पूछना चाह रहा हूं कि 1952 से लेकर के अब तक नये जिले कब-कब बने, उनका नाम और उनका समय, इतना सा बता दें?

श्री हरीश चौधरी (राजस्व मंत्री): माननीय नेता, प्रतिपक्ष, यह बात इस प्रश्न में नहीं थी। इस प्रश्न से बाहर आपने यह बात की है। मैं जल्दी ही स्वयं आपके पास आकर इसका विवरण आपको प्रस्तुत कर दूंगा। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न श्री गुलाब चन्द जी कटारिया

प्रदेश में शिक्षकों के रिक्त पद

4. **श्री गुलाब चन्द कटारिया** (नेता, प्रतिपक्ष): क्या शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में जनवरी, 2014 से नवम्बर, 2018 तक कितने

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

अध्यापकों की वेतन श्रृंखला अनुसार भर्ती हेतु विज्ञप्ति जारी की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उपरोक्त में से कौन-कौनसी भर्ती पूर्ण होकर अध्यापकों को नियुक्ति दे दी गई है तथा कितने पदों एवं वेतन श्रृंखला में न्यायालयों के स्थगन या अन्य कारणों से भर्ती पूर्ण नहीं हो सकी है? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) 01 जनवरी, 2019 तक विभिन्न वेतन श्रृंखला के शिक्षकों के कितने पद रिक्त है? वेतन श्रृंखला अनुसार रिक्त पदों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, शिक्षा (श्री गोविन्द सिंह डोटासरा): (1) प्रारम्भिक शिक्षा विभाग द्वारा जनवरी 2014 से नवम्बर 2018 तक निम्नानुसार तृतीय श्रेणी वेतन श्रृंखला पद हेतु विज्ञप्तियां जारी की गई हैं:-

1. विभाग द्वारा राजस्थान प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सीधी भर्ती 2016 अन्तर्गत लेवल-1 एवं लेवल-2 हेतु 15306 पदों पर सीधी भर्ती हेतु विज्ञप्ति जारी कर भर्ती प्रक्रिया प्रारम्भ की जिसका विवरण परिशिष्ट 'क' पर संलग्न है।
2. विभाग द्वारा राजस्थान प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सीधी भर्ती 2018 अन्तर्गत लेवल-1 एवं लेवल-2 हेतु 54000 पदों पर सीधी भर्ती हेतु विज्ञप्ति जारी कर भर्ती प्रक्रिया प्रारम्भ की जिसका विवरण परिशिष्ट 'ख' पर संलग्न है।
3. माध्यमिक शिक्षा विभाग अन्तर्गत जनवरी 2014 से नवम्बर 2018 तक अध्यापको की भर्ती हेतु विज्ञापित पदों का वेतन श्रृंखला अनुसार विवरण परिशिष्ट 'ग' पर संलग्न है।

(2) प्रारम्भिक शिक्षा विभाग द्वारा जनवरी 2014 से नवम्बर 2018 तक की गई भर्तियों में से पूर्ण या पूर्ण नहीं हो सकी भर्तियों का विवरण निम्नानुसार है:-

1. विभाग द्वारा राजस्थान प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सीधी भर्ती 2016 अन्तर्गत लेवल-1 एवं लेवल-2 हेतु 15306 पदों पर की गई सीधी भर्ती की प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है।
2. विभाग द्वारा राजस्थान प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सीधी भर्ती 2018 अन्तर्गत अध्यापक लेवल-2 के चयनित 27672 अभ्यर्थियों में से 20560 अभ्यर्थियों द्वारा कार्यग्रहण किया

(राज्य मंत्री, शिक्षा)

जा चुका है। शेष पदों पर चयन रीशफल/प्रतीक्षा सूची जारी करने के संबंध में कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

3. विभाग द्वारा राजस्थान प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सीधी भर्ती 2018 अन्तर्गत अध्यापक लेवल-1 के विज्ञापित पदों के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय जयपुर में विचाराधीन डीबी अपील संख्या 1322/2018 महेन्द्र कुमार जाटोलिया व अन्य बनाम राज्य सरकार में पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 23.10.2018 से नियुक्तियां दिये जाने पर रोक लगाई हुई है। उक्त याचिका में मुख्यत: अध्यापक लेवल-1 पर चयन के आधार को चुनौती दी हुई है इस कारण लेवल-1 के 26000 पदों पर नियुक्तियां नहीं दी गई है।
4. माध्यमिक शिक्षा विभाग अन्तर्गत विज्ञापित पदों में से की गई भर्ती एवं शेष भर्तियों का वर्तमान स्थिति का विवरण परिशिष्ट 'ग' में सम्मिलित है। तथा शेष भर्तियों पर माननीय न्यायालय का स्थगन नहीं है।

(3) शिक्षा विभाग अन्तर्गत दिनांक 01 जनवरी, 2019 को शिक्षकों के रिक्त पदों का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.स.	पदनाम	वेतन श्रृंखला	रिक्त पद
1.	प्रधानाचार्य	एल-16	1682
2.	प्रधानाध्यापक	एल-14	1158
3.	व्याख्याता	एल-12	9912
4.	शारीरिक शिक्षक ग्रेड-I	एल-12	224
5.	वरिष्ठ अध्यापक	एल-11	13990
6.	शारीरिक शिक्षक ग्रेड-II	एल-11	496
7.	शारीरिक शिक्षक ग्रेड-III	एल-10	5056
8.	तृतीय श्रेणी अध्यापक लेवल-I	एल-10	11906
9.	तृतीय श्रेणी अध्यापक लेवल-II	एल-10	13940
कुल योग			**58324**

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने परिशिष्ट 'क', 'ख' और 'ग' ये तीन दिये हैं उनमें 'क' में यह

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

है कि जो आपने विज्ञप्ति जारी की 15306 की उसमें से आपने 15100 दे दी पूरी भर्ती हो गई। 'ख' में भी जो 54,000 की आपने भर्ती निकाली थी उसमें से आपने 52,000 की भर्ती कर दी और तीसरी 'ग' में आपने दिया है उसमें 42,577 की भर्ती निकाली उसके अगेन्स्ट में 22,935 की भर्ती कर ली बाकी शेष है।

मैं जानना यह चाह रहा हूं कि 2014 में जब हमने यह कार्य ग्रहण किया था तब टोटल शिक्षकों के पदों की तुलना में रिक्त पद कितने थे और आज लगभग एक लाख भर्ती कर देने के बाद अब हमारी रिक्तता का प्रतिशत क्या है? अभी जो आपने बताया कि 58 हजार पद आज की तारीख में राजस्थान में रिक्त हैं, तो टोटल अध्यापकों की संख्या की तुलना में यह जो 58 हजार पद खाली हैं वह कितने प्रतिशत रिक्त हैं? मैं जानना यह चाहता हूं कि 2014 में शिक्षकों के कुल कितने प्रतिशत पद खाली थे? हमारे कार्यकाल में जो हमने एक लाख भर्ती की, उसकी कितनी पूर्ति हो गई और आज की तारीख में जो आप 58 हजार की भर्ती शेष बता रहे हैं, यह परसंटेज के हिसाब से क्या है और यह जो रिक्त पद हैं, इनको आप कब भर देंगे?

इसी के साथ दूसरा प्रश्न और पूछ लेता हूं, इसमें सैकण्डरी में कोई कोर्ट से रोक नहीं है, लेकिन भर्ती प्रक्रिया में है। इसमें यह जो 5 हजार व्याख्याता के पद हैं, लोकसेवा आयोग द्वारा विज्ञापित पदों की परीक्षा का आयोजन किया जाना शेष है, वह कब तक करेंगे, 5000 पद तो यही हैं। इसी तरह से अधीनस्थ बोर्ड के पास भी 4500 पद हैं, इनका भी अभी परिणाम आना बाकी है, परीक्षा हो चुकी है। इसी तरह से 9 हजार पद सैकिण्ड ग्रेड के हैं, इनकी लोकसेवा आयोग द्वारा परीक्षा आयोजित की जा चुकी है, परिणाम आना बाकी है। यह जो लगभग 13 हजार के परिणाम आना बाकी हैं, यह कब तक आ जायेंगे और इनको नियुक्ति कब तक दे दी जायेगी, इन दोनों प्रश्नों का उत्तर दे दीजिए।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (राज्य मंत्री, शिक्षा): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने यह पूछा है कि ...(व्यवधान) माननीय अध्यक्ष महोदय, लीडर आफ अपोजिशन माननीय कटारिया साहब ने ... (व्यवधान) हम आपको बार-बार कहते थे कि इधर आओगे लेकिन उस वक्त आप मानते नहीं थे इसलिए मेरी वही आदत है। (व्यवधान) आप चिंता मत कीजिए नेता, प्रतिपक्ष हमारे सबके सम्माननीय हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय,

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

मैं इनके जवाब में निवेदन करना चाहता हूं कि माध्यमिक शिक्षा में 40949 रिक्तियां हैं और प्रारम्भिक शिक्षा में 17375 रिक्तियां हैं। यह जो 58324 रिक्तियां हैं लेकिन जो एक्च्युअल में रिक्तियां हैं क्योंकि ग्राउंड पर नहीं आया, जो काउंसिलिंग से मैपिंग हो गई, इसलिए एक्च्युअल जो रिक्तियां हैं वह 82611 हैं। आपने जो परिणाम के बारे में पूछा, यह काम तो आपका था, आपकी सरकार थी लेकिन आपने नहीं किया, हमें करना पड़ेगा और हम करेंगे क्योंकि हम सरकार में हैं। प्रधानाध्यापक जो परिणाम शेष हैं और व्याख्याताओं की भर्ती चूंकि आपने राजनीतिक फायदा लेने के लिये आनन फानन में सैकिण्ड ग्रेड की, आरएएस और व्याख्याता की सारी एक साथ निकाल दी और एक साल तक आप गुर्जर आरक्षण आंदोलन को नहीं निपटा सके, अपने वोट बैंक की राजनीति करते रहे इसलिए आखिरी में 77100 वैकेंसियां आपने निकालीं। (व्यवधान) आपको नेता, प्रतिपक्ष की विद्वता पर भरोसा नहीं है क्या, आप बीच में क्यों बोल रहे हो? आप विराज जाओ, विराज जाओ। (व्यवधान)

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): ...(व्यवधान) लोगों ने आपसे पूछा कि आप इन ज्ञापनों का क्या करते हो? आपने कहा कि इन ज्ञापनों को तकिये के नीचे देकर आराम से सोता हूं। आप क्या भला करोगे?

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (राज्य मंत्री, शिक्षा): आप चिंता मत कीजिए, बैठ जाइए। माननीय अध्यक्ष महोदय, इनकी सरकार को पांच साल का समय मिला था, इन्होंने डेढ़ साल एसबीसी, एमबीसी, गुर्जर आरक्षण आंदोलन, हम यहां चिल्लाते रहे, गुर्जर आंदोलन करते रहे लेकिन अपने राजनीतिक फायदे के लिये इन्होंने कोई काम नहीं किया और आखिरी के साल में आपने 77100 पदों की भर्ती कराई और वह भर्ती भी आप पूरी नहीं कर सके। मैं निवेदन करना चाहता हूं वरिष्ठ अध्यापक की भर्ती के लिये आयोग से अभी प्रस्ताव शेष हैं, उनको जल्दी मंगवाया जायेगा और जो 9 हजार वरिष्ठ अध्यापकों के, शारीरिक शिक्षकों के और माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापकों के परिणाम आना शेष हैं, इनके परिणामों के लिये अधिकारियों को निर्देश दे दिये गये हैं कि वह आरपीएससी से सम्पर्क करें और चयन बोर्ड में जो भर्तियां हैं, उनका परिणाम आना है, उनके लिये वहां से सम्पर्क करें। हमारी सरकार चाहती है, हमारे मुख्य मंत्रीजी ने सबसे पहली मीटिंग में यह कहा था कि हम जल्दी से जल्दी लोक सभा चुनाव से पहले हमारे बेरोजगार

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

बच्चों को नौकरियां दें। इन्होंने अपने राजनीतिक षड्यंत्र के तहत भर्तियां रोकी हैं, इनको हमें जल्दी से जल्दी देना है। आज आपकी वजह से आरएएस के 2016 के लोग बैठे हैं। आज लेवल वन के बच्चे आपकी वजह से बैठे हैं। आपने कभी सुलझाने का काम नहीं किया।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी, प्लीज स्पेसिफिक।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): भाषण दे रहे हैं या जवाब दे रहे हैं। मैंने बहुत स्पेसिफिक प्रश्न आपसे यह पूछा था कि 2014 में जब हमने काम संभाला तब राजस्थान में क्या 50-52 प्रतिशत पद शिक्षकों के रिक्त थे और आज की तारीख में जब आपने यह चार्ज लिया तब राजस्थान कि रिक्तता 58 हजार के लगभग है, इसका मतलब 22 परसेंट है। आपके टाइम में 52 परसेंट रिक्त स्थान थे, हमने आपको 22 परसेंट रिक्त स्थान पर दिया या नहीं दिया, यह स्पष्ट कर दो, बाकी इधर-उधर के भाषण देने से कोई अर्थ नहीं निकलेगा। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): आप सब खड़े हो जाओ तब भी मेरी आवाज को नहीं दबा सकते हो, इस बात को समझ लेना। जितना पूछा, उतना जवाब दे दो। मैंने जो स्पेसिफिक प्रश्न पूछा मैं उसका जवाब चाहता हूं कि 2014 में रिक्तता का प्रतिशत क्या था और आज जब आपको चार्ज मिला तब प्रतिशत में रिक्त पद कितने हैं, वह बता दें।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (राज्य मंत्री, शिक्षा): मैं बिलकुल बता दूंगा, आप चिंता मत कीजिए मैं आपको पूरे बताऊंगा।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, बैठे-बैठे नहीं बोलें प्लीज।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (राज्य मंत्री, शिक्षा): माननीय अध्यक्ष महोदय, नेता, प्रतिपक्ष ने पूछा, इन्होंने जो भर्तियां कीं वह जो कांग्रेस सरकार में हमारी सरकार विज्ञप्ति निकालकर गई थी, अधिकतर भर्तियां वह की हैं आपने, आपने नई भर्तियां की कहां, यह बताइए। 2016 में आपने 15300 पदों की भर्ती की है, एक भर्ती पूरी की है। दूसरी भर्ती आपने 26 हजार और 28 हजार की की। 26 हजार की भर्ती को आपने अटका कर रख दिया, आज की तारीख तक की नहीं। यहां मुख्य मंत्रीजी और आप भाषण देते थे और हम सुनते थे। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय नेता, प्रतिपक्ष को आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि हम कहते थे कि इन बच्चों को

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

भर्तियां दो। कभी थर्ड ग्रेड का सवा लाख का आंकड़ा बता देते थे, कभी 85 हजार का आंकड़ा बताते थे। कालीचरण जी सराफ कभी कोई आंकड़ा बता देते थे और एक भी भर्ती नहीं की ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य। प्रतिपक्ष के नेता खड़े हैं, आप बैठिए प्लीज।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): भाषण नहीं, मैं आपसे सीधा पूछ रहा हूं।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (राज्य मंत्री, शिक्षा): मैं सीधा ही बताऊंगा।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): जब आपने हमको चार्ज दिया तब राजस्थान में शिक्षकों की रिक्तता का प्रतिशत कितना था? जो मैं कह रहा हूं कि 52 परसेंट था, वह सही है या गलत है और उसके बाद आपने मुझे जो फीगर दिया क, ख और ग में उसमें पहली भर्ती हमने 24685 की की और उसके बाद 52367 की ज्वाइनिंग हुई, दोनों मिलाकर 77052 की ज्वाइनिंग हुई। उसके बाद अभी माध्यमिक शिक्षा में 42577 की जो वैकेंसी निकाली जिसके अगेंस्ट में भर्ती चल रही है, उसमें से 22935 ने ज्वाइन कर लिया। ऐसे 99887 लोगों की भर्ती हुई या नहीं हुई, यह बता दो।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (राज्य मंत्री, शिक्षा): माननीय अध्यक्ष महोदय, माध्यमिक शिक्षा में जो यह बात कर रहे हैं विज्ञप्ति निकाली 42577 की, उसकी नियुक्ति दी इन्होंने 22935 । यह विज्ञप्तियां निकालते रहे, खेल करते रहे। (व्यवधान) आप सुनिए, आराम से सुनिए कौन मना कर रहा है, आपको एक-एक चीज बताऊंगा। आपने विज्ञप्ति निकाली 15306, 15140 को नियुक्ति दे दी। आपने लेवल प्रथम 26 हजार की नियुक्तियां निकालीं जो आपने कोर्ट में अटका दीं, बच्चे आज भी घूम रहे हैं। आपने लेवल द्वितीय में 28 हजार नियुक्तियां निकालीं, जिसमें से 20560 नियुक्तियां दे पाये, 7012 हमारे समय में अब प्रक्रियाधीन हैं। माध्यमिक शिक्षा में आपने विज्ञप्तियां निकालीं 42577, उसमें से जरूर आपने 22935 को दी हैं। इसके बाद प्रारम्भिक शिक्षा में 57222 की जो आप बात कर हैं उसमें से 24224 तो कांग्रेस सरकार की भर्तियां थीं, हमारे समय की भर्तियां थीं, आप इसको क्यों जोड़ रहे हैं?

भाजपा द्वारा तो केवल 32 हजार 998 हैं, जिसमें भी वे ग्राउंड पर नहीं ले आये। काउंसलिंग/मैपिंग जरूर हो गयी, लेकिन ग्राउंड पर नहीं ले पाये।

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

इसीलिए असर 2018 ने यह कहा है कि पिछले साल आपकी सरकार रहते हुए प्रारम्भिक शिक्षा की जो गुणवत्ता में कमी आयी है, हम नीचे की ओर आये हैं, माननीय नेता, प्रतिपक्ष महोदय यह इसीलिए हुआ है।

श्री अध्यक्ष: माननीय राठौड़ जी, एक सैकिण्ड।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): जो आपने मुझे दिया है। एक बार आप अपना परिशिष्ट 'ख' निकालिये। इस परिशिष्ट 'ख' में विज्ञप्ति के पद 54 हजार हैं, जो कि विभिन्न ग्रेडों के अलग-अलग हैं। इसमें से 52 हजार 357 की भर्ती हो चुकी है, इसका आपने मुझे परिशिष्ट 'ख' दिया है। क्या यह सही है या फिर आप जो बोल रहे हैं, वह सही है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (राज्य मंत्री, शिक्षा): यह ग्राउंड पर नहीं है।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): हमारी तो बारी ही नहीं आ रही, पांच-पांच पूरक प्रश्न पूछ रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, हम भी हाउस में बैठे हैं।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (राज्य मंत्री, शिक्षा): ये जो रिक्तियों का ब्यौरा निकाला जाता है, उसमें मैपिंग होकर काउंसलिंग हो जाती है तो उन रिक्तियों को फुल मान लिया जाता है, लेकिन जैसा कि मैं कह रहा हूं कि ग्राउंड के ऊपर आपने जो स्थिति पैदा की है, वे 82 हजार 611 रिक्तियां आज भी हैं। इसमें से आप जो एल-1 की 54 हजार बता रहे हो, वे पूरी की पूरी कोर्ट में पड़ी हैं और आपने आखिरी साल इसीलिए निकाला कि हमें राजनीतिक फायदा लेना है। इन बेरोजगारों को रोजगार नहीं देना है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से महाराणा प्रताप जैसे महान शिक्षा मंत्रीजी से जानना चाहूंगा। शिक्षा मंत्रीजी, आपने अपने उत्तर में कहा कि 82 हजार 661 रिक्तियां हैं और आपने अपने श्रीमुख से यह भी फर्माया कि इन रिक्तियों के पीछे महज राजनीतिक कारण रहा और ये अलग-अलग न्यायालयों में गुर्जर और एसबीसी के आरक्षण को नहीं देने के कारण रुकी। मेरा स्पेसिफिक प्रश्न है कि क्या सरकार 82 हजार 611 रिक्तियों को गुर्जर आरक्षण देकर भरना चाहता है? हां, या ना?

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (राज्य मंत्री, शिक्षा): देखिए मैंने दोनों बातें कही हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): दोनों बात नहीं, सीधी बात।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (राज्य मंत्री, शिक्षा): आप सुनने का माद्दा रखो। हमने आपको बहुत सुना है।

श्री अध्यक्ष: बैठे-बैठे ना बोलें, प्लीज।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (राज्य मंत्री, शिक्षा): ग्राउंड के ऊपर आज की तारीख में 82 हजार 611 कार्यरत नहीं हैं। रिक्तियां कम इसीलिए बतायी गयी हैं, क्योंकि जो स्टेटमेंट होता है, उसमें काउंसलिंग से जो मैपिंग होती है तो वह पद भरा हुआ मान लिया जाता है। चूंकि उनकी नियुक्ति प्रक्रिया में हाइ कोर्ट द्वारा रोक लगा दी गयी है, इसलिए वे लोग ग्राउंड पर नहीं गये। इसलिए जो अंतर आप बता रहे हो न, वह अंतर आ रहा है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): एस.बी.सी. को आरक्षण दोगे क्या? एस.बी.सी. के आरक्षण से भरोगे या नहीं भरोगे, यह बताओ न।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): अध्यक्ष महोदय...

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, अभी आप ही कह रहे थे कि सप्लीमेंट्री ज्यादा हो रही है।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी कृपा सिर्फ इधर बरस रही है।

श्री अध्यक्ष: आप विराजें। अगला प्रश्न माननीय अमीन खां जी।

बाड़मेर जिले में नवीन महाविद्यालयों की स्थापना

5. **श्री अमीन खां** (शिव): क्या उच्च शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

सरकार जिला बाड़मेर के पिछड़े इलाकों में महाविद्यालय खोलने का विचार रखती है यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा (श्री भंवर सिंह भाटी): संसाधनों की उपलब्धता एवं गुणावगुण के आधार पर जिला बाड़मेर के पिछड़े इलाकों में नवीन राजकीय महाविद्यालय खोले जाने पर विचार किया जाएगा।

वर्तमान में जिला बाड़मेर में राजकीय क्षेत्र में 09 राजकीय महाविद्यालय व निजी क्षेत्र में 36 निजी महाविद्यालय संचालित हैं।

श्री अमीन खां (शिव): अध्यक्ष महोदय, मेरा लंबा-चौड़ा प्रश्न नहीं है। मंत्रीजी, मैं आपसे छोटा एवं सीधा-सा जवाब चाहता हूं। क्या यह सही है कि बाड़मेर जिले में सीमावर्ती तहसील रामसर और तहसील गडरारोड की लगभग ढाई लाख की जनसंख्या है। शिक्षा के स्तर में राजस्थान में सबसे नीचा स्तर इन सीमावर्ती तहसीलों का है। इन तहसीलों की 85 परसेंट आबादी रिजर्व्ड क्लास में है। यानी 25 परसेंट एस.सी. एवं एस.टी. हैं और 60 परसेंट

(श्री अमीन खां)

ओ.बी.सी. वर्ग है। यहां पर देश की आजादी के 70 साल बाद भी सबको मौका देने के लिये सरकार क्या यहां कालेज खोलने का विचार रखती है या नहीं? गुणावगुण मुझे समझाया जाए कि क्या है?

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): कांग्रेस ने 70 साल आपके साथ अन्याय किया है।

श्री भंवर सिंह भाटी (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा): माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय विधायक महोदय ने बताया कि रामसर उपखण्ड में राजकीय महाविद्यालय संचालित नहीं है, परन्तु तीन निजी महाविद्यालय संचालित हैं। रामसर उपखण्ड से चौहटन उपखण्ड निकटतम उपखण्ड है। रामसर उपखण्ड की चौहटन उपखण्ड से दूरी लगभग 40 किलोमीटर है। रामसर उपखण्ड से शिव की 78 किलोमीटर और बाड़मेर से 63 किलोमीटर है। चौहटन, शिव एवं बाड़मेर उपखण्डों में वर्तमान में राजकीय महाविद्यालय संचालित है। चौहटन उपखण्ड में पांच निजी और एक राजकीय महाविद्यालय है। चौहटन एवं शिव उपखण्ड में महाविद्यालय में सत्र 2018-19 से प्रारम्भ हुए हैं। सरकार संसाधनों की उपलब्धता एवं गुणावगुण के आधार पर बाड़मेर जिले के पिछले इलाकों में और विशेषकर रामसर और गडरारोड उपखण्ड में जो महाविद्यालय खोलने की बात है। अध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि ये सीमावर्ती क्षेत्र हैं और यहां जनसंख्या अधिक है। भौगोलिक दृष्टि से एक गांव की दूसरे गांव से दूरी भी ज्यादा है और एस.सी., एस.टी. और ओ.बी.सी. की जनसंख्या भी यहां ज्यादा है। शिक्षा का इस क्षेत्र में पिछड़ापन है। मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य से निवेदन करना चाहूंगा कि सरकार संसाधनों की उपलब्धता और गुणावगुण के आधार पर बाड़मेर जिले के पिछले इलाकों में आगामी समय में नवीन राजकीय महाविद्यालय खोले जाने का विचार रखती है।

श्री अध्यक्ष: श्री मदन प्रजापत।

प्रदेश में रोजगारपरक शिक्षा की कार्ययोजना

6. **श्री मदन प्रजापत** (पचपदरा): क्या तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में युवाओं को रोजगार परक शिक्षा हेतु क्या कदम उठाये जा रहे हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री मदन प्रजापत)

(2) उक्त शिक्षा हेतु विगत चार वर्षों में प्रत्येक वित्तीय वर्ष एवं चालू वित्तीय वर्ष में आवंटित, व्यय एवं लक्ष्यों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) प्रदेश में बेरोजगारी को मिटाने हेतु युवाओं को रोजगार परक शिक्षा प्रदान करने हेतु सरकार की क्या कार्य योजना है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, तकनीकी शिक्षा (डा. सुभाष गर्ग): (1) तकनीकी शिक्षा विभाग के अधीन संचालित राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा द्वारा युवाओं को रोजगारपरक शिक्षा हेतु पाठ्यक्रमों में नियमित बदलाव किया जाता है। इसी क्रम में सत्र 2017-18 में विश्वविद्यालय द्वारा चोइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम लागू किया गया। छात्रों को राष्ट्रीय/अन्तरराष्ट्रीय संस्थानों में रोजगार के बेहतर अवसर प्राप्त होंगे, क्योंकि अधिकांश संस्थानों में अंकों के स्थान पर क्रेडिट पद्धति प्रचलित है।

राष्ट्रीय स्तर के विभिन्न शिक्षण संस्थानों के साथ विश्वविद्यालय द्वारा एमओयू हस्ताक्षर किये हैं, जिसके परिणामस्वरूप गत वर्षो में छात्रों द्वारा 13 स्टार्टअप प्रारभ किये गये हैं। इसके अतिरिक्त विश्वविद्यालय द्वारा प्रशिक्षण रोजगार हेतु विशेष सैल गठित है जिसके माध्यम से गत 3 वर्षों में 180 प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। 100 छात्रों को सोलिड वर्क्स एण्ड प्रो. की ट्रेनिंग दी गई है, 600 छात्रों को आटो कैड की साफ्टवेयर की ट्रेनिंग दी गई, इन कार्यक्रमों को निरन्तर जारी रखने हेतु वर्ष 2018-19 के बजट में विश्वविद्यालय द्वारा एक करोड़ रुपये का वित्तीय प्रावधान किया गया है।

तकनीकी शिक्षा निदेशालय, जोधपुर द्वारा प्रदेश में युवाओं को रोजगार परक शिक्षा हेतु 19 इंजीनियरिंग शाखाओं तथा 06 नान इंजीनियरिंग शाखाओं में डिप्लोमा प्रदान किया जा रहा है।

राजकीय पालिटेक्निक महाविद्यालय जोधपुर में पैट्रोलियम इंजीनियरिंग मे 3 वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम प्रारम्भ किया जाना प्रस्तावित है।

इसके अतिरिक्त सामुदायिक पोलिटेक्निक योजना के अन्तर्गत युवाओं हेतु 3/6 माह के लघु अवधि प्रशिक्षण आयोजित किये जाते हैं जिन्हें सफलतापूर्वक पूर्ण कर युवा स्वयं का रोजगार प्रारम्भ कर सकते हैं। वर्ष 2017 -18 में सामुदायिक पालिटेक्निक योजना के अन्तर्गत 2011 युवाओं को प्रशिक्षण दिया गया।

(राज्य मंत्री, तकनीकी शिक्षा)

प्रदेश में युवाओं को रोजगारपरक शिक्षा हेतु विभिन्न राजकीय एवं प्राइवेट औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आई.टी.आई.) के माध्यम से प्रशिक्षित किया जा रहा है। इनमें इंजीनियरिंग एवं गैर इंजीनियरिंग सेक्टर के विभिन्न व्यवसायों में प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। वर्तमान में राज्य में संचालित 229 राजकीय आई.टी.आई. में 47202 प्रवेश स्थान तथा 1710 प्राइवेट आई.टी.आई. में 312404 प्रवेश स्थान उपलब्ध कराये गये हैं।

माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को आत्मनिर्भर बनाने, शिक्षा में ड्रापआउट रेट कम करने एवं कौशल विकास की क्षमता विकसित करने के उद्देश्य से Vocationalization of Secondary and Higher Secondary Education योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2014-15 से 11 जिलों के 70 विद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा प्रारम्भ की गई है।

उक्त योजना में प्रत्येक विद्यालय में 02 विद्यालयों का संचालन किया जाता है। वर्तमान में राज्य में 905 विद्यालयों में 12 व्यवसायों में लगभग 1 लाख 20 हजार विद्यार्थी लाभान्वित हो रहे हैं।

राज्य के कृषि विश्वविद्यालयों में युवाओं को रोजगारपरक शिक्षा देने हेतु कृषि शिक्षा के अलावा श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय में वर्ष 2016-17 में कृषि व्यवसाय प्रबंधन महाविद्यालय, जोबनेर में आरम्भ किया गया है। इस महाविद्यालय में कृषि स्नातक व कृषि प्रबंध पाठ्यक्रम चलाया जा रहा है। जिसमें वर्तमान में 168 छात्र अध्ययनरत हैं। स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर में वर्ष 2000 से कृषि व्यवसाय प्रबंधन संस्थान में स्नातकोत्तर व विधावाचस्पति स्तर का पाठ्यक्रम संचालित किया जा रहा है जिसमें 96 छात्र अध्ययनरत हैं। उक्त पाठ्यक्रमों का मुख्य उद्देश्य रोजगारपरक शिक्षा व कौशल विकास है।

इसके अतिरिक्त आरएसएलडीसी द्वारा राज्य के शिक्षित युवाओं को रोजगारपरक प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है।

(2) विगत चार वर्षों में प्रत्येक वित्तीय वर्ष एवं चालू वित्तीय वर्ष में आवंटित, व्यय एवं लक्ष्यों का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(3) उद्योगों की आवश्यकता के अनुसार नये पाठ्यक्रम प्रारम्भ किये जाने हेतु भविष्य का प्लान तैयार किया जाना विचाराधीन है।

शिक्षा को और अधिक रोजगारपरक बनाने के लिए सिलेबस में उद्योगों की सलाह से परिवर्तन करवाया जायेगा।

(राज्य मंत्री, तकनीकी शिक्षा)

प्रदेश में रोजगारपरक शिक्षा को बढ़ाने के लिए जिला स्तर पर महिला पोलिटेक्निक महाविद्यालय खोले जाएंगे। पालिटेक्निक महाविद्यालयों में उद्योगों की आवश्यकता के अनुसार पाठ्यक्रम यथा मेकेट्रोनिक्स, आटोमोबाइल (डिजाइन) आदि प्रारम्भ किये जाएंगे। इन सब के लिए कार्य योजना बनायी जाना विचाराधीन है।

प्रदेश से बेरोजगारी को मिटाने हेतु युवाओं को उद्योगों की मांग के अनुसार विभिन्न प्रतिष्ठानों यथा सिस्कों, बाश, केटरपिलर, सैमसंग टोयेटा, एल एण्ड टी, पिडिलाइट, श्नाइडर इत्यादि के सहयोग से आई.टी.आई. में प्रशिक्षण भी प्रदान किया जा रहा है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि हमारे लोकप्रिय मुख्य मंत्री आदरणीय अशोक गहलोत जी ने बाड़मेर जिले के पचपदरा में पूरे अथक प्रयास करके रिफाइनरी की जो सौगात दी, इस संबंध में मेरा निवेदन है कि पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी और युवाओं के लिए अलग से पचपदरा और बाड़मेर जिले में तकनीकी शिक्षा ताकि आने वाले समय में रिफाइनरी में स्थानीय लोगों को रोजगार मिल सके और रिफाइनरी के प्रयास के लिए माननीय मुख्य मंत्रीजी का आभार व्यक्त करता हूं। मंत्रीजी थोड़ा बताना चाहेंगे ?

डा. सुभाष गर्ग (राज्य मंत्री, तकनीकी शिक्षा): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि इस चीज को देखते हुए और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा माननीय मुख्य मंत्रीजी को गत कार्यकाल में रिफाइनरी की घोषणा हुई थी जिसको अमलीजामा पहना दिया गया था। उसके बाद दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि पिछले पांच वर्षों में वह रिफाइनरी शुरू नहीं हो पायी। लेकिन आपके माध्यम से मैं बताना चाहूंगा इसको ध्यान में रखते हुए तीन वर्षीय पेट्रोलियम इंजीनियरिंग का डिप्लोमा जो जोधपुर यूनिवर्सिटी के अधीन एमबीएम कालेज है और पोलोटेक्निक है, उसमें शुरू किया जाना प्रस्तावित है। इसके अलावा विभागीय स्तर पर इस पर विचार किया जा रहा है कि पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाए। इस पर विचार करके जब भी निर्णय होगा बता दिया जाएगा।

प्रश्न संख्या-7

श्री अध्यक्ष: श्री जोराराम कुमावत।

(अनुपस्थित: कृपया आगे देखें)

प्रश्न संख्या 8

श्री नरेन्द्र नागर।

(अनुपस्थित: कृपया आगे देखें)

श्रीमती किरण माहेश्वरी। बैठे-बैठे नहीं बोलें, माननीय सदस्य।

राजसमन्द जिले में छात्राओं को साइकिल वितरण योजना

9. **श्रीमती किरण माहेश्वरी** (राजसमन्द): क्या शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) छात्राओं को प्रोत्साहित करने के लिए साइकिल वितरण की योजना के मुख्य प्रावधान क्या हैं?

(2) जिला राजसमंद के किन विद्यालयों में कितनी पात्र छात्राओं को वर्ष 2016-17 व 2017-18 में साइकिल का वितरण नहीं हुआ है? उक्त छात्राओं को कब तक साइकिल वितरित कर दी जाएगी? पात्र छात्राओं की कुल संख्या कितनी है इनमें से कितनी छात्राओं को साइकिल वितरित की गयी है? संख्यावार विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, शिक्षा (श्री गोविन्द सिंह डोटासरा): (1) बजट सत्र 2007-08 में घोषणा की गई कि कक्षा 9 उत्तीर्ण कर 10वीं कक्षा में प्रवेश लेने वाली ऐसी प्रत्येक छात्रा को जिसका घर सबसे नजदीक सैकण्डरी विद्यालय से 2.00 किमी. से अधिक दूरी पर है, को एक नई साइकिल केवल 300/- रुपये में दी जायेगी शेष राशि राज्य सरकार वहन करेगी। साथ ही 5 या इससे अधिक छात्राओं के समूह को आवागमन के लिए ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना की सुविधा दी गई। इसके पश्चात वित्तीय वर्ष 2011-12 में घोषणा के अनुसार कक्षा 9 व 10 में अध्ययनरत छात्राओं को दी जाने वाली साइकिल के अंशदान की राशि 300/- रुपये से घटाकर 100/- रुपये की गई तथा साइकिल के स्थान पर ट्रांसपोर्ट वाउचर का लाभ दिये जाने का विकल्प भी दिया गया। वर्ष 2014-15 में घोषणा की गई कि राजकीय विद्यालयों में कक्षा 9 में प्रवेश लेने वाली छात्राओं को नि:शुल्क साइकिल वितरित किये जाने का प्रावधान किया गया। ग्रामीण क्षेत्र में जो छात्राएं अपने निवास से 05.00 किमी से अधिक की दूरी से

(राज्य मंत्री, शिक्षा)

विद्यालय आती हैं तथा जो साइकिल नहीं लेना चाहती, उन्हें ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना का लाभ दिये जाने का प्रावधान है।

(2) राजसमंद जिले की वर्ष 2016-17 तथा 2017-18 में कक्षा 09 में राजकीय विद्यालयों की कक्षा 09 में प्रवेश लेने वाली साइकिल प्राप्त करने के लिए पात्र छात्राएं, वितरित की गई साइकिलों की संख्या तथा वंचित छात्राओं की संख्या का विवरण निम्न प्रकार है:-

क्र. सं.	**वर्ष**	**कुल पात्र छात्राएं**	**वितरित साइकिलों की संख्या**	**वंचित छात्राओं की संख्या**
1.	2016-17	6729	6565	164
2.	2017-18	6535	6535	00

उक्त वंचित 164 छात्राएं 10 विद्यालयों की सूची परिशिष्ट-क पर संलग्न है। तथा इन छात्राओं ने कक्षा 09 में प्रवेश विलम्ब से लिया था, जिसके प्रस्ताव समय पर प्राप्त नहीं हुएं जिस कारण इन छात्राओं को साइकिल वितरण नहीं की जा सकी।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्रीजी ने जो सदन पटल पर जवाब दिया है, मैं आपके माध्यम से जानना चाहती हूं कि जो पूर्ववर्ती सरकार ने एक बहुत ही अच्छी योजना चलाई थी कि नवीं कक्षा में अध्ययनरत जो छात्राएं हैं, उन्हें नि:शुल्क साइकिल वितरण करने की यह योजना थी। जैसा कि इन्होंनें बताया कि वर्ष 2016-17 में 164 ऐसी बालिकाएं/छात्राएं जिनको साइकिल मिलनी चाहिए थी, लेकिन वह वंचित रह गयीं, ऐसी अपनी राजसमन्द जिले की छात्राएं हैं। इनमें नाथद्वारा विधान सभा क्षेत्र की लगभग 89 गर्ल्स है, कुंभलगढ़ विधान सभा क्षेत्र की 41 हैं और भीम की 34 ऐसी बच्चियां हैं जिनको साइकिल नहीं मिल पायी। आपने जो रीजन बताया यह कहा कि उन्होंने विलम्ब से प्रवेश लिया। लेकिन विलम्ब से प्रवेश लेने के बाद चूंकि आनलाइन सारा देना होता है परन्तु वह आनलाइन नहीं कर परन्तु उन्होंने आफलाइन फार्म भर दिया। वे योग्य हैं, उन्हें साइकिल मिलनी चाहिए और वे बच्चियां पात्रता रखती हैं। लम्बे समय से उन्हें साइकिल नहीं मिल पा रही है। मैं आपके माध्यम से यही प्रश्न पूछना चाहती हूं कि क्या इन 164 बच्चियों को, जो कि पात्र हैं उन्हें साइकिल मिलनी चाहिए? वह वंचित

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

रह गई सिर्फ एक टैक्निकल कारण से कि उन्होंने आफलाइन फार्म भरा और वह क्लीयर नहीं कर पाये। क्या उन 164 बच्चियों को, जो वंचित रह गयीं, उन्हें आप साइकिल देंगे?

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (राज्य मंत्री, शिक्षा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय को बताना चाहता हूं कि .... पूर्व मंत्री, ये आदत धीरे-धीरे पड़ेगी। माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि आपके जिले का मामला था, आपकी सरकार थी और आप हमेशा यहां कहते थे कि हमारी मुख्य मंत्री महोदया बहुत संवेदनशील हैं और 164 बच्चियां साइकिल से वंचित रह गयीं। आप साइकिलों का कलर चैंज करते रहे, आपने ध्यान नहीं दिया आपनी राजनीतिक सोच को पनपाने के लिए लेकिन हमारे माननीय मुख्य मंत्रीजी ने बड़ा स्पष्ट कहा है कि एक भी बच्ची साइकिल से वंचित नहीं रहनी चाहिए हमारे प्रदेश में इसलिए जितनी भी छात्राएं हैं, उनको हम या तो काले कलर की साइकिल या ट्रांसपोर्ट वाउचर देंगे। आपकी तरह नहीं रखेंगे। वंचित नहीं रखेंगे। उन छात्राओं को साइकिल या ट्रांसपोर्ट वाउचर, जो भी सम्भव होगा जरूर देंगे।

श्री अध्यक्ष: धन्यवाद मंत्रीजी।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): सवाल का जवाब नहीं मिला। ये क्या देंगे? कब तक देंगे? उसके बारे में क्लीयर कर दें। इसमें नाथद्वारा विधान सभा क्षेत्र अध्यक्ष जी, आपका स्वयं का भी है। पूरे राजसमंद जिले की 164 छात्राओं को ...

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आपकी भावना के अनुरूप उनको मिल जाएगी। धन्यवाद। डा. राजकुमार

राजकीय महाविद्यालय नवलगढ़ में भवन निर्माण

10. **डा. राजकुमार शर्मा** (नवलगढ़): क्या उच्च शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि नवलगढ़ शहर में राजकीय महाविद्यालय स्वीकृत किया गया था? यदि हां, तो कब? आदेशों की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त महाविद्यालय के भवन निर्माण की स्वीकृति कब जारी की गई? स्वीकृति की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(डा. राजकुमार शर्मा)

(3) क्या उक्त महाविद्यालय में भवन निर्माण व अन्य सभी कार्य पूर्ण कर दिये गये हैं? यदि हां, तो कौन-कौन से कार्य कितनी राशि व्यय कर पूर्ण किये गये और कौन-कौन से कार्य अपूर्ण हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त महाविद्यालय में कौन-कौन से पद स्वीकृत हैं तथा उनमें से कितने पद रिक्त हैं? रिक्त पदों को कब तक भर दिया जाएगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या सरकार उक्त महाविद्यालय में वर्ष 2019 में विज्ञान व वाणिज्य संकाय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा (श्री भंवर सिंह भाटी): (1) जी हां। विधान सभा क्षेत्र नवलगढ़ से नवलगढ़ शहर में राजकीय महाविद्यालय वर्ष 2013-14 में स्वीकृत किया गया था, जिसके आदेश दिनांक 29 अगस्त 2013 की प्रति परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) राजकीय महाविद्यालय, नवलगढ़ के भवन निर्माण हेतु दिनांक 05 सितम्बर, 2014 को राशि रुपये 3.00 करोड़ की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की गई है, जिसकी प्रति परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

राजकीय महाविद्यालय, नवलगढ़ के भवन निर्माण के लिए दिनांक 16 दिसम्बर, 2017 को राज्य सरकार एवं सेवा ज्योति आर.आर. मोरारका चैरिटेबल ट्रस्ट नवलगढ़ के मध्य हुए एम.ओ.यू. के तहत स्वीकृति जारी की गई है, जिसकी प्रति परिशिष्ट-3 पर संलग्न है।

(3) राजकीय महाविद्यालय, नवलगढ़ के भवन निर्माण का कार्य ट्रस्ट के द्वारा एम.ओ.यू. के अन्तर्गत किया जा रहा है तथा भूमि का मिट्टी भराव व बाहरी दीवार का निर्माण कार्य राज्य सरकार के द्वारा पी.डब्ल्यू.डी. विभाग के द्वारा करवाया जा रहा है।

विभिन्न कार्यों की वर्तमान स्थिति निम्न प्रकार है-

1. भवन का ढांचा तैयार किया जा चुका है। लिपाई/प्लास्टर एवं फिनीसिंग का कार्य चल रहा है।
2. मिट्टी भराव का कार्य पी.डब्ल्यू.डी. के द्वारा हो रहा है तथा कार्य अभी शेष है।

(राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा)

3. बाहरी दीवार का कार्य चल रहा है। विवरण परिशिष्ट-5 पर संलग्न है।

(4) राजकीय महाविद्यालय, नवलगढ़ में स्वीकृत एवं रिक्त पदों का विवरण परिशिष्ट-4 पर संलग्न है। रिक्त पदों को स्थानांतरण/पदोन्नति एवं चयनित अभ्यर्थी उपलब्ध होने पर भरा जा सकेगा।

(5) संसाधनों की उपलब्धता एवं गुणावगुण के आधार पर राजकीय महाविद्यालय, नवलगढ़ में विज्ञान व वाणिज्य संकाय खोले जाने पर विचार किया जायेगा।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

(12.00 बजे)

श्री अध्यक्ष: प्रश्नकाल समाप्त हुआ ।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हई है :-

(1) श्री मदन दिलावर, सदस्य की ओर से कोटा शहर के वार्ड नं. 4 व 5 के कुछ भाग को वन विभाग के अधिकार क्षेत्र से बाहर करवाकर वहां के निवासियों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाये जाने के संबंध में।

(2) श्री खुशवीर सिंह, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन के ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल सप्लाई में हो रहे भेदभाव से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(3) श्री चन्द्रभान सिंह आक्या, सदस्य की ओर से ग्राम बिलिया में हिन्दुस्तान जिंक द्वारा ग्रीन बैल्ट की भूमि पर प्रस्तावित फर्टीलाइजर प्लांट को निरस्त कर किसानों को राहत प्रदान करने के संबंध में।

(4) श्री रामलाल शर्मा, सदस्य की ओर से जयपुर जिलें में बढ़ रही आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश न लगाये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(5) श्री गुलाब चन्द कटारिया व पांच अन्य सदस्यों की ओर से राज्य में गुजरात की तर्ज पर गरीब सवर्णों को 10 प्रतिशत आरक्षण दिये जाने के संबंध में।

(श्री अध्यक्ष)

(6) श्री राजेन्द्र राठौड़, सदस्य की ओर से राज्य सरकार द्वारा उनके जन घोषणा पत्र में की गई घोषणा के अनुरूप गुर्जर समाज को पिछड़ा/ अति पिछड़ा आरक्षण नहीं दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

उपरोक्त प्रस्ताव ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाए, अत: इन पर अनुमति देने में असमर्थ हूं।

(7) श्री संयम लोढ़ा, सदस्य की ओर से प्रदेश में सेवा केन्द्रों का नाम पूर्व की भांति राजीव गांधी सेवा केन्द्र किये जाने के संबंध में।

(8) श्री कालीचरण सराफ व संदीप शर्मा, सदस्य की ओर से प्रदेश में स्वाइन फ्लू के कारण हो रही मौतों से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(9) श्री हनुमान बैनिवाल, सदस्य की ओर से नागौर जिला मुख्यालय स्थित कोतवाली के मालखाने से मादक पदार्थ डोडा पोस्त चोरी हो जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(10) श्री बलवान पूनियां, सदस्य की ओर से राज्य में सरकार द्वारा बेरोजगारों को भत्ता नहीं दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

उपरोक्त प्रस्ताव भी ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाए, अत: अनुमति देने में असमर्थ हूं। फिर भी माननीय सदस्य श्री संयम लोढ़ा, श्री कालीचरण सराफ एवं श्री संदीप शर्मा, श्री हनुमान बैनिवाल तथा श्री बलवान पूनियां को उनके प्रस्ताव की विषयवस्तु पर दो-दो मिनट बोलने की अनुमति होगी।

नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं

(1) श्रीमती इन्द्रा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र बामनवास में गौशाला खोले जाने के संबंध में।

(2) श्री जौहरी लाल मीना, सदस्य की ओर से सरस डेयरी अलवर में लम्बे समय से हो रही अनियमितताओं के कारण डेयरी अध्यक्ष एवं दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने के संबंध में।

(3) श्रीमती शकुन्तला रावत, सदस्य की ओर से दीनदयाल उपाध्याय योजना के अन्तर्गत डिमाण्ड नोटिस जमा होने के बावजूद बिजली कनेक्शन नहीं दिये जाने के संबंध में।

(श्री अध्यक्ष)

(4) श्रीमती अनिता भदेल, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र अजमेर दक्षिण में मुख्य मार्गों पर हो रहे स्थाई व अस्थाई अतिक्रमणों को हटवाये जाने के संबंध में।

(5) श्री विट्ठल शंकर अवस्थी, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र भीलवाड़ा के पुर में जिंदल शॉ लिमिटेड द्वारा किये जा रहे विस्फोटों से मकानों में आ रही दरारों से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(6) श्री खुशवीर सिंह, सदस्य की ओर से प्रदेश में किसानों को फसल बीमा के नियमों में शिथिलता प्रदान कर किसानों को लाभ दिलवाये जाने के संबंध में।

(7) श्री हरीश चन्द्र मीना, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र देवली उनियारा में बीसलपुर परियोजना से पेयजल उपलब्ध करवाये जाने के संबंध में।

(8) श्री रामनारायण मीना, सदस्य की ओर से सवाई माधोपुर से खातोली बारां मुख्य मार्ग के झरेर नामक स्थान पर पुरानी पुलिया के स्थान पर नवीन पुलिया का निर्माण किये जाने के संबंध में।

(9) श्री रामलाल शर्मा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र चौमूं की ग्राम पंचायत सामोद स्थित राजोला बांध का पुनर्निर्माण किये जाने के संबंध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गयी सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी।

पर्ची

आज दिनांक 21 जनवरी, 2019 को शून्यकाल में बोलने हेतु 17 पर्चियां प्राप्त हुईं, जिनमें शलाका द्वारा 4 पर्चियां निकाली गईं, जो निम्नानुसार हैं:-

(1) श्री फूलसिंह मीणा, यू.आई.टी. उदयपुर ग्रामीण के पेरीफेरी एरिया के गांवों में पेयजल उपलब्ध करवाने के संबंध में।

(2) श्री बलजीत यादव, रोजगार पर चर्चा किये जाने के संबंध में।

(3) श्री सुरेश टाक, नगर परिषद किशनगढ़ में बकाया प्रकरणों का निस्तारण किये जाने के संबंध में।

(श्री अध्यक्ष)

(4) श्री मदन प्रजापत, बालोतरा स्थित राजकीय महाविद्यालयों में रिक्त पदों से विद्यार्थियों को हो रही परेशानी के संबंध में।

स्थगन प्रस्ताव श्री संयम लोढ़ा।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

प्रदेश में सेवा केन्द्रों का नामकरण

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय अध्यक्ष महोदय, आज जिस विषय पर मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान आकर्षित कर रहा हूं उसके लिए मुझे 35 साल पुरानी उस दर्दनाक घटना की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना पड़ेगा कि 31 अक्टूबर, 1984 का वह भयानक दिन जब देश की एकता के लिए प्रयास करते हुए उसी की प्रतिक्रिया में देश की महान नेता स्वर्गीय इंदिरा गांधी को गोलियों से छलनी कर दिया गया। एक ऐसा नौजवान नेता जिसकी मां की लाश जिसके हाथों में थी, आंखों में आंसू थे, उन कठिन परिस्थितियों में अपनी पार्टी के सारे सांसदों की भावनाओं का सम्मान करते हुए नौजवान नेता राजीव गांधी ने देश का नेतृत्व करना स्वीकार किया, उसके बाद उन्हीं के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने 1984 का चुनाव लड़ा और करोड़ देशवासियों ने उनके नेतृत्व में विश्वास व्यक्त करते हुए कांग्रेस पार्टी को ऐतिहासिक बहुमत के साथ सत्तासीन किया।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि मैं उस समय भारतीय छात्र संगठन का कार्यकर्ता था और राजीव गांधी की यह सोच थी कि देश के नौजवानों का हित हो, राजनीतिक पार्टियां देश के नौजवानों के हित में काम करें, उनके हित में योजना बनाएं। उन्होंने एक सोच दिया कि 18 वर्ष के नौजवान को मताधिकार दिया जाए। कांग्रेस के उस वक्त के जितने भी खाटी नेता थे उन्होंने राजीव जी से यह कहा कि आप इन नौजवानों को मताधिकार मत दीजिए, यह क्या फैसला करेंगे इनका कोई पता नहीं है, लेकिन वह देश को बदलना चाहते थे, देश के हालात को बदलना चाहते थे, देश की नौजवान शक्ति को राष्ट्रहित में उनके पूरे सामर्थ्य को काम में लेना चाहते थे। उन्होंने 18 वर्ष के नौजवानों को मताधिकार दिया। मैं आपका ध्यान पंजाब की तरफ आकर्षित करना चाहूंगा, पंजाब जल रहा था, आतंकवाद के साये में था, पूरा देश इस बात से चिंतित था कि कहीं देश खड़ित नहीं हो जाए, देश कहीं टूट नहीं जाए। लेकिन उस महबूब नेता ने देश

(श्री संयम लोढा)

हित की परवाह की, अपनी पार्टी के हित की परवाह नहीं की और लोंगोवाल जी के साथ पंजाब समझौता किया। कांग्रेस पार्टी को चुनाव में पराजित होना पड़ा, उन्होंने वह भी स्वीकार किया लेकिन देश हित के अंदर आज यदि पंजाब भारत का एक अटूट हिस्सा बनकर खड़ा हुआ है तो वह स्वर्गीय राजीव गांधी की महान सोच थी जिन्होंने अपने पार्टी के हितों की परवाह नहीं की और देश के हित की परवाह की।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि असम जल रहा था, असम गण परिषद नेतृत्व के अंदर एक भयानक आंदोलन प्रदेश में चल रहा था उस वक्त भी राजीव गांधी जी ने अपना दूरगामी सोच दिखाया और प्रफुल्ल कुमार महंत और उनके साथियों के साथ समझौता किया। कांग्रेस पार्टी को चुनाव में पराजित होना पड़ा लेकिन राजीव जी ने देश को महत्व दिया, देश की एकता को महत्व दिया और असम समझौता किया। असम आज देश का अटूट हिस्सा बनकर भारत के साथ खड़ा है। इसी तरीके से मिजोरम हो, नागालैण्ड हो, राजीव जी ने कभी पार्टी हित की परवाह नहीं की, उन्होंने हमेशा यह लक्ष्य ध्यान रखा कि देश को एकजुट कैसे रखा जाए, अटूट कैसे रखा जाए, मजबूत कैसे रखा जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर उनके एक-एक फैसले पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करूं तो समय कम पड़ेगा। आज का जो भारत हम देखते हैं, आज की संचार क्रांति देखते हैं, आज का डिजिटल इंडिया का सपना देखते हैं यह स्वर्गीय राजीव गांधी जी की देन है। वो ही थे .... (व्यवधान) जम्मू कश्मीर को तो आप बर्बाद कर रहे हो, आपका प्रधान मंत्री +++ बर्बाद कर रहा है, +++ बर्बाद कर रहा है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य ....(व्यवधान)

श्री सुमित गोदारा (लूणकरणसर): जम्मू कश्मीर में उग्रवाद 87 में राजीव गांधी और फारूख अब्दुल्ला ....(व्यवधान) उग्रवाद की देन, +++ की वजह से उग्रवाद हुआ....(व्यवधान) जम्मू कश्मीर में उग्रवाद हुआ +++ की वजह से हुआ। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, ...(व्यवधान) सीनियर हो। वरिष्ठ मैम्बर हो आप। आप बैठें कृपया।

श्री सुमित गोदारा (लूणकरणसर): जम्मू कश्मीर में चुनाव रद्द हुए उसकी वजह से जम्मू कश्मीर में उग्रवाद पैदा हुआ।

श्री अध्यक्ष: कृपया आप बैठें। (व्यवधान)

श्री सुमित गोदारा (लूणकरणसर): +++ की देन है जम्मू कश्मीर में उग्रवाद। (व्यवधान)

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): आप उनकी पार्टी से जीतकर ....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, बीच में बोलने की आदत नहीं डालें, नहीं तो मुझे अनप्लीजेंट निर्णय लेना पड़ेगा, फिर निवेदन कर रहा हूं आप मेहरबानी करके बीच में टोकोटोकी नहीं करें। माननीय सदस्य, चेयर को देखकर बोलें। प्लीज वाइंडअप।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय अध्यक्ष महोदय, सत्य बहुत कड़वा होता है। लेकिन सत्य तो सत्य होता है। आज पूरा देश देख रहा है, पूरी दुनिया देख रही है कि विदेश नीति के स्तर पर और सामरिक सुरक्षा के स्तर पर जिनकी ये वकालत कर रहे हैं, वह सरकार कितनी बुरी तरह से विफल साबित हुई है। लेकिन मेरा आज का विषय यह नहीं है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, उसी संचार क्रांति के जनक दूरदृष्टा राजीव गांधीजी की स्मृति को बनाये रखने के लिये जब आप भारत सरकार में मंत्री होते थे, डाक्टर मनमोहन सिंह की सरकार के वक्त पूरे देश की हर ग्राम पंचायत में सेवा केन्द्र खोलने का निर्णय किया गया। यह राजीव गांधी का सपना था कि हर गांव इंटरनेट से जुड़े, हर गांव, ग्रामीण स्तर तक रेल का टिकट आदमी को वहीं मिले, बस का टिकट वहीं मिले, बिल वहीं भरा जाये। उस सोच के नतीजे के रूप में भारत सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी किया, मनरेगा में इन सेवा केन्द्रों का नाम स्वर्गीय राजीव गांधी के नाम पर होगा। पूरे देश में स्वर्गीय राजीव गांधी के नाम पर सेवा केन्द्र चल रहे हैं। वह नोटिफिकेशन जो भारत सरकार ने 2009 में जारी किया, आज भी स्टैण्ड कर रहा है। आज भी कायम है। न तो उस नोटिफिकेशन को विदड्रा किया गया, न उस नोटिफिकेशन को निरस्त किया गया। लेकिन अचानक, पूरे हिन्दुस्तान के अन्दर एकमात्र राज्य राजस्थान ऐसा निकला कि जहां की मुख्य मंत्री को रातों-रात यह सपना आया कि राजीव गांधी की स्मृति को नष्ट कैसे किया जाये। अपने एक प्रशासनिक आदेश से एक कागज पर लिख करके प्रिंसिपल सैक्रेटरी रूरल डवलपमेंट को लिख करके भेज दिया कि इसका नाम बदल अटल सेवा केन्द्र किया जाये। लॉ कायम है, नोटिफिकेशन स्टैण्ड कर रहा है। भारत सरकार के नोटिफिकेशन को निरस्त किये बिना कोई सरकार यह नाम नहीं बदल सकती थी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने तत्कालीन मुख्य मंत्री, तत्कालीन मंत्री, सबके पास जा करके फरियाद की कि हमारे महबूब नेता की स्मृति के

(श्री संयम लोढ़ा)

साथ यह खिलवाड़ मत करो। पूरे देश के अन्दर राजीव गांधी सेवा केन्द्र नाम चल रहा है। राजस्थान के अन्दर ऐसा क्या है, आपकी क्या नाराजगी है, क्या कष्ट है कि आपने वह नाम निरस्त कर दिया।

श्री अध्यक्ष: प्लीज वाइण्डअप करें।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय अध्यक्ष महोदय, जब राजस्थान सरकार ने हमारी नहीं सुनी, हम हाई कोर्ट में गये। हाई कोर्ट में हमने पिटीशन दाखिल की। हम सिंगल बैंच में गये। सिंगल बैंच ने कहा पी.आई.एल. में है आप डबल बैंच में जाइये। हम डबल बैंच में गये। डबल बैंच ने कहा कि नहीं, पी.आई.एल. नहीं है, इसमें लॉ-पाइण्ट है। आप सिंगल बैंच में जाइये। हम सिंगल बैंच में गये। माननीय न्यायाधीश ने फिर कहा कि नये आ गये, उन्होंने कहा, नहीं आप डबल बैंच में जाइये। हम फिर डबल बैंच में गये। फिर डबल बैंच ने हमको कहा, नहीं, इसमें लॉ-पाइण्ट है। क्योंकि नोटिफिकेशन स्टैण्ड कर रहा है और एडमिनिस्ट्रेटिव आर्डर से नोटिफिकेशन खतम नहीं किया जा सकता। हम फिर सिंगल बैंच में गये।

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय न्यायाधीश ने अपना निर्णय दिया कि जो राजस्थान की मुख्य मंत्री के निर्देश पर प्रिंसिपल सैक्रेटरी, आर.डी. ने एक प्रशासनिक आदेश से अटल सेवा केन्द्र नाम किया है, उसको निरस्त किया जाता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, गवर्नमेंट आफ इंडिया का नोटिफिकेशन कायम है। पूरे देश में सेवा केन्द्रों का नाम राजीव गांधी केन्द्र चल रहा है। सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव आर्डर से नोटिफिकेशन को खतम नहीं किया जा सकता। इसके लिये माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जब शपथ ली, मेरी इच्छा थी कि माननीय मुख्य मंत्रीजी के हाथ से पहला आदेश वही निकले, इन सेवा केन्द्रों का नाम फिर से राजीव गांधी केन्द्र किया जाता है। इनके पी.ए. सूर्यप्रकाश को मैं स्वयं जा करके अपनी ओर से रिप्रजेंटेशन दे करके आया।

माननीय अध्यक्ष महोदय, उसके बाद मैंने उप मुख्य मंत्रीजी, जो आर.डी. का डिपार्टमेंट सम्भाल रहे हैं, मैं व्यक्तिश: जा करके उनसे मिला। उनको मैंने निवेदन किया कि हमने इतने साल इस बात के लिये लड़ाई लड़ी है। पूरे देश में सेवा केन्द्रों का नाम राजीव गांधी के नाम पर चल रहा है। राजस्थान की इस दिग्भ्रमित पूर्ववर्ती सरकार ने यह कानून के विपरीत गलत निर्णय किया है।

श्री अध्यक्ष: वाइण्डअप, वाइण्डअप, प्लीज।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): वह निरस्त हो चुका है। अत: आप इसका नाम पुन: राजीव गांधी सेवा केन्द्र, जो है, उसको यथावत जारी रखिये। एक चिट्ठी निकालिये कि यह प्रशासनिक आदेश हाई कोर्ट निरस्त कर चुका है। इसलिये यथावत नाम राजीव गांधी सेवा केन्द्र स्वत: ही हो गया।

श्री अध्यक्ष: धन्यवाद। श्री कालीचरण सराफ।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्रीजी बैठे हुए हैं।

श्री अध्यक्ष: एक मिनट। माननीय कालीचरणजी, एक मिनट। (व्यवधान) संयमजी, बैठिये, प्लीज बैठिये, संयमजी।

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय ... (व्यवधान) माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष: सर।

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने कहा है। यह हमने आलरेडी इंस्ट्रक्शंस दे दिये हैं, कि पूरी तरह से प्रक्रिया करके, क्योंकि इन्होंने ठीक कहा कि वह औचित्य नहीं था। जिस प्रकार से नाम बदला गया, इनकी सरकार चाहे केन्द्र में हो, चाहे राज्य में हो, इन्होंने पांच साल तक नाम बदलने के काम ही किये। इसीलिये आप वहां बैठे हैं और हम यहां वापस आ गये। कृपा करके ऐसा ध्यान रखा करें। नाम बदलने से कोई भावना नहीं बदलती। माननीय सदस्य की भावना अभी आपने देखी। राजीव गांधी ने देश के लिये जो सैक्रिफाइस किया, उनको भारत रत्न मिला हुआ था। उसके बावजूद भी आपको थोड़ा-बहुत भी संकोच नहीं हुआ कि देश व प्रदेश के लोग क्या सोचेंगे। फिर भी आपने नाम बदल दिया, कोई कारण नहीं था। फिर भी हमने कहा कि हम सरकार में आएंगे, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी को भी भारत रत्न मिला हुआ है। हम इसका नाम राजीव गांधी अटल सेवा केन्द्र रखेंगे। यह हमारी इच्छा थी। पर माननीय सदस्य जो कह रहे हैं, हाई कोर्ट में जब गये, माननीय अध्यक्ष महोदय, तो हाई कोर्ट ने जिस प्रकार से बदला गया, उसमें लीगल पाइण्ट आ रहा था, भारत सरकार के रिकार्ड के अन्दर पूरे देश के अन्दर राजीव गांधी सेवा केन्द्र ही है, आपके बदलने के बावजूद भी अपने कागजों में भारत सरकार बदल नहीं पाई थी। शायद आपकी जानकारी में होगा। आपने लिख दिया अटल सेवा केन्द्र, परन्तु रिकार्ड के अन्दर आज भी राजस्थान का हर राजीव गांधी सेवा केन्द्र इसी राजीव गांधी सेवा केन्द्र के नाम से ही जारी है, केन्द्र के अन्दर भी। तब भी आपने उसको

(श्री अशोक गहलोत)

ठीक नहीं किया। हाई कोर्ट का आदेश हुआ, तब हमें मजबूरन राजीव गांधी सेवा केन्द्र करना पड़ेगा। हमने निर्देश दे दिये हैं।

श्री अध्यक्ष: श्री कालीचरण सराफ।

प्रदेश में स्वाइन फ्लू से मौतें

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से प्रदेश में जिस कदर स्वाइन फ्लू बेकाबू होता जा रहा है, उसके बारे में सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। 2019 में केवल बीस दिन, अभी केवल 20 जनवरी हुई है। बीस दिन में 1233 पोजिटिव केसेज सामने आये हैं और 50 लोगों की मौत अभी तक स्वाइन फ्लू से इन बीस दिनों के दौरान हुई है। पूरे देश में जहां 75 मौतें हुई हैं, उनमें से 50 मौतें राजस्थान में और 2000 पोजिटिव मरीज पूरे देश में, उसमें से 1233 पोजिटिव केसेज राजस्थान में हैं। यह बहुत ही चिंता की बात है कि पूरे देश में स्वाइन फ्लू से मौतों में राजस्थान पहले नम्बर पर अपना नाम रोशन कर रहा है और सबसे दुर्भाग्य की बात यह है कि चिकित्सा विभाग को स्वाइन फ्लू से मौतें किस प्रकार से कम हों, पोजिटिव केसेज किस प्रकार से कम हों, इसके बारे में उनको चिंता नहीं है। वे तो केवल आंकड़े छिपाने का काम कर रहे हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि औपचारिकता के तौर पर मुख्य मंत्रीजी ने स्वाइन फ्लू की रोकथाम के लिये एक समीक्षा बैठक की। सब डाक्टर्स की छुट्टियां रद्द कर दीं। सभी जगह स्वाइन फ्लू के मरीजों के लिये आइसोलेशन वार्ड होने चाहिए, इसके निर्देश दिये। विभाग के अधिकारी, हमारे चिकित्सा विभाग के जो ए.सी.एस. हैं, वे वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये लोगों को केवल निर्देश दे रहे हैं। पर मैं पूछना चाहता हूं कि मुख्य मंत्रीजी के निर्देश के बावजूद, क्या आज प्रदेश में हर हास्पिटल में, हर सी.एच.सी. में, पी.एच.सी. में क्या स्वाइन फ्लू के लिये आइसोलेशन वार्ड की व्यवस्था हो गई? मैं पूछना चाहता हूं कि क्या डाक्टर्स की छुट्टियां रद्द करने का आदेश जो आपने दिया, क्या उसकी पूरी पालना हो रही है?

अभी कल अख़बार में छपा है। भास्कर ने केवल जयपुर में एक स्टिंग आपरेशन किया। जयपुर में तीस डाक्टर अनुपस्थित पाये गये। पूछा, क्यों अनुपस्थित हैं, कोई शादी में व्यस्त है, कोई रिश्तेदारी निभाने में व्यस्त है। तो क्या सरकार उनके खिलाफ कोई सख्त कार्यवाही करने का विचार रखती है?

(श्री कालीचरण सराफ)

मुझे इस बात का खेद है कि स्वाइन फ्लू इस कदर बढ़ रहा है। परन्तु अभी तक ...(व्यवधान) एक बार बैठिये आप, एक बार बैठ जाइये।

श्री हनुमान बैनिवाल (खींवसर): मैं इनसे मेरी बात करूं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: ना, ना, ना। माननीय सदस्य, माननीय सदस्य।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): आप बैठ जाइये, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिये। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): यह क्या हो रहा है? यह क्या हो रहा है? आप बैठाइये इनको। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, बैनिवालजी। माननीय सदस्य, बैठिए आप। कोई बैठे-बैठे कमेंट्स न करें। मेरी जिम्मेदारी का निर्वहन मुझे करने दीजिए। (व्यवधान)

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): देखिए, यह बीच-बीच में खड़े हो जाते हैं, क्या है यह? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: एक मिनट, कालीचरणजी, एक मिनट। माननीय कालीचरणजी।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, एक सैकिण्ड। माननीय अध्यक्ष महोदय, इतनी सी व्यवस्था आप कर दें कि बिना आपके नाम पुकारे अगर कोई बोले तो उसको रिकार्ड पर नहीं आएगा तो अपने आप ठीक हो जाएगा।

श्री अध्यक्ष: बिलकुल ठीक। बिलकुल ठीक। आज मैं, जो माननीय प्रतिपक्ष के नेता ने कहा वह बात फिर निवेदन कर रहा हूं। बैठे-बैठे नहीं बोलेंगे और यदि जो सदस्य बोल रहे हैं वह यील्ड नहीं करे, उसके बीच में कोई कमेंट करेगा तो अंकित नहीं होगा। कालीचरणजी सराफ।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, इससे ज्यादा दुर्भाग्यजनक बात नहीं हो सकती कि स्वाइन फ्लू जिस तरीके से बेकाबू होता जा रहा है, मौतें बढ़ रही हैं, हमारे यहां राज्य स्तर पर टास्क फोर्स की जो कमेटी बनी हुई है, उसकी आज तक कोई मीटिंग नहीं हुई। अभी तक स्वाइन फ्लू के प्रभावित क्षेत्रों में विशेष अभियान चलाकर, घर-घर जाकर

(श्री कालीचरण सराफ)

जो स्क्रीनिंग होनी चाहिए, उसकी स्क्रीनिंग अभी तक नहीं हुई। स्क्रीनिंग में जिस प्रकार से लापरवाही बरती जा रही है, गम्भीर मरीजों के लिए आई.सी.यू. की व्यवस्था नहीं है। पर्याप्त मात्रा में दवाइयां उपलब्ध नहीं हैं। पी.एच.सी., सी.एच.सी. स्तर पर जांच की सुविधा उपलब्ध नहीं है और मुख्य मंत्रीजी के निर्देश के बावजूद अभी तक आइसोलेशन वार्ड हर जगह पर उपलब्ध नहीं है, हर जगह पर उसकी व्यवस्था नहीं हुई है और वैक्सीनेशन के बारे में तो जागरूकता नहीं है। मैं यह कहना चाहता हूं, चिकित्सा मंत्रीजी, यहां पर बैठकर केवल लफ्फाजेबाजी करने से काम नहीं चलेगा। स्वाइन फ्लू को यदि रोकना है तो आप जिलो में जाइये।

श्री अध्यक्ष: धन्यवाद। माननीय सदस्य।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): और अपने वरिष्ठ अधिकारियों को जहां-जहां प्रभावित क्षेत्र है, वहां पर जाकर व्यवस्था करें।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, हो गया।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): स्क्रीनिंग करें और यह देखिए कि कितनी दुर्भाग्य की बात है ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, अब हो गया।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): नहीं, माननीय अध्यक्ष महोदय, दो मिनट लूंगा। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आपको पांच मिनट से ज्यादा हो गये। प्लीज, वाइंड-अप करिये।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, प्लीज, दो मिनट। आप यह देखिये कि जहां-जहां पर स्वाइन फ्लू फैल रहा है वहां पर स्कूलों में, बस स्टैंड पर, रेलवे स्टेशन पर अभी तक स्क्रीनिंग की कोई व्यवस्था नहीं है। कम से कम स्कूलों में जो सामूहिक प्रार्थना होती है, उसको तो अभी एक बार स्थगित करिए। वर्ना इसका कोई इलाज नहीं होगा। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, समाप्त हुआ। श्री संदीप शर्मा। माननीय सदस्य, हो गया, प्लीज।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): मैं यह कहना चाहूंगा कि

(श्री कालीचरण सराफ)

सरकार इस प्रकार से लापरवाही बरत रही है, यह स्वाइन फ्लू जो बेकाबू होता जा रहा है, इस पर अंकुश लगाइये।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, अब अंकित नहीं होगा।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): 000

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, अंकित नहीं होगा। माननीय सदस्य श्री संदीप शर्मा।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): 000

श्री अध्यक्ष: मदनजी, प्लीज आप बैठिये। आप सीनियर आदमी हैं। आप प्लीज, बैठिये।

श्री बलजीत यादव (बहरोड़): 000

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं होगा। आप सुन नहीं रहे? अंकित नहीं होगा। अंकित नहीं होगा, बैठिये प्लीज। प्लीज बैठिये।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): 000

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार पूर्व चिकित्सा मंत्रीजी कह रहे थे कि स्वाइन फ्लू बड़ी तेजी के साथ पूरे प्रदेश में अपने पैर पसार रहा है परन्तु राज्य सरकार इस ओर बिलकुल गम्भीर नहीं है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय कटारियाजी, इतने सीनियर आदमी हैं, आप समझाइये इनको, ऐसा नहीं करें। (व्यवधान)

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): जिस प्रकार व्यापक रूप से इसके रोकथाम के लिए प्रचार-प्रसार होना चाहिए था ...(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): 000

श्री अध्यक्ष: नहीं, आप बैठिये, प्लीज। बिलकुल नहीं। प्लीज, आप बैठिये। आपका अंकित नहीं हो रहा है, बैठिये आप। आप बैठें, प्लीज। आप बैठें।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): 000

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): हमारी राज्य सरकार ने अभी तक इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: नहीं, आप बैठिये। अंकित नहीं होगा। प्लीज, आप बैठिये। आप बैठिये अंकित नहीं होगा। प्लीज, बैठिये, आपका अंकित नहीं होगा।

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): 54 मौतें अभी तक हो चुकी हैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, और लगभग 1233 लोग इस स्वाइन फ्लू की बीमारी से ग्रसित हैं। जबकि इस बीमारी की सबसे बड़ी रोकथाम के लिए आवश्यकता है, व्यापक प्रचार-प्रसार करके इस बीमारी को वहीं पर रोक दिया जाए परन्तु इस ओर राज्य सरकार अभी तक गम्भीरतापूर्वक ध्यान नहीं दे रही है। न तो अस्पताल में स्टाफ-कर्मी है और न चिकित्सा के चिकित्सा-कर्मी ही है। अस्पताल खाली पड़े हैं। नई जो मशीन है, आर.टी.पी.सी.आर. मशीन, वह अस्पतालों में उपलब्ध नहीं है, जिससे त्वरित उस बीमारी की जांच हो जाए। वैक्सीनेशन नहीं है जबकि वैक्सीनेशन की इतनी बड़ी आवश्यकता है कि चिकित्सा-कर्मियों से लेकर स्टाफ-कर्मी तक सभी लोगों को क्योंकि अगर उनके वैक्सीनेशन नहीं होगा फ्री में, नि:शुल्क रूप से तो निश्चित रूप से वह सबसे पहले स्वाइन फ्लू से ग्रसित होंगे और स्वाइन फ्लू की बीमारी को आगे भी सौगात के रूप में देंगे।

श्री अध्यक्ष: धन्यवाद-धन्यवाद।

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार अगर इस बीमारी के प्रति नहीं चेती तो निश्चित रूप से इस पूरे प्रदेश में जो बीमारी का हाल और आंकड़ा नजर आ रहा है, हम आज पूरे प्रदेश में इस बीमारी में सबसे आगे हैं। ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: धन्यवाद, माननीय सदस्य। माननीय मंत्रीजी, कुछ बोलना चाहेंगे? धन्यवाद, माननीय सदस्य।

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): इसलिए मैं माननीय चिकित्सा मंत्रीजी से यह अनुरोध करना चाहूंगा कि स्वाइन फ्लू की बीमारी को गम्भीरता से लें। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, अब अंकित नहीं होगा। अंकित नहीं होगा। माननीय मंत्रीजी, आप कुछ बोलना चाहेंगे?

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): 000

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): 000

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, कोई अंकित नहीं होगा। आप नियम-कानून का पालन नहीं करेंगे तो मुझे करवाना पड़ेगा। माननीय संयम लोढ़ाजी, नहीं। बिलकुल नहीं। आप बैठ जाइए प्लीज। आप प्लीज बैठ जाइए।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): 000

श्री अध्यक्ष: मैं आपका ध्यान रखूंगा, आप बैठ जाइए।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): 000

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आपने ध्यान दिलाया, उसके लिए धन्यवाद। आप भी ध्यान रखिये। माननीय मंत्रीजी।

श्री रघु शर्मा (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मालवीय नगर से आने वाले माननीय सदस्य और कोटा दक्षिण से आने वाले माननीय सदस्य ने स्वाइन फ्लू, एच1 एन1 को लेकर इस सदन में अपनी चिंता जाहिर की। मैं उनकी जानकारी के लिए यह बताना चाहता हूं कि राज्य सरकार क्योंकि यह मौसमी बीमारी है और मौसमी बीमारी नवम्बर, दिसम्बर, जनवरी और फरवरी, इन चार महीनों में इस बीमारी का प्रकोप केवल इस साल ही नहीं, यह विगत पांच वर्षों के आकड़े भी मेरे पास हैं, यह हर बार होता है लेकिन बीमारी अपनी जगह पर है। जहां तक आरोप लगाया गया इस सदन में कि हमने कोई व्यवस्था नहीं की तो मैं उनकी जानकारी के लिए यह निवेदन करना चाहता हूं कि डेली बेसिस पर विभाग द्वारा इसकी मोनिटरिंग की जा रही है। जैसे ही हमारी सरकार बनी, 29.12.2018 को माननीय मुख्य मंत्रीजी ने खुद संवेदनशील तरीके से सी.एम.ओ. में एक उच्चस्तरीय बैठक की और पहले दिन जहां जोधपुर के अंदर यह ज्यादा प्रकोप था इस बीमारी का, दो विशेषज्ञों की टीमें तत्काल रवाना की गयीं उसके बाद 7 तारीख को और 9 तारीख को दो बार मैंने, अभी माननीय सदस्य कह रहे थे कि हमने तो कुछ, टास्क फोर्स की मीटिंग ही नहीं की। मेरे ख्याल से उनको जानकारी नहीं है। नियमित रूप से टास्क फोर्स की मीटिंग्स विभाग द्वारा हो रही है और अगर टास्क फोर्स की मीटिंग नहीं होती तो करेक्टिव मेजर्स कैसे लिये जाते? आज राजस्थान में जितने भी उप स्वास्थ्य केन्द्र हैं, पहले यह मौसमी बीमारियों के लिए यह दवाइयां उप स्वास्थ्य केन्द्रों पर नहीं होती थीं। हमारी सरकार बनने के बाद उप स्वास्थ्य केन्द्र पर उक्त दवा हमने उपलब्ध कराने के निर्देश प्रदान किए हैं। यह जो स्वाइन फ्लू है, इसका एक ही इलाज है, अध्यक्ष महोदय, टेमी-फ्लू और दूसरा बचाव। बचाव के लिए मैंने बार-बार अपील की है समाचार पत्रों के माध्यम से पैम्फलेट्स के माध्यम से और जहां कहीं पर भी केसेज पाये जाते हैं उनकी बराबर स्क्रीनिंग हमारा विभाग कर रहा है और माननीय सदस्य की जानकारी के लिए मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि आज 21 तारीख है, आज से लेकर 23 तारीख तक पूरे राजस्थान में सघन अभियान चल रहा है, इस बीमारी के ऊपर नियंत्रण पाने का ...(व्यवधान)

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): 000

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य। माननीय सदस्य, आपका यह तरीका ठीक नहीं है। आप इतने सीनियर मैम्बर हैं। आप बैठिये, प्लीज।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): 000

श्री रघु शर्मा (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): आपकी पार्टी की एक विधायक इसी स्वाइन फ्लू से मर गयीं। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह स्वाइन फ्लू की चपेट में हैं। पिछले सालों के आंकड़े हैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप बैठिये प्लीज। माननीय सदस्य, अब नहीं समझ में आ रहा है क्या आपको? कालीचरणजी, बैठिये आप। (व्यवधान)

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): 000

श्री रघु शर्मा (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): 165 लोगों की मौत 2013 में हुई, 2014 के अंदर 34 लोगों की मौत हुई, 2015 में 472 लोगों की मौत हुई। आप राजनीति करना चाहते हैं इसलिए मैं आप लोगों से कह रहा हूं। आपकी नाकामियों को छिपाने के लिए आप कितना भी ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: मंत्रीजी, प्लीज वाइंड अप करिये। माननीय मंत्रीजी, जो रेमेडियल मैजर्स जो सरकार ले रही है, आप उसकी जानकारी दे दें। जो रेमेडियल मैजर्स ले रहे हैं, उसकी जानकारी दे दें। (व्यवधान)

श्री विट्ठल शंकर अवस्थी (भीलवाड़ा): 000

श्री अध्यक्ष: प्लीज आप बैठिये। नीचे बैठिये। मुझे अब अनप्लीजेंट निर्णय लेना पड़ेगा। जो बीच में बोलेंगे या तो प्रश्न में उनका नम्बर हटाना पड़ेगा, कुछ अनप्लीजेंट काम करना पड़ेगा। जब आप सदन को ढंग से चलाना ही नहीं चाहते हैं, हम इतने सीनियर आदमी बैठे हुए हैं, हर आदमी अपनी चीज को बोलना चाहता है। आप कृपया, नियमों का पालन करें और मैं आप वरिष्ठ नेताओं से अपील करूंगा कि अगर आप रोल माडल नहीं होंगे तो नए आदमी रोल माडल नहीं होंगे। कृपया, अपने नियमों का पालन करके सदन को अच्छी तरह से चलने दें। माननीय मंत्रीजी, रेमेडियल मैजर्स, जो गम्भीरता है उसको ठीक करने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है, उसको ब्रीफ में बोल दें।

श्री रघु शर्मा (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से न केवल सदन को, बल्कि राजस्थान की साढ़े सात करोड़

(श्री रघु शर्मा)

जनता को भी यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारा विभाग बराबर यह कह रहा है कि यह बीमारी लाइलाज बीमारी नहीं है। अगर खांसी, कफ, तेज बुखार, ऐसे लक्षण आयें तो चिकित्सक से अगर तत्काल परामर्श कर लें तो इसका इलाज सुनिश्चित किया जा सकता है। हमने वर्ष 2019 में 5,367 सैम्पल की जांच की है, 1233 मामले जो कि 23 प्रतिशत होता है, वह पोजीटिव पाये गये, उसमें से 4 प्रतिशत 49 लोगों की मृत्यु हुई, जिसके लिये मुझे अफसोस है। लेकिन, कई बार अवेयरनैस नहीं होने की वजह से लास्ट स्टेज पर पेशेंट को चिकित्सीय परामर्श के लिये लाया जाता है और उसकी वजह से यह जो वायरल इंफेक्शन है, यह लंग्स तक पहुंचता है और हम लाख कोशिश के बावजूद भी, और यह ऐसा नहीं है, यह आंकड़े बोल रहे हैं 2013 के आंकड़े भी हमारे पास हैं, 2014 के आंकड़े भी हमारे पास हैं। इसके अलावा, माननीय अध्यक्ष महोदय, इनके खुद के टाइम में ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: धन्यवाद, मंत्रीजी धन्यवाद। माननीय हनुमान बैनिवाल जी।

नागौर कोतवाली के मालखाने से डोडा पोस्त की चोरी

श्री हनुमान बैनिवाल (खींवसर): माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने इस गम्भीर मामले पर मुझे बोलने की इजाजत दी। अध्यक्ष महोदय, सबका भरोसा कानून पर होता है और जब भी आदमी संकट के अंदर होता है, तो पुलिस थाने के अंदर वह फोन करता है कि पुलिस आ जाये और मामला खतम हो, झंझट मिटे। लेकिन, पुलिस थाने का मालखाना, जो सबसे ज्यादा सुरक्षित होता है, 24 घंटे उसकी पहरेदारी होती है, उसके अंदर हथियार रखना और जो भी साक्ष्य के मुकदमे होते हैं, उन साक्ष्यों की, चाहे वह मुकदमे के अंदर या अभियुक्त से बरामद किया, वह मालखाने में जमा होती है और मालखाने से 11 दिसम्बर, 2018 को नागौर कोतवाली के मालखाने से 4 बोरी डोडा पोस्त चोरी हो गया। अध्यक्ष महोदय, चोरी होने के दो दिन बाद उसकी एफ.आई.आर. दर्ज होती है और 15 दिन तक वही सी.आई., जिसके मालखाने से चार बोरी डोडा पोस्त चोरी होता है, खुद ही जांच करता है और एक हैड कांस्टेबल को सस्पैण्ड करता है और वही हैड कांस्टेबल रोज डायरी काटने वहां थाने के अंदर जाता है और उसी सी.आई. के साथ काम करता है। जब मैंने इसकी शिकायत उच्च अधिकारियों को की तो जांच बदलकर वहां के डी.वाई.एस.पी. को दे दी। अध्यक्ष महोदय, इससे गम्भीर

(श्री हनुमान बेनिवाल)

घटना नहीं हो सकती कि यह जो सी.आई. है, यह पूर्ववर्ती सरकार के अंदर गृह मंत्रालय के आदेश से सीधा नोखा बीकानेर से नागौर के अंदर लगा था और इसका कोई एक काम यह नहीं है कि मालखाने से चोरी हो गयी, 10 अक्टूबर को इसके एक युवक को 15 दिन तक हिरासत के अंदर रखा। वह युवक भाग गया और उसके बाद एस.पी. ने इसको नोटिस दिया और वहां के सी.ई.ओ. ने जांच करके उसकी इतिश्री कर ली। इसी सी.आई. ने 22.10.2018 को ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप इसी के बारे में बोलें।

श्री हनुमान बैनिवाल (खींवसर): इसी का है, सिर्फ एक मिनट, 22.10.18 को परिवादी सीताराम डिडेल व अजीत, दो परिवाद इसके खिलाफ दर्ज हुए। सीताराम को उसकी माताजी के साथ थाने में सी.आई. ने इसलिये पीटा कि तू बुलेट किसलिये चला रहा है। उसने कहा कि बुलेट तो मैंने खरीदी है, मेरी मां के साथ सब्जी लेने आया हूं। थाने के अंदर ले-जाकर पीटा और कहा कि बाहर अगर किसी को कह दिया तो तुझे जान से मार दूंगा। यही नहीं, जब यह नोखा के अंदर था बीकानेर के अंदर...(व्यवधान) ...

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, डोडा पोस्त चोरी की बात कहिये। स्पेसिफिक मुद्दा है।

श्री हनुमान बैनिवाल (खींवसर): अध्यक्ष महोदय, मैं एक मिनट सी.आई. के बारे में भी आपको बता दूं। मुख्य मंत्रीजी भी विराजें हुए हैं, उप मुख्य मंत्रीजी भी बैठे हुए हैं, गृह मंत्रीजी भी हैं। मैं एक मिनट में निवेदन कर रहा हूं। नोखा के अंदर रहते हुए...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आपने ध्यान आकर्षित कर दिया कि नागौर के थाने से चोरी हुई, वह गम्भीर मामला है। बाकी चीजों के संबंध में चर्चा इसमें नहीं करें। आप अपनी बात को वाइंड-अप करें, प्लीज।

श्री हनुमान बैनिवाल (खींवसर): माननीय अध्यक्ष महोदय, दुर्भाग्य इस बात का है कि यह सी.आई. एक अप्रैल से डी.वाई.एस.पी. बन जाएगा। (व्यवधान) इसको सरकार डी.वाई.एस.पी. बना रही है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्लीज। अब आपकी बात हो गयी, माननीय सदस्य।

श्री हनुमान बैनिवाल (खींवसर): मैं मुख्य मंत्रीजी का ध्यान इस बात

(श्री हनुमान बैनिवाल)

की ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि आप हर मामले में गम्भीर हैं, संवेदनशील हैं, ऐसे मामले के अंदर उस सी.आई. को निलम्बित करके उसके खिलाफ कार्यवाही करें।

श्री अध्यक्ष: धन्यवाद माननीय सदस्य। माननीय श्री बलवान पूनियां।

श्री हनुमान बैनिवाल (खींवसर): चोरी का, जो डोडा पोस्त चोरी हुआ है, उसमें एन डी पी एस का मुकदमा भी सी.आई. के खिलाफ दर्ज हो, इस कार्यवाही की, अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मांग करना चाहता हूं और इस संवेदनशील मुद्दे पर सरकार इस ओर ध्यान देगी और सी.आई. और सी.ई.ओ. को वहां से तुरन्त प्रभाव से हटायेगी। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: धन्यवाद माननीय सदस्य। माननीय बलवान पूनियां।

श्री हनुमान बैनिवाल (खींवसर): आपने सबका जवाब दिलाया है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आपकी बात को सरकार ने गम्भीरता से सुना है। आप बैठें प्लीज।

श्री हनुमान बैनिवाल (खींवसर): मेरे इतने गम्भीर मामले में आप अगर जवाब भी दिलायें अध्यक्ष महोदय, तो फिर ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप विराजें।

माननीय सदस्य, आप विराजें। सरकार को हम कम्पैल नहीं कर सकते हैं। धन्यवाद। आपको बोलना है पूनियां जी। आप बैठिये। माननीय सदस्य, आप बैठिये। (व्यवधान)

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, यह सही है 10 कट्टों में से मालखाने के पीछे की जाली तोड़कर के 4 कट्टे गायब हो गये और इसकी पहली बार जो रिपोर्ट दर्ज करवायी, वह रिद्धकरण, हैड कांस्टेबल ने दर्ज करवायी। इसके बाद आपके द्वारा यह शिकायत की गयी कि इसकी जांच ठीक नहीं हो रही है तो अनुसंधान आपने बदलवाया। डी.वाई.एस.पी. के पास अनुसंधान चला गया। उससे भी आप सैटिसफाई नहीं हुए तो उसके बाद में जो अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक था, उससे जांच करवायी गयी। उससे जांच करवाने के बाद में भी यह देखा गया कि सिर्फ दो के खिलाफ ही एक्शन नहीं होना चाहिये, बल्कि तीन आदमी, जो रात को ड्यूटी पर थे, जिसमें एक भगवाना राम, गरीबा राम और एक राजूराम, उनको भी निलम्बित किया गया है। अब आप इसमें चाहते क्या हैं? अनुसंधान तो जारी है।

श्री हनुमान बैनिवाल (खींवसर): आपने असत्य जानकारी दे दी, सिर्फ एक ही सस्पैण्ड हुआ है भगवाना राम।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, जब मंत्रीजी कह रहे हैं, सदन में कह रहे हैं। उस बात को असत्य मानते हैं।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): तीन आदमियों को, रात्रि को जो ड्यूटी देने वाले तीन व्यक्ति थे, तीनों को निलम्बित कर दिया गया है। सवाल तो यह है कि अनुसंधान तो जारी है। अनुसंधान हो जाएगा, उसके बाद में ...(व्यवधान)

श्री हनुमान बैनिवाल (खींवसर): कितने महीने लगेंगे, साहब? अगर ऐसे संवेदनशील मामले में मंत्रीजी, आप ऐसा जवाब देंगे तो कैसे चलेगा।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): यह वाकया कोई ज्यादा पुराना नहीं है। सिर्फ एक महीने पुराना केस है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप सुनें। माननीय सदस्य, आपका अंकित नहीं होगा।

श्री हनुमान बैनिवाल (खींवसर): 000

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): आप किसको चाहते हैं कि किससे जांच करवाएं।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी, आप इधर देखकर बात करें, उधर नहीं। आप इधर देखकर बात करें। आपको जो भी बात करना है, चेयर को एड्रेस करें। धन्यवाद। माननीय बलवान पूनियां। (व्यवधान) माननीय सदस्य, आप यदि मंत्री की बात सुनना ही नहीं चाहेंगे। (व्यवधान) माननीय सदस्य, हो गया। माननीय सदस्य, अब अंकित नहीं होगा, प्लीज हो गया। माननीय बलवान पूनियां।

श्री हनुमान बैनिवाल (खींवसर): 000

श्री अध्यक्ष: आपके संवेदनशील मुद्दे पर मंत्री बोले हैं। आप कृपया बैठिये। अंकित नहीं हो। बलवान पूनियां जी, आप बोलिये। आप बोलना शुरू करें। अपनी बात कहें।

श्री हनुमान बैनिवाल (खींवसर): 000

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, अंकित नहीं होगा। अभी मंत्रीजी ने कहा उनको भी आप सुनना नहीं चाहते। बलवान पूनियां बोलें।

श्री बलवान पूनियां (भादरा): अध्यक्षजी, बहुत गम्भीर मसला है, पहले हनुमानजी को संतुष्ट कर दो, फिर बोल लूंगा। सी.आई. को सस्पैण्ड कराओ जी, हनुमानजी वाली बात खतम हो जाएगी।

श्री अध्यक्ष: आप बैठें-बैठें नहीं बोलेंगे, कौन सस्पैण्ड होगा, कौन सस्पैण्ड नहीं होगा, बैठें-बैठे नहीं बोलें प्लीज।

श्री हनुमान बैनिवाल (खींवसर): 000

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, अंकित नहीं होगा।

श्री हनुमान बैनिवाल (खींवसर): 000

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, अंकित नहीं होगा, आप विराजें। आप विराजें। अंकित नहीं होगा, माननीय सदस्य। बलराम पूनियां आपको बोलना है, बोलिये।

श्री बलवान पूनियां (भादरा): अध्यक्षजी, कृषि संकट के साथ-साथ रोजगार भी एक ऐसा मुद्दा है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, नहीं, ऐसा नहीं होगा। माननीय सदस्य, नहीं, प्लीज। (व्यवधान) बलवान जी, आप बोलिये। बलवान जी, आपको बोलना है कि नहीं बोलना? माननीय पूनियां जी, बोलना है कि नहीं बोलना आपको?

श्री बलवान पूनियां (भादरा): कृषि संकट के साथ-साथ रोजगार भी एक ऐसा मुद्दा है जिसमें एक ऊपर से नीचे तक जबर्दस्त लापरवाही. और चलता है, का रवैया सरकारों का रहा है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं होगा माननीय सदस्य।

श्री हनुमान बैनिवाल (खींवसर): 000

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं होगा।

श्री हनुमान बैनिवाल (खींवसर): 000

श्री बलवान पूनियां (भादरा): राज्य में भर्तियां, आरक्षण, पेपर लीक और आंसर की और दूसरी लापरवाहियों की वजह से कोर्ट में चली जाती हैं।

श्री हनुमान बैनिवाल (खींवसर): 000

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, अंकित नहीं होगा। सदन में कार्यवाही नहीं थोपें प्लीज। आप बैठें। माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, आप बैठिये, अंकित नहीं होगा।

श्री हनुमान बैनिवाल (खींवसर): 000

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, अंकित नहीं होगा। आप बैठें अंकित नहीं होगा। अंकित नहीं होगा। आप बैठें प्लीज। हो गया अब, प्लीज बैठें।

श्री हनुमान बैनिवाल (खींवसर): 000

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य: Don't' compel the Chair to take action.

राज्य सरकार द्वारा बेरोजगारी भत्ता

श्री बलवान पूनियां (भादरा): माननीय अध्यक्षजी, कृषि संकट के साथ-साथ रोजगार भी एक ऐसा मुद्दा है, जिसमें ऊपर से नीचे तक एक जबर्दस्त लापरवाही और 'चलता है' वाला रवैया सरकारों का रहा है। राज्य में भर्तियां, आरक्षण, पेपर लीक और आंसर की तथा दूसरी लापरवाहियों की वजह से कोर्ट में चली जाती हैं। आर.ए.एस. 2013, आर.ए.एस. 2016, रीट प्रथम लेवल का पेपर, कालेज लैक्चरर, 2014 जैसी भर्तियों में अभी नियुक्तियां नहीं हुई हैं। सोशल मीडिया पर आर.पी.एस.सी. के बारे में एक चर्चा करते हैं लोग कि आर.पी.एस.सी. में परीक्षा में चार चरण होते हैं। चरण पहला प्रारम्भिक परीक्षा, दूसरा मुख्य परीक्षा, तीसरा साक्षात्कार और चौथा कोर्ट।

जिस तरीके से आरपीएससी और दूसरी परीक्षाएं करवाने वाली एजेंसियां समय पर परीक्षा नहीं करवा पातीं, भर्तियां कोर्ट में अटक जाती हैं। सरकार युवाओं को नियुक्तियां नहीं दे पा रही है। स्कूल लैक्चरर, सैकिण्ड ग्रेड परीक्षा एलडीसी, पीटीआई, महिला पर्यवेक्षक, जेल प्रहरी, जूनियर अकाउन्टेन्ट सहित बहुत सी भर्तियां लम्बित पड़ी हैं। लेवल फर्स्ट के 26 हजार बच्चे अवसाद ग्रसित हैं। जिनका शाला दर्पण में नाम चल रहा है, उनको नियुक्तियां नहीं मिली हैं। राज्य का युवा रोजगार को तरस रहा है। परीक्षा के परिणाम एक से अधिक बार जारी करने पड़ते हैं। राज्य में बेरोजगारी की हालत यह है कि पुलिस विभाग में पांच हजार पदों के लिए 17 लाख से अधिक आवेदन आए। रीट में 35 हजार पदों के लिए 10 लाख से अधिक प्रशिक्षित अध्यापकों ने आवेदन किए हैं। एलडीसी और पटवारी की भर्तियों के लिए भी लाखों आवेदन आए।

पिछले तीन सालों में प्रदेश में 08 लाख से अधिक बेरोजगारों का नाम रजिस्टर्ड हुआ है। सेंटर फार मोनीटरिंग इण्डियन इकोनोमी (सेमी) के अनुसार देश भर में बेरोजगारी 6.4 प्रतिशत बढ़ रही है और राजस्थान में यह बढ़कर 9.8 प्रतिशत हो गई है। अलवर में चार नौजवान नौकरी नहीं मिलने की वजह

(श्री बलवान पूनियां)

से यह आशा खो बैठे और ट्रेन के आगे कूदकर उन्होंने आत्महत्या कर ली थी। ऐसी स्थिति में 2014 में करीब एक हजार पदों के लिए कालेज लैक्चरर की भर्ती निकली लेकिन पांच साल में अभी तक भर्ती पूरी नहीं हुई है।

कालेज, व्याख्याताओं के अभाव में जूझ रहे हैं। बेरोजगारी पर नाटक, मंचन, रैली, टेली फिल्में बन रही हैं और लोग कह रहे हैं कि:-

हमें रोजगार देने के लिए लुभाया कई वायदों से,
मगर बेरोजगार भी किया, तुमने कुछ इरादों से।

मेरा सीधा-सीधा सरकार से सवाल है कि बेरोजगारी की स्थिति पर पिछली सरकार ने जो दुर्गतियां की हैं, वर्तमान सरकार इस बारे में प्रदेश के नौजवान को जवाब दे और प्रदेश के नौजवान को यह धीरज बंधाये कि हम सारे प्रशिक्षित नौजवानों को रोजगार भविष्य में देंगे। धन्यवाद।

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

श्री अध्यक्ष: नियम 295, श्रीमती इन्द्रा। (अनुपस्थित) श्री जौहरी लाल मीणा।

सरस डेयरी अध्यक्ष, अलवर द्वारा अनियमितताएं

श्री जौहरीलाल मीना (राजगढ़-लक्ष्मणगढ़): अध्यक्ष महोदय, नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख प्रस्ताव।

महोदय, उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि अलवर जिले में अलवर डेयरी अध्यक्ष के सम्बन्ध में गत बजट सत्र में विधान सभा में विधायक श्री मोहन लाल गुप्ता द्वारा प्रश्न के जवाब में यह बताया गया कि अलवर सरस डेयरी अध्यक्ष, गम्भीर मामलों एवं अनियमितताओं के दोषी हैं....

श्री बलवान पूनियां (भादरा): अध्यक्ष महोदय, मेरे स्थगन का जवाब दिलवा दीजिए।

श्री अध्यक्ष: आप बैठिए। दूसरा शुरू हो गया। प्लीज बैठें। (व्यवधान) माननीय सदस्य, बैठें। अगली कार्यवाही शुरू हो गई।

श्री बलवान पूनियां (भादरा): 3500 रुपये बेरोजगारी भत्ता मांग रहे हैं नौजवान गांवों में।

श्री अध्यक्ष: आप सुन नहीं रहे हैं, माननीय सदस्य? जौहरी लालजी, बोलें।

श्री जौहरीलाल मीना (राजगढ़-लक्ष्मणगढ़): ...लेकिन उक्त सम्बन्ध में अध्यक्ष पर अभी तक कोई अपेक्षित कार्यवाही नहीं की गई है एवं ना ही उन्हें अध्यक्ष पद से बर्खास्त किया गया तथा डेयरी अध्यक्ष द्वारा मंत्रियों के स्वागत सत्कार में राजकीय धन का उपयोग राजनैतिक उद्देश्य से किया गया था जिसके क्रम में भी डेयरी अध्यक्ष पर अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि तत्कालीन भाजपा सरकार के सहकारिता मंत्री द्वारा अलवर डेयरी अध्यक्ष से कोई मिलीभगत तो नहीं की गई।

अत: अलवर डेयरी अध्यक्ष एवं दोषियों के ऊपर सरकार द्वारा तुरन्त प्रभाव से आवश्यक कार्यवाही किया जाना आवश्यक है जिससे कि अलवर जिले की जनता को मिल रही डेयरी की मिलावट सामग्री से छुटकारा दिलाया जा सके।

अत: उपरोक्त लोक महत्व के विषय को ध्यान में रखते हुए मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: श्रीमती शकुन्तलता रावत।

दीनदयाल उपाध्याय योजना के अन्तर्गत बिजली कनेक्शन

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 295 के तहत विषेष उल्लेख-बानसूर में बिजली से संबंधित समस्याओं के सम्बन्ध में।

महोदय, बानसूर विधान सभा क्षेत्र में दीनदयाल उपाध्याय योजना के तहत जितने डिमाण्ड नोटिस जमा हो गए वे कनेक्शन आज तक शेष पड़े हुए हैं। उन्हे तुरन्त कराने के निर्देश प्रदान करें जिससे जनता को राहत मिल सके एवं थ्री फेस के डिमाण्ड नोटिस जमा हो चुके एवं जितनी फाइल लगी हुई हैं। उतने थ्री फेस के ट्रान्सफार्मर 10, 16, 25 और 40 के मंगवाये जाएं जिससे कि किसानों की रबी की फसल गेहूं, चना, जौ, सरसों आदि का किसानों को लाभ मिल सके। किसानों की रोजी, रोटी व बच्चों की पढ़ाई आदि के लिए किसानों की फसल पर निर्भर रहना पड़ता है।

इसलिए मेरा सरकार से अनुरोध है कि किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए जल्दी से जल्दी किसानों के हक के लिए थ्री फेस के कनेक्शनों का सामान तार, खम्भे, मीटर, सिंगल फेस की लीड आदि तुरन्त देकर किसानों की मंशा पूरी हो सके। उसे फसल का लाभ मिल सके एवं बिजली का टाइम बदलकर किसानों को बिजली दिन में मिले, इसकी व्यवस्था हो। सुबह स्कूल के

(श्री मती शकुन्तला रावत)
बालक ताजा पानी से नहाकर स्कूल जा सकें इसलिए बिजली की व्यवस्था को सुधार कर किसानों को राहत मिल सके, ऐसा प्रयास तुरन्त करें।

श्री अध्यक्ष: श्रीमती अनिता भदेल।

अजमेर दक्षिण विधान सभा क्षेत्र में अतिक्रमण

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख।

महोदय, अजमेर शहर की समस्त सड़कें भारी यातायात दबाव एवं अतिक्रमणों के कारण पैदल चलने वाले आम नागरिकों के लिए भारी समस्या का कारण बनी हुई हैं। अजमेर दक्षिण में स्थित मुख्य मार्गों पर स्थित विद्यालयों के छुट्टी के समय दोपहर 01 बजे से 2.30 बजे तक सड़कें आम नागरिकों के उपयोग के लिए अघोषित रूप से प्रतिबन्धित होती हैं। ऐसी स्थिति में अति आवश्यक सेवाएं भी बाधित होती हैं। कई महिलाएं जिन्हें डिलीवरी के लिए अस्पताल ले जाया जाता है। समय पर अस्पताल नहीं पहुंच पाने के कारण रास्ते में सड़क पर ही डिलीवरी करानी पड़ती है। एम्बुलेंस सेवाएं प्रभावित होती हैं। मरीजों को समय पर उपचार नहीं मिल पाता है जिससे अनेक बार व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। इससे अनेक बार दुर्घटनाएं भी होती हैं। उक्त समस्या के समाधान हेतु तत्काल सड़क मार्गाधिकार में आने वाले स्थायी व अस्थायी अतिक्रमणों को हटाया जाए। सड़कों पर अवैध रूप से की जा रही पार्किंग को समाप्त किया जाए। नसीराबाद रोड, ब्यावर रोड, श्रीनगर रोड़, व अन्य मार्गों को यातायात हेतु सुगम बनाया जाए। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, इसमें कागज में लिखा हुआ है, वही होता है। इसके अलावा कुछ नहीं। अंकित नहीं होगा। 295 का सिस्टम है। आप वरिष्ठ सदस्य हैं। मंत्री रही हैं, अंकित नहीं होगा।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): 000

श्री अध्यक्ष: श्री विट्ठल शंकर अवस्थी।

भीलवाड़ा (पुर) में जिंदल शॉ द्वारा किए जा रहे विस्फोटों से मकानों में दरारें

श्री विट्ठल शंकर अवस्थी (भीलवाड़ा): अध्यक्ष महोदय, राजस्थान

(श्री विट्ठल शंकर अवस्थी)

विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख- विधान सभा क्षेत्र भीलवाड़ा के पुर स्थित वार्ड 1, 2, 3 एवं आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में जिंदल शॉ लिमिटेड द्वारा किये जो रहे विस्फोटों से मकानों में आ रही खतरनाक दरारों एवं जनहानि की संभावना बाबत्।

महोदय, उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र भीलवाड़ा में स्थित जिंदल शॉ लिमिटेड द्वारा किये जा रहे खनन में अवैध एवं नियम विरुद्ध विस्फोटों के कारण से शहर के पुर स्थित वार्ड 1, 2, 3, 4 एवं आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग एक हजार मकानों में खतरनाक दरारें आ गई हैं। लाखों रुपये की लागत से बने मकान दो हिस्सों में विभक्त हो रहे हैं। व्यक्ति को उम्र भर की कमाई से बनाये गये मकानों को छोड़कर अन्यत्र रहने को मजबूर होना पड़ रहा है। कई लोग मकान छोड़ चुके हैं। कभी भी जनहानि होने की प्रबल संभावना है। धर्मिक स्थलों, मन्दिरों, मस्जिदों में जो ऐतिहासक एवं सैकड़ों वर्ष प्राचीन स्थान हैं, उनमें भी दरारें आ गई हैं। सड़कें दो भागों में टूट चुकी हैं। प्रशासन को कई बार जनता द्वारा एवं स्वयं मेरे द्वारा इस बारे में अवगत कराया जा चुका है। एसडीएम, कलेक्टर, तहसीलदार, पुलिस प्रशासन वहां मौका मुआयना कर चुके हैं लेकिन समस्या निरन्तर जारी है। जनता आक्रोशित है एवं नुकसान की भरपाई की मांग कर रहे हैं। जिंदल शॉ के खनन में प्रयुक्त विस्फोटों के कारण से हो रही इस समस्या को जनता के आक्रोश के विस्फोट होने से पहले समाधान करने एवं नुकसान की जिम्मेदारी तय कर इसकी भरपाई सरकार सुनिश्चित करे अन्यथा व्यापक जन आन्दोलन जिंदल के खिलाफ खड़ा होगा एवं कानून व्यवस्था भी बिगड़ेगी। सरकार एवं प्रशासन कृपया इसे गम्भीरता से ले।

श्री अध्यक्ष: श्री खुशवीर सिंह।

फसल बीमा नियमों में शिथिलता

श्री खुशवीरसिंह (मारवाड़ जंक्शन): अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख के जरिए कृषि व उद्योग की ऋण नीति नियमों में दोहरा मानदण्ड के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय, उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि किसान अपनी पुश्तैनी जमीन को बैंकों में भूमि अधिग्रहण (रहन) करवाकर ऋण प्राप्त करता

(श्री खुशवीरसिंह)

है। साथ ही जमीन विशेष पर सर्वे/खसरा नम्बर का फसल बीमा करवाकर भी फसल नष्ट होने पर क्लेम का लाभ नहीं ले पाता है क्योंकि सरकार ने बीमा के मापदण्डों में पूरी तहसील को यूनिट माना है जबकि प्राकृतिक आपदा-ओलावृष्टि/अनावृष्टि/पाला, अतिवृष्टि की सीमा तय नहीं होती है।

इसी तरह वाहन बीमा नीति में विशेष वाहन नम्बर का बीमा होता है। उक्त विशेष वाहन को दुर्घटना पर बीमा क्लेम की राशि दी जाती है। ऐसी स्थिति में किसान को अपनी फसल नष्ट होने पर ऋण जमा नहीं कराने पर किसान के घर के आगे ढोल बजाकर भूमि कुड़क की जाती है।

दूसरी ओर उद्योग की स्थापना के लिए सरकार द्वारा ही भूखण्ड, ऋण, अनुदान पूर्ण उपलब्ध कराया जाता है। उक्त उद्योग पर सभी सुविधाएं लेने के बाद भी उत्पादन नहीं होने अथवा ऋण जमा नहीं होने पर भी सरकार उसे बीमारू उद्योग की श्रेणी में मानकर पुन: स्थापित करवाने के लिए सहायता देती है।

अध्यक्ष महोदय, एक देश में दोहरा कानून क्यों? कृषि को भी उद्योग का दर्जा दिया जाए साथ ही किसान के ऋण के लिए भूमि अधिग्रहण नियम समाप्त कर भूमि के खसरा नम्बर को आधार माना जाए क्योंकि गिरदावर/पटवारी द्वारा प्रत्येक खसरा नम्बर का भौतिक सत्यापन के बाद ही गिरदावरी रिपोर्ट दी जाती है। बीमा कम्पनियों द्वारा फसल नष्ट होने पर सर्वे/खसरा नम्बर को ही यूनिट मानकर बीमा क्लेम की राशि व प्राकृतिक आपदा से नष्ट फसल को सरकारी सहायता देकर किसानों के साथ न्याय करें। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री हरीश चन्द्र मीना।

देवली-उनियारा में बीसलपुर परियोजना से पेयजल उपलब्धता

श्री हरीश चन्द्र मीना (देवली-उनियारा): धन्यवाद, अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे मेरे क्षेत्र का महत्वपूर्ण विषय उठाने का नियम 295 के तहत आदेश दिया है।

अध्यक्ष महोदय, मेरे निर्वाचन क्षेत्र देवली-उनियारा में पेयजल की गम्भीर समस्या है। जैसा कि आपको विदित है कि राजस्थान का सबसे बड़ा मुख्य पेयजल स्रोत बीसलपुर बांध मेरे निर्वाचन क्षेत्र में स्थित है जो कि जयपुर, अजमेर सहित आधे से राजस्थान को पेयजल उपलब्ध कराता है और बड़े खेद का विषय है कि जहां राजस्थान के अधिकांश भू-भाग को बीसलपुर

(श्री हरीश चन्द्र मीना)

बांध का पेयजल मिल रहा है, देवली-उनियारा के अधिकांश गांव इस पानी से वंचित हैं।

मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि बीसलपुर बांध के पानी पर पहला हक वहां के स्थानीय निवासियों का है और उनकी मांग आपूर्ति करने के बाद ही इस पानी को राजस्थान के अन्य जिलों को दिया जाए।

अत: मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र देवली-उनियारा की जनता को आवश्यकतानुसार पेयजल उपलब्ध करवाएं ताकि जनता को यह महसूस हो सके कि एक भ्रष्ट एवं नकारा सरकार हट गई है एवं एक ईमानदार एवं कल्याणकारी सरकार का गठन हो चुका है। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री रामनारायण मीना।

सवाई माधोपुर से खातोली-बारां मुख्य मार्ग पर पुलिया निर्माण

श्री रामनारायण मीना (पीपल्दा): अध्यक्ष महोदय, सवाईमाधोपुर से खातोली-बारां मुख्य मार्ग पर चम्बल में झरेर नामक स्थान पर स्थित पुरानी पुलिया के स्थान पर नवीन पुलिया निर्माण करवाने के लिए प्रस्ताव अन्तर्गत नियम 295 के तहत निवेदन करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में सार्वजनिक आवागमन की सुविधाओं में बढ़ोतरी की जाने के लिए प्रमुख आवागमन के मार्गों का क्रमोन्नयन करके आवश्यकतानुसार स्थानों पर उच्च स्तरीय सड़कों एवं पुलों का निर्माण करवाया जाना आवश्यक है। पुराने समय से चले आ रहे सवाईमाधोपुर से खातोली होते हुए इटावा-बारां होकर मध्य प्रदेश निकल रहे मार्ग पर चम्बल नदी में झरेर नामक स्थान पर पूर्व की निर्मित पुलिया की लम्बाई-चौड़ाई कम होने से बारह माह आवागमन सुविधापूर्वक नहीं हो पा रहा है तथा थोड़ी सी बारिश में आवागमन अवरुद्ध हो जाता है, आवागमन नहीं हो पाता है।

चम्बल में झरेर नामक उक्त स्थान पर पूरी लम्बाई-चौड़ाई लेते हुए पुलिया निर्मित की जाने पर राजस्थान तथा मध्य प्रदेश निवासियों को आवागमन की पूर्ण सुविधा प्राप्त हो सकेगी तथा राष्ट्रीय राजमार्ग 550 से राज्य राजमार्ग 70 को जोड़ने से जयपुर-सवाईमाधोपुर होकर खातोली-इटावा-बारां होते हुए मध्य प्रदेश निकल रही सड़क को और अधिक उपयोगी बनाया जा सकेगा।

अत: विनम्र अनुरोध है कि झरेर नामक स्थान पर पुरानी के स्थान पर नई पुलिया निर्मित करवाई जाने की कृपा करें। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री रामलाल शर्मा।

ग्राम पंचायत सामोद स्थित राजोला बांध का पुनर्निर्माण

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख का प्रस्ताव।

अध्यक्ष महोदय, उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र चौमूं में ग्राम पंचायत सामोद में एक प्राकृतिक बांध, जिसको राजोला बांध के नाम से जाना जाता था। इस बांध के भरे रहने से आसपास के ग्राम सामोद, महार, कानपुरा, शोकलपुरा, झीडा, फतेहपुरा, सुल्तानपुरा, मोरीजा आदि गांवों में जलस्तर ऊपर रहता था तथा इस बांध में पशु-पक्षी भी पानी पिया करते थे। 1995 में तेज बारिश आने के कारण यह बांध पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो गया जिससे आसपास के गांवों के किसानों के कुएं भी सूख चुके हैं तथा उपरोक्त गांवों में खेती तो दूर की बात हो गई, पीने का पानी भी मिलना मुश्किल हो गया है।

अत: आपसे निवेदन है कि आप सरकार को तत्काल निर्देशित करें कि इस बांध को अविलम्ब पुन: निर्माण कराया जावे। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री फूल सिंह मीणा।

पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे

यू.आई.टी. उदयपुर ग्रामीण के पेरीफेरी एरिया के गांवों में पेयजल उपलब्धता

श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपका आभार व्यक्त करता हूं कि पर्ची के माध्यम से आज पहली बार बोलने का मौका मिला।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि यू.आई.टी. पेरीफेरी के गांव हैं उनके अन्दर यू.आई.टी. और एसडीओ कन्वर्ट कालोनियां इतनी बस गयी हैं, उन कालोनियों के अन्दर पानी की बहुत भारी समस्या है। यहां तक की वहां पर न तो ट्यूबवैल खोदे जा रहे हैं और न हैण्डपम्प, वहां पर पर्याप्त पानी मिल सके, वहां पानी में फ्लोराइड की बहुत ही ज्यादा मात्रा है, वो पीने योग्य पानी नहीं है।

(श्री फूल सिंह मीणा)

साथ ही, अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि बड़ी तालाब में पानी पर्याप्त है, मीठा पानी है मगर उसमें वहां बड़ी ग्राम पंचायत में भी पानी टंकी के माध्यम से नहीं देकर डाइरेक्ट नल से पानी दे रखा है, अवैध कनेक्शंस भी बहुत हैं और वहां पर ऊपर पानी चढ़ता नहीं है तो पर्याप्त पानी नहीं मिल रहा है। उस पंचायत में हवाला खुर्द और हवाला बड़ा में आज हैण्डपम्प खोदें तो 200 फीट तो क्या 400-500 फीट तक पानी नहीं है। इसलिए यहां पर पानी की बड़ी भारी दिक्कत होने की वजह से यहां पानी चाहिए।

साथ ही तीतरड़ी ग्राम पंचायत में दस-बारह कालोनी ऐसी बन गयी हैं, उन कालोनियों के अन्दर केवल और केवल जनता जल योजना के माध्यम से पानी दे रहे हैं, 15 हजार की आबादी तक पानी मिल सकता है मगर आज की तारीख में वो पंचायत इतनी बड़ी हो गयी हैं, उसकी जनसंख्या 20 हजार के आसपास है। हमारा जयसमंद का पानी भी वहीं से आ रहा है, उससे भी पानी दिला सकते हैं उससे भी नहीं दिलाया। वहां दूसरा कोई ऐसा उपाय नहीं है, पूर्व सरकार में एक मात्र टंकी बनी है जिससे पर्याप्त पानी नहीं मिल पा रहा है, कैसे उन कालोनियों में पानी दिलाया जा सके।

अध्यक्ष महोदय, पूर्व सरकार ने नाकोड़ा नगर, भैरव नगर और मुख्य मंत्री आवास के 1700 मकान भी बने हुए हैं और वहां पेयजल की इतनी भारी समस्या है, जिसमें पूर्व सरकार ने प्रयास भी किया और अभी ट्यूबवैल खोदने का भी आर्डर दिया, उसका भी काम चल रहा है, वो पानी, कब तक उन कालोनियों में पर्याप्त पानी मिल जायेगा? मीठे पानी की बहुत सख्त जरूरत है।

महोदय, साथ ही एक सीसारमा ग्राम पंचायत में अम्बाबाड़ी कालोनी है, उसमें 400-450 फीट हैण्डपम्प और हमने ट्यूबवैल का भी इंतजाम किया मगर वहां पर पानी नहीं आया और न पानी आता है। ग्राम पंचायत के पास में इतना पैसा नहीं है जो वहां उनको पानी दे दिया जाए। वहां पर बड़ी का तालाब से उदयपुर को पानी मिल रहा था और वो पाइपलाइन वहां से ही गुजर रही है, क्या उस पाइप लाइन को वापस चलाकर उन गांवों में पानी की पर्याप्त सुविधा होगी?

साथ ही, अध्यक्ष महोदय, बड़ी के तालाब से जो बड़ी ग्राम पंचायत में नल द्वारा पानी मिल रहा है वहां पर हमने पूर्व सरकार में 12 करोड़ की

(श्री फूल सिंह मीणा)

योजना बनाई थी, उसमें जो हमारे एम.एल.ए. साहब हैं गोगुन्दा के प्रताप जी, उन्होंने और हमने किया था मगर 12 करोड़ की वह योजना, सिंचाई विभाग ने पानी देने से मना कर दिया था इस वजह से हमारी वह योजना अटकी रह गई। क्या उस योजना को वापस चलाकर और बड़ी ग्राम पंचायत में, जो उसी गांव में यह तालाब बना हुआ है, उसमें टंकी बनाकर हवाला बड़ी में और बारह गांवों में पानी दिलाने का हो जायेगा तो माननीय मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं कि यह व्यवस्था कब तक हो जायेगी और नहीं, तो क्यों? धन्यवाद।

(13.00 बजे)

श्री अध्यक्ष: श्री बलजीत यादव।

कारखानों में स्थानीय युवाओं को रोजगार

श्री बलजीत यादव (बहरोड़): धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, चुनाव के वक्त चाहे कोई सी पार्टी हो, वह बड़े-बड़े दावे करती है कि बेरोजगार जवानों को सरकारी व प्राइवेट कंपनियों में रोजगार देंगे। लेकिन चाहे पिछली सरकार रही हो पांच साल, सरकारी नौकरी निकालती, लेकिन आईएएस अधिकारियों से कहकर किसी न किसी बहाने से, अपनी गलत मंशा के कारण, कोर्ट में चली जाए इसलिए कमी छोड़ दिया करती, जिससे बेरोजगार युवा भटकते रहे।

हमारे बहरोड़ के स्थानीय विधायक, रोजगार मंत्री थे। इसी सदन में उन्होंने कहा कि स्थानीय 30 हजार जवानों को नीमराणा की कंपनियों में रोजगार मिलेगा। जापानी सरकार से मैंने एमओयू साइन किया है। लेकिन एक ही जवान को रोजगार नहीं मिला। रोजगार न तो नीमराणा में मिला, न भिवाड़ी में मिला और न टपूकड़ा में मिला। मेरे अलवर जिले में ही नहीं, पूरे राजस्थान के किसी भी जवान को जो यह बाहर की कंपनियां हैं, रोजगार दे नहीं रही हैं। वहां किसी जवान से सर्टिफिकेट नहीं पूछा जाता है। ऐसा अंग्रेजों के काल में भी नहीं होता होगा। उससे यह पूछा जाता है कि आप रहने वाले कहां के हो? वह कहता है कि मैं बहरोड़ का रहने वाला हूं। मैं मुंडावर का हूं। किशनगढ़बास का, तिजारा का, अलवर जिले का या राजस्थान का रहने वाला हूं, तो गार्ड उसको गेट से बाहर भगा देता है कि आपको रोजगार नहीं मिलेगा। मैं कहता हूं कि यह राजस्थान के जवानों के साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है।

कोई भी सरकार आती है तो कहती है कि इंडस्ट्री लगाएंगे। क्या करें

(श्री बलजीत यादव)

ऐसी इंडस्ट्रीज का, जिन्होंने जमीन हमारी ले ली, पानी हमारी खींच लिया। डार्क जोन के नाम पर किसान को कुआं खोदने की अनुमति नहीं होती। ट्यूबवैल खोदने की अनुमति नहीं होती। बिजली कनेक्शन नहीं दिया जाता और उसकी जमीन छीन ली जाती है। किसान का जवान बेटा पढ़-लिख करके, डिग्री लेकर मेरिट में आने वाला बच्चा इंजीनियर बनकर के नौकरी मांगने जाता है तो कोई उसके सर्टिफिकेट नहीं पूछता है, उसको भगा दिया जाता है।

अध्यक्ष महोदय, चुनाव के समय नेता लोग बड़े-बड़े दावे करते हैं कि हम जनता के पाले में खड़े रहेंगे, जवान के पाले में खड़े रहेंगे, लेकिन सरकार बनने के बाद में देखने को मिलता है कि सब के सब पूंजीपतियों के पाले में खड़े नजर आते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट कराना चाहता हूं कि पिछली सरकार में जैसे हुआ, इस प्रकार से इस सरकार में ऐसा नहीं हो। जनता ने बड़ी उम्मीद के साथ आपको सत्ता में भेजा है। मैं आशा रखता हूं कि इस बार मेरे अलवर जिले के जवानों को, मेरे राजस्थान के जवानों को इन कंपनियों में रोजगार मिलेगा। मेरिट के आधार पर रोजगार दिया जाएगा।

अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस पार्टी ने घोषणा पत्र में कहा कि 3500 रुपया बेरोजगार को भत्ता दिया जाएगा। मैं मांग करता हूं कि तुरन्त बेरोजगारों को 3500 रुपया भत्ता दिया जाए। कोई भी मजदूर अगर अपने हक की मांग करता है, उसके साथ इन कंपनियों में इनजस्टिस होता है तो पुलिस के लोग गुंडों के साथ मिलकर के लाठी चार्ज करते हैं। झूठे मुकदमों में श्रमिकों को फंसा दिया जाता है। उनकी आवाज को दबाने का प्रयास किया जा रहा है, जैसा कि अंग्रेज सरकार किया करती थी।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि पहले की सरकार में जैसा हुआ वैसा नहीं करें, वरना जैसा पहले की सरकार के साथ जनता ने किया, कहीं ऐसा नहीं हो कि आपके साथ भी जनता ऐसा करे।

श्री अध्यक्ष: धन्यवाद। श्री सुरेश टाक।

श्री बलजीत यादव (बहरोड़): धन्यवाद, अध्यक्ष महोदय। डाइकिन कंपनी में अभी लाठी चार्ज हुआ।

श्री अध्यक्ष: धन्यवाद। श्री सुरेश टाक।

श्री बलजीत यादव (बहरोड़): अध्यक्ष महोदय, मैं 30 सैकिंड लूंगा। श्रमिकों पर झूठे मुकदमे दर्ज किए हैं। वे दर-दर की ठोकरें खाते घूम रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: हो गया, हो गया।

श्री बलजीत यादव (बहरोड़): उन्होंने यूनियन बनाई।

श्री अध्यक्ष: धन्यवाद। बात हो गई।

श्री बलजीत यादव (बहरोड़): हाई कोर्ट से मान्यता मिल गई।

श्री अध्यक्ष: श्री सुरेश टाक।

श्री बलजीत यादव (बहरोड़): उसके बाद झंडा लगाने पर बुरी तरह से उनके हाथ-पांव तोड़ दिए गए। मैं मांग करता हूं कि ऐसे पुलिस अधिकारियों के खिलाफ सरकार कठोर से कठोर कार्यवाही करे। उनको सस्पैंड करे। वह अधिकारी जमे हुए हैं। उनकी संपत्तियों की जांच करा लो, वह अरबों के मालिक हैं।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, अंकित नहीं होगा।

श्री बलजीत यादव (बहरोड़): 000

श्री अध्यक्ष: धन्यवाद। श्री सुरेश टाक।

किशनगढ़ नगर परिषद् में बकाया प्रकरणों का निस्तारण

श्री सुरेश टाक (किशनगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सर्वप्रथम आसन के प्रति अपना आभार प्रकट करना चाहूंगा कि मुझे पर्ची के माध्यम से आज सदन में प्रथम बार बोलने का अवसर दिया। मैं इस पवित्र सदन में मेरी किशनगढ़ विधान सभा से संबंधित नगर परिषद के जो प्रकरण हैं, उनके बारे में आदरणीय स्वायत्त शासन मंत्रीजी और राज्य सरकार का ध्यानाकर्षित करना चाहूंगा। मैं निवेदन करुंगा कि इन प्रकरणों का निस्तारण शीघ्रातिशीघ्र करें।

सबसे पहले तो मैं यह कहना चाहूंगा कि राजस्थान नगरीय क्षेत्र कृषि भूमि का गैर कृषि प्रयोजनार्थ उपयोग की अनुज्ञा एवं आवंटन नियम, 2012 के नियम 26 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार 12 वर्ष बाद भी निर्माण नहीं किए जाने के संबंध में भवन निर्माण स्वीकृति हेतु काफी प्रकरण प्राप्त हो रहे हैं। ऐसे प्रकरणों में प्रासंगिक आदेश के द्वारा बिन्दु संख्या 'ए' में निर्देश प्रदान किए गए हैं कि राज्य सरकार निर्माण अवधि, निर्धारित दर पर शास्ति जमा कराने की शर्त पर बढ़ा सकती है। इस परिषद क्षेत्र में काफी प्रकरण विचाराधीन हैं। अत: आपसे आग्रह है कि 12 वर्ष बाद जिन भूखण्डधारियों द्वारा निर्माण नहीं किया गया है, उनकी समय सीमा आगामी 2 वर्षों तक

(श्री सुरेश टाक)

बढ़ाने की कृपा करें, जिससे परिषद में प्राप्त प्रकरण और सम्पूर्ण प्रदेश में प्राप्त इस प्रकार के प्रकरणों से आम जन को राहत प्रदान की जा सके और नगर निकायों में प्राप्त राजस्व में भी वृद्धि हो सके।

दूसरा, मैं ध्यानाकर्षित करना चाहूंगा कि सरकारी भूमि नियमन के प्रकरणों का निस्तारण, नगर परिषद क्षेत्र में नगर परिषद के स्वामित्व की भूमियों पर आवासीय प्रयोजनार्थ किए गए अतिक्रमण को नियमित करने हेतु परिषद में 4600 प्रकरण विचाराधीन हैं। अतः इस संदर्भ में सरकारी नियमन हेतु स्पष्ट दिशा-निर्देश भी अपेक्षित है। मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री महोदय प्रशासन शहरों के संग की घोषणा कर चुके हैं, इस अभियान में इन प्रकरणों को जोड़ा जाए ताकि आम जन को राहत मिले।

नगर परिषद की विभिन्न आवासीय योजनाओं में निर्माण की अवधि बढ़ाने हेतु भी मैं आपसे निवेदन करुंगा कि इनमें जो आवंटन नगर परिषद के द्वारा किए जाते हैं, जिनकी नीलामी नगर परिषद के द्वारा की जाती है, ऐसे प्रकरणों में 2 वर्षों के बाद निर्माण स्वीकृति नहीं जारी की जाती है। मेरा निवेदन है कि ऐसे प्रकरणों में लीज राशि की वसूली और निर्माण स्वीकृति करने में बाधा आ रही है। पूर्व में ऐसे प्रकरणों के नियमितीकरण हेतु 31.03.2015 तक की अवधि थी, जिसे बढ़ाया जाना अपेक्षित है जिससे कि आम जन को राहत मिले।

अध्यक्ष महोदय, एक महत्वपूर्ण प्रकरण है खांचा भूमि का। मैं यह कहना चाहूंगा कि नगर परिषद क्षेत्र में आवेदकों द्वारा खांचा भूमि चाहने के आवेदन प्राप्त होते हैं। शिविरों में 150 वर्ग गज तक की खांचा भूमि दी जा सकती है। लेकिन अभी तक 100 वर्ग गज ही दी जा रही है। प्रशासन शहरों के संग अभियान में यह जो सीमा है इसको 150 वर्ग गज तक कर दी जाए, जिससे आम जन को राहत मिले और यह जो लम्बित पड़े प्रकरण हैं, इनका निस्तारण हो सके।

अध्यक्ष महोदय, ऐसे ही मामला किराया और लीज की दुकानों की नियमितीकरण की अवधि बढ़ाने का है। नगर परिषद क्षेत्र में विभिन्न स्थानों पर परिषद द्वारा किराये और लीज की दुकानें आवंटित की जाती हैं। जिसके संबंध में स्वायत्त शासन विभाग द्वारा दिनांक 5.10.2018 को आदेश क्रमांक 8ग/नियम/डीएलबी/18-20237 जारी किया गया। लेकिन दिनांक 31.12.2018 तक की अवधि में विधान सभा चुनाव आचार संहिता के कारण परिषद में

(श्री सुरेश टाक)

विचाराधीन प्रकरणों का निस्तारण नहीं हो सका। उक्त आदेश की भी अवधि में वृद्धि की जाए।

अध्यक्ष महोदय, विवाह स्थलों के संचालन और निर्धारित 60 फीट रोड को कम करने बाबत नगर परिषद क्षेत्र में विभिन्न स्थानों पर वर्षों से सामाजिक भवन, सामाजिक विवाह स्थल, धर्मशालाएं संचालित हैं, जो कि पूर्व में ही निर्मित हैं, अधिकांशत: 60 फीट की रोड से कम रोड पर संचालित हो रही हैं। विवाह समारोह रजिस्ट्रेशन हेतु विभाग द्वारा निर्धारित मापदंडों के अनुरूप मौका स्थिति नहीं होने से रजिस्ट्रेशन में बाधा आ रही है। अत: इसमें शिथिलता अपेक्षित है। समय-सीमा तय करके इसमें अवधि बढ़ाई जाए ताकि विवाह पंजीयन हो सकें। धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री अध्यक्ष: धन्यवाद। श्री मदन प्रजापत।

बालोतरा स्थित राजकीय महाविद्यालयों में रिक्त पद

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): अध्यक्ष महोदय, आपका आभार। मैं आपके माध्यम से माननीय उच्च शिक्षा मंत्रीजी से निवेदन करता हूं कि औद्योगिक एवं धार्मिक नगरी बालोतरा, जहां रिफाइनरी का काम भी चल रहा है, आने वाले समय में बालोतरा शहर और बढ़ने जा रहा है। मैं धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं विशेषकर युवाओं का, जिन्होंने मेरे प्रति भरोसा जताकर दूसरी बार मुझे राजस्थान की विधान सभा में युवाओं की पैरवी के लिए भेजा।

अध्यक्ष महोदय, भामाशाहों के सहयोग से बालोतरा में 2 कालेज, एक लड़कों का व एक लड़कियों का है। उन दोनों कालेज में काफी रिक्त पद हैं। इसमें गलती शायद पूर्व सरकार की नहीं है बल्कि जो हमारे पूर्व जन प्रतिनिधि थे, उन्होंने मंत्री प्रेम और गाड़ी प्रेम के कारण यहां आवाज तक नहीं उठाई। इससे क्या मालूम मैडम नाराज नहीं हो जाए। वह लड़कों और लड़कियों को आश्वासन देते रहे, अभी रिक्त पद भरे जाएंगे, अभी रिक्त पद भरे जाएंगे। हमारी नई सरकार आई है। हमारे लोकप्रिय मुख्य मंत्रीजी और पायलट साहब भी विराजमान हैं। माननीय मंत्रीजी के ऊपर मुझे पूरा भरोसा है कि वह युवाओं की भावनाओं की कद्र करते हुए दोनों कालेज में रिक्त पद भर देंगे। इसका मुझे पूरा भरोसा है। कई बार छात्रों ने आंदोलन किए और उनको सिर्फ भरोसे और आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिला। माननीय अध्यक्ष महोदय, करोड़

(श्री मदन प्रजापत)

रुपयों की लागत से दोनों कालेज का निर्माण, सौ प्रतिशत खर्चा भामाशाह परिवारों ने, दानदाताओं ने किया, मैं आज इस सदन में उन दोनों परिवारों का आभार व्यक्त करता हूं। डीडवानिया रामीदेवी, जसराज महिला गर्ल्स कालेज में, दोनों कालेज में प्रिंसीपल भी नहीं, लेक्चरर के सात-सात पद खाली हैं, दोनों में पीटीआई नहीं, इसलिए मैं आपके माध्यम से इनकी मांग करता हूं। इसके अलावा गर्ल्स कालेज में नया विषय, इतिहास का खोलने का भी निवेदन करता हूं। लड़कों के कालेज में विज्ञान संकाय खोला जाए और रिक्त पद तुरन्त भरने की मेहरबानी कराएं। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि। श्री बुलाकी दास कल्ला।

सदन पटल पर रखे गये पत्र

प्रतिवेदन एवं लेखे

श्री बुलाकी दास कल्ला (ऊर्जा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 395 के अंतर्गत निम्नांकित वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे सदन की मेज पर रखता हूं-

जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड का 18वां प्रतिवेदन वर्ष 2017-18

(1) जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड का 18वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2017-18,

राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड का 18वां प्रतिवेदन वर्ष 2017-18

(2) राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड का 18वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2017-18,

जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड का 18वां प्रतिवेदन एवं लेखा विवरण वर्ष 2017-18

(3) जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड का 18वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा विवरण वर्ष 2017-18, एवं

(श्री बुलाकी दास कल्ला)

राजस्थान राज्य विद्युत वितरण वित्त निगम लिमिटेड का तृतीय प्रतिवेदन एवं लेखा विवरण वर्ष 2017-18

(4) राजस्थान राज्य विद्युत वितरण वित्त निगम लिमिटेड का तृतीय वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा विवरण वर्ष 2017-18.

श्री अध्यक्ष: श्री परसादी लाल।

राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, जयपुर का लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2016-17

श्री परसादी लाल (उद्योग मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड अधिनियम, 1955 की धारा 34(3)(का) के अंतर्गत राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, जयपुर का लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2016-17 सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष: श्री प्रमोद भाया।

राजस्थान को-आपरेटिव डेयरी फैडरेशन लिमिटेड, जयपुर का 28वां प्रतिवेदन वर्ष 2017-18

श्री प्रमोद भाया (खान मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2001 की धारा 54(14) के अंतर्गत राजस्थान को-आपरेटिव डेयरी फैडरेशन लिमिटेड, जयपुर का 28वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2017-2018 सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष: श्री लालचन्द कटारिया।

राजस्थान स्टेट सीड्स कारपोरेशन लिमिटेड का 40वां प्रतिवेदन वर्ष 2017-18

श्री लालचन्द कटारिया (कृषि मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 के अंतर्गत राजस्थान स्टेट सीड्स कारपोरेशन लिमिटेड का 40वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2017-18 सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष: मास्टर भंवरलाल मेघवाल।

आयुक्तालय, विशेष योग्यजन राजस्थान का प्रगति प्रतिवेदन वर्ष 2017-18

मास्टर भंवरलाल मेघवाल (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से नि:शक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 की धारा 65 के अंतर्गत आयुक्तालय विशेष योग्यजन राजस्थान का वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन वर्ष 2017-18 सदन की मेज पर रखता हूं।

अभिभाषण

धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद

श्री अध्यक्ष: श्री महेन्द्रजीत सिंह मालविया (विभाजन संख्या 121), सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 18 जनवरी, 2019 को प्रस्तुत निम्नांकित प्रस्ताव पर अग्रेतर वाद-विवाद होगा:-

'इस सत्र में एकत्रित हम, राजस्थान विधान सभा के सदस्यगण, राज्यपाल द्वारा इस सदन में दिये गये अभिभाषण के प्रति उनके आभारी हैं।'

श्री नरेन्द्र बुडानिया।

श्री नरेन्द्र बुडानिया (तारानगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मुझे राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर अपना पक्ष रखने का मौका दिया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ किसानों, ग्रामीण क्षेत्र की समस्याओं, ग्रामीण क्षेत्र की बेरोजगारी के सम्बन्ध में बात करना चाहता हूं। अपने आपको मैं यहीं तक सीमित करता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे आश्चर्य होता है कि पिछली सरकार ने पांच साल के अंदर किसानों के बारे में कुछ नहीं किया। उनके लिए किसी प्रकार का कदम नहीं उठाया गया। किसानों की सुध क्यों नहीं ली, यह मेरे समझ के बाहर की बात है और किसानों की हालत इतनी खराब हो गई कि उनको आत्महत्याएं करने पर मजबूर होना पड़ा। ऐसा हुआ, हाड़ौती के अंदर 70 किसानों ने आत्महत्याएं कीं। मैं यह भी कह सकता हूं कि पूरे राजस्थान के अंदर सौ किसानों को अपने ऊपर चढ़े हुए ऋण के कारण आत्महत्या करने को मजबूर होना पड़ा।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): 15 का नाम बताओ।

श्री अध्यक्ष: माननीय मदनजी, आप सीनियर हैं।

श्री नरेन्द्र बुडानिया (तारानगर): आप धैर्य रखिए, सब बताऊंगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं हमारे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधीजी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने किसानों की समस्याओं को समझा और समस्याओं को समझकर उन्होंने उस पर ध्यान दिया। मैं हमारे मुख्य मंत्रीजी और उप मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि चुनाव जीतने के तुरन्त बाद, चुनाव जीतने के तुरन्त बाद उन्होंने किसानों का कर्ज माफ करने का निर्णय लिया।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सुन रहा था, मेरे सामने जो भाई बैठे हैं, नेता बैठे हैं उनको और तो कुछ सूझा नहीं, सिर्फ रोडमैप की बात करने लगे। मैं मेरे विपक्ष के भाइयों को कहना चाहता हूं कि रोडमैप भी आएगा, रोडमैप भी आएगा, थोड़ा धैर्य रखिए। वे किसान धन्यवाद भी देने आएंगे सरकार को, महोदय, सदन ने जो किसानों के हित में कदम उठाए, एक नई लहर पैदा हुई, कर्ज माफी तो एक छोटा-सा कदम है, हमारा किसान इस देश का सबसे मजबूत प्रहरी है और आज किसान को भगवान के भरोसे छोड़ रखा है, बहुत दु:ख होता है, जो हमारे लिए दिन-रात मेहनत करता है, हमारा पेट भरता है, लेकिन उनके बारे में कोई नीतियां नहीं बनतीं, उसको मजबूत करने के लिए कोई योजना नहीं बनती लेकिन हमारी सरकार पर मुझे पूरा भरोसा है कि वह किसानों को भगवान के भरोसे नहीं छोड़ेगी, आत्महत्या करने के लिए मजबूर नहीं होने देगी, ऐसी मेरी आशा है।

(13.19 बजे)

(श्री राजेन्द्र पारीक, सभापति, पदासीन)

दिलावर साहब, मदनजी, मैं आपको, माननीय सदस्य, आपने कुछ बातें पूछीं, उसका जवाब मैं जरूर दूंगा लेकिन आप तो अहंकार में रहे पांच साल तक, अहंकार में रहे और इस अहंकार का ही परिणाम आया है कि आपको सामने बैठना पड़ा। महोदय, मैं किसानों की बात कर रहा था कि किसान देश का बहुत बड़ा प्रहरी है। किसान का हमारे राजस्थान की जीडीपी में 30 प्रतिशत योगदान है और किसान आज...

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़): यह क्या बला है जीडीपी? थोड़ा खोल कर बताओ।

श्री नरेन्द्र बुडानिया (तारानगर): आपको जीडीपी के बारे में मालूम नहीं है तो मुझे बहुत ही अफसोस है माननीय सदस्य।

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़): मैं तो सिर्फ चौथी बार ही आया हूं।

श्री सभापति: माननीय सदस्य।

श्री नरेन्द्र बुडानिया (तारानगर): माननीय सभापति महोदय, किसान दिन-रात मेहनत करता है हमारे प्रदेश की उन्नति के लिए और हमारे प्रदेश के विकास के लिए लेकिन बहुत सी तकलीफें उसको सहन करनी पड़ती हैं। पिछले मानसून में राजस्थान के अन्दर बहुत कम बरसात हुई और मैं यह कह सकता हूं कि 9 प्रतिशत बरसात पिछले मानसून सत्र में कम हुई। महोदय, यह राजस्थान के लिए कोई नई बात नहीं है, राजस्थान इन चीजों से हमेशा जूझता रहा है और जब बरसात कम होती है तो हमारी उत्पादन क्षमता कम होती है। जब आये दिन बरसात कम होती है तो इससे हमको कैसे निपटना होगा, इसके लिए हमको कारगर तरीके से निपटना होगा और सबसे बड़ी बात है कि हमको सिंचाई क्षेत्र बढ़ाना पड़ेगा, हमें सिंचाई का रकबा पढ़ाना पड़ेगा तब जाकर हम किसान को मजबूत कर सकते हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): सभापति महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है अगर आप अनुमति दें तो। सभापति महोदय, माननीय सदस्य बोल रहे हैं, महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा हो रही है, बड़े महत्वपूर्ण सुझाव भी आपके आ रहे हैं। राज्यपाल का अभिभाषण एक तरह से नीति पत्र है और ट्रैजरी बैंचेज का हाल देखिए आप, जहां मंत्रियों के नाम पर दो विराजें हैं। मेरा तो आपसे आग्रह ही है कि इस सदन के अन्दर माननीय सदस्य अपनी बात कहे तो यहां रहें। आप आफिसर गैलेरी में देखिये, कभी मैंने इस तरह की अव्यवस्था नहीं देखी।

श्री बुलाकी दास कल्ला (ऊर्जा मंत्री): ऐसा है, आप भी अकेले बैठे रहते थे। वसुंधरा जी कभी यहां नहीं रहती थीं और आप अकेले लिखते रहते थे, हमने देखा है कई बार।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): मैंने व्यवस्था का सवाल खड़ा किया है। महेन्द्र जी, मेरे को कमप्लीट कर लेने दीजिए।

श्री महेन्द्र चौधरी (सरकारी उप मुख्य सचेतक): एक मंत्रीजी ही नहीं बैठे हैं, आप देखो एक मंत्रीजी हैं क्या? आप खुद देख लो, एक, दो, तीन चार। आप अगर मंत्रियों को जानते ही नहीं हो और ये पीछे बैठे हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): माननीय उप मुख्य सचेतक महोदय, आपको

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप सदन में सर्वाधिक बैठते हो पर सभापति महोदय, आफिसर गैलेरी में एक भी अधिकारी नहीं है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप इसकी चिन्ता न करें। आपने अपनी बात कह दी, मेरा अपना काम है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): एक भी अधिकारी नहीं है जो लिख रहा हो। मतलब कोई अधिकारी नहीं है, माननीय सदस्य के बड़े अच्छे सुझाव आ रहे हैं और कोई अधिकारी नहीं है। तीन जो अधिकारी बैठे हैं वो डिप्टी सैक्रेटरी स्तर के हैं। (व्यवधान)

श्री बुलाकी दास कल्ला (ऊर्जा मंत्री): माननीय मुख्य मंत्रीजी के अधिकारी बैठे हुए हैं।

श्री सभापति: राठौड़ जी, आप विराजें। अब आप विराजें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): आपकी प्रशंसा कर रहा हूं कि आप बैठते हो पर इनको भी हिदायत दो आप। आफिसर गैलेरी देखो आप। (व्यवधान)

श्री सभापति: कोई अंकित नहीं होगा।

श्री हनुमान बैनिवाल (खींवसर): 000

श्री सभापति: माननीय सदस्य। श्री नरेन्द्र बुडानिया।

श्री नरेन्द्र बुडानिया (तारानगर): माननीय सभापति महोदय, मैं किसानों की बात कर रहा था, सिंचित क्षेत्र बढ़ाने की बात कर रहा था, सिंचित क्षेत्र का रकबा बढ़ाने की बात कर रहा था। किसान उम्मीद करता है, किसान हमसे भी उम्मीद करता है और किसान मेरे सामने जो नेता लोग बैठे हैं उनसे भी उम्मीद रखता है लेकिन मैं यह महसूस करता हूं कि पिछले 5 वर्ष में किसानों के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया। महोदय, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जो हमारा चालू वित्त वर्ष है उसमें कृषि विकास के लिए 2600 करोड़ रुपये निर्धारित थे और 31 दिसम्बर, 2018 तक मात्र 1000 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं, यह हालत है अपनी। जो कृषि विकास का पैसा ही खर्च नहीं हुआ और मात्र 9 महीने में 46 प्रतिशत पैसा खर्च हुआ है। मैं ऐसा महसूस करता हूं कि किसान कमजोर है, किसान बोल नहीं सकता इसलिए उसके ऊपर उसके लिए बजट में पैसा तय होता है वो पैसा भी खर्च नहीं होता। हमारे बहुत ही युवा और बुद्धिमान कृषि मंत्री हैं, वो शायद अभी तो मौजूद नहीं हैं लेकिन वो नोट कर लें कि यह जो इस प्रकार की अव्यवस्थाएं हैं उनसे

(श्री नरेन्द्र बुडानिया)

निपटना होगा, ऐसा नहीं चलेगा। किसान इतना कमजोर भी नहीं है कि उसका बजट भी खर्च नहीं हो। महोदय, मैं यह बात भी कहना चाहता हूं कि अकेले कृषि उत्पादन से भी भला होने वाला नहीं है। इसके साथ-साथ हमें दोनों एंड की तरफ देखना पड़ेगा, कृषि का उत्पादन बढ़ाना और उसके लिए बाजार तैयार करना। उसके लिए बाजार तैयार नहीं होगा तो किसान को सही भाव नहीं मिल सकता। मैं मेरे एक्सपीरियंस से बता रहा हूं कि मेरे बीजेपी के साथी सोचें कि आपकी सरकार क्यों गई, मुझे इस पर बोलना नहीं है लेकिन मैं मध्य प्रदेश के बारे में बोलना चाहता हूं कि वहां पर किसानों ने जी-तोड़ मेहनत की, कृषि उत्पादन बढ़ाने में दिन-रात एक किया और उन्होंने उत्पादन बढ़ाया लेकिन शिवराज सिंह जी मार्केट तैयार नहीं कर सके। किसान को उसका भाव नहीं मिला और वहां का किसान निराश हो गया तथा निराश होकर उसने सरकार बदल दी।

महोदय, मैं यह भी बताना चाहता हूं कि भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में 50 प्रतिशत एम.एस.पी. बढ़ाने की बात कही थी। मैं राज्य सभा में रहा हूं और मैंने देखा है कि 4 साल तक एम.एस.पी. के ऊपर ध्यान नहीं दिया गया। जबकि होता यह है, आप रिकार्ड उठाकर देख लीजिए, यू.पी.ए. की सरकार में प्रत्येक वर्ष एम.एस.पी. बढ़ी है लेकिन इन चार साल तक नहीं बढ़ी।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): माननीय सदस्य, स्पष्ट करें कि कितनी-कितनी बढ़ी है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य।

श्री नरेन्द्र बुडानिया (तारानगर): मुझे क्यों टोक रहे हैं आप?

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): मैं तो जानकारी चाह रहा हूं।

श्री नरेन्द्र बुडानिया (तारानगर): दिलावर साहब, आप मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं। आप मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं। मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूं, मैं कोई आप पर आरोप नहीं लगा रहा हूं, मैं आप पर आरोप नहीं लगा सकता हूं।

श्री सभापति: नरेन्द्र जी बुडानिया का ही अंकित होगा। (व्यवधान) आप किधर देख रहे हैं? माननीय सदस्य।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): 000

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़): 000

श्री सभापति: माननीय सदस्य बुडानिया जी, आप उनसे बात नहीं करें, आसन से मुखातिब होकर अपनी बात रखें।

श्री नरेन्द्र बुडानिया (तारानगर): सभापति महोदय, एम.एस.पी. नहीं बढाकर हमारे किसान को बिचौलियों के हाथों में सौंप दिया। मुझे याद आता है 2014 का लोक सभा का चुनाव, हमारे देश के प्रधान मंत्री उस वक्त प्रधान मंत्री पद के उम्मीदवार थे, अपने एक खास दोस्त के जहाज में पूरे देश में घूमे। मुझे नाम बताने की आवश्यकता नहीं है, आप सब जानते हैं। उस दोस्त का काम क्या था? फूड-ग्रेन का रिटेल मार्केटिंग का व्यापार था। मेरा आरोप है कि चार साल तक नहीं बढ़ाकर अपने दोस्त को लाभ दिया। चार साल के बाद में आधे-अधूरे मन से.....

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): सभापति महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। हमारे नियमों में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि उच्च अधिकारी और उच्च पदों पर बैठे किसी भी व्यक्ति पर अगर कोई आरोप लगाते हैं तो नियम 273 के अन्दर नोटिस देकर आरोप लगाएं। तारानगर से आने वाले माननीय सदस्य राज्य सभा में रहे होंगे, राज्य सभा में किसी भी तरह कुछ भी उन्होंने किया होगा पर यह राजस्थान की विधान सभा है माननीय सदस्य। आप प्रधान मंत्री का नाम लेकर उनके मित्र.....

श्री सभापति: आसन अपने आप देख लेगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): नहीं, यह ठीक परम्परा नहीं है सभापति महोदय। वो एक्सपंज करा दीजिए।

श्री सभापति: आसन अपने आप देख लेगा, आप चिन्ता नहीं करें।

श्री नरेन्द्र बुडानिया (तारानगर): यदि मैं गलत बोला हूं तो सभापति को अधिकार है और वो गलत बात को हटा सकते हैं। लेकिन मैं जो बात कह रहा हूं और मैं यह बताना चाह रहा था कि चार साल के बाद जब एम.एस.पी. बढ़ाई तो उसकी प्रोपर मार्केटिंग नहीं हुई। इसलिए हमारे देश का किसान जो है वो बहुत पीछे चला गया। महोदय, कृषि उत्पादन, ग्रामीण रोजगार की दिशा में पिछले पांच साल में कुछ नहीं हुआ। गांव में बेतहाशा बेरोजगारी बढ़ी है। अभी बीएआरसी की रिपोर्ट आई है। बीएआरसी की रिपोर्ट में यह बताया गया है कि 2010 में बेरोजगारी की जो प्रतिशत थी वो 6.8 थी और अब 2018 में यह 6.8 से बढ़कर 15 प्रतिशत हो गई है जो बहुत ही चिन्ता का विषय है।

महोदय, नोटबंदी हुई देश के अन्दर, इस नोटबंदी से बहुत लोग

(श्री नरेन्द्र बुडानिया)

बेरोजगार हुए। इसका कृषि के क्षेत्र में भी, पशुपालन के क्षेत्र में भी, बागवानी के क्षेत्र में भी बहुत फर्क पड़ा। महोदय, हम लोग उद्योगों के खिलाफ नहीं हैं। देश में औद्योगीकरण होना चाहिए, लेकिन किसान के हक की कीमत पर नहीं। किसान का हक मारा गया तो किसान सहन नहीं करेगा इस बात को।

महोदय, मैं मनरेगा पर दो शब्द बोलना चाहता हूं। यह बहुत बढ़िया एक्ट बनाया। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं सोनिया गांधी जी को, मनमोहन सिंह जी को, जो देश के गरीब लोगों के लिए इस प्रकार की योजना बनाई। लेकिन, पिछले 5 सालों में मैंने देखा कि यह मनरेगा पोलिटिकल हथियार बन गई, राजनीति की भेंट चढ़ गई। 50 हजार परिवारों को 100 दिन तक का लाभ नहीं मिला, इस मनरेगा के अन्दर। आज ग्रामीण क्षेत्र में बहुत बेरोजगारी है। इसको ठीक करना होगा और मुझे विश्वास है हमारी सरकार के ऊपर कि वो इस पर पूरा ध्यान देगी।

महोदय, मैं यह महसूस करता हूं कि किसानों की भलाई के लिए, हमारा कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए आज जो सबसे जरूरी चीज है वो सिंचाई व्यवस्था पर है। अब मैं सिंचाई की व्यवस्था पर बात करना चाहता हूं तो मदन दिलावर साहब आप बता दीजिए 5 साल में एक इंच भी सिंचाई हुई कहीं पर, बढ़ाई, कहीं बढ़ोतरी हुई? आप बता दें कोई माननीय सदस्य, किसी क्षेत्र में एक इंच नहर बनी हो। 5 साल में कोई बांध बना हो...

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़): आप भी थोड़ा बखान कर दें कि आप क्या करोगे 5 साल में, कहां से पानी दोगे, यह व्यवस्था बताओ।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): परवन सिंचाई योजना को कितने साल पीछे धकेल दिया। राहुल गांधी जी से झूठा शिलान्यास कराकर वाहवाही लूटी और हाड़ौती के किसानों को दर-दर की ठोकरे खाने के लिए मजबूर कर दिया। आप मेरे से पूछ रहे हो तो सुनो...

श्री सभापति: माननीय सदस्य, मेरा आपसे आग्रह है कि आप क्यों इन्वाइट करते हो। आप अपनी बात रखिये।

श्री नरेन्द्र बुडानिया (तारानगर): सिंचाई के लिए कोई नया तंत्र विकसित होना, सिंचाई के लिए कोई नया तंत्र विकसित नहीं हुआ तो हम सिंचाई के क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ सकेंगे।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): सभापति महोदय, बाले-बाले सरकार को बने

(श्री रामलाल शर्मा)

हुए 4 दिन ही हुए हैं और सभापति महोदय 4 दिन के अन्दर ही ये सिर्फ 1 मंत्रीजी विराजें हैं। इतनी बुरी स्थिति।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, प्लीज आप विराजें, आप विराजें।

श्री नरेन्द्र बुडानिया (तारानगर): महोदय, अभी में सिंचाई के ऊपर आना चाहता हूं और सिंचाई के ऊपर..

श्री सभापति: वार्ता नहीं, कृपया शांति रखिए।

श्री नरेन्द्र बुडानिया (तारानगर): इंदिरा गांधी नहर परियोजना, यमुना जल समझौता, ईस्टर्न कैनाल प्रोजेक्ट हमारे परवन परियोजना, हमारे ब्राहमणी, हमारे ईसरदा...

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): आप लाए क्या ये दोनों परियोजना..

श्री नरेन्द्र बुडानिया (तारानगर): मैं इसके ऊपर बोलना चाहता हूं।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आपको अवसर मिलेगा।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): गंगा जी का सौगंध है सच बोलना, बृहद परवन परियोजना आप लाये थे क्या?

श्री नरेन्द्र बुडानिया (तारानगर): मैं तो यह समझाना चाहता हूं कि जब आपका अवसर आए, तो आपकी बात करना। मुझे क्यों टोक रहे हैं बीच में।

श्री सभापति: विराजें आप। आप विराजें।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): क्योंकि आप हमें गिना रहे हैं। असत्य ना बोलें सदन में। ये बृहद परवन परियोजना भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाई है, माननीय वसुंधरा जी के नेतृत्व में। ये असत्य बयान न करें।

श्री गोपाल लाल मीना (जमवारामगढ़): डैम भी बताएंगे, पानी भी कहां से लाएंगे।

श्री नरेन्द्र बुडानिया (तारानगर): महोदय, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, ध्यान से सुनो भाई बहुत इम्पोर्टेंट बात है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना राजस्थान की बहुत बड़ी परियोजना है और इस परियोजना में 19.63 हैक्टेयर सिंचित क्षेत्र रखा गया है।

महोदय, 1981 के अन्दर एक अन्तरराज्यीय समझौता हुआ था। उस

(श्री नरेन्द्र बुडानिया)

समझौते के तहत रावी, व्यास, सतलुज इस नहर का जो अधिशेष पानी था उस पानी को राजस्थान में लाना था। उसके लिए 8.6 एमएएफ पानी हमारे राजस्थान के लिए तय हुआ था। मुझे यह कहते हुए बड़ा अफसोस है सरकारें आती हैं, जाती हैं, लेकिन हमारा 8.6 एमएएफ पानी, वो भी पूरा न मिलकर के 8.0 एमएएफ पानी मिल रहा है। हमारे 0.06 एमएएफ पानी नहीं मिल रहा है। कितना नुकसान किया।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): ये पाप किसने किया। 1981 में तत्कालीन मुख्य मंत्री शिवचरण जी माथुर हमारा 0.06 एमएएफ का हिस्सा छोड़कर आये थे। ये पाप उन्होंने किया जो आज तक भुगत रहे हैं हम।

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़): नहीं-नहीं, आपका कथन सत्य है। नहीं-नहीं आप बड़े मन से बोल रहे हो, कथन बड़ा सत्य है।

श्री नरेन्द्र बुडानिया (तारानगर): मैं किसान के लिए बोल रहा हूं तो आपको छोटी-मोटी बातों पर टीका-टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। आप बात को समझें, मैं आगे बढ़ूंगा तो कई बातें सामने आएंगी कि किसने-किसने क्या किया। मेरे मन में यह तकलीफ है कि किसान को पानी जो समझौते में स्वीकृत है, वो पानी हमें क्यों नहीं मिल रहा, मिलना चाहिए पानी हमें। आज माननीय राजेन्द्र सिंह जी राठौड़ साहब, मैं आपको बताना चाहता हूं कि पंजाब सरकार ने एक एक्ट बनाया विधान सभा के अन्दर और उसको हमारे इस समझौते के अन्दर पानी नहीं देने की कोशिश की, लेकिन उनकी चली नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया।

महोदय, मैं एक बात और बताना चाहता हूं कि सन् 2005 में राजस्थान के अन्दर वसुंधरा जी की सरकार थी। किसान सोच रहे थे इतनी बडी मैजोरिटी थी, किसान सोच रहे थे अब हमारे हित में काम होगा, हमारी भलाई के लिए काम होगा। मुझे बहुत निराशा है कि 2005 में सरकार ने 5.40 लाख हैक्टेयर सिंचित जमीन में से 3.5 लाख हैक्टेयर की कटौती कर दी। जहां किसान ये मानकर चल रहा था कि उसका सिंचाई का रकबा बढ़ेगा, उसका पानी बढ़ेगा लेकिन बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण कदम ये 3.5 लाख हैक्टेयर जमीन असिंचित कर दी और महोदय, इस 3.5 लाख हैक्टेयर में 2.0 लाख हैक्टेयर जमीन हमारी 6 लिफ्ट कैनाल योजनाएं हैं। 2 लाख हैक्टेयर लिफ्ट कैनाल योजनाओं की सिंचित जमीन को असिंचित करने का निर्णय लिया। मुझे बहुत दु:ख है कि आप इस 2 लाख हैक्टेयर सिंचित जमीन जो काटी है आपने उसमें

(श्री नरेन्द्र बुडानिया)

से 1 लाख 38 हजार हैक्टेयर सिंचित जमीन जो कुम्भाराम साहवा लिफ्ट कैनाल की है। वह दो लाख तो आपने पूरे 6 लिफ्ट कैनाल्स में काटी और दो लाख में सिर्फ 1 लाख 38 हजार आपने तारानगर, राजगढ़, सरदारशहर के लिए काट के यहां के किसानों के साथ में धोखा किया। यह मेरा आरोप है। यह क्यों काटा गया रकबा? कांग्रेस के जमाने में तय हुआ। एक सपना लिया गया किसान के लिए, लेकिन साहवा लिफ्ट कैनाल का 1.38 लाख हैक्टेयर रकबा काट करके किसान के साथ अन्याय किया है। मैं निवेदन करना चाहता हूं...।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): बुडानिया जी, 2008 से 2013 तक आप थे न, जोड़ देते और अब जोड़ दो।

श्री नरेन्द्र बुडानिया (तारानगर): आप इस बात पर नहीं सोच रहे कि आपने रकबा काटा है। रकबा आपने काटा कि नहीं काटा वह बता दो मुझे?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): हमने गुनाह किया उसका भुगत रहे हैं, पर अब जोड़ दो आप और 2008 से 2013 तक कौन सा मीर मार लिया, यह भी देख लो कागजों में जरा।

श्री नरेन्द्र बुडानिया (तारानगर): मैं विनम्र निवेदन करना चाहता हूं हमारी सरकार से, हमारे मुख्य मंत्रीजी से। मेरे चुनाव प्रचार में गये थे गहलोत साहब। उनके सामने बात चली यह। हजारों किसानों ने कहा कि हमारे साथ में अन्याय हुआ है। हमारा जो कांग्रेस के वक्त में नक्शा डिजाइन हुआ, जो जमीन तय हुई उसमें से 1 लाख 38 हजार हैक्टेयर जमीन काट दी गई। मुझे पूरा विश्वास है। मुझे विश्वास है इस वर्तमान सरकार के ऊपर कि वह इस दिशा में सोचेगी और कटे हुए रकबे को वापस लेगी। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजें आप। Let him complete.

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): सभापति महोदय, सरकार कितनी संवेदनशील है यह हमारे को दिख रहा है। एक भी अधिकारी सरकार तक हमारी बातें पहुंचाने के लिए नहीं बैठा हुआ है फिर बोलकर क्या करेंगे? सभापति महोदय, कम से कम सरकार को आप निर्देशित तो करें कोई हमारी बात को लिखे तो सही। सरकार तक पहुंचाये तो सही।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): पांच साल बैठे रहे किया कुछ नहीं। बार-बार बोल रहे हैं। (व्यवधान)

श्री अभिनेश महर्षि (रतनगढ़): सभापति महोदय, हमारी बात को सुनने वाला कोई नहीं बैठा है।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): ...(व्यवधान) कोई सुनने वाला नहीं है। कोई अधिकारी गैलेरी में लिखने वाला नहीं है। कैसे पहुंचेगी हमारी बात?

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): आंकड़ों में काम किया इन्होंने। माननीय सदस्य को बोलने नहीं दे रहे हैं।

श्री अभिनेश महर्षि (रतनगढ़): कोई सुनने वाला नहीं है। कोई लिखने वाला नहीं है इस सरकार में।

श्री सभापति: माननीय सदस्य।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): सभापति महोदय, इन्होंने आपकी ही नहीं सुनी, हमारी क्या सुनेंगे। इन्होंने आपकी ही नहीं सुनी।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप विराजें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): माननीय सभापति महोदय, यह बात वास्तव में सही है कि ऐसा नजारा पहली बार देख रहे हैं। इतना अच्छा बोल रहे हैं माननीय सदस्य।

श्री सभापति: मैं जब भी देख रहा हूं आपके इशारे पर ही उठते हैं सारे लोग।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): एक डिप्टी सैक्रेटरी स्तर का अधिकारी बैठा है और इतने दमदार उप मुख्य सचेतक बैठे हैं। आप अपने अधिकार का उपयोग क्यों नहीं करते हो, उप मुख्य सचेतक महोदय। सारे अधिकारी यहां होने चाहिए। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर, नीति पत्र पर चर्चा हो रही है। आप उपयोग करें अपने अधिकारों का।

श्री सभापति: आप विराजें। प्लीज।

श्री नरेन्द्र बुडानिया (तारानगर): सभापति महोदय, मेरे बहुत प्रिय मित्र राजेन्द्र जी राठौड़ साहब विराजें हुए हैं।

श्री सभापति: आप इधर से मुखातिब हों और इधर से ही आप बात करें अपनी। फिर इन्वाइट मत करें आप उनको। मुझे बंद करना पड़ेगा माननीय सदस्य, आप उन्हें इन्वाइट न करें। आप अपनी बात रखें।

श्री नरेन्द्र बुडानिया (तारानगर): हम सब मिलकर के, पक्ष और विपक्ष के सब मिल करके हमारा जो यह नुकसान हुआ है तारानगर, सरदारशहर और राजगढ़ के किसानों के साथ में, मैं समझता हूं कि इस सरकार के अन्दर यह

(श्री नरेन्द्र बुडानिया)

कटा हुआ रकबा जो कांग्रेस ने ही जोड़ा था, कांग्रेस इसको वापस जोड़ने का आदेश करेगी। ऐसा मैं सोचता हूं।

सभापति महोदय, एक बात और कहना चाहता हूं कि यह 1.38 रकबा कटने के बाद में हमारे पास में 1.02 लाख हैक्टेयर सिंचित रकबा बचा है और इसमें से 1 लाख हैक्टेयर पर निर्माण कार्य स्वीकृत हुआ है और इसमें से 92 हजार हैक्टेयर जमीन पर निर्माण कार्य कर सिंचाई की सुविधा प्राप्त हुई है। शेष जो स्वीकृत है उसमें भी बीस हजार हैक्टेयर हमारी जमीन का काम अधूरा पड़ा है। यह तो राठौड़ साहब जानते हैं इन्होंने चुनाव के वक्त में टैण्डर निकलवाये थे। टैण्डर हुए थे चुनाव के वक्त में। महोदय, मैं मुख्य मंत्रीजी से मांग करता हूं कि अपने इस बजट सत्र में जब वे बोलें तो यह जो निर्माण कार्य हमारा बचा हुआ है। हमारा जो 1 लाख 38 हजार हैक्टेयर जमीन रकबा जो असिंचित कर दिया बीजेपी की सरकार ने, उसको वापस सिंचित करें और जो हमारा रकबा अभी स्वीकृत है। 20 लाख हैक्टेयर जो अभी निर्माण हुआ नहीं, बंद है, उसको आप बजट में घोषणा करें कि इसको हम तुरन्त चालू करेंगे। यह मेरा निवेदन है।

सभापति महोदय, मैं यमुना जल समझौते पर बात करना चाहता हूं। मैं यह समझता हूं कि यमुना जल समझौता बहुत अच्छा कदम है और मुझे खुशी होती कि पिछले पांच साल में बीजेपी की सरकार इसको एग्जीक्यूट करा पाती। मैं 1994 में मैं विधान सभा का सदस्य था। उस वक्त यह समझौता हुआ था और इतने लम्बे समय के बाद में इसकी कोई सुध नहीं ली गई। यदि पहले की सरकार पांच साल में कुछ कदम उठाती तो आज चूरू, झुंझुनूं, सीकर के लोग प्यासे नहीं रहते, लेकिन कोई कदम नहीं उठाया।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, कृपया जब कोई अपनी बात रख रहा हो तो आप आसन के और उसके बीच में नहीं आयें। आप नये सदस्य हैं, आगे से इस बात का ध्यान रखें।

श्री नरेन्द्र बुडानिया (तारानगर): मैं नया नहीं हूं, माननीय सभापति महोदय।

श्री सभापति: आपको नहीं कह रहा हूं मैं। माननीय वेद प्रकाश जी, आगे से ध्यान रखें' जब कोई वक्ता बोल रहा हो तो आसन के और उसके बीच में से नहीं आयें। मैं सभी माननीय सदस्यों से जो नये आये हैं उनसे आग्रह करना चाहूंगा कि जब कोई वक्ता बोल रहा हो अपनी बात तो आसन के और

(श्री सभापति)

उसके बीच में नहीं आयें। आप पीछे से गुजरें। (व्यवधान) आप चुप रहें। शान्त रहें आप।

श्री नरेन्द्र बुडानिया (तारानगर): सभापति महोदय, यह यमुना जो जल समझौता है उससे शेखावाटी को पानी मिलना है। सभापति महोदय, आपका जिला भी उसमें शामिल है और इतना महत्वपूर्ण समझौता है इसको एग्जीक्यूट नहीं करा पाये। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं मुख्य मंत्रीजी को कि मुख्य मंत्री बनते ही जब प्रथम बार वे दिल्ली गये तो वहां पर केन्द्रीय मंत्री से मिलकर के इसका एग्रीमेंट करवाया। उसको एग्जीक्यूट करने की बात कही। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि ये 1994 में लटकी यह रेणुका जी बांध परियोजना पर अब जाकर समझौता हुआ है। धन्यवाद है मुख्य मंत्रीजी का।

सभापति महोदय, अब मैं ईस्टर्न कैनाल के बारे में बात करना चाहता हूं। यह बहुत महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है। इसमें कुन्नू, कूल, पार्वती, कालीसिंध और मेज नदियों के सरप्लस वाटर को बाढ़ के हालात में बनास, मोरेल, बाणगंगा, कालीसिल, गम्भीर, पार्वती नदियों में डाइवर्ट करना था और इसमें 13 जिले आते हैं। बहुत बड़ी परियोजना है। 13 जिलों में झालवाड़, बारां, कोटा, बूंदी, सवाईमाधोपुर, अजमेर, टोंक, जयपुर, दौसा, करौली, अलवर, भरतपुर, धौलपुर में पानी की समस्या का समाधान हो सकता है इस प्रोजेक्ट से, लेकिन अभी इतनी बड़ी महत्वपूर्ण परियोजना का सिर्फ परीक्षण ही हो रहा है जबकि सीडब्ल्यूसी ने इस पर अपनी आब्जर्वेशन भी दे दी है। अब इतने दिन राज्य सरकार क्या करती रही मुझे तो मालूम नहीं, लेकिन इतनी महत्वपूर्ण परियोजना पर कोई किसी प्रकार का एक्ट नहीं यह मुझे तकलीफ है। मैं निवेदन करना चाहता हूं राजस्थान सरकार से कि इस परियोजना पर जल्दी ही कोई निर्णय हो और इसमें इर्रिगेशन कंपोनेंट को भी ध्यान में रखा जाए। हमारे किसान भी उम्मीद करते हैं कि इर्रिगेशन कंपोनेंट भी इस परियोजना में शामिल हो।

सभापति महोदय, अब मैं परवन पर आता हूं। यह बारां, बूंदी और झालावाड़ के लिए सिंचाई क्षमता को बढ़ाने के लिए यह माननीय अशोक गहलोत साहब का ड्रीम प्रोजेक्ट है और 2013 में...

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): यह असत्य है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप विराजें।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): इसकी खोज हमने की है। कांग्रेस तो 70 साल तक खोज ही नहीं पायी कि परवन सिंचाई परियोजना का पानी लोगों को मिल सकता है क्या। इनके दिमाग में ही नहीं आया था। यह खोज हमने की है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप विराजें। आप इतने वरिष्ठ सदस्य हैं।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): माननीय सभापति महोदय और ये श्रेय लेना चाहते हैं और यहां सदन में असत्य बात कहना चाहते हैं। यह हमारे द्वारा..

श्री सभापति: विराजें। माननीय सदस्य, अंकित नहीं होगा।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): 000

श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): 000

श्री सभापति: विराजें आप, विराजें आप। एक मिनट माननीय सदस्य, मेरा आप सभी से आग्रह है राज्यपाल के अभिभाषण पर बोलने वाले काफी वक्ता हैं, आप एक दूसरे से वार्तालाप में समय खराब करेंगे तो आसन का तो 5 बजे तक का समय है। जब आपको अवसर मिले तब आप अपनी बात कह देना। आप इतने वरिष्ठ हैं, मेहरबानी रखें थोड़ी। सदन यदि शांतिपूर्वक चलेगा तो अच्छा लगेगा और खास तौर से जो पहली बार माननीय सदस्य आये हैं, उनको बोलने का अवसर मिलेगा और आप अगर इस तरह से इंटरवीन करेंगे तो कैसे अपनी बात रख पाएगे। (व्यवधान) आप विराजें, आसन को पता है क्या कहना है, आप विराजें। सभी माननीय सदस्य इस बात का ध्यान रखें, टोका-टाकी नहीं करें, प्लीज।

श्री नरेन्द्र बुडानिया (तारानगर): सभापति महोदय, मैं परवन परियोजना पर बात कर रहा था और मैं यह भी कह रहा था कि यह मुख्य मंत्रीजी का ड्रीम प्रोजेक्ट है और मैं यह भी कह रहा था कि सन् 2013 में माननीय राहुल गांधी जी ने शिलान्यास किया, इस बहुत महत्वपूर्ण परियोजना का। सरकार बदल गई, इन्होंने दुबारा शिलान्यास किया, पर काम को एक इंच भी आगे नहीं बढ़ाया। हां, एक काम इन्होंने जरूर किया कि इस परियोजना का 30 फीसदी पानी यानी 55 मिलियन क्यूसेक मीटर ...

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): 000

श्री नरेन्द्र बुडानिया (तारानगर): 50 मिलियन क्यूसेक मीटर पानी

(श्री नरेन्द्र बुडानिया)

अडाणी जी को देने पर समझौता हो गया। देखिए, कितना बड़ा काम किया है। 55 मिलियन क्यूसेक मीटर पानी का इन्होंने अडाणी जी के साथ समझौता कर दिया और इसमें 16 मिलियन क्यूसेक मीटर पानी वाइल्ड लाइफ के लिये फिक्स कर दिया जो क्रोकोडाइल पार्क के लिये जाना था। महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं, सरकार के ध्यान में लाना चाहता हूं कि किसान का हक नहीं मरे। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): 000

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप इतने वरिष्ठ सदस्य हैं, आप विराजें। माननीय श्री मदन दिलावर जब भी बोले मेरे आदेश के बिना, कृपया अंकित नहीं करें। मुझे आपको बार-बार कहना पड़ रहा है।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): 000

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आपका व्यवहार अच्छा नहीं है। आप मेहरबानी रखें।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): 000

श्री सभापति: नहीं, नहीं, आपको इजाजत दे रहा हूं, प्लीज विराजो आप। मेरा आपसे आग्रह है, आप इतने वरिष्ठ सदस्य हैं, हम और आप 1990 में आये थे, आप भूल गये, विराजें आप। आप बहुत ऊर्जावान हैं, जब आपको अवसर मिले तब बोलना, पता लग जायेगा कितना बोलते हैं आप। प्लीज, बीच में मत बोलें।

श्री नरेन्द्र बुडानिया (तारानगर): महोदय, अडाणी जी ने इतना ही नहीं किया, पिछली सरकार से मिलकर 16 मिलियन क्यूसेक मीटर पानी के आगे भी चैक बांध बना दिया ताकि वह पानी आगे नहीं जा सके। वहां भी ठगी हो रही है, पानी के ऊपर डाका पड़ रहा है। मैं हमारी सरकार से कहना चाहता हूं कि इस डाके को रोकिए। यह किसान के साथ अन्याय है और मैं समझता हूं कि इस पर तुरन्त कार्यवाही होगी, ऐसा मेरा विश्वास है।

महोदय, एक बात और कहना चाहता हूं कि इस परियोजना में स्प्रिंकलर का उपयोग करने का निर्णय लिया है। महोदय, आप भी वहां गये हैं, मैं भी गया हूं वहां की जो मिट्टी है वह ब्लैक कॉटन है। वहां जब फ़व्वारे से पानी लगता है तो उसके ऊपर एक परत जम जाती है, वह पानी नीचे नहीं जाता है, फसल को कोई फायदा नहीं होता है। हां, आपके और हमारे जैसे

(श्री नरेन्द्र बुडानिया)

एरिये में तो कितना ही फ़व्वारे से पानी लगाओ, वहां फव्वारा पद्धति सक्सेसफुल है। मैं कहना चाहता हूं कि किसान इसके लिये आंदोलन भी कर रहे हैं। बार-बार किसानों ने आंदोलन भी किया है लेकिन पिछली सरकार ने एक भी नहीं सुनी। मेरी गुजारिश है कि किसानों की सुनी जाये और वाइल्ड लाइफ के रिजर्व पानी पर अडाणी जी के डाके को तुरन्त रोका जाए।

अब मैं बात करता हूं ब्राह्मणी और ईसरदा पर। महोदय, मैं इन दोनों परियोजनाओं पर बहुत संक्षिप्त में मेरी बात रखना चाहता हूं। दोनों परियोजनाओं में पिछले पांच साल से कुछ नहीं हुआ। ब्राह्मणी पर तो अभी डीपीआर ही बन रही है। महोदय, मैं ड्रिंकिंग वाटर के लिये बनी इन दोनों महत्वपूर्ण योजनाओं में मैं किसानों का हित भी देखना चाहता हूं। इन ड्रिंकिंग वाटर की योजनाओं के साथ इर्रिगेशन कम्पोनेंट भी किसानों के लिये रखा जाये, यह मेरा निवेदन है।

महोदय, मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि हमारी सरकार बनते ही हमारे गरीबों के लिये, किसानों के लिये तत्परता से सोचा गया है और मैं मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहता हूं, सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने अपने घोषणा पत्र को तुरन्त चीफ सैक्रेटरी को सौंप दिया, यह बहुत बड़ा कदम है। मुख्य मंत्रीजी ने अनाउंस किया कि किसानों का पांच साल तक बिजली का बिल नहीं बढ़ेगा, यह एक सराहनीय कदम है। महोदय, वृद्धावस्था पेंशन भी आपने बढ़ाई, यह भी बहुत महत्वपूर्ण कदम है।

एक दो बातें और हैं, अब मूंग की खरीद चल रही है, वह बहुत धीमी है। सरकार को इस पर तुरन्त ध्यान देना चाहिये। किसान दुःखी नहीं हो, उनको फसल का सही भाव मिल सके, इसलिए इस पर तुरन्त कार्यवाही होनी चाहिये। महोदय, मैं समझता हूं कि नई सरकार से बड़ी अपेक्षाएं हैं। आज चाहे किसान हो, नौजवान हो, गरीब हो, छोटा व्यापारी हो, सबके सब इस सरकार की तरफ देख रहे हैं और मुझे विश्वास है कि मैंने जो बातें बोली हैं उससे किसी को दुःख हुआ हो तो मैं उसके लिये तो क्या कर सकता हूं, मैंने तो किसानों की बात को बोला है। जहां तक मैंने एक आधा आरोप भी लगाया है तो यह मैंने महसूस किया है जहां किसान के साथ अन्याय हुआ है। महोदय, हमारी आंखों के आगे अन्याय हो रहा है। क्या कुम्भाराम लिफ्ट कैनाल का रकबा काट दिया है? क्या तकलीफ नहीं होगी किसान को? क्या उस क्षेत्र में

(श्री नरेन्द्र बुडानिया)

रहने वाले लोगों को तकलीफ नहीं होगी? वहां किसान का गला काट दिया। आपने आने वाली पीढ़ियों के पेट पर लात मार दी। यह जुर्म किया बीजेपी की सरकार ने, मैं यह आरोप लगाता हूं और मैं उम्मीद करता हूं वर्तमान सरकार से और मुख्य मंत्रीजी से कि जो निर्माण कार्य बचा है उसको तुरन्त अगले बजट में शामिल करेंगे और कटे हुए 1.38 लाख हैक्टेयर जमीन को जो असिंचित कर दिया, उसको सिंचित करेंगे, यही बात कह कर मेरी बात समाप्त करता हूं, बहुत-बहुत धन्यवाद।

(14.00 बजे)

श्री सभापति: श्री मदन दिलावर।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): माननीय सभापति महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा हो रही है। मैं भी इसमें शामिल हो रहा हूं। मैं ऐसे क्षेत्र से आता हूं जो पत्थर की चमक और धनिये की सुगंध पूरे देश में फैलाता है। माननीय सभापति महोदय, मेरे घर पर शनिवार के दिन लगभग 50-60 युवा आये और उन्होंने कहा कि दिलावर जी हमारे 3500 रुपये कब मिलेंगे? मैंने कहा कि 3500 रुपये कौनसे? तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस के घोषणा-पत्र में है। हमको प्रतिमाह मिलने वाले थे। कांग्रेस की सरकार ने यह घोषणा की थी। मैं उठकर अंदर गया। राज्यपाल महोदय का अभिभाषण उनको दिखाया। उल्टा-पुल्टा, दांये से-बांये से कई बार देखा और उनको पढ़ाया कि इसमें तो कुछ भी नहीं है। तो उन्होंने कहा कि क्या हमको धोखा देने के लिये इस प्रकार की बात कही गयी थी? क्या युवाओं का अपमान करने के लिये इस प्रकार की बात कही गयी थी? क्या हमको ठगने के लिये इस प्रकार की बात कही गयी थी? हम सोच रहे थे कि लाखों की संख्या में जो बेरोजगार हैं उन लोगों को 3500 रुपया प्रति माह भत्ता मिलेगा, लेकिन कहीं पर उल्लेख ही नहीं है। उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी असत्य सरकार और पार्टी हमने कभी नहीं देखी है। जिस प्रकार का असत्य बोलती है, लोगों को बेवकूफ बनाती है, युवाओं को बेवकूफ बनाती है। माननीय सभापति महोदय, मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि वे कौन से बेरोजगार लोग होंगे, जिनको भत्ता मिलेगा?

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): माननीय सभापति महोदय, ये तो 3500 की बात कर रहे हैं। लोग इंतजार कर रहे हैं कि 15 लाख रुपये कब आएंगे? लोगों को ठगने की कोशिश किसने की थी, यह भी बताएं?

श्री सभापति: विराजें।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): सरकार स्पष्ट करे कौन लोग होंगे, कहां तक पढ़े-लिखे होंगे! यह स्पष्ट नहीं है। यह स्पष्ट इस सरकार को करना चाहिए कि कैसे देंगे, कब देंगे, कितने लोगों को देंगे? यह पता ही नहीं चल रहा है। माननीय सभापति महोदय, मैंने इस अभिभाषण को कई बार उल्टा-पुल्टा, दायें-बायें सब तरफ से देखा है और मुझे बहुत कष्ट हो रहा है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य दिलावर जी। मैं सभी माननीय सदस्य से व्यक्तिगत रूप से फिर आग्रह कर रहा हूं कि करीब 20 सदस्य बोलने वाले हैं। आपस में यदि आप इस तरह से टोकाटोकी करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आप सब लोग अपना समय पूरा कर पाएंगे, बोल पाएंगे। मेरा एक बार आप सब से आग्रह है कि आप अपनी बात रखें और वहीं तक सीमित रहें। क्यों आप वाद-विवाद करते हैं। माननीय सदस्य, श्री दिलावर जी।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): माननीय सभापति महोदय, माननीय सभापति महोदय, ऐसा अभिभाषण में कहा गया है कि 'संवेदनशील, पारदर्शी, सुशासन प्रदान करने, शांति, सौहार्द और सद्भावना बढ़ाना'। मुझे तो इस सरकार की सोच पर भी तरस आता है। मुझे लगता है कि बात तो ठीक है, परन्तु ऐसा करते हैं क्या?

माननीय सभापति महोदय, मैं आपको कुछ उदाहरण देना चाहता हूं। जब से सरकार आई है तब से लव-जिहाद के मामले इस राजस्थान में युद्ध स्तर पर बढ़ गये हैं। क्या बारां, क्या सुकेत, क्या अंता, क्या कोटा। ये तो मेरे ध्यान में हैं। पूरे राजस्थान में ऐसे लव-जिहाद के मामले बढ़ गये हैं। हिंदुओं की लड़कियों को बहला-फुसलाकर लेकर भाग रहे हैं। उनको उठाकर ले जा रहे हैं। कांग्रेस के लोग एक शब्द बोलने को तैयार नहीं हैं। +++ एक माननीय सदस्य तो इसमें शामिल हो गये हैं। उनके सहायक एक लड़की को लेकर भाग गये और +++ उनके परिजनों को बुलाकर धमकी देते हैं कि 50 लाख रुपये ले लीजिए, लेकिन इसका पीछा छोड़िये। यह क्या हो गया है? यह कैसी सरकार है कि +++ सहायता करने के लिए शामिल हो जाएं। माननीय सभापति महोदय, यह सत्य घटना है। मैं बिलकुल भी झूठ नहीं बोल रहा।

श्री सभापति: माननीय सदस्य।

डा. महेश जोशी (सरकारी मुख्य सचेतक): माननीय सभापति महोदय, ये बिलकुल निराधार आरोप हैं। इनकी बात को कार्यवाही से निकाला जाए।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): अंता के पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज है। सुकेत का मामला भी ऐसा ही है। कोटा का मामला भी ऐसा ही है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, एक बार आप बैठें। माननीय नेता, प्रतिपक्ष, मैं आपसे भी आग्रह करूंगा कि इस तरह के आरोप लगाना आसन को अच्छा नहीं लगता। माननीय सदस्य जो जवाब देने वाले हैं, न उनको नोटिस है और न ही उनके संज्ञान में है, न वे खुद यहां पर मौजूद हैं।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): ये तो उनकी गलती है। यह तो आपको नमूना दिखाई दे रहा होगा, यहां की लापरवाह नौकरशाही का..

श्री सभापति: माननीय सदस्य, मैं फिर आपसे आग्रह कर रहा हूं। (व्यवधान) नेता, प्रतिपक्ष बैठे हुए हैं। आपको यह सब अच्छा लगता है क्या? आपको बार-बार टोकना अच्छा लगता है?

ऐसी कोई भी कार्यवाही जो सदन की मर्यादा के विपरीत है, वह अंकित नहीं होगी, निकाल दी जाएगी। मैं फिर आपसे आग्रह कर रहा हूं, आप इतने वरिष्ठ सदस्य हैं। मुझे खुद को अच्छा नहीं लग रहा है। अचंभा होता है कि आप और हम इतने पुराने लोग हैं ...(व्यवधान)

श्री नरेन्द्र बुडानिया (तारानगर): ...(व्यवधान) ये सारी खीज हम पर निकाल रहे हैं।

श्री सभापति: प्लीज आप बैठें।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): माननीय सभापति महोदय, इस अभिभाषण में यह कहा गया है कि अल्पसंख्यकों के लिए विभिन्न प्रकार की कल्याणकारी योजनाएं बनायेंगे और उनको सशक्त करेंगे। यह भी कहा गया है कि अल्पसंख्यक वर्ग के मेधावी छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान कर उन्हें उच्च अध्ययन के लिये प्रोत्साहित किया जायेगा। बहुत अच्छी बात है। इस प्रदेश में सबका विकास होना चाहिए। सब की बहन-बेटियां पढ़नी चाहिए, पर क्या सांसियों की बेटियां नहीं हैं? गाड़िया-लुहारों की बेटियां नहीं हैं क्या? सांठियों की बेटियां नहीं हैं क्या? सपेरों की बेटियां नहीं हैं क्या? कालबेलियों की बेटियां नहीं हैं क्या? बंजारों की बेटियां नहीं हैं क्या? क्या ये गरीब नहीं हैं? उनके उत्थान के लिये एक शब्द क्यों नहीं बोला गया? अल्पसंख्यकों की बेटियों को ही हम पढ़ायेंगे, उनको ही हम एक्स्ट्रा छात्रवृत्ति देंगे। यह इन सारे समाजों का अपमान है। उनके साथ ज्यादती है और उनकी माता-बहनें हमारी बेटियां हैं, यह उनके साथ अन्याय है। उनको

(श्री मदन दिलावर)

शिक्षा से पीछे धकेला जा रहा है, यह ठीक नहीं है। माननीय सभापति महोदय, यह संकीर्ण मानसिकता है। उनसे पूछो तो कहा जाता है कि ये तो भारत माता की पूजा करती हैं। ये तो भारत माता की जय बोलती हैं। क्या भारत माता की जय बोलना अपराध है? मैं एक वीडियो देख रहा था, कांग्रेस पार्टी के एक वरिष्ठ सदस्य जो कि बीकानेर से आते हैं, उस वीडियो में एक कार्यकर्ता का हाथ पकड़कर नीचा कर रहे हैं कि भारत माता की जय नहीं बोलते। यह कांग्रेस पार्टी की मीटिंग है, इसमें सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी की जय बोलिये, भारत माता की जय नहीं बोली जा सकती। सभापति महोदय, आपसे जानना चाहता हूं, सदन से जानना चाहता हूं।

श्री सुखराम विश्नोई (राज्य मंत्री, वन): किसने कहा नहीं बोलते, मैं बोलने के लिये के तैयार हूं। फालतू की बात करते हो। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: आपकी भावनाएं गलत हैं। आप जनता में क्या मैसेज देना चाहते हो? भारत माता की जय।

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): आप भड़काने की कोशिश कर रहे हो।

श्री दानिश अबरार (सवाईमाधोपुर): ...(व्यवधान) यह कौनसी मीटिंग की बात है। ये सरासर असत्य आरोप लगा रहे हैं। इनके पास कोई प्रूफ नहीं है। सभापति महोदय, इसको कार्यवाही से निकलवाइए।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): ...(व्यवधान) यह सच बात है। इसको स्वीकार करना पड़ेगा। माननीय सभापति महोदय, आप फिर कहेंगे कि भारत माता की जय पर चर्चा क्यों कर रहे हैं?

श्री सभापति: आप 15 साल बाद विधान सभा में आये हैं। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): दस साल। आपके पास गलत सूचना है।

श्री सभापति: आप शायद भूल गये हैं, 15 साल बाद आये हैं।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): मैं आता रहूंगा।

श्री सभापति: माननीय दिलावर जी, मुझे आपको कितनी बार कहना पड़ेगा। आप क्यों इन्वाइट कर रहे हैं? मैं तो आपको अवसर दे चुका कि पूरे सदस्य एक साथ बोल लें।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): मैं तो किसी का नाम भी नहीं ले रहा।

श्री सभापति: माननीय सदस्य या तो मैं सबको एक साथ अवसर दूं। आप सब एक साथ बोल लें। सदन को शांतिपूर्वक चलने दें।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): मैंने बीकानेर में मालूम करवाया।

श्री सभापति: आप बीकानेर और जोधपुर की बात छोड़िए।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): जिस कार्यकर्ता को रोका गया था, वह कौनसी पार्टी का था। वह कुछ दिन पहले भारतीय जनता पार्टी का था। उसको कांग्रेस की परम्पराएं ध्यान में नहीं थीं।

श्री सभापति: माननीय नेता, प्रतिपक्ष, प्लीज इन्हें थोड़ा-सा समझाएं। आप सदन की थोड़ी-बहुत तो मर्यादा रखें।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): माननीय सदस्य महोदय, बाटला हाउस कांड का मामला तो आपको सब पता है। पुलिस मुठभेड़ में आतंकवादी मारे गये। पूरे देश में हाहाकार हो गया। देश खुशियां मना रहा था कि देश के दुश्मन आतंकवादी मारे गये। लेकिन मैंने दूसरे व तीसरे दिन अख़बार में पढ़ा तो मुझे आश्चर्य हुआ कि +++

श्री सभापति: मैं आपके लिए फ्री डिबेट रखवा दूं यहां पर।

श्री सुखराम विश्नोई (राज्य मंत्री, वन): 000

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): 000

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): मैंने नाम लिया है, उसको वापस लेता हूं।

श्री पदमाराम (चौहटन): 000

श्री अमीन खां (शिव): 000

श्री सभापति: कोई अंकित नहीं होगा। माननीय सदस्य, आप अभिभाषण पर रखेंगे या नहीं। मैं बिलकुल अलाउ नहीं करूंगा। माननीय नेता, प्रतिपक्ष को इनको बोलना चाहिए। माननीय सदस्य, आप मेहरबानी रखेंगे। माननीय सदस्य, आसन आपको बार-बार टोक रहा है। आप क्यों इस तरह की बाते करते हैं? आप सीधे-सीधे अभिभाषण पर क्यों नहीं बोलते हैं? क्यों किसी का नाम लेते हैं?

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): मैं इतना निवेदन कर रहा हूं.......

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): 000

श्री सभापति: अभिभाषण आपने पढ़ा नहीं और बोलने के लिए आप खड़े हो गये। इधर से उधर आप बोल रहे हैं, कोई मतलब नहीं है इन सब बातों का। अनुशासित रहें। मैं बिलकुल अलाउ नहीं करूंगा। मेहरबानी रखें आप। आसन आपको बार-बार बोल रहा है।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): 000

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): माननीय सभापति महोदय, मैं तो इतना निवेदन कर रहा हूं कि देश का उच्चतम न्यायालय फांसी की सजा सुना दे और मेरे देश के कुछ लोग उनको फांसी की सजा रुकवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएं। व्यवधान आतंकवादियों को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएं......

श्री सभापति: माननीय सदस्य आप विराजिए। श्री मदन दिलावर के अलावा बीच में टोकने वालों का किसी का अंकित नहीं होगा।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): कोई अच्छा व्यक्ति फंस गया हो तो उसके लिए जाकर किसी छोटी-सी कोर्ट का भी दरवाजा किसी ने खटखटाया है। परन्तु देश के दुश्मनों, आतंकवादियों को फांसी से रोकने वाले वहां पर जाते हैं।

श्री सभापति: विराजिए। आप लोग विराजिए।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): अब माननीय सभापति महोदय, आप ही बताएं वे कौन लोग होंगे? मैंने यह भी सुना, मैंने यह भी पढ़ा कि हिन्दुस्तान में लोग.....

श्री सभापति: आप तैयारी से नहीं आए, माननीय सदस्य।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): मैं पूरी तैयारी के साथ आया हूं। इतने सारे कागज है, आप चिंता मत करो। मैं यह भी कहना चाहता हूं हमारे लिए यह कहा गया कि यह मंदिरों में जाते हैं तो लड़कियां छेड़ने जाते हैं। यह देवालयों का, मंदिरों का, हमारी माताओं-बहनों का, हमारा और देश के 130 करोड़ लोगों का अपमान नहीं है। हम लड़कियां छेड़ने जाते हैं, आप लड़किया छेड़ने जाते हैं, मंदिर में जाते हैं तो, विशेष धर्म के लोग लड़कियां छेड़ने जाते हैं। ये कैसी बाते करते हैं? और वही अब तिलक लगाकर, गमछा पहनकर ढोंग करते हुए मंदिर-मंदिर क्यों भटक रहे थे, चुनावों में? क्या हमको बेवकूफ बनाने के लिए भटक रहे थे क्या? जनेऊ पहनकर घूम रहे थे। वीर सावरकर जी ने सच कहा था कि 'ऐसा दिन आयेगा जब लोग दिखाने के लिए कोट के ऊपर जनेऊ

(श्री मदन दिलावर)

पहनकर घूमेंगे, तब सोचना।' वास्तव में हम चाहते हैं कि देश के लोग ...(व्यवधान)

श्री सभापति: विराजिए आप। शांति रखे आप। माननीय श्री मदन दिलावर।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): माननीय सभापति महोदय, यह भी कहा गया सुप्रीम कोर्ट में जाकर कि भगवान राम इस देश में कपोल-कल्पित कल्पना है। भगवान राम इस देश में पैदा ही नहीं हुए। फिर रामसेतु का सवाल ही कहां उठता है। भगवान राम पैदा ही नहीं हुए तो क्या मेरे देश में महापुरुषों द्वारा लिखे गये ग्रंथ असत्य हैं? यह पूज्य रामायण, पूज्य गीता जी का अपमान नहीं है। हमारे हजारों ग्रंथ जितने लिखे हैं, उनका अपमान नहीं है। जितने शिलालेख लिखे हैं, उनका अपमान नहीं है। यह आपका और मेरा अपमान नहीं है। इस प्रकार की चर्चा करना, हमारा अपमान है और फिर कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी मंदिर नहीं बना रही है। भारतीय जनता पार्टी तो मंदिर बनाने में पूरा सहयोग करेगी और इस देश का हिन्दू इस मंदिर का निर्माण करेगा। दुनिया की कोई ताकत उसको रोक नहीं सकती है। यह मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं।

माननीय सभापति महोदय, अनेक प्रकार की बातें कही गयीं। एक दिन मैं अख़बार पढ़ रहा था, अख़बार पढ़ा तो आश्चर्यचकित रह गया। देश के एक प्रांत में कहा गया कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की शाखाएं सरकारी जमीन पर नहीं लगने देंगे। क्या इस देश में कोई ऐसी जमीन है, जो सरकारी नहीं है? किसान का खेत भी सरकारी है। वह भी 99 साल की लीज पर दिया गया है। आपका और मेरा मकान भी 99 साल की लीज पर दिया गया है तो क्या संघ की शाखाओं को इस प्रदेश में और देश में रोकने का संकल्प आप लेते हैं? आपने कहा कि हम उनके खिलाफ कार्यवाही करेंगे जो सरकारी नौकरी में है और संघ की शाखाओं में जाएंगे। संघ की शाखाओं को रोकेंगे, संघ की शाखाओं को नहीं लगने देंगे। आप जानते हैं कि संघ की शाखाओं में क्या होता है? व्यक्ति का निर्माण होता है, चरित्र निर्माण होता है, देशभक्ति सिखाई जाती है। देशभक्ति कूट-कूट कर भरी जाती है, उसको रोकने का प्रयत्न होगा। ईमानदार लोग बनाने का प्रयत्न होता है, चरित्रवान लोग बनाने

(श्री मदन दिलावर)

का प्रयत्न होता है, देशभक्त लोग बनाने का प्रयत्न होता है, उसका उलटा आप क्या करना चाहते है ? संघ की शाखा नहीं लगने देना चाहते, इसका मतलब अब आप लोग बेईमान लोग पैदा करना चाहते हैं, अब आप चरित्रहीन लोग पैदा करना चाहते हैं, आप चोर-लुटेरे पैदा करना चाहते हैं, आप आतंकवादी पैदा करना चाहते हैं, आप नक्सलवादी पैदा करना चाहते हैं। यह कांग्रेस की सोच है। ऐसा नहीं होने देंगे किसी भी कीमत पर, ये देश तो ईमानदार लोगों का रहेगा, चरित्रवान लोगों का रहेगा और यह राष्ट्रीय स्वयं सेघ के कार्यकर्ताओं का संकल्प है, जिसमें हम सब लोग सहायक बनेंगे। आप से भी प्रार्थना है सभापति महोदय, आप भी इसमें सहायक बनें।

सुश्री दिव्या मदेरणा (ओसियां): 000

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): 000

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): 000

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): आप महिलाओं के सम्मान की चिंता करते हैं, +++ आप महिलाओं के सम्मान की चिंता करते हैं, +++

सुश्री दिव्या मदेरणा (ओसियां): 000

श्री दानिश अबरार (सवाईमाधोपुर): 000

श्री सभापति: माननीय सदस्य प्लीज। नेता, प्रतिपक्ष के इतनी बार कहने के बावजूद भी आप....

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): माननीय सभापति महोदय, पाठ्य पुस्तकों में से कई बातें हटाने की चर्चाएं चल रही हैं। महाराणा प्रताप को महान कहने में कांग्रेस के नेताओं को शर्म आती है। महाराणा प्रताप महान नहीं हो सकते, अकबर महान होंगे। उसकी चर्चा मैं ज्यादा नहीं करना चाहता क्योंकि आप कुछ भी कह सकते हैं। आपका इस देश के राष्ट्रभक्तों में, क्रांतिकारियों में और महापुरुषों में विश्वास नहीं है। लगता है इस देश की धरती पर भी आपका विश्वास नहीं है, इसलिए आप कुछ भी कह सकते हैं।

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): 000

श्री अमीन खां (शिव): 000

श्री दानिश अबरार (सवाईमाधोपुर): 000

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): गौपालन पर यहां चर्चा की गई। गौ माता हमारी मां है, गौपालन की चर्चा की गई। (व्यवधान)

श्री सभापति: अभिभाषण पर आपने एक भी बात नहीं कही है। आपने कोई तैयारी नहीं की है आपको आसन कह रहा है यह बात। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): मैंने पूरी तैयारी की है। गौ माता मां है। (व्यवधान) आपके कहने से थोड़े ही है कि तैयारी नहीं की। (व्यवधान) मैंने पूरी तैयारी की है।

श्री सभापति: आप अभिभाषण पर रहें।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): गौ पालन पर चर्चा कर रहा हूं। (व्यवधान)

श्री सभापति: बोलिए न आप।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): मैं बोल रहा हूं।

श्री सभापति: बोलिए आप।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): माननीय सभापति महोदय, गौ पालन की चर्चा की गई है ...(व्यवधान)

श्री सभापति: प्लीज...(व्यवधान)

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): और हमारे ऊपर आरोप लगाया कि हमने गौ पालन पर हमने कुछ नहीं किया। इनकी (व्यवधान) सरकार यहां 50 साल से ज्यादा रही है, गौ पालन मंत्रालय क्यों नहीं बनाया था।

सुश्री दिव्या मदेरणा (ओसियां): 000

श्री सभापति: माननीय सदस्य ...(व्यवधान)

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): यहां की चरागाह भूमि की समस्या ...(व्यवधान)

किसने अट्टालिकाएं खड़ी कीं, किसने बड़े-बड़े लोगों को बेच दिया है? आज गौ माता के चरने के लिए जमीन नहीं है, कहां पर जाए। गौ माता थी उसको भी समाप्त करने की...(व्यवधान)

श्री रामलाल मीणा (प्रतापगढ़): 000

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): देशी गौ माता का यहां अभाव हो गया है, नस्ल को बिगाड़ दिया है। आज देशी गौ माता का दूध पीने के लिए लोग तरसने लग गए हैं। (व्यवधान)

श्री दानिश अबरार (सवाईमाधोपुर): 000

श्री अमीन कागजी (किशनपोल): 000

श्री सभापति: माननीय नेता, प्रतिपक्ष, 20 सदस्य बोलने वाले हैं। माननीय सदस्य, प्लीज...(व्यवधान)

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): 000

श्री सभापति: माननीय सदस्य ...(व्यवधान)

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): 000

सुश्री दिव्या मदेरणा (ओसियां): 000

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): 000

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): 000

श्री सभापति: विराजिए ...(व्यवधान)

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): 000

श्री सभापति: माननीय सदस्य विराजिए ...(व्यवधान)

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): 000

श्री सभापति: माननीय नेता, प्रतिपक्ष ....(व्यवधान)

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): 000

सुश्री दिव्या मदेरणा (ओसियां): 000

श्री सभापति: विराजिए विराजिए, कोई अंकित नहीं होगा। (व्यवधान) कोई अंकित नहीं होगा।

सुश्री दिव्या मदेरणा (ओसियां): 000

श्री सभापति: माननीय नेता, प्रतिपक्ष, प्लीज आप सभी सुने। बीस सदस्य बोलने वाले हैं। माननीय नेता, प्रतिपक्ष, मुझे ...(व्यवधान) प्लीज विराजें आप, बिलकुल नहीं ...(व्यवधान) अलाउ नहीं कर रहा हूं ।माननीय नेता, प्रतिपक्ष, मुझे बाध्य होकर पांच मिनट बाद आवश्यक रूप से बैठाना पड़ेगा। अभी आपको सबको समय मिल रहा है, आपको बोलने का अवसर है, ...(व्यवधान) प्लीज विराजिए आप।

श्री समाराम गरासिया (पिण्डवाड़ा-आबू): 000

श्री सभापति: विराजिए ....(व्यवधान).

श्री समाराम गरासिया (पिण्डवाड़ा-आबू): 000

श्री सभापति: विराजिए, आसन को पता है उसका क्या काम है। (व्यवधान) ..

सुश्री दिव्या मदेरणा (ओसियां): 000

श्री सभापति: प्लीज ...(व्यवधान) मैं बिलकुल अलाउ नहीं करूंगा।

सुश्री दिव्या मदेरणा (ओसियां): 000

श्री सभापति: मैं बिलकुल अलाउ नहीं करूंगा। (व्यवधान) माननीय नेता, प्रतिपक्ष, सचेतक महोदय, मुझे बाध्य होकर पांच मिनट बाद बंद करना पड़ेगा। आप लोग 20 माननीय सदस्य बोलने वाले हैं। आप यदि अपनी बात नहीं रखने की बजाए आपसी वाद-विवाद करेंगे तो फ्री डिबेट तो है नहीं, सदन को अनुशासन में रखना जितनी आपकी डयूटी है, मैं भी चाहता हूं कि सदन अनुशासन में रहे। मैं फिर आपसे कह रहा हूं, माननीय नेता, प्रतिपक्ष, माननीय सचेतक महोदय, अपने लोगों से कहिए कि कृपया शांति रखें। आवश्यक रूप से मुझे पांच मिनट बाद बंद करना पड़ेगा, किसी और का नाम बुलाना पड़ेगा। प्लीज, कोई बीच में नहीं बोलेगा अब।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): माननीय सभापति महोदय, अभिभाषण के पैरा नम्बर 11 में किसान हमारी खुशहाली का आधार है यह बात सही है, इसीलिए तो कांग्रेस ने कई दशकों तक गरीब किसान को लूटा है। राजस्थान प्रदेश में 18 प्रतिशत ब्याज लेते रहे अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार से पहले किसानों से। 18 प्रतिशत ब्याज लोन का लेते रहे, कितना होता है, मुझे वह दृश्य ध्यान है जब मेरे गांव में मैं छोटा था, वसूली करने आए किसान से उसका पैसा नहीं चुका, वह कर्जा नहीं चुका पाया, गर्मी में तेज धूप में उसे खड़ा कर दिया गया, चालीस किलो का पत्थर उसके सिर पर रख दिया और जब तक वह रोने नहीं लग गया, तब तक पांच घंटे तक उसको नहीं छोड़ा, छोड़ने के बाद उसको मुर्गा बना दिया, यह किसानों की खुशहाली की बात करते हैं। (व्यवधान) तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी साहब को मैं बधाई देना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने धीरे-धीरे इस ब्याज को कम किया। मैं आज हमारी पूर्व मुख्य मंत्री वसुन्धरा जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूं, उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि चार प्रतिशत ब्याज पर तीन लाख तक का लोन, जीरो प्रतिशत ब्याज पर डेढ़ लाख तक का लोन मिल रहा है, यह कभी कांग्रेस ने सोचा था क्या ...(व्यवधान) यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही सोच सकती थी। हल्ला होता है यहां ...(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय दिलावर जी के अलावा किसी का अंकित नहीं होगा। प्लीज...

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): यहां हल्ला होता है कि हम किसानों के हितैषी हैं। किसानों को तो जितनी ताकत थी, पूरी ताकत से लूटा गया है। माननीय सभापति महोदय, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि कोई ग्राम सेवा सहकारी समिति से लोन लेता है, सहकारी से लोन लेता है उसका बीमा भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कराना प्रारम्भ किया है। लोन लेने वाले की यदि दुर्घटना से मृत्यु हो जाए तो दस लाख रुपये तक का बीमा क्लेम यानी की सहायता उसके परिवारजनों को मिलती है, ऐसा कांग्रेस में कभी नहीं था। यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो किसानों के बारे में सोचती है। किसानों के बारे में तो कांग्रेस ने सोचा था कि यदि एग्रीकल्चर में बिजली का कनेक्शन होगा तो 12 हजार रुपये एक खम्भे के लिए जाएंगे। डेढ-डेढ़, दो-दो लाख रुपये का बिजली डिमांड नोट आएगा। किसान जमा नहीं करा पाता था, लेकिन इनको तरस नहीं आता था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है कि प्रति पोल पर आज कोई चार्ज नहीं है, यहां प्रति हार्स पावर पर मिनिमम है, आज किसान आसानी से अपना कनेक्शन ले पाता है।

माननीय सभापति महोदय, यही नहीं एक रुपये माह में दो लाख रुपये तक का बीमा हो जाएगा यह कल्पना भी किसने की थी, यह किसी ने नहीं यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही कर सकती थी, जिसने एक रुपये माह बीमा पर दो लाख रुपये तक का बीमा किया। सभापति महोदय, यही नहीं आगे भी सुनिए, इस देश में करोड़ की संख्या में ऐसे लोग थे जिनके सर पर छत नहीं। कांग्रेस ने भी छत बनाने की कोशिश की लेकिन वह लक्ष्य था एक पंचायत में दो इंदिरा आवास देंगे, तीन इंदिरा आवास देंगे, चार इंदिरा आवास देंगे, वह भी 11 हजार रुपये से प्रारम्भ किया और लास्ट तक उसको 40 हजार रुपये तक पहुंचाया। आज भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र जी मोदी का 2022 तक सबको पक्का आवास दिलाने का संकल्प है, लगभग वह संकल्प 2022 तक आसानी से पूरा हो जाएगा। आज एक-एक पंचायत में मैंने देखा है पांच-पांच सौ पक्के आवास बन रहे हैं। एक-एक पंचायत में पांच सौ-पांच सौ, छह सौ-छह सौ आवास बन रहे हैं, यह भारतीय जनता पार्टी की सोच है कि कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं रहे जिसको छत नहीं मिले।

मेरी बहनें-माताएं बरसात के दिनों में धुएं से जूझती रहती थीं। रोटी बनाने के लिए बड़ी मश्क्कत करनी पड़ती थी। फूंकनी से फूंका करती थीं, आंखों में आंसू आते थे, कइयों की रोशनी चली जाती थी, इस पर किसी ने चिंता नहीं की। महिलाओं की चिंता करने वालो को कह रहा हूं, वह भी कान

(श्री मदन दिलावर)

खोलकर सुन लें कि किसी ने चिंता नहीं की, माननीय प्रधान मंत्रीजी ने कहा कि ऐसा नहीं चलेगा, इस देश के धन पर, सम्पदा पर मेरी माताओं का भी अधिकार है। देश की सारी माताओं और बहनों का अधिकार है। इसलिए उन्होंने कहा कि रसोई गैस का कनेक्शन सस्ती रेट पर मिलेगा। फिर उन्होंने कहा नि:शुल्क मिलेगा। आज करोड़ की संख्या में गैस के कनेक्शन नि:शुल्क मिल रहे हैं। यह भारतीय जनता पार्टी की देन है। इसका सोच 80 सालों में क्यों नहीं आया था। क्या सांप सूंघ गया था। महिलाओं के सशक्तीकरण की बात करते हैं न! कई महिलाओं की आंखें, इन्होंने धुएं के कारण से फोड़ दी हैं, उसका जिम्मेदार कौन है, माननीय सभापति महोदय, यही नहीं, मैं आपको यह भी कहना चाहता हूं कि इनके तो यह भी ध्यान में नहीं आया था कि गांव में कितना कीचड़ रहता है तो खरंजा भी बनना चाहिए क्या, सी.सी. रोड भी बननी चाहिए क्या, नाली भी बननी चाहिए थी क्या।

मैं पूर्व मुख्य मंत्री स्वर्गीय माननीय भैरोंसिंहजी शेखावत साहब का भी आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि जब वे 1977 में आये तो उन्होंने काम के बदले अनाज योजना के अन्तर्गत गांव में खरंजा बनाना प्रारम्भ किया, नाली बनाना प्रारम्भ किया। तब से प्रारम्भ हुआ है। ये तो गांव के बारे में कुछ सोचते ही नहीं थे। गांव के बारे में तो इनकी सोच ही नहीं थी। यह तो शहरों पर लगे हुए थे, क्योंकि वहां ज्यादा पैसा मिलता है, कमीशन भी अच्छा आता है। गांव में यह सम्भव नहीं है, माननीय सभापति महोदय।

मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारी पूर्व मुख्य मंत्री श्रीमती वसुंधराजी को कि उन्होंने गांव में गौरव पथ बना करके आज गांव से कीचड़ को समाप्त कर दिया है। जो थोड़ा-बहुत बचा है, उसकी हम अपेक्षा करते हैं, आप समाप्त कर देना। पर इनका ध्यान नहीं है। इनका ध्यान नहीं है, इसलिये इस अभिभाषण में कोई चर्चा भी नहीं है। ऐसा सी.सी. रोड बनाया है जो वर्षों तक न हिले। यह सोच भारतीय जनता पार्टी की थी।

माननीय सभापति महोदय, हम तो मजदूरों के बारे में भी सोचते हैं, विद्‌यार्थियों के बारे में सोचते हैं। माननीय वसुंधराजी के नेतृत्व में मैं भी समाज कल्याण मंत्री था। कई गरीब बच्चे आते थे, मैं इंजीनियर बनना चाहता हूं, मैं डाक्टर बनना चाहता हूं, मेरे पास पैसा नहीं है। मैं गरीब हूं। मेरे पिताजी किसान हैं, मजदूर हैं। मैं पैसा कहां से लाऊं। उनकी जब मार्कशीट देखते थे तो ऐसा लगता है कि बहुत इंटेलिजेंट है, अच्छा लड़का है। यदि इसको कोचिंग

(श्री मदन दिलावर)

करने की सहायता मिल जाये तो आगे बढ़ सकता है। हमने प्रावधान किया कि प्रतिष्ठित कोचिंग क्लासेज में एडमिशन होने के बाद एस.सी., एस.टी. और ऐसे गरीब लोग हैं, बी.पी.एल. हैं, ऐसे सब लोगों को सरकार के खजाने से उनके कोचिंग का शुल्क सरकार देगी और उनको पढ़ायेगी। सभापति महोदय, मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि हजारों की संख्या में डाक्टर्स और इंजीनियर्स बने। आज बड़े-बड़े पदों पर हैं। लेकिन कांग्रेस की सरकार ज्योंहि आई, त्योंही इन्होंने समाप्त कर दिया। आज सारे युवा गाली दे रहे हैं। यह कैसी सरकार आई है, यह कैसी सरकार है कि गरीब लोगों को जो भत्ता दिया जाता था, कोचिंग क्लासेज की फीस दी जाती थी, उसको समाप्त कर दिया है। मजदूरों के बारे में तो बिलकुल ही निष्ठुर हैं। पर मैं भारत के प्रधान मंत्री नरेन्द्रजी मोदी और हमारी पूर्व मुख्य मंत्री वसुंधराजी को बधाई देना चाहता हूं। इसलिये देना चाहता हूं, क्योंकि उन्होंने मजदूरों का पंजीयन प्रारम्भ करवाया। मजदूरों का पंजीयन प्रारम्भ करवा करके उनको कहा कि यदि मजदूर का पंजीयन प्रारम्भ हो जाएगा तो उनको बेटा होगा तो 20 हजार मिलेंगे, बेटी होगी तो 21 हजार रुपये मिलेंगे। मजदूर की बेटी 18 साल की हो गई, आठवीं पास है तो उसको 55 हजार रुपये मिलेंगे। उनको आवास नहीं है तो पांच लाख तक का लोन सस्ते ब्याज पर मिलेगा, और डेढ़ लाख रुपये तक का अनुदान होगा। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, दिलावरजी, मेरा निवेदन है पांच मिनट में अपनी बात समाप्त करें।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): बस पांच मिनट।

डेढ़ लाख तक उसमें अनुदान होगा। यही नहीं, यदि मजदूर 60 साल की उम्र के पहले सामान्य मौत से भी मर जाता है तो उसके परिवारजनों को दो लाख रुपये मिलेंगे। एक्सीडेंट में 60 साल से पहले उसकी मृत्यु होती है तो उसके परिवारजनों को लालन-पालन के लिये पांच लाख रुपये मिलेंगे। माननीय सभापति महोदय, यह तो कांग्रेस के ध्यान में नहीं आया था। इससे यह लगता है कि यह सरकार मजदूरों की विरोधी थी। आज मजदूर कह रहे हैं, पूछ रहे हैं कि यह योजना जो मिली थी, यह कांग्रेस की सरकार आने के बाद उनके पंजीयन की गति धीमी हो गई है। उनको जो लाभ मिल रहे थे, उसकी गति धीमी हो गई है। उसके क्या कारण हैं?

(श्री मदन दिलावर)

माननीय सभापति महोदय, यही नहीं, यहां परवन सिंचाई परियोजना की भी चर्चा की गई थी। क्योंकि मैं पहले वहां से चुन करके आता था, इसलिये मुझे चर्चा करना बहुत आवश्यक हो गया। परवन सिंचाई परियोजना के बारे में मैं आपको पूरी जानकारी देना चाहता हूं। मैं जब सरकार में था, क्योंकि मैं एक चुनाव में वहां भाषण दे करके आया था कि मैं कुछ कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, लेकिन किसानों के खेतों में जरूर पानी लाऊंगा। फिर उन्होंने जिता दिया। जिताने के बाद मुझे चिंता हुई। तो जो-जो उस इलाके में चीफ इंजीनियर रहे थे, उनको मैंने बुलाया और कहा कि मैं इस प्रकार का भाषण देकर आया हूं, यह कैसे होगा। तो मैं आभार व्यक्त करता हूं स्वर्गीय रामसिंहजी मीणा का जो चीफ इंजीनियर रहे थे। उन्होंने कहा, दिलावरजी, तीन महीने का समय दीजिये, मैं जाता हूं। उन्होंने तीन महीने तक देखा, देखने के बाद बताया कि वहां बड़ा प्रोजेक्ट बन सकता है। उन्होंने कहा तीन करोड़ रुपये हमको सर्वे के लिये चाहिए। मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी के पास सर्वे के लिये गया, उन्होंने तीन करोड़ रुपये दिये और योजना बनाई। आज वह साकार रूप ले रही है। कह रहे थे उसमें कुछ नहीं हुआ, कांग्रेस ने शिलान्यास करवा दिया राहुल गांधीजी से, असत्य। जबकि किसी भी प्रकार की स्वीकृतियां हुई नहीं थीं। आज उन तारीखों में देख लीजिये कोई रिकार्ड पर नहीं है और वहां शिलान्यास करा दिया। फिर हमने जितनी बाधाएं थीं, उस प्रोजेक्ट को प्रारम्भ करने में, उन सारी बाधाओं को माननीय मुख्य मंत्रीजी ने दूर किया। आज मेरी जानकारी के अनुसार लगभग 1800 करोड़ से भी ज्यादा उस योजना पर खर्च हो चुके हैं। लेकिन कांग्रेस के लोग कह रहे हैं, कुछ हुआ ही नहीं। यह प्रदेश की जनता को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त करें अब।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): मैं आपको आमंत्रित करता हूं कि आप परवन सिंचाई परियोजना को देखकर आएं, फिर यहां के माननीय सदस्यों को, जिनको पता नहीं है, उनको जानकारी दें।

माननीय सभापति महोदय, मुझे बहुत कष्ट भी हो रहा है। यहां जो माननीय सदस्य आये हुए हैं, उन्होंने कोटा के बारे में कहा था कि बिजली विभाग ने केडीएल कम्पनी को ठेका दिया हुआ है। हम आ जाएंगे तो केडीएल कम्पनी को एक दिन भी कोटा में नहीं रहने देंगे, उसको हटा देंगे। क्योंकि यह जो स्मार्ट मीटर लगे हैं, वे ज्यादा बिजली दे रहे हैं। आप लोगों को बरगला

(श्री मदन दिलावर)

करके सत्ता में आ गये। यदि वे गलत हैं तो हटाते क्यों नहीं। क्या आपका समझौता हो गया क्या, कोई लेन-देन हो गया क्या? क्या बात है, जो चुनाव के पहले की बातों को भूल गये। जो चुनाव में भाषण दे करके आये थे, उनको भूल गये। इसलिये, माननीय सभापति महोदय, बहुत सारी बातें हैं, जिनको करना चाह रहा हूं। परन्तु आपका डर लग रहा है। मैं जानता हूं कि पहली बार जब मैं जहां से चुनाव लड़ रहा था, तो विधान सभा क्षेत्र में गया तो वहां की चार पंचायतें, जिनकी मैं चर्चा करूं तो आप भी दंग रह जाएंगे। डोलिया, भंवरिया, बोरावास, कालाखेड़ी, लाडपुरा पंचायत समिति की लाडगी ...(व्यवधान)

श्री सभापति: समाप्त करें, माननीय सदस्य, समाप्त करें। प्लीज, प्लीज।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): पांच मिनट, पांच मिनट और।

श्री सभापति: नहीं, नहीं, बिलकुल नहीं।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): ढाई मिनट और।

श्री सभापति: प्लीज समाप्त करें, नहीं।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): इतना तो निवेदन सब स्वीकार करते हैं।

श्री सभापति: अंकित नहीं होगा।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): 000

श्री सभापति: मैं सभी सदस्यों से ...(व्यवधान) प्लीज, विराजें, आप। नहीं, नहीं, बिलकुल नहीं। आप विराजिए। (व्यवधान) आप विराजिए। मैं पूरी तरह निष्पक्ष हूं। आप विराजिए।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): 000

श्री सभापति: एक मिनट में अपनी बात समाप्त करें आप।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): इन पंचायतों की हालत इतनी बदतर है कि न वहां पानी है, न बिजली है, न सड़क है, न स्कूल है।

श्री सभापति: एक मिनट में अब आप अपनी बात समाप्त करें।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): हां, मैं एक मिनट में बात समाप्त कर रहा हूं।

(श्री मदन दिलावर)

मैं वहां जा करके, देख करके दंग रह गया कि स्वतंत्र भारत में भी ऐसा होता है क्या। मैं निवेदन कर रहा हूं आप सबसे, मैं निवेदन कर रहा हूं सरकार से कि यह जो चार पंचायतें हैं जो नारकीय जीवन जी रही हैं बोरावास है, डोलिया है, कालाखेड़ी है, भंवरिया है, कोटा जिले के लाडपुरा पंचायत समिति की हैं। इन पर भी ध्यान दें। इन पर क्यों विचार नहीं किया जा रहा है। यदि इनको हटाना है, वहां पर कष्ट है, तो दूसरी जगह बसाइये।

श्री सभापति: समाप्त करें, समाप्त करें, प्लीज। विराजिए।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): परन्तु उनको नारकीय जीवन जीने से मुक्ति दिलाइये। सभापति महोदय, यह मेरा निवेदन है, धन्यवाद।

सुश्री दिव्या मदेरणा (ओसियां): सभापति महोदय, मैं भी आपके माध्यम से निवेदन करना चाहती हूं।

श्री सभापति: धन्यवाद। कोर्ट में जो भी इश्यू विचाराधीन है, उस पर सदन में अनावश्यक रूप से जो भी चर्चा की गई है, विलोपित किया जाए, और मैं सभी माननीय सदस्यों से फिर आग्रह करूंगा कि अपनी बात को संक्षिप्त में रखें, सारगर्भित तरीके से रखें। समय निर्धारित है। क्योंकि आसन समय नहीं बढ़ा रहा है। माननीय नेता, प्रतिपक्ष, आप समय बढ़ा रहे हैं? जब समय नहीं बढ़ा रहे हैं तो समय निर्धारित है। आप लोग, 20 सदस्य बोलने वाले हैं। अपनी बात को संक्षेप में रखें, गम्भीरता से रखें और आप बीच में आप इण्टरवीन नहीं करें। श्री मेवाराम जैन।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): माननीय सभापति महोदय, आज महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बहस हो रही थी। सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष आपस में अपनी-अपनी बातें रख रहे थे।

महामहिम राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में सरकार ने जो जन घोषणा पत्र और सरकार की जो नीतियां हैं कि किस तरह से इस पांच साल के कुशासन से, भारतीय जनता पार्टी के इस शासन ने पांच साल में जनता के साथ किस तरह से धोखा किया, किस तरह से जनता त्रस्त थी, उससे मुक्ति पाकर और जो कांग्रेस की सरकार आई और जिस तरह से एक महीने के अंदर जिस तरह के फैसले हुए, जनता के हित के फैसले हुए वह आपके सामने इस अभिभाषण में और सरकार ने जो किये हैं, वह है।

माननीय सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि इन पांच साल के अंदर जिस तरह से यह जनता के बीच में घोषणा करके आए और

(श्री मेवाराम जैन)

जिस तरह के झूठे वादे किये, अभी एक महीना हुआ नहीं, हमारी सरकार बनी और दो लाख रुपये तक किसानों का लोन माफ करने की बात आई, सिर्फ एक महीना हुआ, इनको मैं यह याद दिलाना चाहूंगा कि आपकी सरकार ने लोक सभा और विधान सभा के चुनावों में किस तरह के वादे किये, वह आपको याद होना चाहिए।

क्या वह विदेशों का काला धन वापस आ गया? जो पन्द्रह लाख रुपये आप प्रत्येक व्यक्ति को देने जा रहे थे, क्या वह आपने दिये? दो करोड़ नौजवानों को प्रति साल नौकरी देने की बात कही थी, क्या आपने वह दी? आप यह कह रहे थे कि एक सिर कटेगा तो दस सिर हम काट कर लाएंगे, यह बात कही, आज हालात क्या है? आप इन पर विचार करें। आप यह सोचें कि किस तरह से आपने झूठे वादे किये और किस तरह से देश के हालात हैं और हमने जब लोन माफी की बात कही, एक महीना भी नहीं हुआ, आप वैल पर आ गये और धरने प्रदर्शन शुरू कर दिये। आप झूठी वाहवाही मत लो। हमने दस दिन का कहा था और दस दिन में लोन माफ करने की घोषणा भी की और आज आप बताइये कि कौनसे बैंक ...(व्यवधान)

श्री बलवीर सिंह लूथरा (रायसिंहनगर): सर्जिकल स्ट्राइक करके हमने दुश्मन की भूमि पर वार किया। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): मैं यह कहना चाहूंगा, आप सुनिये। कौनसी बैंक जनता से लोन के पैसे लेने जा रही है, आप यह बता दें। सारा बंद किया हुआ है। प्रोसेस है। कमेटी बनी है और बिलकुल जो घोषणा की है, उस घोषणा के तहत माफ करेंगे, आप थोड़ा विश्वास तो करो। आपने तो पचास हजार का लोन, हमने पांच साल माथा-फोड़ी की, धरना-प्रदर्शन यहां पर किया तब जाकर आपने पचास हजार की सिर्फ घोषणा की और घोषणा में आठ हजार करोड़ रुपये का लोन था, उसकी जगह सिर्फ दो हजार करोड़ रुपये के लोन माफ किये, बाकी आपने थोथी घोषणा के सिवाय और कुछ नहीं किया। सिर्फ आप वाहवाही ले रहे हो, सिर्फ बातें कर रहे हो। आप बताइये कि कहां आपने पचास हजार का लोन माफ किया? आप इतने उत्तेजित मत हों। (व्यवधान)

श्री सभापति: प्लीज, माननीय सदस्य।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): काम करने दीजिए। सरकार ने आते ही क्या फैसले लिये यह आपको पता होना चाहिए। आपको पता नहीं है, आप सुनिये यह बात। आप बात सुनने का माद्दा रखो।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप बार बार बीच में क्यों बोल रहे हैं? प्लीज।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): पांच साल के अंदर आपने क्या किया? अगर आपने काम किया होता तो आप यहां से इधर नहीं आते। झूठे वादे और झूठे वादों के सिवाय आपने कुछ नहीं किया।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप पांच मिनट में अपनी बात समाप्त करें। पांच मिनट में आप अपनी बात को समाप्त करें, समय की सीमा है। आप इधर आसन की तरफ देखकर अपनी बात कहिये।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): माननीय सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा, अभी मेरे से पूर्व वक्ता बोल रहे थे ...(व्यवधान)

श्री सभापति: आप आसन की तरफ देखकर बोलें और पांच मिनट में अपनी बात समाप्त करें। समय सीमा है।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): तो मैं नीचे बैठ जाता हूं। मैं बैठ जाता हूं।

श्री सभापति: नहीं-नहीं, आप अपनी बात कहें।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): मैं समाप्त ही कर लेता हूं, एक घंटा वह बोले जब तो आप बोले नहीं और मेरे को पांच मिनट हुए और आप बंद कर रहे हो, अब मैं अपना भाषण समाप्त ही करता हूं।

श्री सभापति: पांच मिनट में अपनी बात समाप्त करें। पांच मिनट में अपनी बात समाप्त करें। श्री मेवाराम। मेवारामजी, पांच मिनट में अपनी बात समाप्त करें।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): वह एक घंटा बोले जब तो आप बोले नहीं और पांच मिनट में ही आप मुझे बैठा रहे हो।

श्री सभापति: आप पांच मिनट में अपनी बात समाप्त करें।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): वह एक घंटे बोले जब तो आप बोले नहीं और सिर्फ पांच मिनट में आप मुझे बैठा रहे हो। बोलना ही नहीं मुझे। यह कोई बात हुई क्या? न्याय होना चाहिए सबके साथ।

श्री सभापति: मेवारामजी, आप बोलिये। समय की अपनी सीमा है, समय की मर्यादा है। आप बोलिये। (व्यवधान)

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): नहीं तो इस तरह से चेयरमैन भी ध्यान तो रखे न। (व्यवधान)

श्री सभापति: बोलिये-बोलिये। आप बोलिये।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): मैं यह कहना चाहूंगा कि राजस्थान के जो ड्रीम प्रोजेक्ट्स थे, इन्होंने रिफाइनरी को किस तरह से चार साल तक ठंडे बस्ते में रखा, किस तरह से मैट्रो को इन्होंने बंद करके रखा, किस तरह से अन्य जितने भी पानी के प्रोजेक्ट्स हों, चाहे लिफ्ट कैनाल के प्रोजेक्ट्स हों, सारे प्रोजेक्ट्स को इन्होंने बंद बस्ते में रखा और धीमी गति से सारे बंद करने के कगार पर लाये।

आज यह रिफाइनरी की बात कर रहे हैं कि हमने यह किया, यह बचाव कर लिया, क्या आपने बचाव किया? आप यह बताइये कि इस एग्रीमेंट के अंदर केन्द्र सरकार और राजस्थान के बीच में कोई ठेकेदार था जो बीच में पैसे खा रहा था? आप यह बताइये? जब यह चार साल के बाद आपने दुबारा शिलान्यास किया तो इसका सिर्फ एकमात्र उद्देश्य यह था कि कांग्रेस की सरकार ने यह शिलान्यास किया था, यह जो रिफाइनरी का प्रोजेक्ट शुरू किया है, इसको रोकने का काम आपने किया है। अगर आपकी नीयत साफ होती तो आज की तारीख में वह प्रोजेक्ट शुरू हो जाता और उससे कितने लोगों को रोजगार मिलता और इससे राजस्थान को कितनी आय होती, यह आपको कभी माफ करने वाले नहीं हैं।

आज मैट्रो की हालत वही है। जितनी भी आज हमारी पानी की लिफ्ट कैनाल की योजनाएं हैं, छह साल पहले हमने वर्क आर्डर दिये, काम शुरू करवाये परन्तु आपके इन पांच सालों के हालात आप देखें तो उन योजनाओं का हाल क्या है? आपकी वह टंकियां कहीं पर अधूरी पड़ी हैं, पाइप लाइन डाले हुए रास्ते में पड़े हुए हैं और आपने वह काम नहीं करने दिये और उसके कारण से आज आपको यह दिन देखने पड़े हैं इसलिए मैं यह कहना चाहूंगा कि सिर्फ आपने झूठी बातें की हैं और झूठे वादे किये हैं।

कांग्रेस सरकार हमेशा विकास में विश्वास करती है और आपने देखा होगा कि आते ही बहुत बड़े निर्णय लिये। चाहे लोन माफ करने की बात कहो, चाहे जो बुजुर्ग और असहाय महिला-पुरुष 75 साल से कम आयु के, पांच सौ से साढ़े सात सौ रुपये राशि बढ़ाई और साढ़े सात सौ की जगह एक हजार रुपये की।

आज आपने जिस तरीके से, चाहे मैं राजस्थान के अंदर आज शिक्षा

(श्री मेवाराम जैन)

की बात करूं, चिकित्सा की बात करूं, चिकित्सा के अंदर अभी स्वाइन फ्लू की बात कर रहे थे। क्या आपके समय स्वाइन फ्लू की बात नहीं हुई थी? आज यह केवल राजस्थान में ही है क्या? आप ऊपर भी देखो। आपका राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनके स्वाइन फ्लू कहां पर हो गया, कैसे हो गया? क्या वह राजस्थान में आए थे क्या? यह एक बीमारी है। हम प्रयास कर रहे हैं और यह कोशिश कर रहे हैं कि कैसे इसको रोकें पर ऐसी बातें सदन में नहीं आनी चाहिए और जिस तरह से अभी चर्चा हो रही थी अभिभाषण पर और कहां उसको लेकर गये। कोई अभिभाषण पर पांच शब्द नहीं बोले तो मैं यह कहना चाहूंगा कि जिस तरह से आज प्रदेश में अकाल है, उस अकाल पर चर्चा करें। पानी की समस्या पर बात करें। हास्पिटल में दवाइयां नहीं, डाक्टर नहीं, जो हमारे समय में जितनी शानदार स्कीम थी, दवाइयों की, उस नि:शुल्क दवाइयों की स्कीम का आपने क्या हाल कर दिया? आज हास्पिटल में कोई दवाई नहीं मिल रही है। अब हमारी सरकार आई है, अब उसको ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं। आपने इन योजनाओं की ऐसी दुर्दशा की है, निजीकरण, अस्पतालों का निजीकरण। स्कूलों को आप प्राइवेट में दे रहे हो, रोडवेज प्राइवेट में दे रहे हो, आप चाहते क्या हो? हमें तो यह समझ में नहीं आ रही है, वह ही जनता ने आपका बदला लिया है। आप शिक्षा को निजीकरण में दे रहे हो। मतलब, आपने यही सोचा था कि धन्ना सेठों को देकर इन सरकारी सम्पत्तियों का पाप काटे, तो उसका परिणाम आपने भुगता।

मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि जिस तरह से सरकार में आने के बाद स्थानीय निकायों की जिस तरह से अपने वह साक्षरता का रखा था, उसमें आम आदमी को चुनाव लड़ने से आपने रोका। उसमें हमारी सरकार ने आते ही यह फैसला लिया कि कोई भी आदमी चुनाव लड़ने से वंचित नहीं रहे। जनता है, जिसको चुने अपने आप चुने और यह एम.एल.ए., एम.पी. के लिए लागू नहीं है, सिर्फ निकाय और जिला परिषद और पंचायत समिति के लिए ही सिर्फ लागू थे तो वह एक बहुत बड़ा निर्णय लिया। सीधा चुनाव नगर परिषद का किया, यह भी बहुत अच्छी बात है। धन-बल से खरीद-फरोख्त नहीं होगी और अच्छा आदमी चुनकर आ जाएगा और जिस तरह से पंचायती राज के पांच विभाग थे उनको आपने पंगु करने की कोशिश की। सारे पावर छीन लिये। आज आप पूछ लो, जिला परिषद और पंचायती राज के पास, प्रधान के पास कोई पावर आपने रखे? जितने भी पांच विभाग थे, उन पांचों विभागों की

(श्री मेवाराम जैन)

आपने हालत खराब कर दी और जितनी भी आप बात करें, हमारे बाड़मेर में मेडिकल कालेज, साढ़े पांच साल, छह साल पहले स्वीकृत हुआ। पांच साल आपकी सरकार रही, उस मेडिकल कालेज को आप शुरू नहीं कर पाए। पांच साल तक नहीं कर पाए, हमारी सरकार के टाइम सैंक्शन हुआ पर आप पांच साल में उसको शुरू नहीं कर पाए, इससे ज्यादा बड़े दु:ख की बात क्या है? अगर शुरू होता तो आज कितने लोगों को यह सुविधा मिलती? बाड़मेर में कोई आए तो सीधा ही रैफर कर देते हैं जोधपुर और गुजरात में तो यह किस तरह से आपने इसको देखा। प्रदेश में 18 हजार से ज्यादा स्कूलें बंद कर दीं।

आपने आनन-फानन में अभी चर्चा हो रही थी अध्यापकों की कि आपके समय में ज्यादा खाली पद थे और हमने भर दिये। आपने भर नहीं दिये, आपने स्कूलें ही बंद कर दीं और पद खतम कर दिये तो कहां से आपके पद खाली रहेंगे? हमारी सरकार आयी है, सोच रही है और जो वास्तव में स्कूलें बंद नहीं होनी चाहिये, उसको वापस पुन: चालू करने का निर्णय भी लिया है और वह चालू होगी भी।

श्री सभापति: समय सीमा का ध्यान रखना माननीय सदस्य।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): मैं इसी पर बोल रहा हूं। सभापति महोदय, मैं दूसरी अन्य बातों पर जा ही नहीं रहा हूं। खाली इसी पर बोल रहा हूं इसलिये आप मेहरबानी करके मुझे समय दें। खाद्य सुरक्षा की बात है, आपके समय में गरीब लोगों के, गरीब परिवारों के नाम काटे गये और वह गरीब लोग वंचित रहे और हमारी सरकार ने निर्णय लिया है कि जो गरीबों के नाम कटे हैं, उन परिवारों को वापस नि:शुल्क गेहूं मिले। यह भी वापस होगा।

आज विद्युतीकरण की बात करें। दीनदयाल कुटीर ज्योति योजना का नाम तो आपने राजीव गांधी की जगह बदल दिया, कोई बात नहीं, पर पांच साल के अंदर इस योजना का आपने हाल क्या किया? लोगों ने कितने साल पहले डिमाण्ड राशि भर दी, आप उसके कनेक्शन नहीं कर पाये। मैं उदाहरण दूंगा बाड़मेर की 51 ग्राम पंचायतों में 12 पंचायतों का काम नहीं कर पाये और आपके 39 पंचायतों के हाल यह हैं कि आपने कहा कि हम मार्च तक कर देंगे, कौनसे मार्च में कर दोगे, मुझे पता नहीं। ऐसे असत्य आश्वासन और जिस तरह से इन स्कीमों का हाल किया है, अब आने वाले दिनों में आप देखना कि उसमें भी कि इसने वोट कांग्रेस को दिया है या बीजेपी को दिया है, ऐसा कभी हुआ है। पानी, बिजली, शिक्षा, चिकित्सा में कि इसने वोट कांग्रेस

(श्री मेवाराम जैन)

को दिया है तो इसके बिजली का खम्भा मत लगाना और कनेक्शन मत देना, ऐसा हमने कभी नहीं किया। यह हालत हुई और उसका नतीजा आपने यह भुगता।

आज बजरी का संकट कैसे है, क्या हालात हैं? बजरी माफिया कैसे पनप रहा है? सभापति महोदय, क्या हालात हैं? अब यह कह रहे हैं विकास की बात करें। बजरी आपके पास नहीं, बजरी के बिना एक कमरा भी आप बना नहीं सकते, राजस्थान का विकास करोगे कैसे? उसके लिये कोई ठोस पहल नहीं की गयी, क्योंकि बजरी के अंदर नीचे से लगाकर ऊपर तक सारे अधिकारी और विभाग मिला हुआ था और भ्रष्टाचार में डूबे हुए थे इसलिये वह कार्यवाही नहीं हुई और इसकी वजह से राजस्थान की जनता भुगती।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समय का ध्यान रखें।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि इस बजरी के लिये तुरन्त ऐसा निर्णय करें कि जनता को शीघ्र राहत कैसे मिले, यह निवेदन करना चाहता हूं।

श्री सभापति: समाप्त करें। माननीय सदस्य, समय सीमा का ध्यान रखें और अपनी बात समाप्त करें।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): मैं जल्दी समाप्त करने की कोशिश करूंगा।

श्री सभापति: प्लीज, समय की सीमा अपनी है, मर्यादा है।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): मैं नगर निकायों की बात करना चाहूंगा। पांच साल पूर्व में आप देख लें, हमारी अशोक जी गहलोत की सरकार के समय किस तरह से गांवों और शहरों का विकास हुआ।

श्री सभापति: मुझे सभी और भी माननीय सदस्यों को अवसर देना पड़ेगा। सभी माननीय सदस्यों को अवसर देना पड़ेगा, मेहरबानी करें।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): मैं पांच मिनट में खतम ही कर रहा हूं, पांच मिनट लूंगा।

श्री सभापति: पांच मिनट नहीं, प्लीज एक मिनट में आप अपनी बात समाप्त करें। एक मिनट में अपनी बात समाप्त करें अपनी।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): शहरों के अंदर किस तरह से कच्ची

(श्री मेवाराम जैन)

बस्तियों का विकास हो, कच्ची बस्तियों के लोग बैठे हैं, उनको पट्टे देने की बात पिछले पांच सालों के अंदर इन्होंने बंद कर दिया और मैं निवेदन करना चाहूंगा कि शहरों के अंदर कैसे शहरों का विकास हो, उनमें लोग बैठे हैं, उनको पट्टे मिले। कच्ची बस्तियों का कैसे विकास हो, इस पर भी ध्यान देना होगा, क्योंकि पिछले पांच सालों के अंदर आप देख लें बाड़मेर नगर परिषद में 28 पट्टे पांच साल में मिले हैं, सिर्फ 28 पट्टे, अब बताओ क्या हालत होगी। इसलिये मैं निवेदन करना चाहूंगा कि नगर निकायों के अंदर भी यह काम करायें।

श्री सभापति: सहयोग करें माननीय सदस्य।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): सभापति महोदय, मैं ज्यादा नहीं कहना चाहूंगा और सिर्फ कानून-व्यवस्था की बात करके ही खतम कर दूंगा। पिछले पांच सालों के अंदर कानून-व्यवस्था की हालत आपने कैसे देखी होगी। बाड़मेर के अंदर शराब का ट्रक पकड़ा। वह शराब का ट्रक थाने में खाली करवाया। दूसरे दिन वह आधा ट्रक थाने वालों ने ही बेच दी और अगला थाना जो आ रहा था, उसने उसको पकड़ लिया। अब यह पूछो शराब थाने के अंदर पकड़ी हुई और उसको बेचना और फिर दूसरे थाने के अंदर, उसी शराब को पकड़ना, इससे ज्यादा शर्मनाक बात और क्या हो सकती है। सभापति महोदय, यह हालत कानून-व्यवस्था की है कि राजस्थान के अंदर किस तरह से कानून-व्यवस्था के हालात हैं, आप खुद समझ सकते हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जिस तरह से अभी एक महीना ही हुआ है, आवश्यकता होगी पानी विभाग के अंदर भी जितने पद खाली हैं, ...

श्री सभापति: समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): उन पदों पर जल्दी से जल्दी आप जे.ईएन., ए.ईएन. टैक्निकल हैल्पर और मजदूर लगावें। हालात यह हैं कि आज सारे पदों पर इन्होंने कोई भर्ती नहीं की, इसकी वजह से सारे पद खाली पड़े हैं। स्कीमों को संभालने वाला नहीं है, इसलिये मंत्री महोदय भी बैठे हैं, सभापति महोदय, मैं चाहूंगा कि जल्दी से जल्दी पानी के लिये, जो बहुत महत्वपूर्ण है, पद भरे जायें और भर्ती की जाए। आज लेबर नहीं है, अकाल राहत है, वहां पानी की व्यवस्था के लिये टैंकरों की स्वीकृति दी जाए।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, श्री रामलाल शर्मा। माननीय सदस्य, प्लीज समाप्त करें।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): मैं समाप्त ही कर रहा हूं। सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इन सारी व्यवस्थाओं पर ध्यान दिया जाए। धन्यवाद।

श्री सभापति: प्लीज बैठें। श्री रामलाल शर्मा। माननीय सदस्य, दस मिनट की समय सीमा में आप अपनी बात को समाप्त करेंगे। मुझे सभी माननीय सदस्यों को अवसर देना है और सभी माननीय सदस्य यदि इस तरह से कोआपरेट नहीं करेंगे तो रात के आठ बजेंगे। प्लीज आप सब कोआपरेट करें। माननीय सदस्य, दस मिनट में आप अपनी बात समाप्त करें।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): माननीय सभापति महोदय, मैं तो यह निवेदन कर रहा हूं कि आपके घर जाने का रास्ता, मेरे घर जाने का रास्ता एक ही है तो पांच मिनट और बोनस में दे दी जाएं, कोई दिक्कत नहीं है।

श्री सभापति: दस मिनट में आप अपनी बात समाप्त करें माननीय सदस्य।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): माननीय सभापति महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय के द्वारा इस पवित्र सदन के अंदर जो अभिभाषण पढ़ा गया, उस अभिभाषण के माध्यम से हम सब माननीय सदस्य यह जानना चाहते थे कि आखिरकार सरकार आने वाले समय के अंदर क्या करना चाहती है। सभापति महोदय, मैं आपको पूर्ण आश्वस्त करता हूं कि मैं इस अभिभाषण से बाहर एक भी शब्द नहीं बोलूंगा, लेकिन, सभापति महोदय, मुझे दु:ख इस बात का हुआ कि इस अभिभाषण के......(व्यवधान)

श्री सभापति: आप बहुत भाग्यशाली हैं, दु:खी मत होइये। आप भाग्यशाली हैं, साढ़े सात करोड़ लोगों में से आप एक चुनकर आये हैं, काहे को अपने भाग्य को कोस रहे हो?

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): नहीं-नहीं, मुझे दु:ख इस बात का हुआ, सभापति महोदय, इस अभिभाषण को पूरा पढ़ने के बाद एक भी जगह ऐसा नहीं लगा कि सरकार इस प्रदेश के साढ़े सात करोड़ के अवाम् का कल्याण करने की मंशा रखती है। सभापति महोदय, सबसे पहले इस पूरे अभिभाषण को पढ़ने के बाद में जो मुझे लगा, सिर्फ व्यवस्था की जाएगी-11 बार, कदम उठाये जाएंगे-9 बार, कार्यवाही की जाएगी-8 बार, सुनिश्चित किया जाएगा-12 बार, समुचित विकास होगा-5 बार, सुदृढ़ किया जाएगा-8 बार, बल दिया जाएगा-7 बार और प्रभावी कार्यवाही करेंगे-6 बार। मेरे ख्याल से इससे ज्यादा उपलब्धि इस अभिभाषण के अंदर कोई है नहीं।

(श्री रामलाल शर्मा)

सभापति महोदय, इस अभिभाषण के प्रथम उद्बोधन में लिखा गया कि हमारी सरकार संवेदनशील रहेगी, पारदर्शी रहेगी, जवाबदेही रहेगी और सुशासन भी हम देंगे। लेकिन मेरे ख्याल से एक चीज तो स्पष्ट हो गयी, सभापति महोदय, कि राजस्थान के अंदर साक्षरता का दर काफी बढ़ गया, काफी पढ़े-लिखे लोग हैं। अपराध करने वाले लोग भी पढ़े-लिखे हैं और अपराध करने वाले लोग भी पढ़े-लिखे होने की वजह से यह अभिभाषण भी उन्होंने पढ़ लिया और पढ़ने के बाद में इसमें एक भी शब्द यह नहीं लिखा कि राजस्थान की सरकार कानून-व्यवस्था के ऊपर नकेल डालने का काम करेगी, कानून-व्यवस्था को ठीक करने का काम करेगी, अपराधियों के ऊपर अंकुश लगाने का काम करेगी या उसका जो ध्येय था 'अपराधियों के अंदर डर, आमजन में विश्वास' पैदा करने का काम करेगी और मेरे ख्याल से इस अभिभाषण को पढ़ने के बाद में जो अपराध की शुरूआत हुई, सभापति महोदय, 16 जनवरी जेबकतरों का दुस्साहस, सी.एम. निवास के सामने ही जेब काटकर निकाले एक लाख, अजमेर निवासी सतीश ने बताया कि वह 16 जनवरी को दोपहर 3.45 बजे मुख्य मंत्री निवास पर जन सुनवाई में आया था। गाड़ी पार्क कर मुख्य द्वार पर पहुंचा तो जन सुनवाई खतम हो चुकी थी। कुछ नेता बाहर निकल रहे थे, मीडियाकर्मियों ने उन नेताओं को घेर रखा था। मैं भी उस भीड़ का हिस्सा बन गया। कुछ देर बाद में मैंने देखा तो मेरी पेंट की जेब में से एक लाख रुपये गायब थे। सभापति महोदय, दूसरा 9 जनवरी, राहुल गांधीजी की सभा की तैयारियां चल रही थीं। कड़ी सुरक्षा को ठेंगा दिखाकर चुरा ले गये विद्युत ट्रांसफार्मर।

श्री सभापति: दस मिनट में आपको अपनी बात समाप्त करनी है माननीय सदस्य।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): सभापति महोदय, मैं दस मिनट में ही पूरी बात कहूंगा। जयपुर जिले की कोटखावदा के अदंर घर में घुसे डकैत, महिला के कानों के तोड़े टाप्स, सामना किया तो की फायरिंग। सभापति महोदय, तीसरी बात मैं कहना चाहूंगा पुलिस को सूचना, फिर भी लगातार वारदात को अंजाम दे रहे चोर, 17 जनवरी। सभापति महोदय, जयपुर ही पढ़ रहा हूं सिंधी कैम्प बस स्टैण्ड, आधे घंटे में दो टिकट विण्डों से 31 हजार उड़ाये। 8 जनवरी, पैदल घर जा रही युवती का बाइक सवारों ने छीना पर्स। 20 दिसम्बर, एक ही दिन में 17 वाहन चोरी, यह तो बानगी, सभापति महोदय,

(श्री रामलाल शर्मा)

मैंने आप सबके सामने इस नाते रखी है कि सरकार कितनी संवेदनशील है, कानून-व्यवस्था को कायम रखने के लिये। (व्यवधान).

(15.00 बजे)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): सभापति महोदय, माननीय सदस्य से कहो, वह यह भी बता दें कि कोटा में इनकी पार्टी के विधायक के पति को थाने में बहुत बुरी तरह मारा था। पांच मुकदमे हुए। उसमें से तीन मुकदमे चालान हो गए। आपकी पार्टी के विधायक के पति को ...(व्यवधान) वह भी हिसाब दे दो यहां पर।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजिए।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): आप तो गांधी परिवार का गुणगान करो। (व्यवधान) हम सुनते थे कि संयम लोढ़ाजी बहुत तर्कसंगत बात करते थे।

श्री धर्मेन्द्र कुमार (पीलीबंगा): माननीय सदस्य, आप बता दीजिए कि आप कौनसी पार्टी की वकालत कर रहे हो और कौनसी पार्टी से जीत कर आये हो?

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): इनका सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। (व्यवधान)

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): आपकी पार्टी का नाम तो बता दो लोढ़ाजी। (व्यवधान) आप कौनसी पार्टी से जीत कर आए हो?

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): पुलिस वाले से तीन-तीन मुकदमे किए और बुरी तरह पीटा। (व्यवधान) शर्म से डूब मरना चाहिए? (व्यवधान)

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): ये बीच में क्यों बोल रहे हैं। इनको किसने कहा है बीच में बोलने के लिए?

श्री सभापति: विराजिए।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): हम बैठ जाएंगे, पर इनको भी बैठाओ। (व्यवधान) सभापति महोदय, इनको बिठायें आप।

श्री धर्मेन्द्र कुमार (पीलीबंगा): कौनसी पार्टी की वकालत कर रहे हो? (व्यवधान)

श्री सभापति: प्लीज, प्लीज, विराज जाएं आप।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): आसन की ओर अंगुली नहीं करें आप। (व्यवधान)

श्री धर्मेन्द्र कुमार (पीलीबंगा): आप तय तो कर लो कि कौनसी पार्टी के साथ रहना है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, मुझे बाध्य होकर पांच मिनट बाद आपको बैठाना पड़ेगा। मैं फिर आपसे कह रहा हूं। समय की अपनी सीमा है। आप विराजिए।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): सभापति महोदय, मैं इस अभिभाषण के बाहर नहीं जा रहा। मैं किसी के ऊपर कोई कमेन्ट्स नहीं कर रहा हूं। यह आपकी जिम्मेदारी है कि माननीय सदस्यों को आप नियंत्रित करें।

श्री सभापति: देखिए, मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि समय की सीमा है। प्लीज, चौमूं से आने वाले माननीय सदस्य, एक बार विराजें आप। समय की सीमा है। आप लोग यदि यह नहीं चाहते कि सब लोग बोलें, मुझे कोई दिक्कत नहीं। अगर यदि आप चाहते हैं कि सारे के सारे जो माननीय सदस्य यहां पर बोलना चाहते हैं, उन्हें अवसर तभी मिलेगा, जब आप सहयोग करेंगे। (व्यवधान) प्लीज, आप अपने स्थान पर जाइए। सहयोग करें आप। पांच मिनट में अपनी बात समाप्त करिए आप।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): सभापति महोदय, मुझे तो आप टाइम देंगे तो मैं तीन मिनट में ही पूरी कर लूंगा।

श्री सभापति: सीधे अपने अभिभाषण पर आइए आप।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन यह कर रहा था, सरकार ने यह कहा है कि हम सम्पूर्ण कर्ज माफी करेंगे लेकिन सम्पूर्ण कर्ज माफी के आधार पर कई लोगों ने यह सोचा कि मेरे ऊपर दस लाख रुपये का कर्जा है। सम्पूर्ण कर्ज माफी के अन्दर मेरा भी दस लाख रुपये का कर्ज माफ होगा लेकिन जिस तरीके से किसानों को प्रदेश के अवाम को मुगालते में रखकर सत्ता तक पहुंचने वाली इस सरकार ने दो लाख रुपये की कर्ज माफी की घोषणा की। अब ये दो लाख रुपये का कर्ज माफ कैसे करेंगे? यह सहायता कैसे पहुंचाएंगे? उसमें भी कई प्रकार के बेरीकेड्स लगाने का काम सरकार कर रही है।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सिर्फ सरकार से इतना जानना चाहता हूं कि आपने महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण से जो शब्द कहलवाये, आप तो तिथि निर्धारित कर दो कि किसान के सिर पर जो कर्ज है, वह कितनी तारीख को आप बैंक में जमा करवा दोगे, कितनी तारीख

(श्री रामलाल शर्मा)

तक उसका कर्ज माफी का प्रमाण पत्र उसके हाथ में थमा दोगे? तारीख बताने का काम नहीं कर रहे। पूरे अभिभाषण के अन्दर एक भी जगह इन्होंने ऐसे शब्दों को काम में नहीं लिया कि जो यह तय करे इतने समय के अन्दर हम यह काम करने वाले हैं। आज वास्तविकता यह है कि किसान के घर नोटिस जा रहे हैं, किसान कर्ज जमा नहीं करा रहा। बैंक वाले दूसरे को कर्ज दे नहीं रहे। एक भयावह स्थिति प्रदेश के अन्दर बनी हुई है। इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से चाहूंगा कि इसमें आप अपनी नीयत स्पष्ट करें कि कब तक किसानों को ऋण माफी का लाभ मिल जाएगा?

सभापति महोदय, एक गम्भीर विषय है, जिसका इस अभिभाषण में कहीं पर भी उल्लेख नहीं है। सबसे ज्यादा अगर प्रदेश और अवाम दुःखी है तो वह है मिलावट। एक शब्द मिलावट के बारे में इस अभिभाषण के अन्दर नहीं कहा गया। आज जिस तरीके से हरित क्रांति के नाम पर हमने उत्पादन तो बढ़ा लिया लेकिन उसके साइड इफेक्ट जो निकलकर आये हैं, बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य भी कहेंगे हां, बीकानेर के हास्पीटल में इलाज कराने के लिए एक ट्रेन आती है। उस ट्रेन को कैंसर के नाम से जाना जाता है। सभापति महोदय, खुशी मुझे तब होती तो जब इस अभिभाषण के अन्दर यह कहते कि मिलावटखोरों के खिलाफ हम सख्त कार्यवाही करेंगे, सख्त कानून बनाने का काम करेंगे। अगर यही चलता रहा तो आने वाले समय में आने वाली पीढ़ी हम सबको दोषी मानेगी क्योंकि तब समय था आपके पास, इस मिलावट के खिलाफ अभियान क्यों नहीं चलाया।

सभापति महोदय, पशुधन घट रहा है। उसके बावजूद भी अगर किसी ने रात को यह कह दिया कि मुझे कल दस क्विंटल दूध चाहिए। एक भी डेयरी वाला यह नहीं कहता कि दस क्विंटल दूध मेरे पास नहीं है। आखिरकार वह दूध, पनीर और मावा आ कहां से रहा है? सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि सरकार की यदि मंशा स्पष्ट है तो एक महीने के अन्दर सख्त कानून बनाकर उनके खिलाफ कार्यवाही करने की आवश्यकता है। तब मैं जानूंगा कि वास्तव में सरकार संवेदनशील है। सभापति महोदय, मेरा दूसरा निवेदन इतना ही है कि जो कानून बना हुआ है, उस कानून के अन्दर भी चौदह दिन के अन्दर संबंधित अधिकारी को जो लैबोरेट्री है, उसकी जांच रिपोर्ट पेश करने की आवश्यकता है लेकिन उसके अन्दर भी आज दिन तक ऐसी कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं हुई। किसी भी मिलावटखोर को कोई ऐसी

(श्री रामलाल शर्मा)

सज़ा नहीं मिली जिसके लिए वह एक तरीके से दूसरे लोगों के लिए नसीहत बन सके।

सभापति महोदय, मेरा तीसरा निवेदन यह है, जिसका अभिभाषण में कहीं पर उल्लेख नहीं किया गया है। हां, यह बात जरूर है, पृष्ठ 29 पैरा नम्बर 69 में जनसंख्या के ऊपर जरूर चिन्ता व्यक्त की गई है। पैरा 70 के अन्दर शहरीकरण के ऊपर भी चिन्ता जाहिर की गई है। अगर आपको ध्यान हो, एक कानून इस प्रकार का बना था कि 01 जुलाई, 1995 के बाद यदि किसी व्यक्ति के तीसरी संतान होती है तो वह स्थानीय निकाय और पंचायती राज के चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य है। सभापति महोदय, सरकार क्या यह कदम उठाने के लिए तैयार है कि 26 जनवरी, 2020 के बाद अगर तीसरी संतान किसी व्यक्ति के होती है तो राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली सारी सुविधाओं से उसको महरूम रखा जाएगा? आराम से जनसंख्या नियंत्रण भी हो जाएगी और जो ग्रामीण क्षेत्र से लोग पलायन करके शहरों की ओर आ रहे हैं, वह समस्या भी मिट जाएगी। क्या सरकार अभिभाषण के उत्तर में, सदन के नेता महोदय जब उत्तर दें, उस समय मैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि क्या ऐसा कानून बनाने की मंशा सरकार रखती है? जनसंख्या नियंत्रण के ऊपर भी, कि जो व्यक्ति इस कानून से बाहर जाकर कार्य कर रहा है, उसको राज्य सरकार की सुविधाओं से महरूम रखा जाए?

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): सभापति महोदय, मेरा आपसे एक और निवेदन है, पृष्ठ संख्या 35 पैरा नम्बर 84 पर सड़क दुर्घटनाओं के कारण अनेक लोगों की अकाल मौत होती है। सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए आवश्यक कार्यवाही की जाएगी। अगर वास्तव में सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने की आपकी मंशा है, आपने चुनावी भाषणों में बहुत जोर-जोर से कही है, मैं मुख्य सचेतक महोदय से कहूंगा, मेरे क्षेत्र में भी जाकर सदन के नेता कह कर आये थे कि गोविन्दगढ़ तक मैट्रो ट्रेन चलाएंगे। इस अभिभाषण में अगर आप कह दें कि गोविन्दगढ़ तक मैट्रो ट्रेन अगले साल चल जाएगी तो मैं भी उनको माला पहनाकर स्वागत करता लेकिन इसमें कहीं पर भी मैट्रो ट्रेन का जिक्र नहीं है। अगर वास्तविकता में आपको चिन्ता है तो आप एक प्रयोग तो करके देखें। जयपुर से दौसा, जयपुर से रींगस, जयपुर से चाकसू, इन शहरों के बीच में अगर आप डेमो ट्रेन चलाने का प्रयास करोगे तो आपको पता चल

(श्री रामलाल शर्मा)

जाएगा, मेरे ख्याल से सड़क दुर्घटनाएं भी कम होंगी। लगभग 25 से 30 हजार लोग प्रतिदिन सौ किलोमीटर की परिधि से जयपुर अप-डाउन करते हैं। आखिरकार सड़क के अन्दर दुर्घटनाओं के शिकार भी यही लोग होते हैं तो इस प्रकार से सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने का प्रयास करोगे।

सभापति महोदय, सेना भर्ती के बारे में पृष्ठ संख्या 33 पैरा 78 में कहा गया कि नौजवानों को सेना में शामिल करने के लिए शेखावाटी सहित अन्य क्षेत्रों में भारतीय सैनिक बलों और अर्द्ध सैनिक बलों में भर्ती के लिए प्रशिक्षण केन्द्र खोले जाएंगे लेकिन अगर इसकी जगह आप यह कहते कि प्रदेश के अन्दर जितने भी विश्वविद्यालय हैं, उनमें सैन्य प्रशिक्षण के लिए कोर्स शुरू कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से बेहतर होता। इस अभिभाषण में कहीं पर भी राजस्थान में सबसे ज्यादा अन्तरराष्ट्रीय सीमा राजस्थान के क्षेत्र से जुड़ती हुई जाती है। कहीं पर भी राष्ट्रीय सुरक्षा के बारे में आपने चिन्ता जाहिर नहीं की। उस सीमा पार से जिस तरीके की संदिग्ध गतिविधियां होती हैं, उनकी रोकथाम के बारे में आपने कोई चिन्ता नहीं की। बार्डर के ऊपर किस तरीके से आप क्राइम को कन्ट्रोल करोगे, इसकी आपने कोई चिन्ता नहीं की। शायद इसलिए नहीं की होगी, बार्डर वालों ने आपको अच्छा सपोर्ट किया है, उनको नहीं चाहते कि कोई परेशानी हो।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त करें। एक मिनट में समाप्त करें आप अपनी बात।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): सभापति महोदय, आपने गौवंश की चर्चा की। पृष्ठ 08 पैरा नम्बर 20 गौशालाओं के ऊपर। अगर गायों की वास्तव में चिन्ता है तो, मुख्य सचेतक महोदय यहां विराजमान हैं, मैं कहूंगा कि आप एक आदेश निकलवा दो। जिसका हक है, उसको उसका हक मिल जाए। गायों की स्थिति बिगड़ने का प्रमुख कारण यह है कि उसकी गोचर जमीन के ऊपर लोग कब्जा करके बैठे हैं। आप तो एक काम कर दो कि प्रदेश की जितनी भी गोचर जमीन है, वह सारी की सारी गोचर जमीनों को खाली कराने का एक आदेश सरकार से जारी करवा दो। आराम से गायों की व्यवस्था हो जाएगी। गायें जाएंगी कहां? उनको भी जीने का अधिकार है। सभापति महोदय, सरकार ने काफी महामहिम राज्यपाल महोदय से कहलवाया कि हम गौवंश के प्रति चिन्तित हैं।

आपकी सरकार तीन महीने का अनुदान देती थी, हमारी सरकार ने

(श्री रामलाल शर्मा)

छह महीने का अनुदान किया, अगर आप में संवेदनशीलता है तो आप प्रदेश की समस्त गोशालाओं को बारह महीने का अनुदान शुरू करो, आखिरकार गायों की दशा अपने आप ही सुधर जाएगी।

श्री सभापति: श्री लक्ष्मण मीणा (बस्सी)।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): सभापति महोदय, एक अंतिम निवेदन कर रहा हूं।

श्री सभापति: श्री लक्ष्मण मीणा (बस्सी)। माननीय सदस्य।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): सभापति महोदय, एक अंतिम निवेदन है। लक्ष्मण जी, लक्ष्मण जी, राम की बात पूरी हो जाए।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त करें आप।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): एक मिनट, राम की बात पूरी हो जाए, फिर लक्ष्मण का नम्बर आएगा। लक्ष्मण जी, एक मिनट।

सभापति महोदय, एक अंतिम निवेदन करना चाहूंगा। बिजली के बिलों के बारे में इस सदन के नेता ने कहा कि, साहब, बिजली के बिल एक परसेंट भी नहीं बढ़ाये जाएंगे, सभापति महोदय, आपको भी पता होगा, आप भी ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, एल.ई.डी. के नाम पर 150 रुपये की वसूली इन्होंने शुरू कर दी, वी.सी.आर. भरना शुरू कर दिया, जून, 2018 के बाद में आप ट्रांसफार्मर नहीं दे रहे हो। आखिरकार रात को बिजली दे रहे हो, आपने दिन में बिजली देने की बात कही थी। पिछले एक महीने से लगातार शीतलहर है, आपने अभी तक गिरदावरी कराने का प्रयास नहीं किया, आप मुआवजा कहां तक दोगे? तो मेरी आपसे मांग है कि पूरे प्रदेश में तत्काल गिरदावरी करा कर ...

श्री सभापति: श्री लक्ष्मण मीणा। प्लीज, प्लीज, कोआपरेट करें।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): एक मिनट।

श्री सभापति: नहीं, बिलकुल नहीं। आप विराजिए, विराजिए आप। (व्यवधान)

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): सभापति महोदय, अंतिम निवेदन है।

सभापति महोदय, अंतिम निवेदन इतना ही है हमारी सरकार ने 13 जिलों की साढ़े सैंतीस हजार करोड़ की एक पेयजल योजना बनायी थी, 13 जिलों में पानी पहुंचाने के लिए, इस अभिभाषण में कहीं पर भी उस योजना

(श्री रामलाल शर्मा)

का जिक्र नहीं है। मुझे आशंका है कि सरकार उसके प्रति संवेदनशील नहीं है। सदन के नेता रिप्लाई देते समय कहें कि उसके साथ-साथ यमुना का पानी लाने के लिए भी, क्योंकि आपका जिला भी पानी के लिए तरस रहा है, हमारा जिला भी पानी के लिए तरस रहा है, इन दोनों जिलों के लिए यमुना का पानी लाना बहुत जरूरी है, प्राकृतिक स्रोतों को पुनर्जीवित करना जरूरी है। आने वाले समय में जनता को पानी पिलाने के लिए प्राकृतिक स्रोतों के लिए, वाटर रिचार्ज के लिए सरकार क्या करेगी? इसके बारे में भी स्पष्ट करें। आपने अवसर दिया, आपको धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री लक्ष्मण मीणा। माननीय सदस्य, मुझे बार बार नहीं टोकना पड़े, समय सीमा का ध्यान रखें और कोई ऐसी उकसाने वाली बात नहीं करें जिससे दूसरे आपको इन्टरवीन करें, प्लीज।

श्री लक्ष्मण मीणा (बस्सी): माननीय सभापति महोदय, मुझे माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर मेरा पक्ष रखने का जो अवसर दिया उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। माननीय सभापति महोदय, क्योंकि मैं पहली बार यहां सदन में चुनकर आया हूं।

श्री सभापति: स्वागत है आपका।

श्री लक्ष्मण मीणा (बस्सी): मैं चार-पांच दिन से माननीय सदस्यों के अभिभाषण पर विचार सुन रहा था। सब ने अपने-अपने हिसाब से किसानों के बारे में चिंता की है। माननीय सभापति महोदय, सरकार ने सबसे पहले जो निर्णय लिया है किसानों की कर्ज माफी का, उसका तो मैं स्वागत करता हूं लेकिन यह चीज इसमें स्पष्ट नहीं है कि इसमें एक शब्द यूज किया गया था कि जो डिफाल्टर है, कालातीत और अवधि पार जिनका ऋण हो गया, उन्हीं के माफ किये जाएंगे। इसके बारे में मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करूंगा कि किसानों में इस तरह की भ्रांति पैदा नहीं की जाए कि जो डिफाल्टर है, जो जानबूझकर अपना ऋण नहीं चुकाता है, जो ऋण लेकर अपनी खेती के विकास में नहीं लगाकर कहीं अन्य दूसरे कामों में लगाता है और डिफाल्टर होता है उसका माफ कर दिया जाए तथा जो सही तरीके से सही समय पर देता है उसका माफ नहीं किया जाए। मेरी आपके माध्यम से सरकार से गुजारिश है कि सभी किसानों का, चाहे कितना भी माफ करें लेकिन सभी किसानों को एट-पार रखा जाए, सबका समान रूप से ऋण माफ होना चाहिए।

किसानों की दशा सुधारने के बारे में यहां काफी-कुछ बोला गया है।

(श्री लक्ष्मण मीणा)

प्रदेश के किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए ऋण माफी के अलावा भी बहुत सारे कदम उठाने की आवश्यकता है। जब तक किसान के खेत में पानी और बिजली समय पर नहीं पहुंचेगी, उनके विपणन की व्यवस्था ठीक नहीं होगी, जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस निर्धारित की जाती है, उनके अनुसार उनकी परचेजिंग नहीं होगी, समय पर उनका भुगतान नहीं होगा तो किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार होना सम्भव नहीं होगा।

तारानगर से आने वाले माननीय सदस्य एक सुझाव दे रहे थे ईस्टर्न कैनाल प्रोजेक्ट के बारे में। माननीय सभापति महोदय, राजस्थान की चाहे कोई भी सरकार आयी हो, सबने सिंचाई का विस्तार करने के लिए कुछ न कुछ काम किया है। वेस्टर्न राजस्थान हो, आप हिमालय से पानी लेकर आये और बाड़मेर तक लाये, सरदार सरोवर से पानी लेकर आपने बाड़मेर तक पहुंचाया, हाड़ौती क्षेत्र में भी काफी काम हुआ है लेकिन जो सिंचाई का विस्तार ईस्टर्न राजस्थान के 13-14 जिलों में होना चाहिए था, उस पर कोई विशेष काम नहीं हुआ है। मैं आपके माध्यम से सरकार से गुजारिश करूंगा कि यह जो ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट है, जिसकी लागत करीबन 37 हजार करोड़ बतायी गयी है, इसकी डी.पी.आर. भी बनायी गयी है, उसको इम्प्लीमेंट किया जाए।

इसमें शायद एक बाधा आ सकती है कि इसकी जो कोस्ट है, जो एस्टीमेटेड कोस्ट है वो अभी 37 हजार करोड़ है। शायद हो सकता है कि राज्य सरकार के पास इतने संसाधन नहीं हों। तो मैं आपके माध्यम से सरकार से भी निवेदन करूंगा और विपक्ष से भी निवेदन करूंगा कि वहां इनकी सरकार है, इसको एक राष्ट्रीय प्रोजेक्ट घोषित करवाया जाए ताकि आपको भी अगले चुनावों में काफी फायदा होने की गुंजाइश है और फिर इसको वो करे, इससे आपके 13 जिलों में सिंचाई भी होगी, ड्रिंकिंग वाटर भी मिलेगा और भू-जल के स्तर में भी सुधार होने की पूरी-पूरी गुंजाइश है।

मेरे को जहां तक जानकारी है, इसकी जो डी.पी.आर. बनायी है, जिसमें चम्बल नदी के बेसिन में स्थित नदियां हैं जिसका माननीय सदस्य हवाला भी दे रहे थे, उनमें कुनू है, आपकी पार्वती है, आपके मेज नदी है, आपकी बनास नदी है और सबसे बड़ी एक कालीसिंध है, उनका बहुत सारा जो पानी वेस्ट जाता, सरप्लस वाटर है, उसको लाकर इस इलाके को बहुत मजबूती दी जा सकती है। अगर यह काम किया जाता है तो मेरे ख्याल से कुछ समय बाद में किसान आपसे ऋण माफी की कोई बात ही नहीं करेगा।

(श्री लक्ष्मण मीणा)

इसके अलावा विपणन की जो व्यवस्था है, माननीय सभापति महोदय, किसानों के पास खूब अनाज पैदा होता है, सब्जियां होती हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस भी निर्धारित कर रखी है लेकिन जब तक मंडियों का जाल नहीं बिछाया जाएगा और मंडियों तक सामान को, उनकी जो प्रोड्यूज है उसको लाने के लिए सड़कें अच्छी नहीं होंगी तो उनको किसी भी तरीके से फायदा नहीं मिलेगा। यह देखा गया है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस तो सरकार ने तय कर दी लेकिन वहां तक इनकी परचेज होती है तो किसानों की परचेज को खरीदा नहीं जाता। वहां जो सरकारी अधिकारी लगे रहते हैं उसमें कुछ न कुछ कमी निकालकर और उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है। मेरे को ध्यान है अभी दूदू के किसान को कहा गया कि, भई, आपका मूंग बस्सी की मंडी में बेचा जाएगा, वहां जाइए। बस्सी की मंडी वालों ने कहा, नहीं, आप चाकसू जाइए। तो इस तरीके से किसान लेकर मंडी दर मंडी घूमता फिरे तो वह निराश होकर फिर वापस लाकर अपने घर रखता है और जो प्राइवेट व्यापारी हैं, सेठ हैं, उन्हीं को उसको बेचना पड़ता है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, दो मिनट में अपनी बात समाप्त करें।

एक माननीय सदस्य: पहली बार बोल रहे हैं।

श्री सभापति: मुझे पता है।

श्री लक्ष्मण मीणा (बस्सी): सर, मैं तो पहली बार ही बोल रहा हूं। ...(व्यवधान)

श्री सभापति: समय आपके पास में है, जिसको मर्जी हो एक बार एक साथ सबको बुला लीजिए भले, मुझे दिक्कत थोड़ी है।

श्री लक्ष्मण मीणा (बस्सी): किसानों की स्थिति ठीक करने के लिए उनको ऋण माफी की बजाय अगर उनको ब्याज मुक्त ऋण दिलाया जाता है, जैसे पिछली कांग्रेस सरकार ने एक लाख रुपये तक का यह प्रावधान किया था लेकिन जो पूर्ववर्ती सरकार है उसने विथड्रा किया था।

पशुधन और डेयरी में भी यहां अच्छा स्कोप है। जिन एरियाज में खेती नहीं हो पाती है, रेतीली जमीन है, पानी कम है, वहां पशुधन को बढ़ाने के लिए प्रयास किए जाएं जिससे अच्छी नस्ल के पशु पैदा हों। वहां डेयरी का विकास होगा तो निश्चित रूप से किसानों की स्थिति ठीक होगी।

सभापति महोदय, माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में कहा

(श्री लक्ष्मण मीणा)

गया है कि गौ शालाओं के लिए शेड्स तैयार किए जाएंगे। चारे की व्यवस्था की जाएगी। उनके लिए पेयजल की व्यवस्था की जाएगी। मुझे जहां तक जानकारी है, जितनी भी आज राजस्थान में गौ शालाएं हैं, उनमें जितना भी गौ वंश है, उससे दस गुणा तो बाहर खेतों में घूम रहा है। यह किसानों के लिए जबरदस्त समस्या है। किसान अपनी फसल तैयार करता है और अगर वह एक दिन भी चूक जाता है तो उसकी सारी फसल बर्बाद हो जाती है। इसके लिए भी आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करूंगा कि वह इसके बारे में कोई पालिसी बनाए कि उनको किस तरह से आप हैंडल कर सकते हैं। इससे किसानों को बहुत बड़ी राहत मिलेगी।

सभापति महोदय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में बोला गया है। मैं बस्सी से आता हूं। मैंने देखा है कि बस्सी में पिछली कांग्रेस सरकार के समय में 2 सीएचसी और 5 पीएचसी बनाई। लेकिन आज तक उनको कोई जमीन नहीं मिली। वहां किसी डाक्टर की पोस्टिंग नहीं हुई। जो भी पहले से हास्पिटल थे, उनमें डाक्टर ही नहीं हैं। डाक्टर अगर हैं भी तो वह दूसरी जगह से डेपुटेशन पर लाए हुए हैं। वहां स्वास्थ्य सेवाओं के हालात बहुत खराब हैं। इनमें सुधार की बहुत ज्यादा आवश्यकता है।

सभापति महोदय, शिक्षा के बारे में अभिभाषण में कहा गया है कि पूर्ववर्ती सरकार के द्वारा कुछ स्कूलों को बंद कर दिया गया था। करीबन 27 हजार का फीगर बताया गया है। सरकार ने यह निर्णय लिया है कि उनको पुन: खोला जाएगा। मैं इसका स्वागत करता हूं। यह बहुत अच्छा निर्णय है। इससे लोगों को जो दूर-दूर तक जाना पड़ता था, उनके बच्चों को वहीं शिक्षा मिल पाएगी। शिक्षा गुणवत्तापूर्ण हो, ऐसा अभी नहीं हो रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी प्राइमरी स्कूलों के हालात बहुत खराब हैं। वहां या तो टीचर्स ही नहीं हैं या कक्षा के कक्ष नहीं हैं। वहां टायलेट्स की व्यवस्था नहीं है। पानी की व्यवस्था नहीं है। टीचर्स कभी आते हैं और कभी नहीं आते हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करूंगा कि इस पर विशेष ध्यान दिया जाए ताकि हमारी प्राइमरी एजुकेशन का सुधार हो।

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री लक्ष्मण मीणा (बस्सी): एक मिनट, एक मिनट और लूंगा। मेरे बस्सी विधान सभा क्षेत्र में करीब 10 हजार बच्चे, बच्चियां कालेज जाते हैं। लेकिन वहां राजकीय कालेज नहीं होने की वजह से उनको प्राइवेट कालेज में

(श्री लक्ष्मण मीणा)

जाना पड़ता है। वहां केवल एडमिशन लिया जाता है। वहां कोई पढ़ाई नहीं होती है। वह वहां केवल बी.ए. पास करते हैं। उसका कोई मतलब नहीं है। मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार से मांग करता हूं कि वहां एक डिग्री कालेज खोला जाए।

सभापति महोदय, पेयजल के बारे में निवेदन करना चाहूंगा कि वहां पिछली कांग्रेस सरकार ने एक बीसलपुर पेयजल परियोजना प्रोजेक्ट बनाया था। यह बहुत अच्छी योजना है। घर-घर, ढाणी-ढाणी में पानी पहुंचा है। लेकिन उसका जो इम्प्लीमेंटेशन हुआ, वह बहुत खामियों वाला है। मैं सरकार से मांग करूंगा कि जो ढाणियां, मजरे रह गए हैं, उनके अंदर भी पानी पहुंचाया जाए।

सभापति महोदय, युवाओं को रोजगार के बारे में जो बात कही है, वह बहुत अच्छी बात है। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यानाकर्षित करना चाहूंगा कि अभी जो लोगों ने कांग्रेस पार्टी को वोट दिए हैं, उसमें एक बहुत बड़ा कारण था कि युवाओं को बहुत ज्यादा आशा थी कि कांग्रेस सरकार आएगी तो उनको रोजगार मिलेगा। जितनी भी भर्तियां करीबन 30 हजार पैंडिंग हैं, उनके द्वार खोले जाएंगे।

सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा 2016 के आरएएस के चयनित बच्चे हैं, जो एक साल से इंधर-उधर घूम रहे हैं, उनको कहीं अपाइंटमेंट नहीं मिल रहा है। वह परेशान हैं। अगर इसी तरह का सलूक हम हमारे होने वाले प्रशासकों के साथ करेंगे तो उनसे हम क्या अपेक्षा कर सकते हैं कि वह पब्लिक में जाकर के सरकार की योजनाओं, नीतियों के अनुसार काम कर पाएंगे। मेरी सरकार से मांग है कि चीफ सैक्रेटरी, डीओपी सैक्रेटरी, आरपीएससी के चेयरमैन, तीनों को बैठाकर के एक मीटिंग की जाए और इसका निर्णय करके जल्दी से जल्दी उनको अपोइंटमेंट देने की कार्यवाही की जाए।

श्री सभापति: समाप्त करें माननीय सदस्य। श्री अमीन खां, शिव।

श्री लक्ष्मण मीणा (बस्सी): सभापति महोदय, जेडीए में बस्सी की 12 पंचायतें आती हैं जिनमें 41 गांव जेडीए के हैं। इनमें किसी प्रकार का कोई विकास कार्य नहीं हो रहा है। कृपया करके सरकार का निर्देश दें।

श्री सभापति: विराजिए। विराजिए। श्री अमीन खां।

श्री लक्ष्मण मीणा (बस्सी): सभापति महोदय, एक मिनट, एक मिनट

(श्री लक्ष्मण मीणा)

लूंगा। बस्सी विधान सभा क्षेत्र में 55 किलोमीटर के एरिया में बड़ा हास्पिटल नहीं है। मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि बस्सी के अंदर एक सेटेलाइट हास्पिटल खोला जाए, जिसमें ट्रोमा की भी सुविधा हो, ताकि जो जन हानि होती है, एक्सीडेंट होते हैं नेशनल हाई वे पर, उससे लोगों को राहत मिल सके।

श्री सभापति: विराजिए। श्री अमीन खां। प्लीज, अब आप कोआपरेट करें।

श्री लक्ष्मण मीणा (बस्सी): सभापति महोदय, नई नाथ को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की भी आपके माध्यम से मैं सरकार से मांग करता हूं। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: विराजिए। श्री अमीन खां।

श्री अमीन खां (शिव): सभापति महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय ने इस सदन में 17 तारीख को पधारकर अति कृपा की। उन्होंने अपना भाषण पढ़ा, जिसका धन्यवाद प्रस्ताव मालवीय जी ने रखा और शकुंतला रावत जी ने उसका समर्थन किया। उस प्रस्ताव का मैं भी समर्थन करता हूं और महामहिम को धन्यवाद देता हूं।

सभापति महोदय, आम चुनाव दिसम्बर में हुए और राजस्थान की जनता ने अच्छा शासन देने के लिए इंडियन नेशनल कांग्रेस पर भरोसा किया और इस कारण से कांग्रेस सत्ता में आई। अभी समय कम ही हुआ है लेकिन कांग्रेस पार्टी ने आते ही जन हित में अच्छे निर्णय लिए। जो गरीब, कमजोर इंसान गांव में रहता है उसके लिए 500 से 750, 750 से 1000 रुपए तक जो पेंशन की है, यह एक बहुत अच्छा कदम है। किसान का 2 लाख तक का कर्जा माफ करने के लिए सरकार बनने के 10 दिन के भीतर का वादा था, लेकिन इस सरकार ने 2 दिन में आदेश जारी कर दिए। इससे किसान का 2 लाख तक का कर्जा माफ हो गया।

(15.26 बजे)

(श्री सी.पी. जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

अध्यक्ष महोदय, मैं कोई ज्यादा विद्वान नहीं हूं। हर इंसान का फर्ज है कि उसे सच्चाई के साथ रहना चाहिए। चालाकी, चतुराई से, झूठ और तोड-मरोड़ करके किसी की बदनामी करना यह किसी अच्छे इंसान के काम नहीं हैं।

(श्री अमीन खां)

मैं तो कहता हूं कि अगर 50 हजार तक का किसान का कर्जा बीजेपी ने भी माफ किया है तो हम उसकी आलोचना नहीं करें। अगर 2 लाख तक का कर्जा कांग्रेस पार्टी ने माफ किया है तो उधर बैठने वालों को भी इसकी तारीफ करने में कोई नुकसान नहीं है। आज हम यहां एक-दूसरे की आलोचना करते हैं, लेकिन इस आधार पर न तो आपको वोट मिलते हैं और न ही हमें मिलते हैं। वोट तो वोटों के वक्त जो समीकरण और जो वातावरण होता है उसके आधार पर मिलते हैं। अभी एक-दूसरे की आलोचना करना अच्छे इंसान का काम नहीं है। मैं ऐसा महसूस करता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसे मैं खुद एक पशुपालक परिवार से हूं। मैं 13 साल की उम्र से 40 साल की उम्र तक गायों का ग्वाला रहा हूं। गाय की जो उधर बैठने वाले बहुत ज्यादा पूजा जैसी बात करते हैं, हम उनको भी अच्छी तरह से जानते हैं। मैं मेरे एरिये की बात कहता हूं। हमारे यहां तीन जाति गाय को पालती हैं, एक सिंधी मुसलसमान, एक राजपूत और एक चारण। जाट और विश्नोई भी हमारे से अच्छे काश्तकार हैं, उस काश्त की वजह से इनका मूल धंधा काश्तकारी का है, सिर्फ छाछ और दूध तक की गाय रखते हैं। हम लोगों ने सौ-सौ, दो-दो सौ गाएं रखी हैं। हमारे पड़ोस में एक रेडाणा गांव था, उसमें कायम नाम एक चानिया था, जो सदा गायों के साथ रहता था हर मौसम में, रोटी भी गायों के बीच में खाता था, नींद भी गायों के बीच लेता था। जिस दिन उस आदमी की मौत हुई, गायों ने गांव वालों को लाश नहीं उठाने दी। फिर किसी आदमी ने समझाया कि ऐसे लाश नहीं उठाने देगी, दूसरी चारपाई बिछाओ उस पर कायम की कम्बल बिछाओ और वह उस लाश वाली चारपाई बाहर निकालो, गायें भूल जाएंगी। दो दिन गायें, उसी जगह बैठी रहीं, कायम की लाश दफनाने के बाद तक। माफ करना ऐसा हिन्दू मैंने आज तक नहीं देखा, वह मुसलमान था।

मेरी खुद की भी एक गाय ऐसी थी जब मैं जब जयपुर से ढाणी जाता था तो मेरी चारपाई के पास बैठती थी, मेरी घाल चढ़ती थी। किसी और आदमी को पास में नहीं आने देती थी। मैं हकीकत में ईमानदारी की बात कहता हूं, उस गाय की आज मुझे याद आती है तो जैसी मेरी मां मर गई उससे ज्यादा अफसोस मुझे उस गाय का हुआ।

एक ढोंग रचना किसी सम्प्रदाय को बदनाम करना, यह सच्चे मनुष्य का फर्ज नहीं है। न तो कोई हिन्दू धर्म में ऐसी कोई नसीहत दी गई है, न

(श्री अमीन खां)

कोई इस्लाम धर्म में नसीहत दी गई है, सभी धर्मों ने कहा है, आज अपनी सुरक्षा करो और दूसरों की सुरक्षा और इज्जत भी सम्भालना आपका पहला कर्तव्य है। जैन धर्म के भगवान महावीर ने बहुत अच्छा नारा दिया, उस पर अपने का चलना चाहिए। उनका नारा देखो कितना कीमती है, जीओ और जीने दो, यानी वे सबसे पहले कहते हैं तुम जीओ और उसके बाद दूसरों को भी जीने का हक दो। हिन्दुस्तान की आजादी से पहले इस देश को जो गुलाम बनाकर बैठे थे उन लोगों के खिलाफ हमारी कौम ने भी जिहाद छेड़ने में और शहीद होने में पीछे हटना नहीं सीखा। आज हम हरेक के भाषण सुनते हैं, लेकिन मुसलमान का कोई नाम नहीं लेता है। क्या हिन्दुस्तान के आखिरी बादशाह जफर को हिन्दुस्तान की धरती पर कब्र के लिए तीन फुट जमीन नहीं मिली, क्या वह देश का वफादार नहीं था? इतिहास लिखने वाले चतुर लोग कुछ न कुछ ऐसी लिखा पढ़ी कर देते हैं जिससे वह कम दिमाग रखने वाले आदमी जिनमें मुसलमान भी हैं, हम यह नहीं कहते हैं कि मुसलमानों में नहीं है, मुसलमानों में भी एक आरएसएस है और हिन्दुओं में भी एक आरएसएस है, मुसलमान की आरएसएस की परख है, एक सलवार और एक सफेद टोपी और इनकी आरएसएस है खाकी नेकर और काली टोपी। दोनों एक जैसे ही हैं। हम इन दोनों से ही अपील करते हैं हिन्दुस्तान महान देश है और इस हिन्दुस्तान को अजीम देश दुनिया इसलिए मानती है कि यह सैक्यूलर है और सैक्यूलरिज्म के कारण करोड़ दूसरे सम्प्रदाय के लोग भी यहां रहते हैं। भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ और अमेरिका ने यूएनओ में वीटो किया, हिन्दुस्तान का सफल और सबल ताकत का समर्थन किया रशिया ने जो सैक्यूलर स्टेट थी और हिन्दुस्तान की प्रधान मंत्री इन्दिरा गांधी पक्की सैक्यूलर थीं इस कारण से दुनिया में उनकी शान बढ़ गई।

मेरी आप सभी से गुजारिश है कि हम सब इस सदन में आने के बाद में एक दूसरे के वफादार बनें और पांच साल के बाद में अपने-अपने क्षेत्र में अपनी-अपनी नीतियां और प्रोग्राम लेकर जाओ, पसन्द जनता करेगी, वही होगा।

इस संदर्भ में मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि जैसे पशुधन का धंधा खतम हो गया, यह धंधा खतम होने के साथ अपन गौर नहीं करते हैं, कानून भी बनाने की परवाह नहीं करते हैं। सबसे पहले छूट रखी हिरण की, इसको कोई मार नहीं सकता, हिरणों ने किसानों के खेतों में तबाही कर दी, फिर यह

(श्री अमीन खां)

जंगली सूअर आए, पहले ये सिटी में थे भंगियों के पास, आजकल ये किसानों के खेतों में जो इंसान के मासूम बच्चों को भी खतरा पैदा हो गया है, किसानों की फसल नष्ट करते हैं। अब रही गाय, गाय की अच्छी नस्ल कीमती है, अच्छी नस्ल की गाय में दूध ज्यादा होता है। अच्छी नस्ल की गाय का बछड़ा पैदा होकर अच्छा बैल बनता है, जिससे किसान खेती करते हैं। अब बैल-बछड़े को बधिया करना कानूनी जुर्म हो गया। अब सारे बैल-गायें मैंने देखा है, सड़कों पर घूम रहे हैं और इनको कोई नहीं पालता है। यह भी किसानों के लिए मुसीबत है।

आपने फिर ऊंट को भी राज्य पशु घोषित कर दिया। अब ऊंट भी किसानों के खेतों में छुट्टा चर रहे हैं, अब कई किसान तो सबल हैं अपने खेत की बाड़ बढ़ा लेते हैं, इस कारण से फसल बचा लेते हैं। कई किसान इतने गरीब हैं, जिनकी बाड़ बनाने की हैसियत नहीं है, उनकी खेती चौपट हो जाती है, आखिर उनको फावड़ा और गैंती का काम ही मिलता है और उनको भूख का सामना करना पड़ता है। इन बिन्दुओं पर सरकार किसी की भी हो, उसको गौर करना चाहिए। आपके पंचायत एक्ट में कांजी हाउस है, क्या आज इनका कोई काम है क्या? कांजी हाउस में कोई जानवर दे नहीं सकता, जानवर को देगा तो पंचायत के पास कोई छुड़ाने वाला नहीं होगा, छुड़ाने वाला नहीं होगा तो पशु को कोई नहीं पकड़ेगा, यह पंचायत एक्ट में जो प्रोविजन है, अब यह एक नाकाम प्रोविजन हो गया है।

कांग्रेस की सरकार ने एक निर्णय यह भी अच्छा लिया है कि मात्र हिन्दी पढ़ा लिखा आदमी, हिन्दी पढ़ ले, लिख ले, उसको सरपंच, प्रधान, प्रमुख बनने का हक है। यह बहुत अन्याय की बात है। एक शर्त लगा देना कि दसवीं पास बिना सरपंच नहीं बनेगा, दसवीं पास बिना प्रमुख नहीं बनेगा, दसवीं पास बिना प्रधान नहीं बनेगा तो यह लोकतंत्र के लिए एक बाड़ खींची है और लोगों को वंचित रखने का कानून था। मैं धन्यवाद देता हूं मुख्य मंत्रीजी को कि इसमें संशोधन किया, यह तारीफ के काबिल है।

अब रहा अनपढ़ का सवाल। अनपढ़ में क्या ऐब है? साधु कबीर को सभी धर्मों ने अच्छा ज्ञानी माना है, क्या वह पढ़ा लिखा था? हजरत मोहम्मद जिसने इस्लाम धर्म पैदा किया और कयामत तक इस्लाम धर्म रहेगा, क्या वह पढ़ा लिखा था, हिन्दुस्तान का शहंशाह अकबर, 14 साल से 50 साल तक देश की बादशाही की, क्या वह पढ़ा लिखा था, जैसलमेर के हिज-हाईनेस जवाहर

(श्री अमीन खां)

सिंह भाटी थे, वह अनपढ़ आदमी थे, जमाने के अनुसार। वाह, क्या बात थी, क्या वह हुकूमत चलाना नहीं जानते थे?

ये बातें सोचना बेकार है। गांव और चौपाल में न्याय, शांति और भाईचारा अनपढ़ आदमी अच्छा जमा सकते हैं और पढ़े-लिखे आदमी तो उसमें 10 फितूर पैदा करके 100-100 कोस दूर रख देते हैं।

अंत में मेरा यह भी सुझाव है, आप भी चाहते हो कि किसानों का कर्जा माफ होना चाहिए, हम भी चाहते हैं कि किसानों का कर्जा माफ होना चाहिए और एक-दूसरे की होड़ में लगे हुए हैं कि कौन ज्यादा और कौन जल्दी करे। अच्छी बात है, किसान को राहत मिली है और उसकी मुखालफत में हम नहीं हैं। लेकिन आपकी कर्जा माफी की योजना चोरों को ज्यादा निहाल करती है और साहूकार को कोई फायदा नहीं है, इस पर गौर करना चाहिए।

दूसरा, किसान को पनपाने के लिए किसान ही नहीं, कोई भी एक मिसाल लो कि मेरे पास आज अगर कोई धंधा नहीं है तो आप सब लोग मेरे को मिलकर एक-एक आदमी हजार-हजार रुपये दोस्ती के नाते दे जाओ तो इससे मेरा घर खुशहाल नहीं होगा। भीख मांगकर खाना भी हर मजहब ने हराम कहा है और भीख का खाना तथा चोरी का खाना कानून में बराबर है।

किसान को सब्सिडी खाद पर दो, किसान को खेती करने में अच्छी सहूलियत दो, सिंचाई करने पर उनके कर मत लगाओ। इन चीजों में सहूलियत देकर किसान को आगे बढ़ाओ तो किसान बढ़ेगा। माफी वाले में तो अक्लमन्द आदमी यही कहते हैं कि यह वोट को तोड़-मरोड़ कर बेवकूफ बनाकर वोट लेना है चाहे देश की स्थिति मजबूत रहे या कमजोर रहे इससे कोई मतलब नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, आखिर में मैं कहना चाहूंगा कि जिस जगह से मैं आता हूं वो पाकिस्तान से लगती हुई सीमा है। सारे हिन्दुस्तान में पढ़ाई का स्तर राजस्थान में नीचा है और सारे राजस्थान में पढ़ाई का स्तर बाड़मेर जिले के सीमावर्ती एरिया में नीचा है, जैसलमेर भी हमसे ऊपर है। सुबह मेरा सवाल भी था और अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत सरकार से बहुत अदब से गुजारिश करना चाहूंगा कि तहसील रामसर, तहसील गड़रा रोड, यह ढाई-तीन लाख की आबादी है, इसमें 80-85 प्रतिशत आबादी रिजर्व क्लास की है, पढ़ाई का स्तर यहां पर सबसे नीचा है इसलिए इन गरीबों को उच्च शिक्षा में प्रवेश

(श्री अमीन खां)

के लिए सरकार के लिए कोई बड़ा काम नहीं है तो इन दोनों तहसीलों के बीच में एक कालेज खोल दिया जाए। धन्यवाद, जय हिन्द।

श्री अध्यक्ष: श्री अशोक लाहोटी।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): बहुत-बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय कि मुझे माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने के लिए आपने वक्त दिया, मेरी पार्टी ने मुझे वक्त दिया। मैं आज इस सदन में मेरी पार्टी से भी जो दो मुख्य मंत्री हमारे यहां से रहे, जिन्होंने राजस्थान का नेतृत्व किया, आदरणीय भैरोंसिंह शेखावत, जिन्होंने राजस्थान में अन्त्योदय की योजना और ग्राम पंचायतों को मजबूत करने का काम किया तथा आदरणीय वसुंधरा जी, जिन्होंने राजस्थान को विकसित राज्य की श्रेणी में लाने का काम किया, मैं उन दोनों को याद करते कहना चाहूंगा।

अध्यक्ष महोदय, मैं सदन में पहली बार बोल रहा हूं, चुनाव जीतकर आया हूं, छात्र राजनीति से और स्थानीय निकाय की राजनीति से आया हूं। लेकिन मैं आज तक सुनते आया था कि माननीय राज्यपाल महोदय का अभिभाषण किसी भी सरकार के एक साल के काम का आईना है। अध्यक्ष महोदय, पूरे 38 पेज के 90 बिन्दुओं के इस अभिभाषण को मैंने पढ़ा तो इसमें न तो कहीं कोई विजन दिखता है, न कोई दिशा है, न कोई दशा है, न इस अभिभाषण की कोई नीति है, न इसमें कोई निर्णय कहीं नजर आ रहा है और न इसमें कोई निर्णय होता हुआ दिखाई दे रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि यह अभिभाषण राजस्थान के नौजवान, राजस्थान के किसान, राजस्थान की महिलाओं को सीधे-सीधे बेवकूफ बनाने का काम किया जा रहा है। मैं आपके माध्यम से गुजारिश करूंगा कि सरकार तो बेवकूफ बनाने का प्रयास कर रही है पर बेवकूफ समझने का प्रयास नहीं करें, लोक सभा चुनाव सामने हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं धन्यवाद भी दूंगा कि इस अभिभाषण की शुरुआत इस अभिभाषण के तीसरे ही बिन्दु से पहले पृष्ठ पर हमारे परम पूज्य परम पिता राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को याद करके की है और इसमें लिखा है कि उनकी 150वीं वर्ष जयन्ती पर यह पूरी पार्टी और उनका शासन इस पर समर्पित रहेगा। इसके बिन्दु संख्या 88 और 89 पर भी उसके एक-एक लफ्ज को उन्होंने दोहराया है। उन्हीं गांधीजी को, जिनके लिए 'दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत...' हम सुनते आए हैं अध्यक्ष

(श्री अशोक लाहोटी)

महोदय। पर, अध्यक्ष महोदय, इस पूरे अभिभाषण में कहीं स्वरोजगार, ग्रामोद्योग, सत्यनिष्ठा, गांधी जी के किसी एक विजन को, 'हे राम' उनके शब्द को भी आगे बढ़ाने का काम किया होता तो मुझे लगता कि यह अभिभाषण हमारे लिए बहुत ही सार्थक और महत्वपूर्ण होता। अध्यक्ष महोदय, इसी अभिभाषण में मैं कहूंगा कि गांधीजी ने अपनी पुस्तक 'My Experiments with truth' में लिखा भी है और उनके जीवन का एक ध्येय था, वो था स्वच्छता। उन्होंने जगह-जगह पर यह कहा है कि राजनीतिक स्वतंत्रता से भी ज्यादा इस देश को स्वच्छता की आवश्यकता है। इस अभिभाषण में ग्रामोत्थान की भी बात की गई। इस अभिभाषण में ग्रामोत्थान के साथ-साथ गांधी जी की इन बातों को भी दोहराते कि स्वच्छता के माध्यम से हम गांवों को आदर्श बनाएंगे तो मैं समझता कि इस अभिभाषण का कहीं गांधीजी के प्रति समर्पण होता।

अध्यक्ष महोदय, इस मौके पर मैं धन्यवाद देना चाहूंगा देश के प्रधान मंत्रीजी को जिन्होंने प्रधान मंत्री बनते ही पहली बार लाल किले की प्राचीर से जब पूरी दुनिया देख रही थी कि प्रधान मंत्री डिफेंस पालिसी पर बात करेंगे, फाइनेंस पालिसी पर बात करेंगे, फोरेन पालिसी पर बात करेंगे, तब प्रधान मंत्रीजी ने एक बात दोहरायी कि गांधी जी का सपना कि मेरे ड्राइंग रूम से ज्यादा मेरे देश में टायलेट्स का महत्व है। उन्होंने 150वीं जयंती को टार्गेट करके पूरे देश में एक स्वच्छता को आंदोलन बनाया, स्वच्छता ही सेवा को आंदोलन बनाया और स्वच्छता के लिए साढ़े सात करोड़ टायलेट बनाने का काम आजाद हिन्दुस्तान में पहली बार इस देश के प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने किया जिनको मैं सदन के माध्यम से धन्यवाद देना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद देना चाहूंगा राजस्थान की पूर्व मुख्य मंत्री वसुंधरा जी को जिन्होंने 80 लाख टायलेट बनाकर हमारे जयपुर महानगर सहित पूरे राजस्थान को खुले में शौचमुक्त किया। हम वुमन एम्पावरमेंट की बात तो करते हैं पर उन महिलाओं की दशा किसी ने नहीं सोची जो गांवों में खुले में शौच करने जाती थी। 80 लाख टायलेट बनाकर उनको इससे मुक्ति दिलाने का काम राजस्थान में यदि हुआ तो हमारी पूर्व सरकार में आजादी के बाद पहली बार हुआ।

अध्यक्ष महोदय, इस पूरे अभिभाषण के पाइंट नम्बर 60 पर केवल एक बिन्दु स्वच्छता पर लिखा। शहरी पर्यावरण हेतु ठोस कचरा प्रबन्धन एक

(श्री अशोक लाहोटी)

शब्द लिखा है। अभी मंत्री महोदय यहां हैं नहीं, मैं उनको कहना चाहता हूं कि यदि इसमें यह भी लिखा होगा कि इस ठोस कचरा प्रबन्धन पर पहली बार जयपुर और जोधपुर में वेस्ट-टू-एनर्जी-प्लांट के टेंडर करके 300 करोड़ रुपये के कार्यादेश जारी किए गए हैं और वो राज्य सरकार के पास केवल पीपीए के लिए अटका हुआ है। अब सरकार कांग्रेस की है, उसका पीपीए जारी करके वेस्ट-टू-एनर्जी-प्लांट को शुरू करें तो शायद ठोस कचरा प्रबन्धन का पूरी दुनिया का बेहतरीन नमूना हमारे प्रदेश के जयपुर और जोधपुर में देखने को मिलेगा। उस काम को आगे भी बढ़ाएं, यह मैं राज्य सरकार से गुजारिश करूंगा।

अध्यक्ष महोदय, मुझे बड़े खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि इस अभिभाषण में पूरे 38 पेज, 90 बिन्दुओं में शहरों के विकास के बारे में कहीं पर एक शब्द भी नहीं है। अध्यक्ष महोदय, 2018 के आज के आंकड़ों में 38 प्रतिशत आबादी शहरों में रहती है और प्रोजेक्शन में 2025 में 53 प्रतिशत आबादी शहरों में आ जाएगी। गांव से नौजवान उठता है, किसान का बेटा हो चाहे मजदूर का बेटा हो, रोजगार के लिए शहरों में आता है। शहरों की समस्याएं दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं और अध्यक्ष महोदय, ग्रोथ रेट भी जहां गांवों की 12 प्रतिशत है, वहां शहरों की 32.31 प्रतिशत है। इन शहरों के विकास के बारे में एक शब्द भी इस पूरे अभिभाषण में कहीं भी नहीं लिखा गया। अध्यक्ष महोदय, बिन्दु संख्या 69 और 70 में शहरों में उत्पन्न समस्याओं के बारे में जरूर लिखा है।

मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा और मैं कहूंगा पार्टी से ऊपर उठकर कि आजादी के 70 साल बाद भी आज भी यदि हम शहरों की बात करें तो मैं केवल मेरे जयपुर शहर का उदाहरण दूं तो विकास में पैसा तो जरूर खर्च हुआ है।

अध्यक्ष महोदय, पिछले 15 साल में 38 हजार करोड़ रुपये इस जयपुर के डवलपमैन्ट पर अलग-अलग सरकारों के माध्यम से खर्च हुआ है। लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि शहर का विकास 11 अलग-अलग एजेन्सीज कर रही हैं। कहीं पीएचईडी, कहीं पीडब्ल्यूडी, कहीं हाउसिंग बोर्ड, कहीं नगर निगम, कहीं जेडीए, कहीं आईआरयूडीपी, कहीं रूडको, कहीं सिस्को, कहीं अमृत मेक, स्मार्ट सिटी में ऐसे अलग-अलग फेस में शहरों का विकास किया जा रहा है। 38 हजार करोड़ रुपये लगाने के बावजूद भी आज भी जयपुर शहर में 70 प्रतिशत आबादी बीसलपुर के पानी के लिए तरस रही है।

(श्री अशोक लाहोटी)

अध्यक्ष महोदय, केवल मेरी विधान सभा सांगानेर क्षेत्र में 1300 से ज्यादा ऐसी कालोनियां हैं, जिनमें आज भी मूलभूत आवश्यकता नहीं है। वहां पीने का पानी नहीं है, चलने के लिए सड़क नहीं है, बारिश के दिनों में सीवरेज और ड्रेनेज के कारण लोग घरों से बाहर नहीं निकल पाते हैं। ऐसी भद्र दयनीय हालत वहां पर बनी हुई है।

अध्यक्ष महोदय, मैं मांग करूंगा आपके माध्यम से कि शहरों की आबादी को रोकने के लिए हमको सबर्ब डवलप करने पड़ेंगे। जो अभी पूर्व सदस्य ने एक बात कही थी मैट्रो के बारे में, इस पूरे अभिभाषण में मैट्रो के बारे में एक शब्द नहीं लिखा हुआ। सबर्ब की यदि हम बात करें तो चाहे सांगानेर हो, चाहे चाकसू हो, चाहे चौमूं हो, चाहे बस्सी हो। इन सब-अर्ब्स को जब तक हम डवलप नहीं करेंगे। माननीय, विजय नगर कह दूंगा मैं, आप चिन्ता मत करो।

अध्यक्ष महोदय, जब तक हम इन सबर्ब को डवलप नहीं करेंगे तब तक हम शहरीकरण पर निजात नहीं पा सकते। सबर्ब को डवलप करने के लिए एक इंटीग्रेटेड प्लान बनाना पड़ेगा। हमको सीवरेज और सड़क की सुविधाएं देनी पड़ेगी। हमको कालेज और हास्पिटल की सुविधाएं देनी पड़ेगी। आज सांगानेर कस्बे में 2 लाख की आबादी के बावजूद भी केवल कस्बे-कस्बे में वहां पर एक हास्पिटल नहीं है, वहां पर कालेज नहीं है, पीने के लिए बीसलपुर का पानी नहीं है। जो मैंने बताया 1300 कालोनियों में सीवरेज नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा और धन्यवाद देना चाहूंगा देश के प्रधान मंत्रीजी को कि शहरीकरण पर बात तो हम कर रहे हैं। पर इन्होंने स्मार्ट सिटी के नाम पर जो प्रोजेक्ट देश में शुरू किया। राजस्थान के चार शहरों को स्मार्ट सिटी में जगह मिली और केवल बात नहीं की, 4 हजार करोड़ रुपये राजस्थान को सैंक्शन किए और जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और कोटा, चारों स्मार्टसिटियों में काम धड़ल्ले से चल रहा है और यदि इसी गति से चलता रहा तो 2020 तक चारों स्मार्टसिटी में सबर्ब भी डवलप होंगे और स्मार्ट सिटी भी डवलप होगी अध्यक्ष महोदय।

अध्यक्ष महोदय, अभी हमारे एक वरिष्ठ सदस्य एज्यूकेशन के बारे में बात कर रहे थे। मैं नौजवान हूं, युवा हूं, मेरा मत इससे भिन्न है। इस अभिभाषण संख्या 52 और 53 में शिक्षा को बढ़ावा देने की बात कही गई

(श्री अशोक लाहोटी)

अध्यक्ष महोदय। लेकिन बड़ी अजीबो गरीब बात है कि 52 और 53, मैं 40 का अभी हो ही रहा हूं, अभी हो जाऊंगा एक-दो महीने में। लेकिन, 52 और 53 में लिखने के बाद बिन्दु संख्या 27 में लिखा गया है कि लोकल बाडीज में पंचायती राज में शिक्षा की अनिवार्यता को खतम किया जाता है।

अध्यक्ष महोदय, मैं एक उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा। मैं जब महापौर था तो महापौर के रूप में राजस्थान के स्मार्ट सिटी के मेयर्स और सभी जो आफिसर्स थे, उनका डेलीगेशन अमेरिका गया था। वहां बोस्टन यूनिवर्सिटी के कुछ छात्र-छात्राएं हमको मिले थे। उसमें कोलकाता की एक छात्रा थी प्रियंका शारडा, वो बाद में यहां पर दौरा करने भी आई थी। उन्होंने अपने इकानोमिक्स में, अपने रिसर्च पेपर में राजस्थान के उस उदाहरण को कोट किया था कि राजस्थान पहला स्टेट है, जहां पर लोकल बाडीज में शिक्षा की अनिवार्यता की गई है। इस अभिभाषण में ही आपने लिखा ऊपर सरकार ने कि विधायक और सांसदों में शिक्षा की अनिवार्यता नहीं है। हमें खुशी होती अध्यक्ष महोदय, हम 60 प्रतिशत नौजवान इस बात से और खुश होते कि आप नौजवानों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। यदि इस अभिभाषण में यह जोड़ते कि हम विधायक और सांसदों की भी शिक्षा की अनिवार्यता करेंगे। यदि इसको सदन में लेकर आते तो शायद हमारे जैसा 2 करोड़ 60 लाख युवा मतदाता आपका स्वागत करता अध्यक्ष महोदय।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ही उदाहरण कोट करूंगा। मैं जब राजस्थान विश्वविद्यालय में छात्र राजनीति कर रहा था। आप स्वयं उस समय उच्च शिक्षा मंत्री थे। आप विश्वविद्यालय के चुनाव में नये नियम लेकर आए। हम सब छात्र आपसे मिलने आए थे। हमने कहा था कि साहब, यह मूल अधिकार के खिलाफ है तो आपने एक बात मुझे कही थी और मुझे आज तक याद है। आपने कहा बेटा, अच्छे कामों की शुरूआत कहीं तो करनी पड़ेगी, इसके लिए किसी न किसी को तो त्याग करना ही पड़ेगा। अध्यक्ष महोदय, हो सकता है कुछ तथाकथित लोग, राजस्थान में एक-दो प्रतिशत लोग जो तथाकथित लगातार सरपंच बनते आ रहे हैं, लगातार प्रधान बनते आ रहे हैं, हो सकता है वो नहीं बन पाते पर कहीं उनकी नौजवान पीढ़ी बन पाती। अध्यक्ष महोदय, युवा सोच और युवा ऊर्जा का दर्द कांग्रेस पार्टी में कई जगह है, मुझे दिख रहा है। इसलिए हो सकता है इसको उससे जोड़कर कहीं न कहीं रोकने का प्रयास किया होगा।

(श्री अशोक लाहोटी)

अध्यक्ष महोदय, इसी अभिभाषण में एक जगह एक बात कही गई है कि स्थानीय निकायों को, पंचायती राज को, सहकारिता को हम मजबूत करेंगे। अच्छा होता 1973 एक्ट को यदि लागू करने की बात की जाती तो वास्तविक रूप से स्थानीय निकायों को मजबूती का कहीं अधिकार मिलता। अध्यक्ष महोदय, एक तरफ तो स्थानीय निकायों को मजबूत करने की और सहकारिता को मजबूत करने की बात कही गई है। हां, मजबूत करने का एक आदेश राज्य सरकार ने जरूर किया अध्यक्ष महोदय। किसानों की कर्ज माफी से पहले, 2 करोड़ 60 लाख नौजवानों की बेरोजगारी भत्ते से पहले, और तो और मंत्रिमण्डल की बैठक से भी पहले, विधान सभा के सत्र से पहले, आपने एक आदेश जारी किया। अध्यक्ष महोदय, सरकार ने अध्यादेश जारी किया है और एक माननीय सदस्य को सहकारिता में फायदा पहुंचाने के लिए राज्यपाल के अधिकारों का उपयोग करते हुए सर्कूलर के माध्यम से आदेश जारी किया गया है अध्यक्ष महोदय। ये दर्शाता है कि कांग्रेस पार्टी किस ढंग से पद से चिपक कर रहना चाहती है। सहकारिता के एक आदेश के लिए, सेम यह नगरपालिका एक्ट में भी था, पंचायती राज में भी था। अध्यक्ष महोदय, हम भी चाहते तो चार-चार हाईकोर्ट के डबल बैंच के निर्णय थे। इसी अध्यादेश की कापी लेकर कोर्ट में जा सकते थे। हमारे एक और माननीय विधायक यहां पर विराजमान हैं हरेन्द्र जी निनामा, घाटोल से प्रधान हैं, वो भी जा सकते थे। लेकिन, हमने एक उदाहरण प्रस्तुत किया और हमने 14 दिन से पहले आगे चलकर इस्तीफा दिया और जनता-जनार्दन का सम्मान करते हुए जनता ने हमें जिस पद पर चुना, उस पद का महत्व समझते हुए, जनता के आदेश को मानते हुए, वहां से इस्तीफा देकर आपके सदन में यहां पर बैठने के लिए आए हैं।

अध्यक्ष महोदय, ये भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के चरित्र का फर्क है। अध्यक्ष महोदय, यहीं नहीं रूकता, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा इस अभिभाषण के बिन्दु संख्या 6, 7, 8, 9, 39 में कहीं पर तो आपने आंकड़े दिये हैं, जो आपने तुलना की है। वो साल 2009 और 2010 के किये, कहीं 2013 और 2014 की कर दी, कहीं 2014 और 2015 की कर दी, कहीं 2017 और 2018 की कर दी और पोलिटिकल अपनी बात को कहने के लिए कहीं 2018 और 2019 को बीच में ले आए।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं ठीक है, यदि अभिभाषण को पॉलिटिकली करना था और पॉलिटिकली तुलना करनी थी तो

(श्री अशोक लाहोटी)

50 साल बनाम 5 साल की कर लेते। 50 साल में यदि मैं ई-मित्रों की बात करूं तो जिस एक पार्टी ने 50 साल तक शासन किया। उसके शासनकाल में केवल 6 हजार ई-मित्र खुले। आप ई-मित्र की बात कर रहे हो, आप अभिभाषण में वाई-फाई की बात कर रहे हो, आप मजबूती की बात कर रहे हो, आप डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हो, आप स्किल डवलपमेंट की बात कर रहे हो, धन्यवाद दूंगा राजस्थान की पूर्व सरकार को और पूर्व मुख्य मंत्री को जिन्होंने 55 हजार ई-मित्र खोले, नौ सौ प्रतिशत ज्यादा, 50 साल बनाम 5 साल। यदि शौचालय निर्माण की बात करें तो 50 साल में केवल 25 लाख शौचालय बने और 5 साल में 80 लाख शौचालय राजस्थान में बने। सौर ऊर्जा उत्पादन, आपने पाइंट नम्बर 38 पर लिखा है। यदि उसकी मैं बात करूं तो केवल 67 मेगावाट का सौर उत्पादन था और अभी हमारे राज में 1618 मेगावाट का सौर उत्पादन हुआ। यदि ग्राम-ढाणियों की बात करें, पेयजल की तो केवल 4 हजार 900 ढाणियों को जोड़ा गया और अभी 10 हजार ढाणियों को जोड़ा गया, दे सौ प्रतिशत ज्यादा।

अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करें तो 7260 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग 50 साल में बनाए और 8178 किलोमीटर राजमार्ग केवल इन पांच साल में बनाए गए। यदि मैं मेडिकल कालेज की बात करूं तो पिछले 50 साल में राजस्थान में केवल 7 मेडिकल कालेज खुले और अकेले इन 5 सालों में 7 मेडिकल कालेज खोले गये हैं अध्यक्ष महोदय। यानी, 50 साल बनाम 5 साल। यदि राजनीतिक तुलना ही करनी थी तो स्पष्ट रूप से करते अध्यक्ष महोदय। अभिभाषण को घुमाने की जरूरत नहीं थी, अभिभाषण को तोड़ने-मोड़ने की जरूरत नहीं थी। आंकड़ों को तोड़-मोड़ने की जरूरत नहीं थी। आपने पवन ऊर्जा की बात की पाइन्ट नम्बर 38 पर, 2710 मेगावाट आपने किया 50 साल में, 1581 मेगावाट केवल 5 साल में। राजकीय महाविद्यालय की कल बात कर रहे थे एक हमारे मंत्री महोदय, 171 राजकीय महाविद्यालय खुले थे 50 सालों में, और 81 राजकीय महाविद्यालय खुले हैं केवल 5 सालों में। अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी ने एक बात और कही थी कि कोलायत में घोषणा की और राजकीय महाविद्यालय खुला नहीं।

(16.00 बजे)

मैं ध्यानाकर्षण करना चाहूंगा मंत्री महोदय का कि 2013 के उस शासन को मत भूलो जब आपने युवाओं के साथ खिलवाड़ किया था। आपने

(श्री अशोक लाहोटी)

एक-एक कमरे में यूनिवर्सिटी खोली थी, कालेज ही नहीं और जब उनकी जांच हुई तो वे कमरे भी होटल के कमरों में कमरा नं. 1 में एक यूनिवर्सिटी, 2 में दूसरी यूनिवर्सिटी, 3 में तीसरी यूनिवर्सिटी बिना किसी बजटरी प्रोविजन के, बिना किसी वित्तीय प्रबंधन के, बिना यूजीसी की परमीशन के आप विश्वविद्यालय खोलकर गये, जिसका राजस्थान के नौजवानों ने आपको वापस जवाब भी दिया और उस चुनाव में आपको सबक भी सिखाया।

अध्यक्ष महोदय, अभिभाषण के बिन्दु संख्या-62 में ...(व्यवधान) महेन्द्र जी भाई साहब, आप तो इसको देखकर आये हो, आप चेंज करवा लो।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (राज्य मंत्री, शिक्षा): ऊपर से नीचे तक एक ही ट्रेनिंग है क्या? असत्य बोलो, असत्य बोलो।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी, पहली बार बोल रहे हैं। प्लीज, डोंट इंटरवीन।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): मंत्री महोदय, चलो आपने कहा है तो मैं पांच साल बनाम पांच साल भी कह देता हूं। मैं तो पचास साल से कर रहा था। आपने कहा है तो मैं पांच साल का भी ले लेता हूं। माननीय मंत्री महोदय, आपके पिछले पांच साल के शासन में सड़कों के विकास पर आपने खर्च किये 15 हजार करोड़ रुपये। अब तो शासन भी आपका है, जो मैं कह रहा हूं वे शब्द भी रिकार्ड हो रहे हैं। आप इसको चैक भी करवा लेना और मैं गलत होऊं तो आपसे क्षमा मांगने के लिए भी आऊंगा और आगे से कभी आपके इस तरह के गलत आंकड़े नहीं दूंगा। हमने खर्च किये 49 हजार 500 करोड़ रुपये। अध्यक्ष महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज में इन्होंने खर्च किये 36 हजार करोड़ रुपये और हमारे राज में खर्च हुए 52 हजार करोड़ रुपये, कृषि एवं उद्यानिकी योजना में इन्होंने खर्च किये 4300 करोड़ रुपये और हमने खर्च किये 6500 करोड़ रुपये, पेयजल पर खर्च इन्होंने खर्च किये 12,200 करोड़ रुपये और हमने खर्च किये 22 हजार करोड़ रुपये, सिंचाई परियोजनाओं पर इन्होंने खर्च किये 3600 करोड़ रुपये और हमने खर्च किये 8,200 करोड़ रुपये और विद्युत पर इन्होंने खर्च किये 36 हजार करोड़ रुपये और हमने किये 1 लाख 35 हजार करोड़ रुपये। यह मैं केवल पांच साल बनाम पांच की तुलना बता रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय, अभिभाषण के बिन्दु संख्या-62 में सरकार ने दूषित जल के उचित प्रबंधन की बात कही। मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा कि यह दूषित

(श्री अशोक लाहोटी)

जल की समस्या राजस्थान के कुछ इलाकों में ज्यादा है। उसमें एक मेरा विधान सभा क्षेत्र भी है। भिवाड़ी में है, बालोतरा में है, पाली में है, जयपुर के सांगानेर में है। सांगानेरी प्रिंट का एक अपना इतिहास है। तीन सौ साल पुराना इतिहास है। लगभग सत्तर हजार लोग उससे जुड़े हुए हैं। 1800 फैक्ट्रियां जुड़ी हुई हैं, अध्यक्ष महोदय। मुझे खुशी होती अगर इसमें थोड़ी सच्चाई और लिख देते कि 1999 के कांग्रेस के राज में ही ठीक से पैरवी नहीं करके आने के कारण 2 लाख लोगों के रोजगार पर संकट आया और माननीय हाई कोर्ट ने उन फैक्ट्रियों को बंद करने का आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट में गये यहां के लोग। 2003 में जब वसुंधरा जी की सरकार बनी तो एक मंत्रिमंडलीय उप समिति बनी। उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी। सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया और जो एक एफलुएंट प्लांट, जो सीईटीपी प्लांट लगने की बात हुई। यदि इसमें दो लाइन और जोड़ देते कि 145 करोड़ रुपये का सांगानेर का प्लांट आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी और वसुन्धरा जी की बजट की घोषणा में अस्सी करोड़ रुपये केन्द्र ने दिये, चालीस करोड़ रुपये स्टेट ने दिये। कुछ वहां के व्यापारियों ने मिलाये तब जाकर वहां सीईटीपी प्लांट लगा। इस तरह के प्लांट्स की राजस्थान में और भी आवश्यकता है। यदि आप वाकई इस दूषित जल को रोकना चाहते हैं तो इस तरह के प्लांट्स की और भी आवश्यकता है। यदि आप वाकई इस दूषित जल को रोकना चाहते हैं तो इस तरह के प्लांट्स की और भी व्यवस्था करें। केवल लिखने मात्र से दूषित जल नहीं रुकेगा।

अध्यक्ष महोदय, अभिभाषण में सबसे ज्यादा यदि किसी को निराशा हुई है तो राजस्थान के नौजवानों को हुई है। इसमें नौजवानों के लिए यह तो लिखा है कि हम नौजवानों को पढ़ाएंगे। उनके रोजगार की समुचित व्यवस्था करने का प्रयास करेंगे। उसके लिए वातावरण बनायेंगे, पर अध्यक्ष महोदय, घोषणा पत्र के पेज नं. 15 पर आपने एक लाइन भी लिखी थी पहली पंक्ति में कि हम 3500 रुपये प्रति माह देंगे। मैं यह तो मानता हूं कि आप कह दोगे कि हमने कमेटी बनाई है, हम देने का प्रयास कर रहे हैं और हम बिलकुल देंगे, लेकिन अध्यक्ष महोदय, राजस्थान के नौजवान इतने बेवकूफ नहीं हैं। राजस्थान के नौजवानों ने पांच साल के लिए वोट दिया है तो यह 3500 रुपये भी पूरे पांच साल के लिए लेंगे। आप कोई कमेटी बनायें या लाल पत्र भरायें या नीला पत्र भरायें, लेकिन जिस दिन भी घोषणा लागू करो तो एक करोड़ नब्बे लाख बेरोजगार राजस्थान में इसकी श्रेणी में आते हैं, उन एक करोड़

(श्री अशोक लाहोटी)

नब्बे लाख लोगों का पूरे साठ महीनों का आप 3500 रुपयों का भुगतान करें। यह मेरा आपके माध्यम से इनसे निवेदन है। चूंकि वोट आपने पांच साल के लिए लिये हैं। आप दो साल बातों में निकालकर तीन साल दे दो तो तीन साल के लिए वोट नहीं लिया आपने। राजस्थान के नौजवान ने पांच साल के लिए वोट दिया है।

अध्यक्ष महोदय, पांच सालों तक ये संविदाकर्मियों के साथ धरने पर बैठे, भाषण दिये, फोटो खिंचवाई, सोशल मीडिया में लगाये और आज जब कुछ करने की बारी आई तो कहा कि हम कमेटी बनाकर इसकी जांच कर रहे हैं। आपने तो खुद ने भाषण दिये हैं आपने अपने खुद के फेस बुक पर लिखा है उस अकाउंट को ही चैक कर लेते। आपने खुद ने उसमें लिखा है। आपको तो एक-एक चीज एक-एक दु:ख-दर्द पता है उनका। यदि आते ही कहीं पर ये इस तरह की घोषणा करते। किसी एक विभाग की तो घोषणा करते कि हम एक विभाग में संविदाकर्मियों को हम नियमित कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, ई-मित्र की जो मैंने बात कही है, आपने बिन्दु संख्या-32 और 81 में वाई-फाई, ई-मित्र, कंप्यूटरीकरण, इंटरनेट की बात कही है। यदि इसमें एक लाइन और जोड़ते कि जब राजस्थान में एजुहब हुआ था तब मैं भी वहां मौजूद था। देश और दुनिया के साइबर के लोग आये हुए थे। उन्होंने राजस्थान के लिए एक बहुत बड़ी गर्व की बात कही थी कि किसी जमाने में इस तरह के साइबर के योद्धा केवल बंगलौर में बैठा करते थे। Now Rajasthan is the No. 1 in the cyber or digital world. इस वर्ड को भी यदि जोड़ते तो शायद यह राजनीति से ऊपर होता और हमारे यहां के भामाशाह डेटा सेन्टर्स की दोनों बिल्डिंग और उनके काम को देखने के लिए तो पूरे देश और दुनिया के लोग आ रहे हैं उसको भी जोड़ते तो हमको लगता कि कहीं राजनीति से ऊपर आपने अभिभाषण पढ़ा है।

अध्यक्ष महोदय, बिन्दु संख्या-57, 58 और 81 में युवाओं के प्रशिक्षण और रोजगार की बात कही है। आपने प्रशिक्षण और रोजगार की बात तो कही पर कहीं एक लाइन उसमें धन्यवाद भी देते। आपने ऋण माफी के लिए तो प्रधान मंत्रीजी को पत्र लिखने की बात कह दी पर कहीं मुद्रा योजना और कहीं स्टार्टअप योजना का भी इसमें जिक्र किया होता देश के प्रधान मंत्रीजी का तो शायद यह राजनीतिकरण से ऊपर होता।

अध्यक्ष महोदय, इसमें बिन्दु संख्या-60 और 61 पर उद्योग और

(श्री अशोक लाहोटी)

व्यापार की बात तो कही गयी है, लेकिन मुझे बड़े दु:ख और खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि इसमें किसी तरह के टैक्स रिबेट की, मध्यमवर्गीय व्यापारी को, खुदरा व्यापारी को, गली-मोहल्ले के दुकानदार को कहीं रिबेट की बात नहीं की है और मैं आपके माध्यम से अध्यक्ष महोदय, यह मांग करता हूं कि आदरणीय मुख्य मंत्रीजी सदन के नेता जब जवाब दें तो राजस्थान में एक व्यापारी कल्याण बोर्ड बनाने की बात करें जिससे राजस्थान के व्यापारियों के हितों को संरक्षित किया जा सके। छोटे व्यापारियों को बचाया जा सके। मध्यमवर्गीय व्यापारियों को बचाया जा सके। यदि व्यापारी कल्याण बोर्ड की बात करेंगे तो निश्चित रूप से इसका फायदा आपको भी होगा।

अध्यक्ष महोदय, बिन्दु संख्या-76 में बाल श्रम की बात जो कि मेरे से पूर्व सदस्य ने उठा दी। श्रमिक कार्ड की बात भी कह दी। मैं उसमें नहीं जाऊंगा। 42, 43, 44, 45, 46, 48 और 50 में चिकित्सा सुविधा की बात कही गई है। मैं आपके ध्यान में लाना चाहूंगा कि चिकित्सा सुविधा की बात तो आपने की, पर चिकित्सा सुविधा की बात के साथ-साथ हमने कभी आपकी सरकार की शुरू की हुई योजना पेंशन योजना को बंद करने की बात नहीं कही। आपकी सरकार ने फ्री मेडिकल देने का काम किया हमने उसको बंद करने की बात नहीं कही। आप राजनीति से ऊपर उठते। सरकार बनते ही कई मंत्रियों के मीडिया में बयान आये। हम भामाशाह कार्ड को नहीं मानते। हम भामाशाह कार्ड को बंद कर देंगे। भामाशाह कार्ड के टुकड़े कर देंगे। अध्यक्ष महोदय, भामाशाह कोई भारतीय जनता पार्टी के तो थे नहीं। भामाशाह तो राजस्थान के लिए गर्व थे। हमने अपने नेता के नाम पर तो रखा नहीं। मैंने तो यह भी कहा था कि देश के प्रधान मंत्रीजी पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने स्वच्छता का काम तो किया पर अपने फायदे के लिए गांधी शब्द का उपयोग नहीं किया। अपने नाम के पीछे भी गांधी नहीं लिखा और अपने काम के आगे भी बापू नहीं लिखा तो भामाशाह तो किसी के नहीं थे और अध्यक्ष महोदय, आप तो मेवाड़ से हैं। आपसे ज्यादा भामाशाह के बारे में कौन जानते हैं, उस भामाशाह कार्ड को आगे बढ़ाने की बात करते जिसमें आम गांव में बैठा हुआ व्यक्ति, गरीब व्यक्ति जो कभी सोच भी नहीं सकता था कि मैं ईएचसीसी होस्पिटल में, फोर्टिस होस्पिटल में, नारायण हृदयालय में, बिरला होस्पिटल में जाकर तीन लाख रुपये का मुफ्त इलाज कराऊंगा। मंत्रीजी बयान दे रहे थे कि प्रधान मंत्रीजी ने आयुष्मान भारत के सीधे क्यों भेज दिये। हमारे माध्यम से

(श्री अशोक लाहोटी)

भेजते। आप तो राजनीति करो और प्रधामंत्रीजी पत्र आपको दे दें। आप अपने अभिभाषण में एक लाइन कहीं जोड़ते कि देश के प्रधानमंत्रीजी को धन्यवाद दे रहे हैं कि आपने आयुष्मान भारत जो विश्व की सबसे बड़ी मेडिकल योजना शुरू की है पचास करोड़ भारतीयो को उसका फायदा मिलेगा। पांच लाख प्रतिवर्ष फायदा मिलेगा।

अध्यक्ष महोदय, इसी अभिभाषण में एक जगह यह भी लिखा हुआ है कि ऋण बढ़ा दिया गया है। ऋण बढ़ाने की बात कही गई है। 3 लाख और कुछ हजार ऋण कर दिया।

बिजली कंपनियों में एक लाख करोड़ से ऊपर का ऋण कर दिया। अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा कि इस अभिभाषण में एक लाइन यह भी लिखते कि शायद यह किसी लोक कल्याणकारी सरकार का सबसे बड़ा एक इंडिकेशन है। कभी भी सड़क में, परिवहन में, रोडवेज में, मेडिकल में जो संस्थाएं सरकार की बनाई जाती हैं, यह कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी तो थी नहीं कि राज्य सरकार के मंत्री और राज्य सरकार के लोग ऋण लेकर अपने घर ले गये और यदि ऐसा अगर आपको मन में लगता है तो सरकार आपकी है, आप जांच करवाएं। लेकिन यदि वाकई ऋण बढ़ा है तो इससे बड़ा कोई उदाहरण नहीं हो सकता कि वह राजस्थान की सबसे बड़ी लोक कल्याणकारी सरकार थी। क्योंकि यह कोई प्रोफिट मैकिंग संस्था नहीं है अध्यक्ष महोदय, पूरी दुनिया में जहां इस तरह की पब्लिक फैसेलिटीज रहेगी, चाहे वह ट्रांसपोर्ट का सैक्टर हो, चाहे सीवरेज का हो, चाहे पानी का हो, चाहे बिजली का हो, वह लोक कल्याणकारी सरकार का सबसे बड़ा उदाहरण है कि वह लोस मैकिंग संस्था है। वहां जितना ज्यादा लोस हो रहा है उतना ज्यादा जनता को फायदा मिल रहा है।

अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात यहीं समाप्त करते हुए केवल इतना ही कहूंगा यहां पर अटल बिहारी वाजपेयी जी की एक कविता को याद करते हुए कि

'हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा काल के कपाल पर
पहले विधान सभा आपने लिखी है,
अब हम भी जनता के बीच में जाएंगे, आपकी बात को मिटाएंगे
और लोक सभा हमारे नाम लिखेंगे'।

(श्री अशोक लाहोटी)

अध्यक्ष महोदय, बहुत-बहुत धन्यवाद, भारत माता की जय, जय हिन्द।

श्री अध्यक्ष: श्री राजेन्द्रसिंह जी गुढ़ा।

श्री राजेन्द्रसिंह गुढ़ा (उदयपुरवाटी): अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे समय दिया, उसके लिये आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं दो दिन से राज्यपाल के अभिभाषण पर पक्ष और विपक्ष की डिबेट सुन रहा हूं, अच्छे सुझाव हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं तो आपको एक बात बताना चाह रहा हूं पिछले पांच साल में, भाजपा के शासन में जिस तरीके से सरकारी मशीनरी का जम कर दुरुपयोग किया गया, जो लोग धर्म की बात करते हैं, जो राम मंदिर बनाने की बात करते हैं मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक मनसा माता का बहुत ही प्राचीन मंदिर है। लाखों लोगों का वहां आवागमन है। उस मंदिर के जीर्णोद्धार का जो कार्य चल रहा था, उसको पांच साल तक इन लोगों ने रोक दिया। एक हमारे यहां जमुवाय माता का मंदिर है, पूर्व माननीय मुख्य मंत्री वसुंधरा जी वहां गईं और जाने के दूसरे दिन बाद उस जमुवाय माता के मंदिर के काम को भी रोक दिया गया। जो लोग गाय पर बोल रहे हैं, गाय की चिंता कर रहे हैं, मैं यह जानना चाह रहा हूं कि गाय पर बोलने वाले माननीय सदस्य के खुद के घर में तो गाय है क्या? क्या उस गाय की देख रेख वह अपने घर में करते हैं क्या? अध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक बच्चे का शादी के 6 महीने बाद में एक्सीडेंट हो गया था और उदयपुरवाटी थाने से मात्र, हमारे राज्यपाल के अभिभाषण में दुर्घटनाओं के बारे में लिखा गया है, इन पर चिंता व्यक्त की गई है, मैं उसी पर पीछे और वर्तमान में आना चाह रहा हूं, दो किलोमीटर दूरी पर बच्चे का एक्सीडेंट हुआ, 6 महीने पहले उसकी शादी हुई थी, दो घंटे तक वहां पुलिस नहीं पहुंची, मैं जयपुर से वहां पहुंच गया। उसके बाद हमारे जाने के बाद वहां पुलिस पहुंची, घायल ने दम तोड़ दिया था। अध्यक्ष महोदय, सदन के माध्यम से हकीकत बता रहा हूं। यह बीजेपी के लोग जो यहां बैठे हैं, हमने उस बच्चे को उठाया, हमने पोस्टमार्टम कराया, हमने दाह-संस्कार किया। वहां किसी तरह की राज कार्य में बाधा की कोई बात ही नहीं हुई, इन्होंने हमारे पर झूठे मुकदमे लगाये और हमें जेल में डाल दिया। 50-50 हजार लोग इकट्ठे होकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हैं। पूरे शेखावाटी में, झुंझुनूं, सीकर, चूरू में जिस तरह की अराजकता रही, अध्यक्ष महोदय, पूरी शेखावाटी में आज तक आजादी के 70 साल बाद भी राजद्रोह का

(श्री राजेन्द्रसिंह गुढ़ा)

कोई मुकदमा ही नहीं हुआ। मेरे उदयपुरवाटी विधान सभा क्षेत्र में तो मात्र 8-10 हजार माइनोरिटी के लोग हैं और आज तक पूरे विधान सभा क्षेत्र में एक भी मुकदमा माइनोरिटी के खिलाफ कोर्ट में नहीं चल रहा, स्कूल में पढ़ने वाले छोटे-छोटे बच्चों के खिलाफ राजद्रोह के मुकदमे लगा दिये और उन बच्चों पर आतंकवादियों के खिलाफ जो धाराएं लगती हैं, 50-50 बच्चों को जेल में डाल दिया। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं, हमारे पूर्व गृह मंत्री महोदय यहां विराजमान हैं। एक 14 साल की माइनोरिटी की बच्ची का अपहरण हुआ, उनके परिजन थाने के सामने शांति से धरना दे रहे थे, उन लोगों पर वहां लाठीचार्ज हुआ, बेरहमी से उनको पीटा गया। 50-60 लोगों को जेल में टिका दिया। 200 लोगों पर झूठे मुकदमे किये गये। मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं किसी का पक्ष भी नहीं ले रहा, विपक्ष में भी नहीं बोल रहा, लेकिन पुलिस के साथ सिविल लोग जो बजरंग दल के नाम से, और किसी नाम से, विश्व हिन्दू परिषद के नाम से लोगों के घरों में घुस-घुसकर, लोगों को घरों से निकाल-निकालकर थानों में पुलिस के साथ मिलकर अध्यक्ष महोदय, एक लाख लोग इकट्ठे हुए।

अध्यक्ष महोदय, मेरा तो आपसे यही कहना है अभिभाषण में सरकार ने एक महीने में जो निर्णय किये, निर्णय अच्छे हैं। वृद्धावस्था पेंशन वाली बात है, उसमें साढ़े सात सौ और हजार रुपया किया गया, उनको पन्द्रह सौ और हजार रुपया कर दें तो ज्यादा अच्छी बात होगी। बेरोजगारों की चिंता की गई है लेकिन हकीकत में राजस्थान में जो शिक्षित बेरोजगार हैं उनकी सबसे ज्यादा बुरी स्थिति है, उनके लिये यदि कुछ किया जाये, जो 3500 रुपये भत्ता देने की बात हुई है, दूसरी बातें हुई हैं, इसमें विकलांग की बात भी हो रही है, वृद्ध की बात भी हो रही है लेकिन शिक्षित बेरोजगार के बारे में हमें चिंता करनी चाहिये।

इसके साथ-साथ अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताना चाह रहा हूं पिछली माननीय गहलोत जी की सरकार के समय में हमारे यहां पीने के पानी की गम्भीर समस्या थी, उसके लिये कुम्भाराम लिफ्ट योजना के फर्स्ट फेस में हमारे गांवों को जोड़ दिया गया था, पांच साल में एक इंच भी काम नहीं हुआ। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से बताना चाह रहा हूं राजनीतिक द्वेषता से जितने ट्रांसफर और पोस्टिंग किये गये, जितने लोगों पर झूठे मुकदमे लगाये गये, जिस तरीके से हमारे झुंझुनूं जिले में एक बीजेपी के सांसद और

(श्री राजेन्द्रसिंह गुढ़ा)

उस समय के विधायक ने राजनीतिक द्वेषता से, जातीय द्वेषता से सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके जो हालात बना दिये गये, जहां तक मेरी जानकारी है अध्यक्ष महोदय, पिछले राज में हमारी पूर्व मुख्य मंत्री वसुंधरा जी का इतना टेरर था कि उनके सामने विधायक तो क्या, मंत्रियों की हिम्मत नहीं होती थी। मंत्री बोल नहीं सकते थे, अधिकारियों की हालत खराब थी। पूरा पावर एक जगह सैंट्रलाइज कर लिया गया था। राजस्थान को जिस तरह से बंधुआ बना दिया गया था अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से बताना चाह रहा हूं जिस तरीके की बातें की जा रही हैं, सच बात तो यह है कि चाहे पक्ष हो, चाहे विपक्ष हो, दो चुनाव मैंने खुद ने बिना किसी पार्टी के जीते हैं, तीसरा चुनाव मैंने ही जीता है और झुंझुनूं की उदयपुरवाटी जैसी सीट पर बिना किसी बड़ी पार्टी के चुनाव जीतना, अपने दम पर राजनीति करना और 36 कौम के लोगों को साथ लेकर चलना, यहां जितने भी ज्यादातर लोग हैं, तीन-तीन चुनाव लगातार जीतना मेरे हिसाब से कोई साधारण बात नहीं हो सकती। अध्यक्ष महोदय, मेरा तो आपको यही कहना है मुझे पता नहीं राजस्थान लेवल पर प्रदेश में रिफाइनरी की बातें हो रही हैं, मैट्रो की बातें हो रही हैं, दूसरी बातें हो रही हैं लेकिन सच बात तो यह है कि भयंकर भ्रष्टाचार का बोलबाला था। मुख्य मंत्रीजी हमारे विधान सभा क्षेत्र में आईं, अलग-अलग जातियों से मिलना कि ब्राहमण समाज आ जाये, राजपूत समाज के लोग आ जाओ, जाट समाज के लोग आ जाओ, जिस तरीके से राजस्थान को चलाने का काम किया और कोई बोलने की हिम्मत नहीं करता था। किसी की बोलने की हिम्मत नहीं थी। इन्होंने जाति के आधार पर हमारे राजस्थान को बांटने का काम किया और साम्प्रदायिक सौहार्द को खतम करने का काम किया। अध्यक्ष महोदय, आप मुझे टोकेंगे उससे पहले ही मैं बैठ जाऊंगा। मैं तो आपको यही बताना चाह रहा हूं। सच बात तो यह है कि इनकी पूर्व मुख्य मंत्री वसुंधरा जी के टाइम में राजस्थान का बेड़ा गर्त हो गया था और किसी की हिम्मत नहीं थी कि उनके सामने कोई बोल जाए। उनको मजा आता था जब कोई कहता था कि मुख्य मंत्रीजी, आपसे हम डरते हैं, यह उनको बहुत अच्छा लगता है। उन्होंने जिस तरीके से काम किया। मैं तो सोच रहा हूं कि इनकी इतनी सीटें कैसे आ गयीं, शायद इधर वालों ने गलतियां की हैं, उसी से यह हुआ है। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री राजकुमार रोत।

श्री राजकुमार रोत (चौरासी): अध्यक्ष महोदय, इस सदन में और विधान सभा में यह मेरा जीवन का पहला मौका है, बीच में मजबूरन मौका लिया था। अध्यक्ष जी ने एक मिनट दिया था। मैं कई दिनों से इस सदन में अनुभव कर रहा हूं। इस सदन में ऋण माफी को लेकर कई दिनों से बड़ा हंगामा हो रहा है। मैं आपके माध्यम से पक्ष और विपक्ष दोनों का ध्यान आपके माध्यम से आकर्षित करना चाहता हूं कि इस हंगामे को देखकर हमारे आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र के लोग संकोच में हैं, क्योंकि वहां के लोगों को ऋण मिला ही नहीं। आपने पत्रिकाओं में पढ़ा होगा कि आदिवासी क्षेत्र में एक लैम्पस में आठ करोड़ रुपये का घोटाला निकला है और अभी तक डूंगरपुर जिले में तीन हजार शिकायतें दर्ज की गयी हैं। मैं राज्य सरकार को धन्यवाद देना चाह रहा हूं कि उन्होंने जांच टीम भेजी है, पर मैं यह भी कहना चाह रहा हूं कि वह जांच टीम वर्तमान में लीपापोती कर रही है। जो लोग लैम्पस पर गये ही नहीं। लैम्पस की चिड़िया नहीं चढ़े, उन लोगों के नाम से 70-80 हजार रुपये का लोन ले लिया गया है। मैं राज्य सरकार से अपील करना चाह रहा हूं कि इसकी सही तरीके से जांच की जाये। इसी कड़ी में अभी वर्तमान में 20 से 25 लैम्पस पर ग्रामीणों द्वारा ताला लगाया गया है। प्रशासन और ग्रामीणों में बहुत संघर्ष चल रहा है। मैं राज्य सरकार से अपील करना चाह रहा हूं कि वहां पर ऐसी कोई अनहोनी घटना न हो, उससे पहले कोई अच्छा निर्णय लिया जाए। वर्तमान में जो व्यवस्थापक हैं, उन व्यवस्थापकों को तुरन्त हटाया जाए।

इसी कड़ी में, राज्यपाल का जो अभिभाषण है, उसमें 35 नंबर पर, सिंचाई के लिए सीमित जल की उपलब्धता। हमारे क्षेत्र में जो व्यवस्था है, उस पर मैं अध्यक्ष महोदय के माध्यम से सदन को बताना चाह रहा हूं कि डूंगरपुर-बांसवाड़ा में माही बांध और कडाणा बांध बना हुआ है। इनके बनने से वहां के आदिवासी लोगों को कई जगहों पर विस्थापित किया गया है। 1962 में गुजरात सरकार एवं राजस्थान सरकार के बीच में एक समझौता हुआ था कि गुजरात में नर्मदा कैनाल का पानी अगर पहुंच जाता है। उसके बाद कडाणा डैम और माही डैम का पानी राजस्थान के लोगों को दिया जायेगा। वहां पर अभी गुजरात में नर्मदा-कैनाल का पानी पहुंच गया है, पर राजस्थान सरकार ने अभी तक इसके लिये कोई पहल नहीं की है और वहां पर यह स्थिति है कि 100 परसेंट पानी गुजरात उपयोग कर रहा है और वहां के विस्थापित लोग जो कि 5 किलोमीटर दूर रह रहे हैं, उन लोगों को पानी की सुविधा नहीं मिल रही है। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय और मुख्य मंत्री महोदय को संदेश देना

(श्री राजकुमार रोत)

चाह रहा हूं, अपील कर रहा हूं कि इसके लिए कोई विशेष टीम बनाकर कोई योजना बनाएं और वहां के लोगों को पानी की सुविधा उपलब्ध करवायी जाए।

इसी संबंध में, अगली कड़ी में पाइंट नंबर 52 के माध्यम से मैं कहना चाह रहा हूं कि सरकार के द्वारा नयी शिक्षा व्यवस्था बनाकर समस्त बच्चों को गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने पर विशेष ध्यान दिया जायेगा। मैं कहना चाह रहा हूं कि जो बच्चे अपनी मातृभाषा भाषा स्थानीय भाषा में, परिवार से निकलकर जब स्कूल में जाता है तो स्कूल में जो शिक्षा व्यवस्था है, जो लैंग्वेज है, उस लैंग्वेज से वह दबाव में आ जाता है। जैसे कि हमारे आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में 50 परसेंट छात्र उपस्थित होते हैं। 50 परसेंट छात्रों का स्कूल में ठहराव नहीं हो पाता है। हमने जो वहां पर अध्ययन किया, उससे यह निष्कर्ष निकला है कि गर्वनमेंट स्कूलों में जिस लैंग्वेज में पढ़ाया जा रहा है, उसे लड़के समझ नहीं पाते हैं। मैं सदन को अपील करना चाह रहा हूं कि कक्षा एक से पांचवी तक स्थानीय लैंग्वेज में या उसका काम्बीनेशन बनाकर पढ़ाया जाए, जिससे बच्चों का ठहराव रहेगा और बच्चों का विकास होगा। इसी क्रम में जो शिक्षा व्यवस्था वर्तमान में चल रही है, जो पोषाहार व्यवस्था चल रही है और जो दूध वाला कार्यक्रम चल रहा है, उसके अंतर्गत हमने हमारे क्षेत्र की स्कूलों में देखा है कि कर्मचारी बंधु और शिक्षक बंधु पूरे दिन उसी व्यवस्था में लगे रहते हैं। इससे गवर्नमेंट महाविद्यालयों की स्थिति खराब होती जा रही है और शिक्षा व्यवस्था प्रभावित हो रही है।

इसी क्रम में पाइंट नंबर-66, खनिज की दृष्टि से राजस्थान एक समृद्ध प्रदेश है। यहां पर 81 प्रकार के खनिज उपलब्ध हैं। इसमें से 57 प्रकार के खनिजों का खनन किया जा रहा है। वर्तमान सरकार के द्वारा खनिज नीति की समीक्षा कर नई खनिज नीति का निर्धारण किया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार को कहना चाह रहा हूं कि शिड्यूल एरिया में जो खनन हो रहा है और उससे आसपास के लोगों का स्वास्थ्य प्रभावित हो रहा है। शिड्यूल एरिया में जो खनन हो रहा है तो शिड्यूल एरिया के लोगों को इसका फायदा नहीं हो पा रहा है। बाहर के जो उद्योगपति लोग हैं, वे इसका उपयोग कर रहे हैं। मैं कहना चाह रहा हूं कि शिड्यूल एरिया के लिए विशेष खनन नीति बनायी जाए, जिससे इसमें स्थानीय लोगों को भागीदारी मिले और वहां पर व्यवस्था सही बनी रहे क्योंकि वहां पर जमीन की लड़ाई है। बाहर के उद्योगपति वहां पर आकर अतिक्रमण करते हैं, जिससे वहां पर साम्प्रदायिक

(श्री राजकुमार रोत)

व्यवस्था फैलती है। अभी वर्तमान में बीजेपी के जो राज्य सभा सांसद हैं, उन्होंने कमेंट किया है कि आदिवासी एरिया में नक्सलवाद फैल रहा है। इन्हीं कारणों की वजह से लोग अपने अधिकारों के लिये आवाज उठाते हैं। इसके लिए जो पार्टी कमेंट करती है, उस पर हम कटाक्ष करते हैं।

इसी क्रम में पाइंट नंबर 72-राजस्थान एक ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक सम्पदा से परिपूर्ण है। यहां के ऐतिहासिक किलों, स्मारकों तथा संस्कृति के विभिन्न रंग देखने को मिलते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं इस संबंध में सरकार को अवगत कराना चाह रहा हूं कि आदिवासी बहुल क्षेत्र की जो संस्कृति थी, रीति-रिवाज हैं, परम्परा, कला है, वे धीरे-धीरे खतम होती जा रही हैं। शिड्यूल एरिया में अलग से बजट का प्रावधान हो रहा है तो उस बजट के माध्यम से सभी जिलों में सांस्कृतिक केन्द्र बनाये जाएं, जिससे वहां की संस्कृति, रीति-रिवाज, परम्परा और जो स्वतंत्रता सैनानी हैं, उनका इतिहास जीवित रहे। प्रति वर्ष शिड्यूल एरिया में जो बजट आता है, वह प्रति वर्ष लैप्स हो जाता है। इसके लिए विशेष प्रावधान बनाया जाए।

इसी क्रम में पाइंट नंबर 85-प्रदेश में अमन चैन, भाईचारा और शांति बनाये रखने के लिये साम्प्रदायिकता, वैमनस्य एवं धार्मिक उन्माद फैलाने वाले असामाजिक तत्वों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जाएगी। इस पाइंट के माध्यम से मैं कहना चाह रहा हूं कि आदिवासी बहुल क्षेत्र में अधिक से अधिक धर्मांतरण हो रहा है। कहीं-कहीं लोभ देकर, कहीं-कहीं लोगों को दबाकर धर्मांतरण किया जा रहा है, तो मैं सरकार को अवगत कराना चाह रहा हूं कि उसके लिए कोई विशेष कठोर कानून बनाया जाये। जो लोग ऐसी हरकतें कर रहे हैं, उनके लिये कठोर कानून बनाया जाए और उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए।

वहां पर भोले-भाले आदिवासी बहुल क्षेत्र के लोग रहते हैं, उनका कई धर्मों में धर्मान्तरण किया जा रहा है और उनका मिस-यूज किया जा रहा है। इसके लिए कोई विशेष प्रावधान किया जाए। इसी क्रम में हमारे राज्य के प्रशिक्षित युवाओं के साथ जो घिनौना खेल हो रहा है, इसके संबंध में मैं अध्यक्ष महोदय के माध्यम से सरकार को अवगत कराना चाहता हूं कि आरएएस भर्ती, 2016 अभी तक कोर्ट में अटकी हुई है और 2018 का भी रिजल्ट इस तरह दिया गया कि स्टूडेंट आज भी गुमराह है। मैं अध्यक्ष महोदय के माध्यम से सरकार को कहना चाहता हूं कि जो नियम 15 है, उसकी सही

(श्री राजकुमार रोत)

व्याख्या की जाए। इस नियम के अनुसार प्रत्येक वर्ग से प्री में 15 परसेंट यानी 15 अनुपात में स्टूडेंट लिये जाएंगे। परन्तु ऐसा नहीं हो रहा है। अभी जो रिवाइज रिजल्ट आया, उसमें एसटी और एससी को इसमें नहीं जोड़ा गया। एससी व एसटी को जो जनरल कैटेगिरी है, उसमें नहीं लिया गया। इसके लिए नियम 15 का विशेष उल्लेख किया जाए और उसको स्पष्ट किया जाए। पिछली सरकार की जो भर्ती है, उसमें सामान्य एरिया पर स्टे लगा हुआ था किंतु शिड्यूल एरिया के जो अभ्यर्थी थे, उन पर कोई स्टे नहीं था, उस भर्ती पर। वह विज्ञप्ति अलग थी। फिर भी आज तक उस भर्ती को लटकाया जा रहा है। इसके लिए विशेष टीम बनाकर, इसकी पैरवी की जाए।

मैं अध्यक्ष महोदय के मार्फत सरकार को कहना चाहता हूं कि शिड्यूल एरिया में जो प्रतिवर्ष बजट आता है, वह प्रतिवर्ष लैप्स हो जाता है। उसके लिए कोई विशेष प्रावधान बनाया जाए। वहां पर स्थितियां ऐसी हैं कि वहां पर साल में वर्षा ऋतु में ही सिंचाई होती है, शीतकालीन में कोई सिंचाई नहीं होती है, कोई खेती नहीं होती है। उस बजट के लिए कोई विशेष प्रावधान बनाया जाये। शिड्यूल एरिया में जो आरक्षण का प्रावधान है, उसको सरकार के माध्यम से स्पष्ट किया जाए। अंत में 60 नंबर पाइंट- रोजगार के लिए। उदयपुर संभाग में 50 प्रतिशत ऐसे मजदूर हैं जो गुजरात में जाते हैं। उनके लिए विशेष कोई प्रावधान किया जाये। वहां पढ़े-लिखे लोग भी, अभी एक ताजा उदाहरण पेश हुआ था हमारे सामने कि बी.एड धारी स्टूडेंट गुजरात में जाकर मजदूरी कर रहे हैं, अभी उसकी डैथ हो गई थी। शिक्षित बेरोजगारों के लिए ऐसी स्थिति है। ऐसा कोई विशेष प्रावधान किया जाये जिससे ऐसी नौबत न आए। इसी क्रम में एक लास्ट पाइंट नंबर 85, पाइंट नंबर 88-सैनिकों के लिए। मैं अध्यक्ष जी के माध्यम से सरकार को अवगत कराना चाहता हूं कि शिड्यूल एरिया में सैनिक भर्ती होती है तो शिड्यूल एरिया से बहुत कम स्टूडेंट जाते हैं। शिड्यूल एरिया में सैनिक स्कूल खोलने का प्रावधान किया जाये। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: पदमाराम जी।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): माननीय अध्यक्ष महोदय, डूंगरपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो बात कही है, वह सही बात है। धर्मान्तरण हो रहा है, सरकार को इस पर कोई कानून बनाना चाहिये, रोक लगाना चाहिए, बहुत गम्भीर मामला है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य प्लीज आप बैठिए। आप सीनियर आदमी हैं। बार-बार कहना पड़ता है, अच्छा लगता है क्या? डिबेट में सबको बोलना है। पदमाराम जी।

श्री पदमाराम (चौहटन): माननीय अध्यक्ष महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर दो दिन से चर्चा हो रही है। आपने बोलने का मौका दिया, आपको बहुत-बहुत बधाई व धन्यवाद। प्रजातंत्र के अंदर जनता का जो फैसला होता है, वह किसी भी पार्टी के लिए मंजूर होता है और राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी के कुशासन को समाप्त करने के लिए कांग्रेस को राजस्थान की जनता ने जनादेश दिया है। राजस्थान की जनता को सुशासन दें, राजस्थान की जनता के साथ अन्याय न हो, राजस्थान की जनता प्रगतिशील हो, राजस्थान का विकास हो, इसको मध्येनजर रखते हुए माननीय राज्यपाल महोदय ने एक साल के अंदर कांग्रेस की सरकार राजस्थान को आगे कैसे बढ़ाएगी, इसकी रूपरेखा अभिभाषण में है। मैं इसके पक्ष में बोलना चाहता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान की 70 परसेंट जनता गांवों में रहती है और ज्यदातार लोग कृषि प्रधान हैं, कृषि पर आश्रित हैं। किसानों को समय पर ऋण मिले, किसानों को उच्च क्वालिटी की बिजली मिले, किसानों की पैदावार का अच्छा मूल्य मिले। इसके लिए हमारी सरकार कटिबद्ध है। पिछले पांच साल से किसानों को समय पर बिजली नहीं मिल रही थी। किसानों को समय पर ऋण नहीं मिल रहा था। किसानों को उपज का अच्छा मूल्य भी नहीं मिल रहा था। इसलिए किसान दिनों-दिन कर्जे के भार से दब रहे थे। भारतीय जनता पार्टी के शासन में भी ऋण माफी की घोषणा की गई, जो सिर्फ घोषणा मात्र थी। उन्होंने पचास हजार तक का कर्जा माफ करने की घोषणा कर दी। परन्तु उसके अंदर एक कंडीशन डाल दी कि सिर्फ बारह बीघा ऋण लेने वाला किसान है, उसका ही पचास हजार तक का कर्जा माफ होगा। को-आपरेटिव बैंक के अंदर 12 बीघा वाले को 25 हजार से ज्यादा ऋण दिया ही नहीं जा रहा था। मैं को-आपरेटिव के अंदर नौकरी करके आया हूं। 25 हजार से ज्यादा का ऋण दिया ही नहीं जा रहा था तो 50 हजार का कर्जा कैसे माफ होगा?

दूसरी बात, उन्होंने यह कंडीशन डाल दी कि चुनाव आ गए और चुनावों के अंदर ज्यादा से ज्यादा लाभ कैसे लें, पूरे नेताओं ने गांव-ढाणी के अंदर जबरदस्त मीटिंग्स बुलानी चालू कर दी और प्रमाण पत्र देना चालू कर

(श्री पदमाराम)

दिया। हमने सोचा कि बैंक के जितने भी ऋणी हैं, उनको ऋण माफ हो गया है और पैसे सब किसानों के खाते में आ गये हैं। जब किसानों से बात की, ग्राम सेवा सहकारी समिति के व्यवस्थापकों से बात हुई तो उन्होंने कहा कि सरकार का दबाव है कि ज्यादा से ज्यादा प्रमाण पत्र वितरित किये जाएं और पैसा अभी तक एक भी नहीं आया। मात्र दो हजार करोड़ रुपये जमा हुए, वह किसी बैंक के अंदर गये, किसी बैंक के अंदर नहीं गये। जब विधान सभा स्टार्ट हुई तो ये माननीय सदस्य नारेबाजी कर रहे थे 'किसानों के साथ धोखा-किसानों के साथ धोखा', जब आपने ऋण माफी की, आपने लोगों को एक पैसा भी नहीं दिया। लोगों के साथ छलावा किया और वोट लेने के लिए बड़ी-बड़ी बातें कीं तब धोखा नहीं हुआ। कांग्रेस की सरकार आई और माननीय मुख्य मंत्रीजी ने शपथ लेते ही घोषणा कर दी कि हम को-आपरेटिव बैंक के जितने भी अल्पकालीन ऋण है, वह पूरे माफ करेंगे और कामर्शियल बैंक हैं, जो राष्ट्रीयकृत बैंक हैं, उनके अवधि पार ऋण, जो बड़े-बड़े कामों के लिए ट्यूबवैल के लिए, मशीन के लिए, फव्वारों के लिए जो ऋण लिया, उसके अवधि पार लोन है, उनको दो लाख तक का कर्जा माफ किया। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे निवेदन है, सभी माननीय सदस्यों की मंशा है कि अवधि पार ऋण जो समय पर नहीं चुका सके, उसका माफ करें। उसके साथ-साथ जो किसान समय पर ऋण भर रहा है, उसके भी दो लाख तक का कर्जा माफ करें तो आम आदमी को राहत मिलेगी। किसान को सम्बल मिलेगा। किसान उन पैसों से अपने बच्चों को अच्छी क्वालिटी की शिक्षा दिला सकता है, खुद के बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए सहयोग दे सकता है।

मेरा यह निवेदन है कि हमारे सिंचाई क्षेत्र के अंदर मेरे विधान सभा क्षेत्र के अंदर नर्मदा नहर चल रही है और नर्मदा नहर का काम पिछली भारतीय जनता पार्टी के शासन में हुआ था। उस समय उन्होंने ऐसा पैमाना बनाया कि पूर्व के अंदर नहर चल रही है, लोगों के खेतों की जमीन एक्वायर्ड हो गयी है परन्तु पूर्व की तरफ उन्होंने पूरा कम्बाइन्ड एरिया कर दिया और उत्तर की तरफ का क्षेत्र नहर के एक इंच भी आगे नहीं बढ़ाया। पहले भी मैंने विधान सभा के अंदर निवेदन किया था और माननीय हेमाराम जी जल संसाधन मंत्री थे, उन्होंने मुझे आश्वासन दिया था कि आपकी 15-16 पंचायतें जो इसके अंदर जुड़ रही हैं, उनको जोड़ने की कोशिश करेंगे। परन्तु पिछली सरकार ने इसको आगे बढ़ाने की बात तो बहुत दूर है।

(श्री पदमाराम)

जो कमांड एरिया था उसके अंदर समय पर पानी नहीं आया। कभी पानी आता था, कभी पानी नहीं आता था। अवैध पानी लोग बीच में से चुरा लेते थे, टेल पर रहने वाले खेतों को पानी नहीं मिला। अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से निवेदन है, माननीय जल संसाधन मंत्री, सरकार जो वंचित क्षेत्र है उनको जोड़ने की अनुशंसा करवाएं। पानी है, नदी के अंदर ओवर फ्लो फ्लड के कारण नदी के अंदर डाल रहे हैं, आगे वाले किसानों को इसका सदुपयोग करवाएं तो आम आदमी को मजबूती मिलेगी।

दूसरा मेरा निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने 40 हजार किसानों को कृषि कनेक्शन देने की घोषणा कर दी, किसानों के सब डिमांड निकल गए, किसानों के सब डिमांड भर दिए, सब लोग यह चाह रहे थे कि हमको बिजली मिल जाएगी। आज हालत यह है कि दो सब सेंटर, एक के अंदर तीन सौ को कनेक्शन मिला है और एक के अंदर ढाई सौ को कनेक्शन मिला है बाकी पांच हजार कनेक्शन उधार लेकर, दूसरों से लेकर, बैंकों से ऋण लेकर डिमांड भर दी, किसानों के साथ धोखा किया है। उस धोखे की भरपाई करने के लिए हमारे मुख्य मंत्रीजी ने घोषणा की है कि हम 30 जून तक, 01 जुलाई तक एक लाख किसानों को कृषि कनेक्शन, जितने भी सामान, उन्होंने डिमांड भरे हैं उनको सामान दे देंगे, हम इनको बधाई देना चाहते हैं। निवेदन करना चाहते हैं कि जिन किसानों ने डिमांड भर दी है वह आज दर-दर की ठोकरे खा रहे हैं उनको कभी पोल नहीं मिल रहा है, कभी ट्रान्सफार्मर नहीं मिल रहा है, कभी कोई सामान नहीं मिल रहा है। मेरा आपसे यह निवेदन है ऊर्जा मंत्रीजी यह सुनिश्चित करें कि समय पर जितने भी आदमियों को आप कनेक्शन दे रहे हैं उनको समय पर सामान उपलब्ध करवाएं, उसको किसी तरह की तकलीफ नहीं हो। गरीब आदमी अपने खेत की जुताई के लिए ऋण लेकर डिमांड भरते हैं, कृषि करने के लिए वह तैयार रहते हैं लेकिन उसको समय पर सामान नहीं मिलता है जिससे उनके साथ बहुत बड़ा धोखा होता है, आप मेहरबानी करके उसको सुनिश्चित करें।

मेरा दूसरा निवेदन है कि भारतीय जनता पार्टी के राज में किसानों की बिजली रेट बढ़ा दी, चार साल तक किसानों को लूटा गया। बीच के अंदर इन्होंने घोषणा की कि जो पैसे हमने बढ़ाए थे वह वापिस किसानों के खातों में जमा करा देंगे लेकिन असत्य की तो इन्होंने पीएचडी की हुई है। दूसरों के ऊपर जो भी बोलते हैं तो यह कहते हैं असत्य बोलते हैं, इन्होंने तो असत्य पर

(श्री पदमाराम)

पीएचडी की हुई है। कोई भी बोलो, जो भी बोलो असत्य बोले। जोर-जोर से बोलो और बार-बार बोलो तो सामने वाले को अहसास हो कि यह सच बोल रहे हैं। यह जनता को साबित कराना चाहते हैं कि आगे लोक सभा चुनाव है। लोक सभा चुनाव में हम अपना रिजल्ट ऐसा कैसे करें उसको मध्यनजर रखते हुए यह यहां पर जोर-जोर से और अपनी छवि सुधारने का काम कर रहे हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि मुख्य मंत्रीजी ने अभी घोषणा की है कि पांच साल तक बिजली के बिल की रेट नहीं बढ़ाएंगे वह सराहनीय कदम है। एक गरीब आदमी के लिए, किसान के लिए यह बहुत बड़ी घोषणा है।

दूसरा निवेदन है, अभी सिविल लाइन से आए माननीय सदस्य फर्मा रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के राज में कर्जा बढ़ गया। इन्होंने मंहगाई, पहले तो डिमांड एक थी बहुत हो गई महंगाई अब होगी मोदी सरकार। सब लोगों की इच्छा थी कि मोदी जी के राज में किसी प्रकार की मंहगाई नहीं होगी, भ्रष्टाचार खतम हो जाएगा, 15-15 लाख रुपये खाते में आ जाएंगे, दो लाख जवानों को नौकरी मिल जाएगी। बड़े-बड़े भाषण दिए जाते थे, गरीब के बेटे को कलेक्टर बनाना कि नहीं बनाना, गरीब को फैक्ट्री लगानी कि नहीं लगानी। सब लोगों को ऐसा लग रहा था कि अब स्वर्ण युग आ जाएगा, अब किसी को कमाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मोदी जी राज के अंदर सब लोग आराम से बैठे रहेंगे। एक परिवार के अंदर 15 सदस्य हैं, 15 सदस्यों के पास करोड़ रुपये आ जाएंगे, ब्याज को खर्च करेंगे तब भी हमें तकलीफ नहीं होगी यह असत्य बोले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

महारानी जी ने सुराज यात्रा के अंदर यह कहा था कि मैं हर साल तीन लाख लोगों को नौकरी दूंगी, पूरे पांच साल निकल गए लेकिन रोजगार के नाम पर कुछ नहीं। नरेगा के अंदर रोजगार चल रहा था उसको भी इन्होंने बंद कर दिया। नरेगा के अंदर ईआरजी अभियोजना थी, ईडीपी योजना थी अन्टाइड फण्ड था, टीएफसी थी वह सब बंद कर दी। उन सब मिलाकर मुख्यमंत्री जल संवर्धन योजना चालू कर दी। एक पंचायत के अंदर ऐसे लोगों को तीन-तीन, चार-चार करोड़ रुपये दे दिए। नरेगा के अंदर पहले टांके चल रहे थे, इन टांकों की रेट 80 हजार थी उसको बढ़ाकर डेढ़ लाख रुपये कर दिया गया। नरेगा के अंदर टांके चल रहे हैं उसमें दूसरी योजनाओं को, आम आदमी के गांव का विकास कैसे हो, गली का विकास कैसे हो। दूसरा इन्होंने गांवों में गौरव पथ

(श्री पदमाराम)

का बहुत बड़ा तोहफा दे दिया। गौरव पथ में एक किलोमीटर के अंदर ...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: गौरव पथ है।

श्री पदमाराम (चौहटन): गौरव पथ है, आप ज्यादा पढ़े लिखे हो हम बैकवर्ड एरिया से आते हैं इसलिए थोड़ा याद नहीं है, आप याद दिलाना। गौरव पथ में एक किलोमीटर के अंदर 58 लाख रुपये कर दिए, 25 लाख के अंदर डामर रोड़ बन रही है, दो किलोमीटर हो सकती है, ग्रामीण इलाके में गौरव पथ की कोई जरूरत नहीं थी। यदि यह पैसे किसी ढ़ाणी को जोड़ने के लिए, किसी गांव को जोड़ने के लिए, किसी जगह पर काम लेने के लिए होते तो बहुत अच्छा होता। इससे विदित होता है कि यह भ्रष्टाचार बंद करने की सोच रहे हैं परन्तु ऐसा सुनने में आया है, महानुभाव आपके विराजमान हैं, खैर इनको ज्यादा नॉलेज होगी, हम तो विधान सभा में नहीं थे परन्तु ऐसा सुनने में आया है कि जयपुर स्टेज पर इनके टेंडर हुए उसके अंदर पता नहीं कुछ-कुछ होगा।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि हम सीमावर्ती क्षेत्र से आते हैं, हमारे यहां एस टी के लोग बहुत गरीब हैं, उनको बोर्डर क्षेत्र पर विद्युत कनेक्शन में प्राथमिकता नहीं मिल रही है। टाडा माडा में टीएसपी क्षेत्र में प्राथमिकता मिलती है। मेरा आपसे, सरकार से, माननीय मुख्यमंत्रीजी से भी निवेदन है कि जब जवाब दें उस समय सीमावर्ती क्षेत्र, बोर्डर क्षेत्र के गरीब एस टी के लोगों को विद्युत कनेक्शन के अंदर प्राथमिकता से जोड़े।

एक निवेदन यह है, अभी माननीय सदस्य बता रहे थे कि कांग्रेस का राज आने के बाद चोरियां हो गई, प्रशासन नाम की चीज नहीं है, मेरा निवेदन है कि 02 अप्रैल के अंदर अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों ने अपने हक के लिए संविधान में जो संशोधन किया उस संशोधन को रूकवाने के लिए, अपने हक को बचाने के लिए इन्होंने आंदोलन किया। उस आंदोलन के अंदर आंदोलनकारियों के साथ पशुओं सी बर्बरता की, पुलिस द्वारा उनकी पिटाई की गई उन पर देशद्रोही के मुकदमे किए गए, 302 के मुकदमे लागू किए गए। अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि ऐसे असत्य मुकदमे वापिस लिए जाएं। अनुसूचित जाति और दलित लोगों की रक्षा की जाएं। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

डा. महेश जोशी (सरकारी मुख्य सचेतक): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय एक घंटे के लिए बढ़ा दिया जाए।

श्री अध्यक्ष: सबकी सहमति है?

(स्वीकृत)

श्री नारायण सिंह जी देवल।

अभिभाषण

धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद

श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा): अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने का मौका दिया, मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। इस पवित्र सदन में 17 तारीख को महामहिम राज्यपाल महोदय ने अभिभाषण दिया। राज्यपाल महोदय का अभिभाषण सरकार का नीति पत्र होता है। मेरा ऐसा मानना है कि यह अभिभाषण नीतिहीन और दिशाहीन है क्योंकि इस अभिभाषण में राज्य सरकार ने जो गाइड लाइन रखी है उस पर खरा उतरना लगभग असम्भव है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जयपुर की एक आम सभा में एक से लगाकर दस तक तालियां पीटते-पीटते, ऋण माफी की घोषणा की गई थी।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि आज एक महीना और चार दिन से ऊपर हो गया है, इनका जन घोषणा पत्र था कि दस दिन के अंदर दो लाख का कर्जा माफ करना। इस संबंध में अभी भी यह स्पष्ट नहीं है कि राज्य के किन-किन किसानों का ऋण माफ होगा, कौन पात्र होगा। राष्ट्रीयकृत बैंक, अनुसूचित बैंक व क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक से ऋण लेने वाले किसानों का कर्जा माफ किया जाएगा, क्या भूमि विकास बैंक और जिले की केन्द्रीय सहकारी बैंक से किसानों द्वारा लिए गए ऋण माफ किया जाएगा।

कब तक ऋण माफ होगा, किस प्रकार से योजनाओं को क्रियान्वित किया जाएगा। क्या भा.ज.पा. सरकार ने जिन किसानों का ऋण माफ किया था, उनका ऋण भी पुन: माफ किया जाएगा, और भा.ज.पा. सरकार ने

(श्री नारायण सिंह देवल)

सहकारी अल्पकालीन फसली ऋण माफ करने के पश्चात किसानों को पुन: फसली ऋण वितरित किया गया था, क्या वर्तमान सरकार भी किसानों को पुन: खरीफ व रबी का फसली ऋण वितरित करेगी, और किसानों का कर्जा माफ करने के लिये सरकार वित्तीय संसाधन कहां से और किस प्रकार जुटायेगी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें अभी तक कोई भी बात स्पष्ट नहीं हुई है और मेरा ऐसा मानना है कि यह सरकार की थोथी घोषणा है। बिना किसी स्पष्ट नियम, प्रावधान से यह घोषणा कर दी। अभी तक किसी भी किसान के द्वारा कर्ज माफी का कोई लाभ नहीं मिला है और लगता नहीं कि इन पांच सालों के अन्दर मिलेगा। अगर मिल गया है तो कितने किसानों को इसका लाभ मिला? मैं आपके माध्यम से सरकार को यह पूछना चाहता हूं, और अभी तक सरकार ने कितने किसानों का कर्जा माफ किया। यह सारा एक चुनावी जुमला था, जबकि पूर्ववर्ती भा.ज.पा. की सरकार में 50 हजार से अधिक ऋण माफी की घोषणा की गई, इसमें किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया गया। 50 हजार के अलावा, जिस किसान के ऊपर पैनल्टी या ब्याज भी था, जैसे 50 हजार का ऋण लिया हुआ था और 40 हजार की पैनल्टी और ब्याज था, ऐसे में 90-90 हजार तक की ऋण माफी पूर्ववर्ती सरकार के द्वारा की गई। इसमें करीब 27 लाख 82 हजार 302 किसानों को राजस्थान में लाभ मिला। 9 लाख 02 हजार से अधिक बड़े काश्तकारों को भी इसका लाभ मिला।

माननीय अध्यक्ष महोदय, 01 अप्रैल से 30 नवम्बर, 2018 तक जो ऋण माफी की घोषणा हुई, इसके अन्दर 21 लाख किसानों में से लगभग 19 लाख 50 हजार किसानों को 50 हजार तक फसली ऋण दिया गया। ऋण का एक किसान का औसत 48 हजार है। इसमें यह भी कहा गया कि जो किसान डिफाल्टर है, उन्हीं का ऋण माफ होगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, शिव से आने वाले माननीय सदस्य भी चिंता कर रहे थे और इसके अलावा भी कई सदस्यों ने यह चिंता की कि डिफाल्टर को तो हमेशा ऋण माफी का या और किसी इस टाइप की घोषणा का फायदा मिलता है, परन्तु जो किसान समय-समय पर ऋण भर रहा है, साहूकार किसान है, उनको यह लाभ नहीं मिलता। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि ऋण माफी में सभी किसानों को, चाहे बड़े हों या चाहे छोटे हों, उन सभी को इसका लाभ

(श्री नारायण सिंह देवल)

मिल सके। मेरा एक अनुमान है कि लगभग एक लाख 50 हजार किसानों का लगभग 50 हजार का ऋण लिया हुआ है और उसमें से डेढ़ लाख किसानों ने एक लाख से अधिक का लोन ले रखा है। कांग्रेस सरकार मात्र कुछ हजार किसानों का ऋण माफ करेगी। कांग्रेस सरकार वाहवाही तो ऐसे लूट रही है, जैसे इन्होंने कोई करिश्मा कर दिया।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे से पहले अभी चौरासी से जो सदस्य अपनी बात कह रहे थे, मैं भी आपका उसमें ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। कुछ समाचार पत्रों में डूंगरपुर जिले की कुछ सोसायटियों में कर्ज माफी को लेकर अनियमितता व घोटाले की खबरें प्रकाशित हुई हैं। मैं आपके माध्यम से यह मांग करूंगा कि इसकी जांच की जाए। एक समाचार पत्र में पीलीबंगा और हनुमानगढ़ तहसील में 17 किसानों की जमीन की कुर्की, नीलामी निकाली। मैं आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहता हूं कि यह किस टाइप की कर्ज माफी है। माननीय अध्यक्ष महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में सरकार ने जो किसानों को कृषि के लिये आसान ऋण उपलब्ध कराने की बात कही है, मैं आपके माध्यम से सरकार से यह पूछना चाहूंगा कि किसानों को कृषि के लिये आसान ऋण कहां से उपलब्ध कराएंगे। क्या सरकार ने इसके लिये कोई वित्तीय प्रावधान या प्रबंधन किए हैं, या यह भी सिर्फ आगामी लोक सभा चुनावों को मध्यनजर रखते हुए एक जुमला है।

पिछली कांग्रेस सरकार ने चुनावी साल में अनेक लोक लुभावनी योजनाएं शुरू की थीं, जिससे राजस्थान के ऊपर लगभग एक लाख 29 हजार 900 करोड़ रुपये का वित्तीय भार पड़ा था फिर भी पिछली कांग्रेस सरकार ने चुनावी लाभ के लिये बिना किसी वित्तीय प्रबंधन, मुफ्त दवा और पेंशन आदि योजनाएं शुरू कीं, जो सही प्रकार से क्रियान्वित नहीं हो पाईं, और जनता ने चुनावों में धरातल दिखा दिया, एक सशक्त विपक्ष की भूमिका की स्थिति के लायक नहीं रहे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके बाद भी पूर्ववर्ती भा.ज.पा. की सरकार ने इन योजनाओं को बंद नहीं किया। बल्कि इसमें और अधिक सुधार करने के लिये हमारी यशस्वी मुख्य मंत्री ने भामाशाह योजना के माध्यम से गरीब का 30 हजार से लगाकर 3 लाख तक का इलाज, और अच्छी क्वालिटी का गुणवत्तापूर्वक इलाज कराने की भामाशाह योजना लाये। इसमें सरकारी अस्पताल के साथ-साथ में बड़े अस्पताल भी स्वीकृत थे। सरकार ने यह प्रयास

(श्री नारायण सिंह देवल)

किया कि गरीब और अमीर की जो खाई थी, उसको पाटने की कोशिश की। जिस हास्पिटल के अन्दर बड़ा आदमी इलाज कराता था, उसी हास्पिटल के अन्दर गरीब आदमी भी भामाशाह योजना के माध्यम से यह नि:शुल्क इलाज करा सकता था।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आज हम विपक्ष में हैं। परन्तु आज भी राजस्थान के जनमानस के स्मृति पटल में पूर्ववर्ती भा.ज.पा. सरकार की अमिट छाप है। पिछली बार भी कांग्रेस की सरकार 'खजाना खाली है', 'खजाना खाली है', यह रट लगाती रही। इस बार भी इन्होंने राज्य की सत्ता सम्भालते ही 'खजाना खाली है', 'खजाना खाली है', यह रट लगाना चालू कर दिया।

माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार द्वारा रबी सीजन में किसानों को फसली ऋण नहीं दिया जा रहा है। जबकि पूर्ववर्ती भा.ज.पा. की सरकार में 62 हजार करोड़ का फसली ऋण किसानों को बांटा गया। जालौर जिले के साथ दूसरे जिलों में 2017 की जो अतिवृष्टि हुई, उसके जो मुआवजे के पैसे हैं, वे भी किसानों को नहीं मिल रहे हैं। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय का इसकी ओर भी ध्यान आकर्षित करूंगा, और राज्य सरकार ने इस वर्ष राज्य में जो कमजोर मानसून था, उसको देखते हुए रोजगार, पेयजल और चारे के लिये कोई ठोस प्रबंधन की तैयारी नहीं की। जिससे आने वाले समय में हर वर्ष इसके लिये परेशानी होगी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से यह कहना चाहूंगा कि इस राज्यपाल अभिभाषण में यह कहा गया है कि जनवरी, 2012 तक जो डिमाण्ड नोटिस जमा हो चुके हैं, एक लाख किसानों को कृषि कनेक्शन देंगे। मेरा ऐसा मानना है कि अभी तक हमारे वहां 2011 से 2012 तक जो डिमाण्ड नोटिस जारी हुए हैं, वह सामान भी नहीं मिल रहा है। किसान आज भी बिजली विभाग और कर्मचारियों के पीछे चक्कर लगा-लगाकर थक चुका है। यह जो घोषणा की है, वह धरातल पर कहीं भी पूरी होती नजर नहीं आ रही है।

(17.00 बजे)

चौहटन से आने वाले माननीय सदस्य जो कह रहे थे, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहूंगा कि अभी कुछ ही दिनों पहले मैं रामदेवरा से इस बैल्ट में आया था, पहले जो बिजली थी वह कोई बड़े-बड़े राजा महाराजा या बड़े सेठ साहूकार के घरों में बिजली

(श्री नारायण सिंह देवल)

टिमटिमाती थी परन्तु मैं यह धन्यवाद देना चाहूंगा देश के प्रधान मंत्री आदरणीय मोदीजी को और हमारी यशस्वी मुख्य मंत्री आदरणीया वसुन्धराजी को, पंडित दीनदयाल ग्राम ज्योति विद्युत योजना के तहत उन झोंपड़ियों के अंदर, उन कच्चे मकानों के अंदर आज बिजली टिमटिमा रही थी और मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि चुनाव होने के बाद में आज पंडित दीनदयाल ग्राम ज्योति विद्युत योजना का काम सारा ठप्प पड़ा है और वह काम भी जल्दी से जल्दी कराया जाए।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

इसके अलावा, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा कि जो पेयजल और सिंचाई के लिए बेहतर प्रबंधन की बात कही गयी है तो मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहूंगा कि जालौर और बाड़मेर जिले के लिए जो नर्मदा लिफ्ट कैनाल है वह एक वरदान साबित हुई है। चूंकि, बांध की हाइट बढ़ाई गयी है तो सांचौर की जो ग्यारह पंचायतें हैं उनमें किसानों को खेती के लिए पानी दिया जाए और हमारे जो ड्रिंकिंग वाटर के प्रोजेक्ट थे, डी.आर. प्रोजेक्ट, उसमें चालीस गांवों में पानी जा रहा है, उस पर भी आज ध्यान देने की आवश्यकता है और हमारे जो ई.आर. प्रोजेक्ट हैं, इसमें जालौर, रानीवाड़ा और आहोर और भीनमाल के 256 गांव हैं यह काम भी चल रहा है और इसके लिए 455 करोड़ रुपये की मंजूरी भी मिल गयी है, मुख्य पाइप लाइन का 80 परसेंट काम भी हो गया है परन्तु क्लस्टर का काम नहीं हुआ है, इसकी ओर भी आप ध्यान दें।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे आपने राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने के लिए समय दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री आलोक बेनीवाल।

श्री आलोक बेनीवाल (शाहपुरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर आपके द्वारा समय देने पर मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा करते हुए, चुनावों के बाद में यह सरकार बनी, कांग्रेस की सरकार बनी, जो घोषणा पत्र था कांग्रेस का उसमें किसानों की ऋण माफी का मुद्दा काफी अहम था और ऋण माफी के मुद्दे पर सरकार के द्वारा घोषणा भी की गई, उस घोषणा का मैं स्वागत करता हूं।

(श्री आलोक बेनीवाल)

साथ ही, जो वृद्धावस्था पेंशन में वृद्धि की गयी, वह भी सराहनीय है। साथ ही, इस ऋण माफी में आज भी गांवों में कई भ्रम की स्थिति पैदा हो जाती है। जब शुरूआत में यह ऋण माफी का मुद्दा चला था, जब भी एक डिफाल्टर का मामला ऐसा इसमें है जो लगातार, जब ग्रामीण क्षेत्र में हम जाते हैं तो वह यह कहते हैं कि जो डिफाल्टर का मामला है इसको आप क्लियर करें लेकिन मैं सरकार से यह उम्मीद रखता हूं और जो कमेटी सरकार ने बनाई है उससे भी उम्मीद रखता हूं कि जो हमारा किसान है उसका, चाहे वह राष्ट्रीयकृत बैंक है, चाहे उसका के.सी.सी. है, चाहे उसका ग्रामीण बैंक से जो ऋण है और साथ ही जो कृषक समृद्धि योजना, एक सहकारी बैंक यह चलाती है जो 11 परसेंट पर ब्याज देती है एक से तीन लाख रुपये, वह भी इसमें शामिल करें और सम्पूर्ण जो कर्जा माफी का मामला है, उसको ध्यान में रखते हुए उस काश्तकार का भी ऋण माफ करें जो साहूकारी से उसको अदा करता है।

साथ ही, मैं आपको यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो मेरा विधान सभा क्षेत्र है, उसमें आज पेयजल की भारी कमी है और आज भी मेरे शाहपुरा नगरपालिका क्षेत्र में और मनोहरपुर में जो कि दो बड़े कस्बे हैं, पानी की जितनी आवक वहां पर होनी चाहिए, उतनी आवक वहां पर नहीं हो पा रही है क्योंकि जो पानी के सोर्सेज हैं, उन सोर्सेज से पानी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। मैं सरकार से यह मांग करूंगा, यही स्थिति मेरे पूरे क्षेत्र की लगातार होती जा रही है, लगभग दो तिहाई से ज्यादा हिस्सा मेरे यहां पर काफी सूख गया है, जहां पर पानी की उपलब्धता बहुत कम है। कई पंचायत क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर एक सिंगल फेस बोरिंग करने की भी स्थिति नहीं है क्योंकि पानी का जो लेवल है, वह बहुत नीचे चला गया है इसलिए बड़ी चिंताजनक स्थिति मेरे विधान सभा क्षेत्र में पेयजल की हो चुकी है और इसके कारण जो काश्त का काम है वह भी काफी कम होता चला जा रहा है।

पीने के पानी के लिए भी टैंकरों के द्वारा ही कई जगह पर व्यवस्था की जाती है इसलिए मैं राज्य सरकार से यह मांग करूंगा कि कोई न कोई इसका स्थाई समाधान निकालकर वहां के काश्तकार और आम जनता को राहत देने का काम करें तो निश्चित तौर से यह बहुत बड़ा काम होगा क्योंकि जो पूर्वी राजस्थान के अंदर जयपुर जिला भी आता है उसमें भूजल की स्थिति लगातार बड़ी खराब होती जा रही है इसलिए कोई न कोई जल्दी से जल्दी और

(श्री आलोक बेनीवाल)

समयबद्ध तरीके से कोई योजना इस क्षेत्र में आए तब जाकर इस क्षेत्र के किसान और आम आदमी का भला हो पाएगा।

साथ ही, मैं आपके माध्यम से सरकार को कहना चाहूंगा कि शाहपुरा जयपुर दिल्ली नेशनल हाई-वे पर मौजूद है और एक व्यस्ततम सड़क वहां से नेशनल हाई-वे की चलती है। बहुत लम्बे समय से इस क्षेत्र की एक मांग थी कि यहां पर एक मल्टी स्पेशलिटी हास्पिटल और ट्रोमा सेंटर बने, जिससे कि जो नेशनल हाई-वे की कैजुअल्टी है, प्लस जो इस क्षेत्र के आस-पास की भौगोलिक स्थिति है उसको देखते हुए यहां की आम जनता को सस्ता और सुलभ स्वास्थ्य का लाभ मिल सके जिससे आम जनता को इसका लाभ मिले तो मैं सरकार से यह मांग करूंगा कि आने वाले समय में मेरे इस क्षेत्र की मांग का ध्यान रखें।

साथ ही, अभिभाषण के बिंदु संख्या 52 और 56 में प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा की गुणवत्ता के सुधार पर बात कही गयी है। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं महिला शिक्षा के बारे में आपके माध्यम से यह कहना चाहूंगा कि मेरे क्षेत्र में जो उधर अमरसरवाटी और खेजरोली का क्षेत्र है, उसमें महिला शिक्षा के रूप में एक महाविद्यालय की बहुत आवश्यकता है इसलिए मैं राज्य सरकार से यह मांग करूंगा कि आने वाले समय में मेरे उस क्षेत्र में एक महाविद्यालय खोलने का अगर प्रावधान करेंगे तो मैं कृतज्ञ होऊंगा।

साथ ही, अभिभाषण के 71वें बिंदु में खेल नीति के संबंध में कहा गया है। मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि बहुत समय पहले जब यहां से आदरणीया कमलाजी इस क्षेत्र का नेतृत्व करती थीं उस समय उस क्षेत्र में एक खेल स्टेडियम की जगह उन्होंने तलाश की थी और उसका निर्माण वहां पर करवाया था। उस स्टेडियम को अच्छा विकसित करके और वहां खेल के कोच लगाकर नौजवान साथियों को एक अच्छा प्लेटफार्म देने का काम करें तो राज्य सरकार से मैं यह भी मांग करता हूं।

साथ ही, मेरे इस क्षेत्र में जो नेशनल हाई-वे से जुड़ा हुआ है, आधा क्षेत्र मेरा ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): अनुमति हो तो, अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि इतनी अच्छी बहस चल रही है, एक भी कैबिनेट मिनिस्टर सदन में उपस्थित नहीं है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: वहां पर धारीवाल साहब बैठे हुए हैं।

श्री गोविंद राम (खाजूवाला): राठौड़ साहब, यह बैठे हैं न।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): इनकी वहां पर सीट नहीं है। इनको हिदायत दीजिये, यह गरिमा की बात है। (व्यवधान)

श्री गोविंद राम (खाजूवाला): राठौड़ साहब, इधर बैठे हैं। इधर नजर घुमाइये।

श्री अध्यक्ष: आपकी बात मान ली सब ने। आपकी बात पर गौर कर लिया सब ने।

श्री गोविंद राम (खाजूवाला): इधर घुमाइये नजर।

श्री अध्यक्ष: आप बोलिये, बोलिये।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): अध्यक्ष महोदय, मैं सदन के कार्य संचालन नियम की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि जब भी कोई वक्ता बोल रहा हो तो आसन और वक्ता के बीच में इस तरह से खड़ा होना नियमों का उल्लंघन है। आप रूल 269, 280 देख लो।

श्री अध्यक्ष: धन्यवाद। बेनीवाल साहब, आप बोलिये।

श्री आलोक बेनीवाल (शाहपुरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, शाहपुरा जयपुर से लगभग 65 किलोमीटर पड़ता है और मैं यहां पर उपस्थित सरकार से भी निवेदन करना चाहूंगा कि जयपुर और चौमूं, जो रोडवेज की लो-फ्लोर बस चलती है जे.सी.टी.एल. वालों की, वैसी ही बस सेवा शाहपुरा और जयपुर के बीच में चलायी जाये, मैं उनसे मांग करना चाहता हूं।

साथ ही आपसे एक बात और कहना चाहता हूं नेशनल हाईवे, जो दिल्ली और जयपुर का है, शाहपुरा पर जो फ्लाई-ओवर है, आपके पावटा का फ्लाई-ओवर कमप्लीट हो गया, कोटपूतली का हो गया, बहरोड़ का हो गया, लेकिन शाहपुरा का जो फ्लाई-ओवर है, वह आज भी पैंडिंग पड़ा हुआ है। वैसे वह केन्द्रीय सरकार का मामला है, लेकिन मैं इस सदन के माध्यम से और आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहूंगा कि इस फ्लाई-ओवर का निर्माण, जो एक-दो साल से बंद पड़ा है, उसको शीघ्रातिशीघ्र पूरा करके जन सुविधा का ध्यान रखते हुए, क्योंकि वहां लगातार दुर्घटनाएं हो रही हैं और उन दुर्घटनाओं के कारण इस फ्लाई-ओवर का निर्माण बहुत जरूरी है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि इस बात को भी

(श्री आलोक बेनीवाल)

शीघ्रातिशीघ्र पूरा किया जाए। साथ ही, आपसे एक बात और कहना चाहूंगा कि मेरे क्षेत्र में ट्रांसपोर्ट लाइन का बहुत बड़ा काम है। सरकार में पहले भी प्रयास हुए हैं। मेरे क्षेत्र में ट्रांसपोर्ट नगर का अगर निर्माण कार्य कहीं हो तो सरकार से हम मांग करते हैं कि ट्रांसपोर्ट नगर के निर्माण कार्य के लिये शीघ्रातिशीघ्र कोई न कोई आदेश जारी करके वहां के ट्रांसपोर्ट व्यवसायियों को लाभ देने का काम करेंगे, तब जाकर इसका लाभ मिल पाएगा।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

एक मिनट और लूंगा मैं। मेरे यहां स्वास्थ्य सेवाओं के लिये भी बोल दिया मैंने। सबसे बड़ी जो समस्या है, वह आज पानी की है। उस पानी की समस्या के संबंध में सरकार से निवेदन किया है, उसका शीघ्रातिशीघ्र समाधान करेंगे। आपने बोलने का मौका दिया, उसके लिये मैं आपका तहेदिल से धन्यवाद करता हूं। जय हिन्द। जय भारत।

श्री अध्यक्ष: श्री अमीन कागजी।

श्री अमीन कागजी (किशनपोल): आदरणीय अध्यक्ष महोदयजी, इससे पहले कि मैं अपने सम्बोधन की शुरूआत करूं, मैं अपने सदन के नेता और कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष, आदरणीय राहुल गांधीजी को और अशोक गहलोतजी को बधाई देता हूं कि मुझे आज इस मंच पर इस भारत मां के संविधान के मंदिर में बोलने का मौका दिया। साथ ही नमन करता हूं देश के निर्माताओं को, जिनकी आहुती की वजह से आज हम सभी लोकतंत्र के इस पावन मंदिर में बैठे हैं। जहां से न जाने कितने जननायकों ने प्रदेश की जनता के लिये उनकी आवाज बनकर आमजन में देश के संविधान के प्रति विश्वास और लोकतंत्र की शान बढ़ायी।

मेरे वालिद महरूम सलीम कागजी साहब अक्सर कहा करते थे कि इंसान वही, जो इंसान के लिये जिये। आज वह इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमारी कांग्रेस पार्टी इंसानों को बिना धर्म, जाति में बांटे अपने मूल सिद्धांत लोक हित के कर्तव्य-पथ पर एक बार फिर से अग्रसर होने जा रही है, जिसके लिये प्रदेश की जनता का कोटि-कोटि आभार व्यक्त करता हूं।

माननीय अध्यक्षजी, निर्विघ्न रूप से सर्वसम्मति से आपको विधान सभा अध्यक्ष के रूप में जो नई जिम्मेदारी मिली है, मैं उसके लिये भी आपको तहेदिल से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। कांग्रेस में रहकर मैंने आपकी कार्यशैली

(श्री अमीन कागजी)

को भली प्रकार से देखा है। आप बेबाक व्यक्तित्व के धनी हैं, ऐसे में आपकी अगुवाई में नवनिर्वाचित जन-प्रतिनिधियों को अपने क्षेत्र की जनता से जुड़ी समस्याओं को, हर पक्ष को रखने का बराबर मौका मिलेगा, ऐसा मेरा विश्वास है।

आदरणीय अध्यक्षजी, मैं भूतकाल पर ज्यादा बोलना नहीं चाहता, क्योंकि सदन में बैठे सभी साथी जानते हैं कि भूत बड़ा डरावना होता है। फिर भी भूतकाल में कार्य प्रणाली में कमियों का जो पिटारा हमारे सामने छोड़कर गया है, उसे हम छोड़ने वाले नहीं हैं। उसका हम सटीक एवं गहन प्रसंज्ञान लेंगे, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियों के भविष्य के लिये हमारी सरकार एक स्वस्थ वातावरण का निर्माण कर सके।

माननीय अध्यक्षजी, प्रदेश की जनता इस समय सदन की ओर एक उम्मीद से देख रही है, क्योंकि जिस प्रकार से विगत कुछ वर्षों में राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के चलते जनता को जाति, धर्म एवं विभिन्न प्रकार के विषयों में उलझाकर उनकी मूलभूत सुविधाओं से उन्हें दरकिनार कर दिया गया। यह विडम्बना नहीं तो क्या है कि आज के इस युग में भी सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा और सुरक्षा जैसे जरूरी मुद्दों से हटकर आमजन को बंटवारे की राजनीति में उलझाकर रख दिया गया, उनकी आवाज दबा दी गयी। मैं विश्वास दिलाता हूं कि अब जनता की सरकार आ गयी है और अब उन्हें खुलकर अपनी बात रखने का मौका दिया जाएगा।

माननीय अध्यक्षजी, हम केवल-केवल अपने घर को पूरे जीवन के लिये बड़ा करने और चमकाने में विश्वास नहीं रखते, बल्कि ग्रामीण आवास जैसी महत्वपूर्ण योजनाओं से प्रदेश के जरूरतमंद लोगों को आवास उपलब्ध कराना हमने सुनिश्चित किया है। इतना ही नहीं अध्यक्षजी, मैं इस सदन में कहना चाहता हूं कि पिछली भाजपा सरकार ने अपने सुराज संकल्प-पत्र में किसानों के नाम केवल तीन पेज लिख डाले थे, जबकि सलिखित के तीसरे बिन्दु में कृषक सुरक्षा अधिनियम की बात कही, मगर कैसा अधिनियम और कैसा सुराज, जिसमें मेरे प्रदेश के किसान भाइयों को आत्महत्या करने के लिये मजबूर होना पड़ा और रातों गड्ढो में खड़ा रहना पड़ा और सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। मैं आभार व्यक्त करता हूं हमारे प्रदेश के जननायक आदरणीय मुख्य मंत्रीजी श्री अशोक गहलोत जी का और दूरगामी सोच के धनी युवा उप मुख्य मंत्री श्री सचिन पायलटजी का, जिन्होंने जिम्मेदारी संभालते ही

(श्री अमीन कागजी)

हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय राहुल गांधीजी की सोच को अमलीजामा पहनाते हुए किसान को सर्वप्रथम राहत देने की सोची। ऐसे किसान हितैषी फैसलों के लिये मैं पुन: मुख्य मंत्रीजी और उप मुख्य मंत्रीजी का हार्दिक अभिनन्दन और स्वागत करता हूं।

आदरणीय अध्यक्षजी, धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक सद्भाव और सहनशीलता वैसे पूरे विश्व की तुलना में भारत के डी.एन.ए. में ज्यादा है एवं भारत में अल्पसंख्यकों के संवैधानिक, सामाजिक और धार्मिक अधिकार अधिक सुरक्षित हैं। लेकिन, अध्यक्ष महोदयजी, याद दिलाना चाहता हूं कि पिछले कुछ वर्षों से राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के चलते अल्पसंख्यक वर्ग की उपेक्षा की शुरुआत की गयी है। बीजेपी के घोषणा पत्र में इसकी छाप साफ तौर से दिखाई दी। बड़े शर्म की बात है संकल्प पत्र में पहली बार अल्पसंख्यकों की भलाई के लिये कोई भी एजेंडा नहीं रखा गया था, जबकि 2013 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के घोषणा-पत्र में जो पन्ना अल्पसंख्यक समुदाय को समर्पित था, वह पन्ना 2018 के संकल्प पत्र में पूरी तरह से गायब मिला। वही हमारी सरकार के आने के बाद मुख्य मंत्री आदरणीय अशोक गहलोत जी एवं उप मुख्य मंत्रीजी सचिन पायलट जी से उम्मीद करता हूं कि परम्परागत लघु उद्योगों के लिये अब अल्पसंख्यकों को लोन दिया जाना आसान हो सकेगा।

वक्त सम्पत्तियों का राजस्व रिकार्ड स्थापित किया जा सकेगा। वक्त सम्पत्तियों पर से अतिक्रमण हटाये जाएंगे। मदरसों का आधुनिकीकरण सम्भव होगा। ऐसे तमाम महत्वपूर्ण मुद्दों पर ध्यान रखा जाएगा जिस पर पूर्व सरकार ने अपने संकल्प-पत्र में होने के बावजूद पूरी तरह से कन्नी काटी।

अध्यक्ष महोदय, मैं सदन में बताना चाहता हूं कि जिस किशनपोल की जनता ने मुझे चुनकर भेजा है, वह किशनपोल क्षेत्र केवल चार-दीवारी नहीं, इस प्रदेश की राजधानी जयपुर का दिल है, उसकी धड़कन है, जो पिछले कई वर्षों से ढुलमुल रवैये और लचर कार्य-प्रणाली और कमजोर नेतृत्व की भेंट चढ़कर अस्त-व्यस्त पड़ा है।

स्मार्ट सिटी के नाम पर, जो लोग राम मन्दिर की बातें करने वाले थे, वह अपने डिस्कशन में सैकड़ों मन्दिर लोगों की भावनाओं को तोड़ते हुए राम मन्दिर की जगह राज मन्दिर पहुंच गए। मुझे खेद है कि जिस तरीके से पिछली सरकार ने शहर में मन्दिरों को तोड़ा, वह एक निन्दनीय कदम है।

(श्री अमीन कागजी)

ऐसा जो पार्टी जनहित की भावनाओं को ध्यान में रखकर बात करती है, मैं सदन में कहना चाहता हूं कि उनके विधायक मैट्रो अधिकारियों को यह लिख कर देते हैं कि ये मन्दिर हटा दिए जाएं। ऐसी ये बातें करते हैं, वह कहीं दिखाई नहीं देता। मैं बधाई देना चाहूंगा माननीय मुख्य मंत्रीजी को, जिन्होंने हमारे यूडीएच मिनिस्टर आदरणीय शान्ती धारीवालजी से सत्ता में आने के तुरन्त एक हफ्ते के अन्दर-अन्दर मैट्रो का निरीक्षण करने के लिए भेजा। जहां तक मैट्रो प्रोजेक्ट का सवाल है, तत्कालीन गहलोत साहब की सरकार ने, जिसे फेस-वन-ए कहा 9.6 किलोमीटर का जो मैट्रो प्रोजेक्ट था, वह चार साल और तीन महीने में पूरा हुआ और वहीं 21 सितम्बर, 2013 को तत्कालीन प्रधान मंत्रीजी आदरणीय मनमोहन सिंहजी के द्वारा फेस वन-बी का फाउण्डेशन स्टोन रखा गया आदरणीय अशोक गहलोतजी के नेतृत्व में, लेकिन आज भी उसका 25 परसेंट काम बाकी है जिसका यूडीएच मिनिस्टरजी ने वहां के व्यापारियों और लोगों के साथ जिनके चार साल बड़े संकट से निकले। मैं बधाई देता हूं कि जिन्होंने तुरन्त अधिकारियों को निर्देश दिए कि वहां की जो समस्या है, उसको अगस्त तक दूर किया जाए।

अध्यक्ष महोदय, प्रदेश की राजधानी होने के बावजूद मेरे क्षेत्र में पार्किंग प्रणाली, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, सुरक्षा व्यवस्था, शैक्षणिक और चिकित्सा संस्थानों में हो रही अनियमितताओं की ओर कभी ध्यान नहीं दिया गया। कोई ठोस प्लान बनाकर शहर को सुव्यवस्थित करने की नहीं ठानी गई।

अध्यक्षजी, रुका पड़ा मैट्रो कार्य और धूमिल पड़ी स्मार्ट सिटी हमें सौगात में मिली है। सदन में तीन दिन से बात हो रही है कि पानी का बहुत संकट है। पेयजल की समस्या सामने दिख रही है। आदरणीय जल संसाधन मंत्री बी डी कल्ला साहब से मिलकर मैंने निवेदन किया कि जो रामगढ़ बांध सरकार की प्रोपर्टी है, उसके अन्दर ट्यूबवैल बनाकर शहर में सप्लाई के लिए कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए जाएं। ऐसा मैं मानता हूं। सरकार मेरी रिक्वेस्ट पर ध्यान देगी और उन्होंने मुझे विश्वास दिलाया है कि यह कदम सराहनीय है।

आपने मुझे बोलने का मौका दिया। अधिक समय नहीं लेते हुए कहना चाहूंगा कि आप सभी ने नया विधायक होने के बावजूद मेरे वक्तव्य को इतना ध्यान से सुना। इसके लिए मैं कांग्रेस पार्टी और सदन का तहेदिल से शुक्रिया अदा करता हूं। बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द, जय कांग्रेस।

श्री अध्यक्ष: श्री रूपा राम।

श्री रूपा राम (मकराना): माननीय अध्यक्ष महोदय, वैसे तो मैं एक बार निर्दलीय जीत गया। आते-आते बीस साल बीत गया। व्यवधान) गीत शायद यहां अलाउ नहीं है।

संख्या के आधार पर लोकतंत्र जिन्दा है।

संख्या की कमी को देखकर रूपा शर्मिन्दा है।

भारत मां के सच्चे लाल, लेकिन पांचवें दिन सदन का यह हाल,

वैसे सारे दो सौ भारत मां के हैं सदन लाल।

अध्यक्ष महोदय, मैं बिन्दुवार नहीं बोलकर सारगर्भित बात बोलने की कोशिश करूंगा क्योंकि जब बोलते-बोलते वक्त थोड़ा देर से मिलता है तो जिस बिन्दु पर हम तैयारी करते हैं, हमारे कुछ माननीय सदस्य बोल देते हैं और मैं इस बात को लेकर चिन्तित रहता हूं कि कही हुई बात को दोबारा कहें तो शायद हम सदन का समय जाया करते हैं।

मैं थोड़ी-सी भूमिका बनाऊंगा।

What is our life? What is the aim of our life? Don't worry, I am not a graduate but when I am going to speak, nobody believes about my education. I am only double E. Once I asked a gentleman, Sir, what is your qualification, and then he told me that I am a double M.A. and after sometime he asked me, Sir, what is your qualification? Then, I replied him back, don't worry, you are a double M.A, and I am a double E. He asked me, what is the definition of double E? I replied, Sir, I didn't pass Eleventh, in one time, so I tried second time, आप डबल एम ए हैं, मैं डबल ई हूं। There is not much difference.

जीवन क्या है? (व्यवधान) अभी तो शुरू हुआ हूं। जीवन की मान्यताएं क्या हैं? जीवन जीने का आधार क्या है? राम और राज। एक मनुष्य का जीवन राम और राज के आधार पर चलता है। कभी किसी का अगर राम रूठ जाता है तो राज से आशाएं रखी जाती हैं। मैं कोशिश करूंगा। मैं एक अनुशासित विधायक हूं। पांच दिन में पहले कभी नहीं बोला हूं। बीच में ही उठने वाले हमारा समय खराब कर देते हैं। या तो इनको पाबन्द करो या हमको ही बीच में बोलने के लिए रजामन्द करो। यहां पर जो अनुशासित हैं सच्चे और अच्छे, उनका हक मारा जाता है। जीवन में पुलिस ने मेरा कभी

(श्री रूपाराम)

चालान नहीं किया। बैल्ट रखता हूं, हैलमेट रखता हूं। हम जिम्मेदार हैं। हमारी जिम्मेदारी का लोगों को इसी से पता लगता है। चाहे शहर हो, चाहे गांव हो, चाहे सड़कें हों। हमें जिम्मेदार रहना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, मैं जीवन के आधार पर राम और राज को मानता हूं। राम किसी का रूठ जाता है, राम के किए गए कार्य को हम मनुष्य प्रभावित नहीं कर पाते हैं, राम के दिए गए परिणाम को भी हमें भुगतना पड़ता है लेकिन लोकतंत्र में कितनी महान व्यवस्था है मनुष्य के लिए। अगर राज हमारे अनुकूल नहीं है, राज जनहित के अनुकूल नहीं है तो हम हमारे मत द्वारा, वोट द्वारा हमारे राज को बदल देते हैं। इसलिए लोकतंत्र महान है। जीवन की सार्थकता के बारे में मैंने लिखा है, शास्त्रों में दर्शाया गया है, धर्मों में दर्शाया गया है कि जीवन सफल हो, सार्थक हो, स्वर्ग हो।

अभी माननीय मुख्य मंत्रीजी नहीं हैं। एक बार मैं 1994 में यूनिवर्सिटी में कह रहा था तो किसी बच्चे ने कहा कि नेता चोर होते हैं तो मैंने कहा कि:-

इस तरह के झूठे शोर होते हैं,
मेरे गढ़ की मैं जानूं या फिर मेरा रब जाने
हमको चोर कहने वाले,
खुद पागल, तू मेरे मन की कब जाने

मैं यह बात कह रहा हूं कि मैंने सोचा कि जीवन सार्थक कैसे करें। हम जाएं यहां से तो स्वर्ग में कैसे जाएं। स्वर्ग हमारे शास्त्रों और धर्मों में दर्शाया गया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने बहुत चिन्तन किया। साधु-सन्त, ऋषि-मुनि, ज्ञानी-ध्यानी, तपस्वी-योगी और धनवान भी एक अच्छे और सच्चे राजनीतिज्ञ के सामने बहुत छोटे कद के लगते हैं। एक सच्चा और अच्छा जन प्रतिनिधि भगवान और देवताओं से बड़ा होता है। एक सच्चे और अच्छे मुख्य मंत्रीजी की वजह से सात करोड़ लोगों का भला होता है। सात करोड़ लोगों के हित की योजना बनाई जाती है। मैं पैसे वाला हूं। किसी को दो रुपये सैकड़े में दे दूंगा, किसी को ज्ञान दे दूंगा, किसी को भाषण दे दूंगा। वैसे तो हम माननीय विधायकों ने दिया ही दिया है, लिया क्या है। आश्वासन दिया है, विश्वास दिया है। किसी ने कभी-कभी झांसा दिया है, किसी-किसी ने धोखा दिया है, हमने तो दिया ही दिया है, लिया क्या है जनता से।

(श्री रूपाराम)

तो मैं जो कह रहा हूं अगर स्वर्ग में जाना है, जीवन को सफल बनाना है, मैं तो सच कह रहा हूं। मैं जो कहूंगा सच कहूंगा, क्योंकि मैंने प्रतिज्ञा ली है, मैंने शपथ ली है। आप राजनीति के माध्यम से इस दुनिया में अच्छे कर्म करके स्वर्ग में जा सकते हैं। राजनीति एक साधना है। लोकतंत्र के माध्यम से राजनीति साधना है, आराधना है, तपस्या है, स्वर्ग का मार्ग यही है। विधान सभा की कार्यवाही देखने के बाद में मैं आज पांचवे दिन बोल रहा हूं, लाया तो बहुत था लेकिन थोड़ा मुंह खोल रहा हूं। क्योंकि यह भी है मैं अनुशासित हूं। आप यह कहोगे न, बैठ जा, उससे पहले बैठ जाऊंगा। मैं तो कहूं, आप तो खैंखारा करो जद तंई बैठ जाऊं मैं तो, कै समझ ग्यो, कोई इसारो न आग्यो है। तो अगर किसी को खांसी हो तो कृपया शांत रहें।

मैंने यहां की कार्यवाही देखी है, एक-दूसरे पर दोषारोपण। प्रजातंत्र या लोकतंत्र में बहुत बड़ी है वो यह है, माननीय अध्यक्ष महोदय, कि हमने, पार्टियों ने तय कर लिया कि चाहे कांग्रेस हो, चाहे बी.जे.पी. हो, अगर कोई अच्छा कार्य करेगा तो भी हम उसके पक्ष में नहीं बोलेंगे। यह प्रजातंत्र में जनहित में नहीं है। क्या कभी आप लोगों ने या कांग्रेस ने अच्छे काम नहीं किये? क्या बी.जे.पी. ने नहीं किये? कभी नहीं निकलता। इसका अर्थ यही है एक-दूसरे पर दोष देते हैं। जो आपने किया वो ही हमने किया, जो हमने किया वो ही आपने किया। जब भी मिला मौका खूब खाया, खूब पीया, जो आपने किया वो ही हमने किया। जब खुद को बेगुनाह साबित करने का आया मौका, पूरा दोष एक-दूसरे पर मढ़ दिया, जो आपने किया वो हमने किया। कभी खाने के लिए हमने दांत घिस लिये, कभी खाने के लिए आपने दांत घिस लिये, इस दांतों की एक्सरसाइज में हमारे दांत तो मजबूत हो गये, लेकिन गरीब नागरिक और भी गरीबी से पिस लिये। यह जीवन का सार आ रहा है।

जीवन मिले न मिले, मैं तो यहां तक कहता हूं हम सबको:-

'हम रहें न रहें खुशबू हमारी रहा करेगी,
लोग कहें न कहें, ये जमीं तो कुछ कहा करेगी,
जमीं बोलती है आदमी के जाने के बाद,
आदमी तो सिर्फ बोलता है आदमी के आने के बाद,
बहार भी आयेगी पतझड़ के जाने के बाद,
कभी हम भी याद आयेंगे जमाने से जाने के बाद,
कभी हम भी याद आयेंगे जमाने से जाने के बाद।'

(श्री रूपाराम)

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सारांश ही बोल देता हूं, सार ही बोल देता हूं। मैंने कुछ लिखा है:-

'ए देश के नेताओं, मत लूटो मेरे देश को,
मत बदनाम करो खादी के भेष को,
ए देश के नेताओं, बेवजह किसी को शहीद मत होने दो,
मेरी हंसती-खेलती बहन-बेटियों को मत रोने दो।'
'मैंने देखा है शहीदों के कफन के सौदागरों को,
मैंने देखा है जिंदी लाशों के मुर्दाघरों को'

प्रदूषण पर:-

'अब तो दिन भी धुएं से सटे पड़े हैं बड़े शहर,
हर खाने-पीने की चीज में मिल रहा है जहर,
आदमी आदमी की जिंदगी का सौदा करने लगा है,
जिस दवाई से बचना है उसी से तो मरने लगा है,
जिस दवाई से बचना है उसी से तो मरने लगा है।

चौमूं से आने वाले मेरे भाई ने बहुत बड़ा प्रश्न उठाया। माननीय अध्यक्ष महोदय, चाहे गरीब हो, चाहे पैसे वाला हो, आप एक भी ऐसा खाद्य और पेय पदार्थ बता दीजिए जिसमें मिलावट नहीं हो। इसके जिम्मेदार हैं कौन? हम ही हैं। आने वाला वक्त, जैसे कैंसर से ट्रेनें भर-भरकर आ रही हैं, डाक्टर कहता है फल-फ्रूट खाओ, सलाद खाओ, अगर कोई नहीं मरने वाला है तो ही पांच दिन में मर जाएगा, पीलिया हो जाएगा। हर चीज में जहर दिया हुआ है। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि हम लोग लालच में उलझे हुए हैं, हम दूसरे की जिंदगी की परवाह नहीं कर रहे हैं।

मैंने दो लाइनें यह भी लिखी हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, सरपंच, एम.एल.ए. और मंत्री, इनकी प्रजातंत्र में जरूरत क्या है जब सरकार के पैसे हैं, हमारी योजना के पैसे हैं, ठेकेदार और अफसर मिलकर लगा लेंगे। तो मैंने भी इसमें हमारी चर्चाएं की हैं कि हम उसकी रोकथाम करें, पारदर्शिता दिखाएं या हिस्सा डाल लेवें।

'मकसदे जिंदगी क्या है, जरा गौर फर्माइये,
मिले फुर्सत के दो पल तो खुद को खुद ही समझाइये,

(श्री रूपाराम)

बनाया मालिक ने इन्सान तो इन्सान तो रह जाइये,
हुकूमत करो लोगों अपने हक पर, पर हराम की तो मत खाइये,
बनाया मालिक ने इन्सान तो इन्सान तो रह जाइये।'

मुझे खुशी हुई हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्रीजी ने कहा भ्रष्टाचार पर जीरो टोलरेंस। वैसे तो इस पुस्तक में सारी समस्या का समाधान आ गया। सुप्रीम कोर्ट की कई बार दलील आयी, हाई कोर्ट की आयी कि हिन्दुस्तान में सबसे बड़ी समस्या की जड़ है भ्रष्टाचार और इसमें आपने भ्रष्टाचार के बारे में जीरो टोलरेंस लिखा है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे समझने में आई नहीं, मैंने दो बार पढ़ा, रात को दो बार उठकर पढ़ा। मैंने कहा, टोलरेंस, भ्रष्टाचार करने के लिए है या नहीं करने के लिए, यह मेरे समझ में नहीं आया। आप एक भी ऐसा विभाग बता दीजिए जो सरकारी विभाग है, सरकारी उपक्रम चल रहा है और उसमें भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है। मुझे दु:ख है कि यह हम देखते हुए अंधे हैं। हम कौन जगायेगा? जो जाग रहे हैं वो अंधे हैं। मैं यह कह रहा हूं, मेरा बहुत बड़ा सुझाव है, हम लोग राजस्थान को 100 साल तक आगे विकास की ओर ले जा सकते हैं सिर्फ 200 लोग। भ्रष्टाचार की जिम्मेदारी किसकी है? जब सीढ़ियों से झाड़ू लगाते हैं तो ऊपर से लगाते हैं। आज हम 200 विधायक प्रण कर लेवें कि हम न खायेंगे न खाने देंगे, इसके लिए माननीय सदस्यों, मैं एक सुझाव भी देता हूं। जब कोई भ्रष्टाचार पर चर्चा हो या जांच हो, जैसे खींवसर से आने वाले माननीय एम.एल.ए. ने कहा कि उसकी जांच तीन-चार बार हो गयी, तो भ्रष्ट की जांच भ्रष्ट से कराओगे नतीजा यही आएगा। नई टैक्नोलोजी है, नया जमाना है, भ्रष्टाचार, चाहे आरोप नेता पर लगे चाहे किसी अधिकारी पर लगे, उसकी टैक्नोलोजी के हिसाब से लाई डिटेक्ट कीजिए न, नारको टैस्ट कीजिए और अगर इसकी जरूरत पड़े तो सबसे पहले मेरा कर लीजिए। ईमानदारी में तो कोई ज्यादा आने वाला नहीं है, कोई छोटी-मोटी दूसरी घटनाएं आ सकती हैं, तो मेरा यही सुझाव है।

अब मैं संक्षेप में इतना ही बोलूंगा। ऐतिहासिक धरोहर, स्मारकों का रख-रखाव। माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में अलग-अलग क्षेत्रों में अलग-अलग महापुरुष हुए हैं, लोक देवता हुए हैं, उनकी गाथाएं गायी हुई हैं, उनके गुणों पर भी हमने दर्शाए हैं जो हमारे विचार हैं। इस पर मैं एक कहना

(श्री रूपाराम)

चाहूंगा। जैसे ऐतिहासिक स्मारक हैं, किले हैं, इसके साथ-साथ मेरा सुझाव है कि हमारी संस्कृति और सभ्यता को जिंदा रखने के लिए हमको राजस्थान के जयपुर में बहुत बड़ा संग्रहालय बनाना चाहिए। हमारी वेशभूषा जैसे बखतरी, कुर्ता, साफा, धोती, पाजामा, इन चीजों का हो, आने वाले बच्चे नहीं समझते। आज बखतरी में इधर बटन जड़ा जाता है। वो नहीं समझ पायेंगे। ठीक इसी तरह हमारी खेती के काम आने वाले हल हैं, हळ वाणी। ठीक इसी तरह लोक देवताओं के गाये हुए, जैसे भक्त शिरोमणि मीरा जी, करमा बाई, राना बाई।

'ए रे मैं तो दर्द दीवानी, मेरो दर्द न जाने कोई,
ए रे मैं तो दर्द दीवानी, मेरो दर्द न जाने कोई,'

भक्त शिरोमणि मीरा को दुनिया में जानते हैं। करमा बाई हुई, उसने अपने विश्वास से आत्मा से ईश्वर को खीचड़ा खिलवाया। आज जगन्नाथपुरी में खीचड़ा का भोग लगाया जाता है। करमा हमारे मकाराना की थी कालवा की, वो गायो न :-

'करमा बेटी जाट की, बा ल्यावे गरबी, बा ल्यावे बरतू बाट की,
तू जीम जीम नन्द लाल, खालै खीचड़लो,'

ठीक इसी तरह और भी, गोगा जी, पाबू जी देवता, यह हमारी फडे हैं रामदेव जी की देवता की। दूसरा, हमारे नागौर में एक देवता हैं तेजा जी, धूम मचाते हैं। आपको उस पर भी रिसर्च करना चाहिए। क्या गाया है, कैसे गाया है, कितनी ताकत से, अगर बुरा न मानें तो एक लाइन सुना दूं?

'हे अरे नागौरी तू सूरावो, धरती रा अवतारी वो,
सतवंती तू राजावो, अरे लीलण रा असवारी हो,
हे, हे, हे, रे, हे,

इसमें कोई समझता भी नहीं है, मैं भी एक ही लाइन जानता हूं, पूरी रात लोग गाते रहते हैं।

लेकिन मैं यह आत्मा से, दिल से कह रहा हूं। आपसे मेरा निवेदन है, सुझाव है, यह सारे लोक गीतों पर करें। सारे राजस्थान में अलग-अलग क्षेत्रों में लोक देवता हुए हैं। महान पुरुष हुए हैं, गोगा जी, रामदेव जी, इनके गीतों का एक बड़ा संग्रहालय हो।

हमारे दैनिक जीवन में काम आने वाली वस्तुएं जैसे कुड़छी है, छिपियो है, बांटकी है, चूल्हो है, यह धीरे-धीरे खतम हो जाएगी। यह कम से

(श्री रूपाराम)

कम एक हजार नाम हैं। मैं इसमें पीएचडी करने की सोच रहा हूं। यह सच्चाई है। मैं इसी आशा के साथ में आपसे पुरजोर निवेदन कर रहा हूं कि आपकी सारी स्थिति इसमें है।

अध्यक्ष महोदय, एक बात बताऊं, टोलरेंस, भ्रष्टाचार पर अगर विचार हो जाएगा तो फिर राजस्थान में समस्या ही खतम हो जाएगी। लोग कहते हैं कि हमने इतना खर्च कर दिया। हमने इतना बजट दिया। यह नहीं कहते कि हमने खा कितना लिया। एक हमारे पहले वाले मंत्रीजी कह रहे थे कि हमने स्कूल बनाए, सड़क बनाई, अस्पताल बनाए। मैंने कहा हो सकता है। इस जनता को देखो, इसने कई ऐसे सड़क छाप को एमएलए, मंत्री बना दिया और वह कह रहे हैं कि हमने सड़क बनाई। पैसे आपके थे? लाए कितने?

अध्यक्ष महोदय, मैं तो यह कह रहा हूं कि यह जीवन दुबारा नहीं आएगा। इसी जीवन में जो कुछ करना है, कर लो। हो सकता है कि मेरी बातें सुनकर कुछ मुझे पागल घोषित कर दें। जिनकी जमाने में आत्मीयता ईश्वर से रही है, वह पागलों जैसी ही हरकतें करते हैं। कुल मिलाकर मुझे भी जमाने में सब पागल नजर आते हैं। कोई लूटकर पागल, कोई लुटाकर, कोई पीटकर, कोई पिटाकर, कोई खा कर, कोई खिला कर, कोई हंस कर, कोई हंसा कर, कोई रो कर, कोई रूला कर, सब जमाने में पागल हैं। अगर आपने यहां लूट लिया तो आगे लुटने वाले हैं। यहां लुट गए तो आगे फिर वापस लूट लोगे। ईश्वर पर या तो पूर्ण विश्वास हटा लें हम, या आस्तिक बनकर के जीएं। Now Sir, I am 65 years old, I am a regular Football player. Nobody believes about my games when I am going to play football in my ground. जातिवाद की बात करते हो? मेरी फुटबाल टीम मैं 45 साल से चला रहा हूं। मुझे और मेरे भाई को छोड़कर सारे अल्पसंख्यक हैं। मेरी बेटी का नाम बिसमिल्लाह है। सबसे नजदीक दोस्त मेरा मुसलमान है। मैं फिर भी कह रहा हूं, ऐ देश के नेताओं, मातृभूमि का ध्यान रखो। यह देश उसी का है जो मातृभूमि को प्यार करता है।

अध्यक्ष महोदय, मैं किसानों के बारे में 2 मिनट बोल लूं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। किसानों की समस्याओं का समाधान तभी हो सकता है जब 200-300 बीघा जमीन लेकर 5 आदमियों की कमेटी गठित हो जाती है। मैं तो किसान हूं, मुझे 5 पैसे मिले हुए हैं। मैं गाड़ी ढंग की लाता हूं, तो वह तुलना करते हैं कि रूप जी किसान हैं और मैं किसान कहां से हूं। मैं तो पत्थर का व्यापार करता हूं। किसानों के लिए मैं आत्मा से कह रहा हूं कि इस देश का किसान जब टूट जाएगा तो ईश्वर हमसे रूठ जाएगा।

(श्री रूपाराम)

अध्यक्ष महोदय, मैं बिजली के बारे में इतना ही कहता हूं कि जब किसान फसल पैदा करता है और बिजली के तार को जोड़कर, बिना कनेक्शन मोटर चलाकर अपने बच्चों को पालता है, इस देश को पालता है, तो उसको चोर मत कहिए। झूठ, कपट, बेईमानी, मान-सम्मान, अय्याशी के लिए अरबों कमाने वाले लोग झूठे हो सकते हैं। वह बेइमान हो सकते हैं। हमारे मेडिकल में एक प्रावधान है, आपको पता है मंत्रीजी, मेडिकल वाला, जब आदमी ज्यादा बीमार हो जाता है तो उसको आक्सीजन दे दी जाती है, उसको वेंटिलेटर पर लिटा दिया जाता है। किसान अपने बच्चों को जिंदा रखने के लिए अगर तार जोड़कर बिजली ले लेता है तो वह चोर नहीं हो सकता। वह तो जब आदमी के अधिकारों का हनन होता है तो मनुष्य खुद अपराध की तरफ चला जाता है।

अध्यक्ष महोदय, मेरे और भी पाइंट आगे हैं, जैसे खेलकूद के बारे में हैं, कई समस्याएं हैं, रख-रखाव के बारे में हैं। भजनों के बारे में हैं। मैं आपसे आशा रखता हूं, अभी शुरूआत हुई है। मेरा हौसला बढ़ाते रहना। मैं यह तो साफ-साफ कहूंगा कि आप में और हम में फर्क कहां है। कल आप यहां बैठे थे। हम जिस चीज के लिए जोर मारकर चिल्ला रहे थे, आज आप उसी के लिए कह रहे हैं। कल आप जिस चीज के लिए कह रहे थे कि यह करो, वह करो, वही आज हम कह रहे हैं। कहीं हमारी यह विधान सभा नूरा कुश्ती की कार्यवाही ना साबित हो जाए। मैच फिक्सिंग ना साबित हो जाए।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

अध्यक्ष महोदय, यह सदन राजस्थान की जनता का सबसे बड़ा न्यायालय है। यहां राजस्थान के सभी लोगों का भविष्य तय होता है। इसी आशा के साथ में धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री खुशवीर सिंह।

श्री खुशवीरसिंह (मारवाड़ जंक्शन): अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद। मैं महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण का स्वागत करता हूं। इसमें जो बातें कहीं गई हैं वह एक से बढ़कर एक हैं। लेकिन उसमें मैं कुछ सुझाव भी देना चाहूंगा।

अध्यक्ष महोदय, मैं कृषि से अपनी बात प्रारम्भ करता हूं। कृषि के लिए 2 लाख रुपए माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने माफ करने की बात कही

(श्री अध्यक्ष)

है। यह मुख्य मंत्रीजी का स्वागत योग्य कदम है। पिछली सरकार ने भी 8 हजार करोड़ रुपए माफ करने की बात कही और नहीं कर पाए। कोई बात नहीं। लेकिन हम कब तक और कहां तक वर्ष, प्रति वर्ष या चुनावों के वक्त 5 वर्ष में ऐसी घोषणाएं करते रहें और किसान को हमारे ऊपर आश्रित करते जाएं। साथ में उस किसान के ऊपर सदन में चर्चाएं होती हैं कि हम उनका ऋण माफ कर रहे हैं, उस अन्नदाता का ऋण माफ कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि कृषि को अगर उद्योग का दर्जा दे दिया जाए, आज एक उद्योग लगाने के लिए मुझे भूखण्ड सरकार उपलब्ध करवाती है। मुझे बैंक उस पर लोन देती है। सरकार उस पर अनुदान देती है। किसी कारण से अगर मैं उत्पादन नहीं कर पाता, या मैं उसमें कुछ गड़बड़ भी कर लूं अनुदान लेने के लिए, उसके बाद मैं ऋण नहीं जमा करा पाऊं, अनुदान का अनुचित लाभ उठा लूं तो भी सरकार उसे सिक यूनिट घोषित कर देती है। बैंक और सरकार कहती हैं कि आप वापिस आइए, आप बीमारु उद्योग की श्रेणी में आते हैं। पुन: इसको स्थापित करने के लिए हम आपको और पैसा, सहायता दे रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, दूसरी तरफ, किसान अपनी फसल का बीमा करवाता है। बैंक में लोन लेने जाता है तो बैंक वाले अपनी मनमर्जी से जिंस अंकित कर देते हैं।

माननीय मंत्री महोदय, मैं थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: मंत्री महोदय। माननीय मंत्री महोदय। माननीय संसदीय कार्य मंत्री महोदय।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): दुर्भाग्य है। दुर्भाग्य है यह।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य बोल रहे हैं, प्लीज। माननीय सदस्य बोल रहे हैं।

श्री खुशवीरसिंह (मारवाड़ जंक्शन): मैं भी किसी समय आपकी पार्टी का हिस्सा था, इसलिए मुझे भी बोलने का समय दें।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): आपके पास तो कोई बैठता नहीं है। मेरे पास तीन आदमी तो बैठे हैं।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री, प्लीज। बोलिए, बोलिए, माननीय सदस्य।

श्री खुशवीरसिंह (मारवाड़ जंक्शन): अध्यक्ष महोदय, बैंक वाले मनमर्जी से जिंस दर्ज कर लेते हैं और जब फसल खराब हो जाती है, नष्ट हो जाती है प्राकृतिक आपदा से तो बैंक वाले यह कहते हैं कि हमने जो जिंस दर्ज किया वह आपकी गिरदावरी रिपोर्ट में नहीं आ रहा है, इसलिए आपको इसका लाभ हम नहीं दे सकते। नुकसान की भरपाई हम नहीं कर सकते हैं। यह दुर्भाग्य है। जब हमारा पटवारी, सरकारी एजेंसी उसका भौतिक सत्यापन करके गिरदावरी करता है और उसके बाद में बैंक यह कह रहे हैं। पिछले 5 वर्षों में प्रीमियम 4 गुना बढ़ा दिया पिछली सरकार ने। केन्द्र सरकार ने प्रधान मंत्री बीमा योजना के नाम से, जबकि पहले कांग्रेस सरकार की चलाई हुई थी। इसमें मैं कहना चाहूंगा कि गिरदावरी को ही आधार माना जाए।

अध्यक्ष महोदय, दूसरा मेरा निवेदन है कि प्राकृतिक आपदा में कोई स्थान निर्धारित नहीं होता। प्राकृतिक आपदा कहां होगी, कहां नहीं होगी, यह पता नहीं होता। लेकिन हमने हमारी सुविधा के हिसाब से एक तहसील को यूनिट मान लिया। पाला गिरेगा, अनावृष्टि, ओलावृष्टि, अतिवृष्टि जो भी प्राकृतिक आपदा आ गई तो बैंक और बीमा कंपनियां हमें यह कहती हैं कि पूरी तहसील को यूनिट माना है, इसलिए आपको हम नहीं मानते हैं।

ऐसी स्थिति में किसान अपने सर्वे नम्बर के आधार पर प्रीमियम जमा करवाता है। जिस तरह खसरा नम्बर के आधार पर प्रीमियम जमा होता है, जिस तरह हम हमारे वाहन का प्रीमियम इन्श्यारेंस के लिए जमा करवाते हैं, नम्बर के आधार पर और वाहन की दुर्भाग्य से अगर दुर्घटना हो जाती है तो बीमा कम्पनी यह नहीं कहती है कि पूरी तहसील को यूनिट माना, हमने इसलिए पूरी तहसील की यदि दुर्घटनाएं होंगी तो हम शामिल करेंगे। यह दुर्भाग्य है तो हमारे खसरा नम्बर और सर्वे नम्बर के आधार पर प्रीमियम जमा होता है और भौतिक सत्यापन के बाद में गिरदावरी होती है तो मैं चाहता हूं कि पटवारी की रिपोर्ट को माना जाए और किसानों को यह लाभ दिया जाए।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं हमारे मुख्य मंत्री महोदय की सोच को सैल्यूट करता हूं। उन्होंने एक ऐसी बात कह दी, कभी उन्होंने धर्म की आड़ में राजनीति की नहीं और न ही धर्म की आड़ में उन्होंने कभी वोट मांगे लेकिन एक सोच है उनकी। देशी गौवंश को कैसे बचाया जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, गाय की बात तो हम सभी करते हैं, हमारे वोट लेने के लिए हम किस तरह, यह सभी को मालूम है लेकिन मेरा आपके माध्यम से सरकार को सुझाव है कि गाय की उपयोगिता अगर वास्तव में हम देखें तो समाप्त हो

(श्री खुशवीरसिंह)

चुकी है। जब से यह मशीनी युग आया है, पहले 60 के दशक में हमने उन्नत कृषि के नाम से कि उन्नत कृषि करेंगे और उसके नाम से हमारी जो स्थानीय और पश्चिमी राजस्थान की नस्ल थी, काकरेज, थारपारकर, वह दुधारू नस्ल भी थी और खेती के लिए भी मजबूत थी लेकिन उन्नत कृषि के नाम पर हमने नागौरी नस्ल नागौर से लेकर आए और वह जुताई के अंदर उनकी थोड़ी स्पीड इनसे अधिक थी तो हमारी यह नागौरी नस्ल पश्चिमी राजस्थान में फैल गई। माननीय अध्यक्ष महोदय, हुआ क्या कि धीरे-धीरे मशीनी युग आया, पम्प आ गए, पम्प सैट आ गए, ट्रैक्टर आ गए तो हमारे उन बैलों की उपयोगिता पूर्णत: समाप्त हो गई और ऐसे में हमारी गाय की नस्लें थीं वह क्रोस ब्रीड हो गई और उसकी वजह से हमारी जो मिल्किंग काउज थीं उनका दूध देना कम हो गया। हम बात तो करते हैं कि गाय पालेंगे, गाय के नाम पर राजनीति कर लेते हैं, वोट मांग लेते हैं, गले में वह डालकर घूम लेते हैं, कोई दुर्घटना हो जाती है तो झगड़ा कर लेते हैं, उनको पकड़कर मार देते हैं, पीट देते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, माब लिंचिंग भी हो रही है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं आपके माध्यम से सरकार को कि मात्र गौशाला स्थापित करके, मैं हिंगोनिया का उदाहरण यहां नहीं दूंगा, लेकिन मात्र गौशालाओं से हमारी गाय का उद्धार होने वाला नहीं है, इसके लिए हमें गाय को वाइबल यूनिट बनाना होगा और इसके लिए आज हमें सोचना होगा क्योंकि अब कृषि में हमारे बैलों की आवश्यकता नहीं है। मैं चाहूंगा उस गाय को जिसको हम गौ माता कह रहे हैं वह आज हमारी गलियों में घूम रही है और दुर्घटना का सबब बन चुकी है और नेशनल हाईवेज पर मानसून में सबसे अधिक सड़कों के ऊपर मच्छरों से बचने के लिए गाय रहती है और उस समय अधिक दुर्घटनाएं होती हैं। मैं पिछले पांच वर्षों से प्रति मानसून में हजार से पन्द्रह सौ किलोमीटर तक रात को यात्रा करता हूं मेरी टीम के साथ में और मैं गायों के जहां पर भी झुण्ड देखता हूं सड़क पर बैठी हुई, मैं जाकर रेडियम की चिप्स लगाता हूं उनके सींगों पर ताकि दूर से गाड़ी को नजर आ सके कि वह गाय वहां पर बैठी है। खाली गाय रात को नजर नहीं आती है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा इसमें सरकार को सुझाव है कि अब गौशाला के स्थान पर गौ संवर्द्धन शाला बनाने की आवश्यकता है। हमारे गिर के अंदर देशी नस्ल है और वह ब्राजील, साउथ अमेरिका जा रही हैं। मैं चाहूंगा

(श्री खुशवीरसिंह)

कि वहां पर 45 लीटर अगर दूध दे सकती है तो क्यों नहीं हमारी गौशालाओं के माध्यम से प्रत्येक जिले में एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर एक-एक माडल के तौर पर एक-एक गौशाला या जो लगाना चाहे उसको सरकार सहायता प्रदान करे और नंदी शाला अलग हो और उन गौशाला में वहां के सांड लाकर उस नस्ल को इंट्रोड्यूस किया जाए।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी गौमाता सिर्फ कहने को रह गई है। हम कोई भी भैंस माता नहीं कहते हैं बावजूद इसके एक भी भैंस हमारे यहां आवारा घूमती नजर नहीं आ रही है क्योंकि उसके पीछे कारण है, वह फायदे का सौदा है, गाय हमारे घाटे का सौदा है। इसके लिए मेरे दो सुझाव हैं सरकार को, एक तो उस नस्ल को इंट्रोड्यूस किया जाए ताकि वह हमारे यहां वह 45 लीटर की जगह 15 लीटर दूध भी देगी तो कोई भी गौमाता नहीं कहेंगे बावजूद उसके वह हमारी गायें सुरक्षित रहेंगी। आज जो भी गाय मरती है आप कभी भी, कहीं भी जाकर देख लें, उसके पेट में कम से कम दस से पन्द्रह किलो पोलीथिन निकलेगा, जिसको हम गौमाता कहते हैं। मेरा सुझाव है कि जितनी भी हमारा चरागाह भूमि है उस चरागाह भूमि में हमारे अंग्रेजी बबूल को निकालकर इरिडिकेट करके, जड़ मूल से नष्ट करके और हमारी जो पौष्टिक घास है, धामण, सेवण, पौभ, उनको पुन: स्थापित किया जाए चरागाह के अंदर तो हमें घास भी मिल जाएगी और हमारे गाय की नस्ल भी बच जाएगी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बिजली के बारे में निवेदन करना चाहता हूं कि किसानों के लिए बिजली दिन में दी जाए, किसानों को रात में बिजली दी जाती है, रात में इतनी कड़ाके की सर्दी होती है, उस सर्दी में पानी कैसे किसान लगाएगा? माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा सरकार से निवेदन है कि कम से कम संवेदनशील सरकार है, हमारी इस सरकार को तो सोचना चाहिए कि दिन के वक्त किसानों को बिजली दे, उद्योगों में आप रात को दे दें, वह उद्योग वाले अंदर बैठकर काम करते हैं, किसान खेत के अंदर पानी पिलाता है उस कड़ाके की ठंड के अंदर तो मैं चाहूंगा कि दिन में बिजली दें।

माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार ने घोषणा की कि पांच वर्ष तक बिजली की दरें किसानों के लिए नहीं बढ़ाई जाएंगी, वास्तव में स्वागत योग्य कदम है, लेकिन पिछली बार भी मुख्य मंत्रीजी ने घोषणा की थी और दाम नहीं बढ़ाए थे लेकिन पिछली भारतीय जनता पाटी की सरकार ने तीन बार

(श्री खुशवीरसिंह)

किसानों की बिजली की दरें बढ़ाई हैं। उसके साथ में भी एक काम और किया कि पिछली सरकार ने प्रति माह बिल देना शुरू कर दिया, उससे हुआ यह कि जो मीटर की दर ली जाती है, सेवा शुल्क लिया जाता है वह डबल हो गया, दो महीने में 35 रुपए आ रहे थे वह प्रति माह 35 रुपए और जुड़कर आने लग गए तो मैं चाहूंगा कि पिछली सरकार ने जो इस तरह के काम किए, छुप कर काम किए, जनता के साथ धोखा किया है तो वह उजागर भी होना चाहिए और मैं सरकार से भी चाहूंगा, मुख्य मंत्री महोदय से चाहूंगा कि आप घोषणा कर दें कि दो माह से बिल लिया जाएगा ताकि वह डबल पैसा किसानों के और उपभोक्ताओं के चाहे वह डोमेस्टिक हो, उनके वह न लगे। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: कृपया समाप्त करें।

श्री खुशवीरसिंह (मारवाड़ जंक्शन): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं संविदाकर्मियों के बारे में निवेदन करना चाहूंगा। पिछली गहलोत सरकार ने संविदाकर्मियों की, मैं पंचायती राज में रहा हुआ हूं, उस समय जिला प्रमुख था मैं, पंचायती राज के अंदर 19 हजार एलडीसी की भर्ती निकाली गई थीं। तीन चरणों में भर्ती होनी थी, उसमें प्रथम चरण में भर्ती कर दी गई थी, द्वितीय चरण की भर्ती की प्रक्रिया पूरी हो चुकी थी लेकिन न्यायालय में जाने की वजह से कुछ विलम्ब हो गया और सुप्रीम कोर्ट की डबल बैंच ने आदेश दिया कि इनको बोनस अंक देते हुए राज्य सरकार इनकी भर्ती तुरन्त करे। पिछली सरकार ने बहुत दिमाग से काम किया। उन्होंने प्रथम चरण में जो भर्ती हुई थी, उसी भर्ती को दुबारा उन्होंने दर्शाते हुए घोषणा कर दी कि हमने इतनी भर्ती कर दी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि जो शेष रह गए उनमें से पांच-छह हजार पोस्ट समाप्त भी कर दी गई। (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं चाहूंगा, मैं पहली बार बोल रहा हूं, पांच मिनट का समय मुझे दीजिए।

श्री अध्यक्ष: समय सीमा एक मिनट बची है।

श्री खुशवीरसिंह (मारवाड़ जंक्शन): माननीय अध्यक्ष महोदय, पांच मिनट और।

श्री अध्यक्ष: एक मिनट बचा है, सदन की कार्यवाही एक घंटे बढ़ाई गई है। आप आगे के लिए प्लीज।

श्री खुशवीरसिंह (मारवाड़ जंक्शन): जब तक मैं बोलूं तब समय बढ़ा दिया जाए, मेरा निवेदन है आपसे सचेतक महोदय।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप दस मिनट बोल लिए, वाइंडअप प्लीज। आप वाइंडअप कीजिए। आपके बोलने तक सदन की कार्यवाही बढ़ाई जाती है। प्लीज वाइंडअप।

अभिभाषण

धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद

श्री खुशवीरसिंह (मारवाड़ जंक्शन): धन्यवाद। आपने समय दिया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि मुख्य मंत्री महोदय ने एक बहुत बड़ी घोषणा की है और उस पर मैं कहना चाहूंगा कि समय के अभाव में मेरा एक अंतिम बिन्दु है मैं उसको समाप्त करता हूं क्योंकि कोई उसको सोच नहीं सकता है।

माननीय मुख्य मंत्रीजी ने अपने पिछले कार्यकाल में..... (व्यवधान) माननीय सदस्य।

(18.00 बजे)

श्री अध्यक्ष: आप अपनी बात बोलिए न, आप डाइवर्ट मत हों, सब सुन रहे हैं।

श्री खुशवीरसिंह (मारवाड़ जंक्शन): मैं डिस्टर्ब हो रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, 2012-13 में पिछली सरकार में गहलोत साहब ने एक ऐसे प्रोजेक्ट की स्वीकृति जारी की थी, प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, जो जैसलमेर के अन्दर है। जो गोडावण हैं, अध्यक्ष महोदय, मैं पांच मिनट का समय लूंगा, फिर मेरी बात समाप्त करूंगा।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप बोले ही जा रहे हैं, भूमिका बना रहे हैं। अपनी बात को सम-अप करिए।

श्री खुशवीरसिंह (मारवाड़ जंक्शन): अध्यक्ष महोदय, गोडावण पूरे विश्व में हिन्दुस्तान में ही पाई जाती है और हिन्दुस्तान में भी मात्र राजस्थान के

(श्री खुशवीरसिंह)

अन्दर जैसलमेर में उसका ब्रीडिंग सेंटर रह गया है। ऐसे आन्ध्र प्रदेश में, कर्नाटक में, महाराष्ट्र में भी पिछले तीन-चार वर्षों में, दस वर्षों में 5-6, 5-6 नजर आ रही हैं लेकिन ब्रीडिंग सेंटर राजस्थान ही रह गया है। पिछली सरकार में 2012 के अन्दर सोरसन में प्रजनन केन्द्र स्थापित करने हेतु मुख्य मंत्रीजी ने उसको आगे बढ़ाने के लिए घोषणा की है तो उसका जो जुड़ाव है वो है हमारा इंक्यूबेशन सेंटर जो रामदेवरा में बन रहा है वहां उसमें क्या होगा, वह मैं बताना चाहूंगा कि गोडावण एक ऐसा पक्षी है जो दो साल में एक बार एक ही अंडा देता है और पिछले वर्षों में कई बार देखा गया है कि वहां जो आवारा कुत्ते हैं वो अंडा खा जाते हैं। मुख्य मंत्रीजी ने पिछली बार घोषणा करके वहां उनका जाली लगाकर जो कंजर्वेशन किया है उससे सुरक्षा तो मिली है लेकिन अब वो जाली गल चुकी है इसलिए, अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि उस गोडावण को बचाने के लिए, जहां पिछले डेढ़ वर्षों में वहां पर सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा के वाइड तार खींचे गये हैं उन तारों से टकरा-टकरा कर छह गोडावण मर चुके हैं। उनकी वन विभाग से मीटिंग भी हो चुकी है और वन विभाग ने आग्रह किया कि आप अण्डरग्राउंड तार वहां पर लगाइए ताकि इन गोडावण की रक्षा हो सके, क्योंकि 60 गोडावण ही बचे हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि इसके ऊपर प्रभावी काम हो और जोर-शोर से जल्दी काम किया जाए तो हम इस पक्षी को बचा सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय, अंत में मैं मेरी बात समाप्त कर रहा हूं कि किसान की छीजत के नाम पर जो बिजली वाले इस तरह का एक माहौल बनाकर उनको थैफ्ट के नाम से, चोरी के नाम से कर रहे हैं पर असली छीजत कहां हो रही है वह मैं बताना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, मैं पिछली सरकार की बात कहना चाहूंगा कि आप उसकी जांच करवाइए और अगर सही जांच होती है तो करोड़ रुपये का घोटाला उजागर होकर सामने आएगा। अध्यक्ष महोदय, अजमेर के अन्दर वर्ष 2013-14 में अण्डरग्राउंड लाइन का कांट्रेक्ट हुआ था और वहां पर किलोमीटरों में अण्डर ग्राउंडलाइन बिछाई गई। उसका टेंडर हुआ और 50 करोड़ रुपये का आर्डर दिया गया। बिना आदेश किए उसको तीन गुना, चार गुना बढ़ा दिया गया और वहां से जो पुरानी लाइन और टावर हटाये गये, अध्यक्ष महोदय, मैं चाहूंगा कि मुख्य मंत्रीजी इसका जवाब दें और सीबीआई से इसकी जांच करवायें तथा जो पुराने कंडक्टर, टावर थे वो स्टोर के अन्दर एक

(श्री खुशवीरसिंह)

जमा नहीं हुआ। वो कहां पर बिके, कहां वो गये हैं उनका अगर पूरा ब्यौरा लिया जाए तो वास्तव में छीजत तो यहां हो रही है जबकि हम किसानों के पीछे पड़े हैं। इसलिए, अध्यक्ष महोदय, इस छीजत को यदि हम रोक दें, जो हजारों करोड़ रुपये की छीजत है तो किसानों का भला होगा और प्रदेश का भला होगा। वो छीजत अगर रुक जाती है तो उसके आधार पर बीपीएल परिवार और किसानों को नि:शुल्क बिजली दी जा सकती है। धन्यवाद, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष: सदन की बैठक मंगलवार, दिनांक 22 जनवरी, 2019 के प्रात: 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 18.04 बजे मंगलवार, दिनांक 22 जनवरी 2019 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र तखतगढ़ (पाली) में चिकित्सकों के रिक्त पद

7. श्री जोराराम कुमावत (सुमेरपुर): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) पाली जिले के तखतगढ़ नगरपालिका क्षेत्र में स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में चिकित्सिकों/विशेषज्ञ चिकित्सकों के कुल कितने पद स्वीकृत हैं?

(2) उक्त स्वीकृत पदों में से कितने पद रिक्त हैं?

(3) क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र तखतगढ जिला पाली में चिकित्सकों/ विशेषज्ञ चिकित्सकों के कुल 7 पद स्वीकृत हैं। जिनकी सूची परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, तख्तगढ़ जिला पाली में वर्तमान में चिकित्सकों के 6 पद रिक्त हैं।

(3) जी हां। पदोन्नति के रिक्त पदों को डीएसीपी के अन्तर्गत पदोन्नत चिकित्सकों से/पीजी पूर्ण चिकित्सक उपलब्ध होने पर यथासम्भव शीघ्र भरने के प्रयास किये जाएंगे।

चिकित्सा अधिकारी के रिक्त पदों को शीघ्र भरने के प्रयास किये जाएंगे।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

झालावाड़ जिले के गांवों में श्मशान हेतु भूमि का आबंटन

8. श्री नरेन्द्र नागर (खानपुर): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

यह सही है कि वर्तमान में झालावाड़ जिले के सभी राजस्व गांवों में शमशान भूमि का आबंटन नहीं है। यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सभी गांवों में श्मशान हेतु भूमि का आबंटन करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी नहीं। झालावाड़ जिले के समस्त राजस्व गांवों में श्मशान स्थित (आबंटित) है। राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 92 के अन्तर्गत ग्राम की आवश्यकतानुसार श्मशान हेतु भूमि सेट-अपार्ट करने के लिए जिला कलक्टर प्राधिकृत है। वर्तमान में श्मशान हेतु भूमि आबंटन का कोई प्रकरण झालावाड़ जिले में विचाराधीन नहीं है।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

किशनगढ़ के चिकित्सालयों में रिक्त पद

1. श्री सुरेश टाक (किशनगढ़): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ में कितने सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, उप केन्द्र एवं डिस्पेन्सरीज संचालित हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उपरोक्त स्वास्थ्य केन्द्रों/उप केन्द्रों पर किस-किस श्रेणी के कितने-कितने पद स्वीकृत हैं व उनमें से कितने पद भरे हुए हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) किशनगढ़ विधान सभा क्षेत्र में स्वीकृत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, उप स्वास्थ्य केन्द्र एवं डिस्पेन्सरियों की सूचना परिशिष्ट- अ पर संलग्न है।

(2) किशनगढ़ विधान सभा क्षेत्र में संचालित चिकित्सा संस्थानों में चिकित्सकों के स्वीकृत/कार्यरत/रिक्त पदों की सूचना परिशिष्ट-ब पर संलग्न है एवं अराजपत्रित संवर्ग के स्वीकृत/कार्यरत/रिक्त पदों की सूचना परिशिष्ट-स पर संलग्न है।

(3) जी हां। पदोन्नति के रिक्त पदों को डीएसीपी के अन्तर्गत पदोन्नत चिकित्सकों से/पीजी पूर्ण चिकित्सक उपलब्ध होने पर शीघ्र भरने के प्रयास किये जाएंगे।

चिकित्सा अधिकारी के रिक्त पदों को स्थानान्तरण से शीघ्र भरने के प्रयास किये जायेंगे।

विभाग में नर्सिंग/पैरामेडिकल संवर्ग में रिक्त पदों को भरे जाने हेतु उनके नाम के सम्मुख अंकित तिथि को विज्ञप्ति जारी करते हुए आनलाइन आवेदन पत्र प्राप्त किये जा चुके हैं, जिसकी भर्ती की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। भर्ती की कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात रिक्त पदों को प्राथमिकता के साथ भरे जाने का प्रयास किया जायेगा।

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

क्र.सं.	**पद का नाम**	**रिक्त पदों की संख्या**	**जारी विज्ञप्ति की दिनांक**
1	नर्स श्रेणी द्वितीय	6557	30.05.2018
2	म.स्वा.का.	5602	18.06.2018
3	फिजियोथेरेपिस्ट	30	29.03.2018
4	प्रयोगशाला सहायक	1534	29.05.2018
5	फार्मासिस्ट	1736	13.08.2018
6	ईसीजी टैक्नी.	362	01.08.2018
योग		**15821**	

विभाग में पदोन्नति वाले रिक्त पदों को विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक उपरान्त रिक्त पदों को भरे जाने के प्रयास किये जाएंगे।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत जी एन एम के पदों पर भर्ती

2. श्री हनुमान बैनिवाल (खींवसर): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 2016 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत जीएनएम की भर्ती हेतु आनलाइन परीक्षा आयोजित की गई थी? यदि हां, तो उक्त भर्ती में कितने अभ्यर्थियों ने भाग लिया तथा परीक्षा के आवेदन से कितनी राशि सरकार को प्राप्त हुई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त परीक्षा का परिणाम 11 जनवरी, 2019 तक जारी नहीं किया गया? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त परीक्षा का शीघ्र परिणाम जारी करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? कारण सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। जीएनएम पद की आनलाइन परीक्षा में 40011 अभ्यर्थियों ने भाग लिया।

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत दिनांक 28.01.2016 को जारी विज्ञप्ति में विज्ञापित पदों के आवेदन शुल्क के रूप में 4 करोड़ 57 लाख रुपये की राशि प्राप्त हुई।

(2) जी हां। उक्त पद का परिणाम माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में दायर रिट याचिका संख्या 392/2016 ओमप्रकाश व अन्य बनाम राज्य सरकार में पारित स्थगन आदेश दिनांक 17.03.2016 के कारण परिणाम जारी नहीं किया जा सका।

तदोपरान्त माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय दिनांक 29.11.18 द्वारा उक्त स्थगन आदेश निरस्त किया गया था। उक्त निर्णय की पालना में संविदा जी.एन.एम. का परिणाम जारी करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(3) जी हां। उक्त परिणाम शीघ्र जारी करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

राजस्थान पर्यटन विकास निगम की बन्द पड़ी इकाइयों को लीज पर देने की योजना

3. **श्री नारायण सिंह देवल** (रानीवाड़ा): क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान पर्यटन विकास निगम (आर.टी.डी.सी.) के होटल्स, मिड-वे, यात्रिका भवन निर्मित होने के बावजूद संसाधनों के अभाव में बन्द पड़े हैं? यदि हां, तो ऐसी कितनी इकाईयां कहां-कहां पर बन्द हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या ऐसी उक्त बन्द इकाइयों, भवनों को निजी क्षेत्र में लीज/ठेके पर दिया गया है? यदि हां, तो कितनी को कब से नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राजस्थान पर्यटन विकास निगम के बन्द होटल, मिडवे, कैफेटेरिया, यात्रिकाओं की सूची परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) राजस्थान पर्यटन विकास निगम की बंद इकाइयों में से 4 इकाइयां लाईसेंस पर दी हुई हैं, जिनका विवरण परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

अन्य इकाइयों के संबंध में मंत्रिमण्डल द्वारा सैद्धान्तिक निर्णय लिया

(पर्यटन मंत्री)

गया है, उसके अनुरूप कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। मंत्रिमण्डल निर्णय की प्रति परिशिष्ट "स" पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

पश्चिमी राजस्थान में डेजर्ट सर्किल बनाने की कार्ययोजना

4. **श्री मदन प्रजापत** (पचपदरा): क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या प्रदेश में पर्यटन नीति बनाई गई है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) विगत पांच वर्षों में धार्मिक एवं ऐतिहासिक पर्यटन स्थलों के रख-रखाव एवं प्रोत्साहन हेतु सरकार द्वारा कितनी धनराशि व्यय की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) प्रदेश में देशी एवं विदेशी सैलानियों को आकर्षित करने हेतु सरकार द्वारा क्या-क्या ठोस कदम उठाये जा रहे हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार बालोतरा-बाड़मेर सहित पश्चिमी राजस्थान में डेजर्ट सर्किल बनाकर धार्मिक एवं ऐतिहासिक पर्यटन स्थलों के संरक्षण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु कोई प्रभावी कदम उठा रही है? यदि हां, तो क्या? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। राजस्थान की पर्यटन नीति, 2001 की छायाप्रति परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) धार्मिक एवं ऐतिहासिक पर्यटन स्थलों के रख-रखाव एवं प्रोत्साहन हेतु विगत पांच वर्षों में राज्य योजनान्तर्गत राशि रु. 153.551 करोड़ तथा केन्द्रीय प्रवर्तित योजनान्तर्गत भारत सरकार से प्राप्त राशि रु. 180.46 करोड़ का व्यय किया गया है।

(3) देशी एवं विदेशी सैलानियों को आकर्षित करने हेतु एग्रेसिव मार्केटिंग के तहत राष्ट्रीय एवं अन्तराष्ट्रीय स्तर पर विज्ञापन जारी कर तथा देश-विदेश में पर्यटन मार्टस/प्रदर्शनियों के माध्यम से राजस्थान पर्यटन का प्रचार-प्रसार किया जा रहा है।

देशी एवं विदेशी सैलानियों को आकर्षित करने हेतु प्रदेश में मेले-

(पर्यटन मंत्री)

त्यौहारों का आयोजन कराया जाता है। इसमें प्रमुख रूप से पुष्कर मेला-पुष्कर (अजमेर), मरु महोत्सव जैसलमेर, कुम्भलगढ़ फेस्टिवल-राजसमन्द, पतंग उत्सव-जयपुर, शरद समारोह-माउण्ट आबू, तीज उत्सव-जयपुर, गणगौर उत्सव जयपुर, ऊंट उत्सव-बीकानेर, बेणेश्वर मेला-डूंगरपुर, मारवाड़ समारोह-जोधपुर आदि हैं।

इसके अतिरिक्त देशी विदेशी सैलानियों को आकर्षित किए जाने हेतु प्रमुख पर्यटन स्थलों का प्रचार साहित्य, पोस्टर्स, मेले त्यौहारों के ब्रोशर, प्रचार साहित्य मुद्रित कराया जाकर विभिन्न पर्यटन आयोजनों यथा मार्टस, सेमीनार, विभागीय मेले-त्यौहारों इत्यादि में तथा पर्यटन ट्रेड के व्यक्तियों एवं अधिनस्थ कार्यालयों के माध्यम से पर्यटकों को वितरित किये जाते हैं।

(4) पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार की स्वदेश दर्शन योजनान्तर्गत राशि रु. 97.24 करोड़ का डेजर्ट सर्किट प्रोजेक्ट पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार को प्रेषित किया गया है, जिसमें बाड़मेर हेतु राशि रु. 9.18 करोड़ के किराडू, पेट्रो-टूरिज्म एवं महाबार सेन्ड डयून्स के विकास कार्य प्रस्तावित किये गये हैं।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

गडरा रोड तहसील के ग्रामों में गौचर भूमि पर अतिक्रमण

5. श्री अमीन खां (शिव): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) तहसील गडरारोड-जिला बाड़मेर के गांव देतांनी-राणासर-खुडांनी हरसांनी-मौसेरी व खारची में सैटलमेंट के समय कितनी-कितनी भूमि गैर मुमकिन गौचर थी? ग्रामवार रकबा व खसरा नंबर सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त ग्रामों में कितना-कितना रकबा सुरक्षित भूमि है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) सरकार द्वारा उक्त ग्रामों की गौचर भूमि से अतिक्रमण हटाने की क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) तहसील गडरारोड जिला बाड़मेर के ग्राम देतांनी-राणासर-खुडांनी हरसांनी, मौसेरी व खारची में सैटलमेंट के समय मूल ग्राम हरसाणी व खारची थे, जिसमें से हरसाणी मूल ग्राम से देतांणी, राणासर, खुडाणी, हरसाणी एवं

(राजस्व मंत्री)

दूसरे मूल ग्राम खारची से से खारची व मौसेरी बने हैं। सैटलमेंट के समय मूल ग्राम हरसाणी में कुल खसरों की संख्या 105 एवं कुल रकबा 32915.15 बीघा किस्म गै.मु.गौचर भूमि एवं वक्त सैटलमेंट मूल ग्राम खारची में कुल खसरों की संख्या 7 एवं कुल रकबा 2831.04 बीघा किस्म गै.मु.गौचर दर्ज थी, जिसकी खसरावार सूची मूल ग्राम हरसाणी एवं खारची की सूची परिश्ष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) ग्राम हरसाणी, देतांनी, राणासर, खुडाणी, मौसेरी व खारची में वर्तमान में सुरक्षित गौचर भूमि क्रमश: 3582.02, 5303.04, 532.06, 4181.13, 1189.11 एवं 1525.04 बीघा है जिसकी सूची परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

(3) अतिक्रमण की सूचना प्राप्त होने पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही की जाती है, जो कि एक सतत प्रक्रिया है। वर्ष 2018 में ग्राम देतांणी में 01-12 बीघा गौचर भूमि पर अतिक्रमण के प्रकरण प्रस्तुत होने पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही करके बेदखल किये गये। वर्तमान में उपरोक्त ग्रामों में कोई अतिक्रमण के प्रकरण पटवारियों द्वारा प्रस्तुत नहीं हुए हैं।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

फुलेरा में जन समस्याओं के आवेदनों का निस्तारण

6. **श्री निर्मल कुमावत** (फुलेरा): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र की फुलेरा एवं किशनगढ़ रेनवाल तहसील कार्यालय में जन समस्याओं से संबंधित कितनी परिवेदनाएं/अभ्यावेदन जनवरी, 2016 से दिसम्बर, 2018 तक प्राप्त हुए? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त प्राप्त परिवेदनाओ/अभ्यावेदनों में से कितने का निस्तारण किया गया और कितने किस कारण से वर्तमान में लम्बित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) तहसील किशनगढ़ रेनवाल में जनवरी 2016 से दिसम्बर 2018

(राजस्व मंत्री)

तक कुल 237 परिवेदनायें प्राप्त हुई हैं तथा तहसील फुलेरा में जनवरी 2016 से दिसम्बर 2018 तक कुल 361 परिवेदनायें प्राप्त हुई हैं। सूची परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) तहसील किशनगढ़ रेनवाल में प्राप्त परिवेदनाएं/अभ्यावेदनों में से 234 का निस्तारण किया गया है व 3 वर्तमान में लम्बित हैं तथा तहसील फुलेरा में प्राप्त परिवेदनायें/अभ्यावेदनों में से 350 का निस्तारण किया गया है व 11 वर्तमान में लम्बित हैं। लम्बित का कारण संलग्न सूची परिशिष्ट-अ में अंकित है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रदेश में रीट लेवल परीक्षा की पात्रता

7. **श्री राजकुमार रोत** (चौरासी): क्या शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) रीट लेवल परीक्षा की पात्रता के क्या नियम हैं? नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि रीट लेवल प्रथम में सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को 60 प्रतिशत अंक लाने पर व अनुसूचित जनजाति को 36 प्रतिशत अंक लाने पर पात्र माना गया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि अनुसूचित क्षेत्र में पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध होने के उपरान्त भी करीब 1200 पद रिक्त रखे गये हैं? यदि हां, तो क्यों?

(4) क्या यह भी सही है कि रीट लेवल प्रथम पर सामान्य क्षेत्र (नान ट्राइबल) में भर्ती पर राज. उच्च न्यायालय ने रोक लगा रखी है? यदि हां, तो क्या यह भी सही है कि उक्त रोक में जनजाति क्षेत्र (अनुसूचित जनजाति क्षेत्र) पर भी सरकार ने रोक लगा रखी है? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या सरकार अनुसूचित जनजाति क्षेत्र (ट्राइबल एरिया) में रीट लेवल पर लगी रोक हटाये जाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? व अब कब तक नियुक्ति दे दी जावेगी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) रीट लेवल परीक्षा की पात्रता के नियम परिशिष्ट क पर संलग्न है।

(2) जी हां। रीट लेवल प्रथम में सामान्य वर्ग एवं ओ.बी.सी., अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के साथ सभी अभ्यर्थियों को 60 प्रतिशत अंक लाने पर ही पात्र माना गया है केवल अनुसूचित क्षेत्र (TSP) के अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को 36 प्रतिशत अंक लाने पर पात्र माना गया है। जिसका विवरण परिशिष्ट क के बिन्दु संख्या 02 एवं परिशिष्ट-ख पर संलग्न है।

(3) जी नहीं। अनुसूचित क्षेत्र में सामान्य वर्ग के 910 एवं अनुसूचित जाति वर्ग के 267 पात्र अभ्यर्थीयों उपलब्ध नहीं होने के कारण अनुसूचित क्षेत्र में पद रिक्त है। पात्र अभ्यर्थी (रीट/आरटेट में 60 प्रतिशत अंक) उपलब्ध होने पर रिक्त पदों को भरा जा सकेगा।

(4) जी हां। शिक्षक भर्ती 2018 अन्तर्गत गैर अनुसूचित क्षेत्र में लेवल प्रथम के विज्ञापित 20497 पदों के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय जयपुर में डीबी संख्या 1322/2018 महेन्द्र कुमार जाटोलिया व अन्य बनाम राज्य सरकार व अन्य में पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 23.10.2018 से नियुक्तियों से रोक लगाई हुई है। उक्त याचिका में मुख्यत: अध्यापक लेवल प्रथम पर चयन के आधार को चुनौती दी हुई है इस कारण टी.एस.पी. व नॉन टी.एस.पी. क्षेत्र में लेवल प्रथम के चयनित किसी भी अभ्यर्थी को नियुक्ति नहीं दी गई है।

(5) माननीय उच्च न्यायालय जयपुर में विचाराधीन डीबी संख्या 1322/2018 महेन्द्र कुमार जाटोलिया व अन्य बनाम राज्य सरकार व अन्य में पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 23.10.2018 से नियुक्तियों से रोक लगाई हुई है। उक्त याचिका में मुख्यत: अध्यापक लेवल प्रथम पर चयन के आधार को चुनौती दी हुई है। माननीय न्यायालय द्वारा टी.एस.पी. एरिया में लेवल प्रथम के चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्तियां दिए जाने पर प्रत्यक्षत: कोई रोक नहीं लगाई हुई है किन्तु अध्यापक लेवल प्रथम के पद पर चयन के आधार टी.एस.पी. व नान टी.एस.पी. क्षेत्र हेतु समान हैं। अत: माननीय नयायालय के निर्णयानुसार ही नियुक्ति दी जा सकेगी।

(विवरण पुस्कालय में रखा गया)

अनूपगढ़ में विद्यालयों का क्रमोन्नयन

8. श्रीमती संतोष (अनूपगढ़): क्या शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ में ऐसी कितनी ग्राम पंचायतें हैं, जिनमें उच्च प्राथमिक विद्यालय संचालित नहीं हैं? ग्राम पंचायत वार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र की ऐसी ग्राम पंचायतों में प्राथमिक विद्यालयों को क्रमोन्नत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ में कुल 56 ग्राम पंचायते हैं। इन सभी ग्राम पंचायतों में राजकीय उच्च प्राथमिक स्तर (कक्षा 1 से 8 तक की अध्ययन सुविधा वाले) के विद्यालय संचालित हैं। ऐसी कोई ग्राम पंचायत नहीं है, जिसमें कक्षा 1 से 8 स्तर तक की शिक्षा सुविधा उपलब्ध न हो।

(2) बिन्दु संख्या 01 के अनुसार।

खानपुर में राजकीय महाविद्यालय हेतु भूमि का आबंटन

9. श्री नरेन्द्र नागर (खानपुर): क्या उच्च शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि खानपुर उपखण्ड मुख्यालय पर राजकीय महाविद्यालय के लिए कोई भूमि व भवन स्वीकृत नहीं है? यदि हां, तो क्या सरकार भूमि व भवन के निर्माण की स्वीकृति प्रदान करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी हां। राजकीय महाविद्यालय, खानपुर वर्तमान में सीनियर उच्च माध्यमिक विद्यालय, खानपुर के अस्थाई भवन में संचालित है।

राजकीय महाविद्यालय, खानपुर के लिए भूमि आबंटन का प्रकरण राज्स्व विभाग के स्तर पर लंबित है। (परिशिष्ट-1)

कालेज शिक्षा विभाग के स्तर पर भूमि आबंटन हेतु समय-समय पर प्रयास किये जा रहे हैं। (परिशिष्ट-2)

भूमि आवंटन की कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात सार्वजनिक निर्माण

(राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा)

विभाग से भवन निर्माण हेतु अनुमानित राशि का तकमीना प्राप्त कर राशि स्वीकृत करने की कार्यवाही की जा सकेगी।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

राजकीय महाविद्यालय बूंदी के छात्रावास के लिए भूमि का आबंटन

10. श्री रामनारायण मीना (पीपल्दा) : क्या उच्च शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए राजकीय महाविद्यालयों के संलग्न छात्रावासों का निर्माण किए जाते रहे हैं? यदि हां, तो प्रदेश में कितने महाविद्यालयों में छात्रावास निर्मित हैं तथा कितनों के लिए छात्रावास निर्मित किया जाना प्रस्तावित है? सूची सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त महाविद्यालयों के कई छात्रावास बंद हैं? यदि हां, तो किन कारणों से तथा क्या सरकार बंद पड़े छात्रावासों को पुन: चालू करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि राजकीय महाविद्यालयों बूंदी के छात्रावास के समीप स्थित भूमि को छात्रावास के लिए आबंटित किए जाने के स्थान पर अन्य संस्था/व्यक्तियों को आबंटित किया गया है? यदि हां, तो कब तक एवं किन कारणों से? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार उक्त आबंटित भूमि के संबंध में पुनर्विचार कर उक्त भूमि को महाविद्यालय (छात्रावास) के लिए आबंटित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राजकीय महाविद्यालयों में सामान्यत: उच्च शिक्षा विभाग द्वारा महाविद्यालय भवन का ही निर्माण करवाया जाता है। इन महाविद्यालयों में छात्रावास का निर्माण सामान्यत: उच्च शिक्षा विभाग द्वारा नहीं करवाया जाता। महाविद्यालयों में विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर अन्य राजकीय विभाग यथा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जनजातीय विकास विभाग, ग्रामीण विकास विभाग आदि द्वारा अपनी योजनाओं के

(राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा)

अन्तर्गत छात्रावास का निर्माण करवाया जाता है। विभाग में उपरोक्तानुसार व्यवस्था से वर्तमान में 65 राजकीय महाविद्यालयों में छात्रावास का निर्माण हुआ है।

(2) राजकीय महाविद्यालय के परिसरों में विभिन्न योजनाओं के तहत छात्रावास स्वीकृत है, जिनमें महाविद्यालयवार संचालन की स्थिति एवं संचालित ना होने का कारण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(3) जी नहीं।

(4) वर्तमान में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)